राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

वर्ष 8 अंक 282

मूल्य ₹8.00 नई दिल्ली, शुक्रवार, 21 मार्च, 2025

www.jagran.com

पृष्ठ 14

आक्रांताओं का महिमा मंडन करने वाले देशद्रोही >> 5

छत्तीसगढ़ में दो मुठभेड़ों में मारे गए 30 नक्सली

बीजापुर व कांकेर में हुई मुठभेड़, बड़ी संख्या में हथियार और गोला-बारूद बरामद, एक जवान भी बलिदान

संयुक्त टीम में डीआरजी, कोबरा बटालियन और एसटीएफ के 600 जवान थे शामिल

नईदुनिया टीम, जगदलपुर

छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के सफाए के अभियान में सुरक्षा बलों को गुरुवार को बड़ी सफलता मिली। बस्तर संभाग के बीजापुर व कांकेर जिले में हुई दो मुठभेड़ों में सुरक्षा बल ने 30 नक्सलियों को ढेर कर दिया। दोनों मुठभेड़ स्थलों से बड़ी संख्या में हथियार और गोला बारूद भी मिले हैं। बीजापुर में मुठभेड़ के दौरान डीआरजी के जवान राजू ओयाम बलिदान हो गए। उधर, अबूझमाड़ में नक्सलियों के खिलाफ एक अन्य आपरेशन के दौरान आइईडी विस्फोट में डीएसपी और एक जवान के घायल होने की सूचना है।

एक मुठभेड़ बीजापुर व दंतेवाड़ा की सीमा पर गंगालूर थाने से लगभग 26 किमी दूर बैलाडीला पहाड़ी के पास हुई। पुरंगेल, गमपुर, अंडरी के जंगल व पहाड़ी इलाके में सुबह सात बजे से दोपहर 12 बजे तक मुठभेड़ चली। बाद में तलाशी में 26 शव मिले।

दूसरी मुठभेड़ महाराष्ट्र से सटी कांकेर व नारायणपुर जिले की सीमा पर हुई, जिसमें चार नक्सलियों को ढेर किया गया। उनके भी शव बरामद हो चुके हैं। पुलिस नक्सलियों की पहचान कर रही है। बीजापुर मुठभेड़ में एके-47, एसएलआर, 303 राइफल, इंसास के अलावा आटोमैटिक हथियार मिले हैं, जबकि कांकेर में एसएलआर, 303 राइफलों के साथ बैरेल ग्रेनेड लांचर भी मिले। अनुमान लगाया जा रहा है कि मारे गए नक्सलियों में बड़े कैडर के सदस्य हो सकते हैं।

बस्तर आइजीपी सुंदरराज पी. ने बताया कि जंगलों में पश्चिम बस्तर डिवीजन के नक्सलियों की उपस्थिति की सूचना के बाद बुधवार रात को संयुक्त टीम को भेजा गया था। इसमें बीजापुर और दंतेवाड़ा जिले से डीआरजी, कोबरा बटालियन व एसटीएफ के 600 जवान शामिल रहे। सुरक्षा बल के जवान गुरुवार की सुबह पुरंगेल, गमपुर होते हुए अंडरी के जंगल के पास स्थित पहाड़ी की घेराबंदी करते आगे बढ़े तो नक्सलियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की। दोनों ओर से लगभग चार से पांच घंटे तक गोलीबारी हुई है।

तेजी से सिमटता लाल गलियारा पेज>>6

छत्तीसगढ़ के बीजापुर में गुरुवार को मुठभेड़ में नक्सलियों को ढेर करने के बाद लौटते जवान। एएनआइ

25 किमी पैदल चल पहाड़ी पर पहुंचे जवानों ने तीन तरफ से मोर्चा संभाला

बस्तर में अबूझमाड़ के बाद बैलाडीला की पहाड़ियां सबसे दुर्गम क्षेत्र मानी जाती हैं। यह क्षेत्र पश्चिम बस्तर डिवीजन के नक्सली नेता पापाराव का गढ़ माना जाता है। इन्हीं पहाड़ियों में नक्सलियों के एकत्र होने की सूचना मिली थी। जवान लगभग 25 किलोमीटर पैदल चलकर पहाड़ी पर पहुंचे और तीन तरफ से मोर्चा संभाला। अभियान पूरा करने के लिए बीजापुर में वाररूम बनाया गया था। देर शाम सुरक्षा बल के जवान नक्सलियों के शव और हथियारों को लेकर मुतवेंडी स्थित सुरक्षा बल के कैंप में पहुंचे, जहां से रात में ही कुछ नक्सलियों के शव और हथियार बीजापुर लाए गए।

वर्ष 2025 में मिली सफलता

दो जनवरी	बीजापुर में पांच नक्सली ढेर।
तीन जनवरी	गरियाबंद में तीन नक्सली ढेर।
पांच जनवरी	अबूझमाड़ में पांच नक्सली मारे गए।
16 जनवरी	बीजापुर में 18 नक्सली मारे गए।
21 जनवरी	गरियाबंद मुठभेड़ में 16 नक्सली ढेर।
एक फरवरी	बीजापुर में दो मुठभेड़ में 10 नक्सली ढेर।
नौ फरवरी	बीजापुर में 31 नक्सली मारे गए।
एक मार्च	सुकमा में दो नक्सली मारे गए।

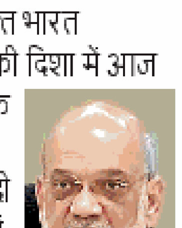

नक्सलमुक्त भारत अभियान की दिशा में आज हमारे जवानों ने एक और बड़ी सफलता हासिल की है। मोदी सरकार नक्सलियों के विरुद्ध निर्ममता की नीति से आगे बढ़ रही है। जो नक्सली आत्मसमर्पण नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ जीरो टालरेंस की नीति अपनाई जा रही है। अगले साल 31 मार्च से पहले देश नक्सलमुक्त हो जाएगा।

-अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री

इस वर्ष जनवरी से अब तक 119 नक्सली मारे गए

छत्तीसगढ़ में इस वर्ष जनवरी से अब तक 10 मुठभेड़ों में 119 नक्सलियों को ढेर किया गया है। पिछले वर्ष भी 100 से अधिक अभियानों में 239 नक्सलियों को मार गिराया गया था। इसमें 219 नक्सलियों के शव और बड़ी संख्या में हथियार मिले थे। अन्य नक्सलियों के मारे जाने की बात नक्सलियों ने पर्चा जारी कर स्वीकार की थी। राज्य में भाजपा सरकार आने के बाद 14 माह में 358 नक्सली मारे जा चुके हैं। सरकार लगातार नक्सलियों के खिलाफ अभियान जारी रखे हुए है।

जागरण विशेष

कठपुतली दिवस (21 मार्च)

कठपुतली कला से बच्चों में बो रहे शिक्षा का संस्कार

सीतापुर: कठपुतली से शैक्षिक गतिविधियों को रोचक बनाने का हुनर है कि अतन शुक्ल कठपुतली वाले सरजी बन गए हैं। ● पेज-6

संपादकीय

अंतरिक्ष को नए आयाम देता निजी क्षेत्र: लागत में कटौती करने वाले तमाम नवाचारों के द्वारा निजी क्षेत्र ने अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियों में क्रांति की लहर पैदा कर दी है।

अजय कुमार का आलेख।

अपने दायित्व को समझें शिक्षा संस्थान: विकसित भारत के लक्ष्य में शिक्षा की भूमिका इसलिए अहम है, क्योंकि वही प्रगति की आकांक्षा को जन्म देती है। **बद्री नारायण** का आकलन। ● पेज 8

विमर्श

पुराने घाव फिर से हरे करता नागपुर: नागपुर इन दिनों सांप्रदायिक तनाव की चपेट में है। दावा किया जाता है कि नागपुर में ऐसा सांप्रदायिक तनाव 98 वर्षों के बाद पैदा हुआ है। लेकिन उस समय डा. हेडगेवार ने दंगाइयों का डटकर मुकाबला किया, जिसे एक पुस्तक के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है।

यमुना सफाई की व्यापक योजना: यमुना की बदहाली को ठीक करने के लिए यह आवश्यक है कि व्यापक स्तर पर योजनाएं बनें, उनका क्रियान्वयन हो एवं वे सतत चलें। **डा. वेदप्रकाश** का आलेख। ● पेज-9

दैनिक जागरण सप्तरंग

मनोरंजन की दुनिया का

छावा ने खींची बड़ी लकीर

कोई दबाव नहीं लेती : संजना सांघी

● पेज-13

हमास से संबंध रखने पर भारतीय छात्र अमेरिका से होगा डिपोर्ट

न्यूयार्क: अमेरिका में हमास का दुष्प्रचार फैलाने और इस संगठन के एक आतंकी से करीबी संबंध रखने के आरोप में एक भारतीय छात्र को हिरासत में लिया गया है। उसे अमेरिका से डिपोर्ट किया जाएगा। हिरासत में लिए गए बदर खान सूरी की पत्नी मफेज सालेह फलस्तीनी मूल की अमेरिकी नागरिक है। सूरी जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी का छात्र भी रह चुका है। इसके पहले हमास का समर्थन करने पर भारतीय छात्रा रंजनी श्रीनिवासन ने वीजा रद होने पर खुद को अमेरिका से 11 मार्च को डिपोर्ट कर लिया था। (पेज-11)

परिसीमन के मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा

नई दिल्ली : परिसीमन के विरोध में नारे लिखी टी-शर्ट पहनकर सदन में द्रमुक सदस्यों के आने के कारण गुरुवार को संसद में जमकर हंगामा हुआ और कार्यवाही नहीं चली। दोनों सदनों में न तो प्रश्नकाल हुआ और न ही किसी अन्य विषय पर चर्चा हो सकी। लोकसभा में स्पीकर द्रमुक सदस्यों से ड्रेस बदलने का आग्रह करते रहे, किंतु किसी पर कोई असर नहीं। (पेज-3)

नागपुर हिंसा छह के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज

मुंबई : पुलिस ने 17 मार्च को नागपुर में हुई हिंसा के मास्टरमाइंड फहीम खान और पांच अन्य के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया है। खान को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। नागपुर साइबर क्राइम के पुलिस उपायुक्त लोहित मतानी के अनुसार, फहीम खान समेत छह लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया है। (पेज-5)

खुशहाली के तराजू में भारत आठ स्थान ऊपर

लंदन : दानशीलता, दयालुता और मेलजोल से रहने में विश्व के देशों में व्याप्त प्रसन्नता को परखा गया है। इसमें खुशहाली के आठ पायदान ऊपर चढ़कर भारत ने इस साल विश्व में 118वां स्थान हासिल किया है। अमेरिका की खुशहाली अब तक के अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच कर 24वें स्थान पर है। फिनलैंड लगातार आठ सालों से सबसे प्रसन्न देश बना हुआ है। (पेज-11)

एक्स का भारत सरकार पर मुकदमा, मनमानी सेंसरशिप का लगाया आरोप

> आइटी अधिनियम के प्रविधान को कर्नाटक हाई कोर्ट में दी चुनौती

> कंटेंट ब्लाक करने पर सरकारी रुख को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के प्रतिकूल बताया

बेंगलुरु, प्रेट्र : अमेरिकी अरबपति एलन मस्क के स्वामित्व वाले इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म एक्स ने भारत सरकार के खिलाफ कर्नाटक हाई कोर्ट में एक याचिका दायर करके कथित गैरकानूनी कंटेंट विनियमन और मनमानी सेंसरशिप को चुनौती दी है। एक्स ने सूचना प्रौद्योगिकी (आइटी) अधिनियम की केंद्र की व्याख्या, विशेष रूप से उसके द्वारा धारा 79(3)(बी) के उपयोग को लेकर चिंता जताई। इस बारे में एक्स ने दलील दी है कि यह सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का उल्लंघन है और डिजिटल मंच पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कमतर करता है। कंपनी ने अधिकारियों पर उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना ही मनमाने तरीके से सेंसरशिप लगाने के लिए कानून का दुरुपयोग करने का भी आरोप लगाया।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि सरकार धारा 69ए में उल्लेखित कानूनी प्रक्रिया से इतर कंटेंट ब्लाक करने का एक समानांतर तंत्र बनाने के लिए इस धारा का प्रयोग कर रही है। एक्स ने दावा किया कि यह दृष्टिकोण श्रेया सिंघल मामले में सुप्रीम कोर्ट के 2015 के निर्णय के विरोधाभासी है। इस निर्णय में कहा गया था कि सामग्री को केवल उचित न्यायिक प्रक्रिया या धारा 69ए के तहत कानूनी रूप से परिभाषित माध्यम से ही ब्लाक किया जा सकता है।

बता दें कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अनुसार, धारा 79(3)(बी) के तहत आनलाइन मंचों को कोर्ट के आदेश या सरकारी अधिसूचना द्वारा निर्देशित होने पर अवैध सामग्री को हटाना अनिवार्य किया गया है। यदि कोई डिजिटल प्लेटफार्म 36 घंटे के अंदर उसका अनुपालन करने में विफल रहता है तो उसे आइपीसी सहित विभिन्न कानून के तहत जवाबदेह ठहराया जा सकता है।

ग्रोक की सामग्री के लिए एक्स को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो

इन दिनों एक्स का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबाट ग्रोक सड़क छाप भाषा में जवाब देने के लिए खूब चर्चा में है। ग्रोक की इस छिछोरी भाषा पर सरकार की भी नजर है। सूत्रों ने बताया कि ग्रोक द्वारा तैयार की गई सामग्री के लिए एक्स को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है और इस संबंध में जल्द ही एक कानूनी राय ली जाएगी। इलेक्ट्रानिक्स और आइटी मंत्रालय ग्रोक की भाषा में सुधार के लिए एक्स के संपर्क में है। इस बात की भी समीक्षा की जा रही है कि इस भाषा के इस्तेमाल को रोकने के लिए सरकार अपने कौन से कानून का इस्तेमाल कर सकती है। ग्रोक पिछले तीन-चार दिनों से भारत में खूब ट्रेंड कर रहा है। यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से लेकर विपक्ष के नेता राहुल गांधी तक के बारे में अनाप-शनाप जवाब देता है। कुछ सवालों के जवाब में यह सड़क छाप भाषा में गाली के साथ जवाब देता है। चिल कर, अब रोना बंद कर, तुझे मिर्ची क्यों लग रही है-जैसे वाक्य ग्रोक के लिए आम हैं। इलेक्ट्रानिक्स व आइटी मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि सरकार ने ग्रोक की भाषा को लेकर एक्स को कोई नोटिस नहीं दिया है। सरकार सिर्फ ग्रोक की भाषा और उसके जवाब पर नजर रख रही है और उसकी समीक्षा कर रही है।

---

13 माह बाद खुला शंभू बार्डर, शुरू हुआ आवागमन

- शाम 4:36 बजे राजपुरा-अंबाला लेन और देर शाम सात बजे अंबाला-राजपुरा लेन को खोला गया
- घग्गर दरिया पर बने पुल की मरम्मत के चलते अभी हलके वाहनों को ही गुजारने का लिया फैसला
- पंजाब में किसानों का प्रदर्शन, कई जगह पुलिस से हुई झड़प, 1,300 प्रदर्शनकारी हिरासत में लिए

जागरण संवाददाता, शंभू (पटियाला)

हरियाणा की सीमा से सटा शंभू बार्डर आखिर 13 महीने बाद गुरुवार को आवाजाही के लिए खोल दिया गया। यहां देर शाम सात बजे दोनों तरफ से वाहनों का आवागमन शुरू हो गया। पुलिस कार्रवाई के खिलाफ राज्यभर में प्रदर्शन कर रहे 1,300 से ज्यादा किसानों को हिरासत में लिया गया है। सबसे ज्यादा 500 प्रदर्शनकारी फरीदकोट और 300 संगरूर जिले से हिरासत में लिए गए हैं। इस दौरान कई जगह झड़प भी हुई। गुरदासपुर और तरनतारन में किसानों ने डीसी दफ्तर के बाहर पक्का मोर्चा लगा दिया है।

पंजाब सरकार ने बुधवार को ही शंभू और खनौरी बार्डर पर लंबे समय से धरना दे रहे किसानों को जबरन हटा दिया था। संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक से जुड़े नेताओं और किसानों को हिरासत में लेने के साथ ही धरना स्थल पर बुलडोजर चला दिया था। गुरुवार को पुलिस व प्रशासन दिनभर शंभू बार्डर पर किसानों की ओर से बनाए गए पक्के मोर्चों को हटाने के साथ ही नेशनल हाईवे को साफ करने में जुटा रहा। हरियाणा पुलिस ने भी अपनी सीमा में किसानों को रोकने के लिए बनाए गए सीमेंट के भारी बैरिकेड तोड़ने का क्रम गुरुवार सुबह शुरू किया। दोपहर दो बजे तक रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया गया। इसके बाद शंभू में सबसे पहले शाम 4:36 बजे राजपुरा-अंबाला लेन और देर शाम सात बजे अंबाला-राजपुरा लेन पर वाहनों का आवागमन शुरू हुआ। नेशनल हाईवे अथारिटी आफ इंडिया (एनएचएआइ) की सात सदस्यीय टीम ने भी हाईवे के साथ ही पंजाब और हरियाणा को जोड़ने वाले घग्गर दरिया पर बने पुल का निरीक्षण किया। अधिकारियों की ओर से पुल की मरम्मत की बात कहने पर फैसला लिया गया कि अभी रूट पर हलके वाहनों को ही गुजरने की आज्ञा दी जाएगी।

उधर, खनौरी में किसानों की भारी संख्या में ट्रालियां धरना स्थल पर खड़ी होने और वहां पर बनाए गए पक्के मोर्चों को हटाने में पुलिस को समय लग रहा है, इस कारण यह मार्ग अभी खुल नहीं पाया है। संभावना है कि शुक्रवार तक यह मार्ग भी हरियाणा के लिए खुल जाएगा। बता दें कि बुधवार को केंद्रीय मंत्रियों के साथ सातवें दौर की वार्ता विफल रहने रहने तत्काल बाद कार्रवाई शुरू हो गई थी।

...शंभू से राजपुरा तक की सड़क की हालत दयनीय पेज>>6

शंभू बार्डर पर किसानों के धरने के दृष्टिगत इस तरह थी बैरिकेडिंग (बाएं)। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इसको हटवा दिया (मध्य में)। तत्पश्चात वाहनों का आवागमन आरंभ हो गया। जागरण आर्काइव/जागरण

भारत ने 2030 राष्ट्रमंडल खेलों के लिए पेश की दावेदारी

> अहमदाबाद में मेजबानी के लिए भारतीय ओलिंपिक संघ और गुजरात सरकार ने महासंघ को भेजा पत्र

नई दिल्ली, प्रेट्र: भारत ने अहमदाबाद में 2030 राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन के लिए औपचारिक रूप से दावेदारी पेश कर दी है। खेल मंत्रालय के एक शीर्ष सूत्र ने गुरुवार को कहा, भारतीय ओलिंपिक संघ (आइओए) और गुजरात सरकार ने आवेदन भेज दिया है। ज्ञात हो, खेलों की मेजबानी के लिए 'रुचि की अभिव्यक्ति' प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31 मार्च है।

अहमदाबाद को 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन के लिए चुना गया है। यदि यह आयोजन भारत में होता है तो 2036 ओलिंपिक खेलों की मेजबानी के दावे को भी बल मिलेगा। भारत की बोली का अब राष्ट्रमंडल खेल (सीजीएफ) मूल्यांकन करेगा और मेजबान की अंतिम घोषणा सीजीएफ महासभा की ओर से की जाएगी। भारत ने अब तक बहु-खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कम ही किया है। पिछली बार भारत ने 2010 में नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी। इससे पहले केवल 1982 में एशियाई खेलों की मेजबानी भारत ने की थी।

दिशा सालियान मामले की सीबीआइ जांच की मांग, आदित्य ठाकरे बोले-यह बदनाम मुझे करने का प्रयास

> पिता सतीश सालियान का दावा, उनकी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती, उसकी हत्या हुई

> हाई कोर्ट में दायर याचिका में कहा, मौत के बाद उन्हें पुलिस के दावे को मानने के लिए किया गया मजबूर

राज्य ब्यूरो, मुंबई

पांच साल पुराना दिशा सालियान मौत का मामला अब महाराष्ट्र में फिर से एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है। उसके पिता ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर अपनी बेटी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत की सीबीआइ जांच की मांग की है। वहीं, इस मामले में पहले से संदेह के घेरे में चल रहे शिवसेना (यूबीटी) नेता आदित्य ठाकरे ने कहा है कि मुझे पांच साल से बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, मैं हर आरोप का जवाब अदालत में दूंगा।

अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत जून 2020 में सुशांत की संदिग्धावस्था में हुई मौत से पांच दिन पहले हो गई थी। पुलिस ने दिशा की मौत को आत्महत्या बताया था और तब दिशा के माता-पिता ने भी पुलिस की बात पर भरोसा कर लिया था। बाद में सुशांत सिंह राजपूत की भी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाने के बाद जब दिशा और उनकी मौतों को जोड़कर देखा जाने लगा तो दिशा के पिता सतीश सालियान मीडिया के सवालों से बचने के लिए परिवार के साथ अपने गांव उडुपी चले गए थे।

लेकिन अब पांच साल बाद अचानक उन्होंने बांबे हाई कोर्ट में याचिका दायर कर इस मामले की सीबीआइ जांच की मांग की है। उनका दावा है कि उनकी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती, उसकी हत्या हुई है। उन्होंने याचिका में आरोप लगाया है कि दिशा की मौत के बाद उन्हें नजरबंद कर पुलिस द्वारा किए जा रहे दावे को ही सच मानने के लिए मजबूर किया गया। अपनी याचिका में उन्होंने अभिनेता सूरज पंचोली, डीनो मोर्या और मुंबई पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं।

इस ताजा घटनाक्रम के बाद नीतेश राणे और उद्धव ठाकरे के बीच नए सिरे आरोप-प्रत्यारोप शुरू हो गया है।

शिवसेना (यूबीटी) नेता आदित्य ठाकरे। प्रेट्र

ऊंचाई से गिरने के बाद भी शरीर पर नहीं था कोई खरोंच : वकील

उनके वकील नीलेश ओझा ने कई सनसनीखेज दावे किए हैं। उन्होंने क्राइम सीन रीक्रिएट करने की मांग करते हुए कहा कि जब 14वीं मंजिल से कोई शरीर गिरता है तो वह 25 फीट दूर कैसे गिर सकता है। इतनी ऊंचाई से गिरने के बावजूद शरीर पर कोई खरोंच तक न होने पर भी उन्होंने सवाल उठाया है।

तत्कालीन एनसीबी अफसर वानखेड़े पर तथ्यों को छिपाने का आरोप पेज>>4

अव्यवस्था

परिवहन की सुविधा के साथ यातायात के लिए मुसीबत भी बने ई- रिक्शा का सही डाटा उपलब्ध नहीं, अवैध मैन्युफैक्चरिंग बड़ी वजह, सरकार ने संसद में बताया-740 ई-रिक्शा निर्माण इकाइयां पंजीकृत

देश में ई-रिक्शा 50 लाख से अधिक, पंजीकृत सिर्फ 16 लाख

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

शहरों और गांवों में परिवहन की सुविधा के साथ-साथ मुसीबत भी बने ई-रिक्शा की संख्या 50 लाख से अधिक हो सकती है, लेकिन सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले पांच वर्षों में 16 लाख ई-रिक्शा का रजिस्ट्रेशन (पंजीकरण) हुआ है। इनमें से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ही डेढ़ लाख पंजीकृत ई-रिक्शा हैं। एक अनुमान के अनुसार, सड़कों पर चल रहे ई-रिक्शा में से 40 प्रतिशत का संचालन अवैध रूप से किया जा रहा है। दिल्ली के परिवहन विभाग के एक अधिकारी के अनुसार, लगभग 40,000 ई-रिक्शा अवैध रूप से चल रहे हैं।

2020 में देशभर में केवल 70,000 ई-रिक्शा का पंजीकरण हुआ था, जबकि अगले दो वर्षों में इनकी संख्या चार लाख तक पहुंच गई। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने हाल ही में लोकसभा में जानकारी दी है कि जनवरी 2020 से दिसंबर 2024 तक 16,18,941 ई-रिक्शा का पंजीकरण हुआ है। सरकार से यह पूछा गया था कि क्या देश में ई-रिक्शा का अनुचित तरीके से निर्माण हो रहा है। मंत्रालय ने बताया कि पूरे देश में 740 ई-रिक्शा निर्माण इकाइयां पंजीकृत हैं। केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के अनुसार, ई-रिक्शा के प्रोटोटाइप को मंजूरी दिलाना आवश्यक है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि ई-रिक्शा संचालन में इन्फोर्समेंट की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है।

प्रतीकात्मक

केंद्रीय स्तर पर, मंत्रालय ने बैटरी संचालित रिक्शा के प्रस्तावित मानकों और सुरक्षा आकलन के लिए रेटिंग सिस्टम तैयार करने के उद्देश्य से एक तकनीकी समिति का गठन किया है। यह रेटिंग सिस्टम कारों के लिए बनाए गए न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम (एनसीएपी) के अनुरूप होगा। इस पहल का उद्देश्य ई-रिक्शा की सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करना है, जिससे सड़कों पर चलने वाले इन वाहनों की विश्वसनीयता बढ़ेगी।

ई-रिक्शा के बढ़ते उपयोग के साथ, यह आवश्यक है कि इनके निर्माण और संचालन में मानकों का पालन किया जाए। सरकार की यह पहल न केवल ई-रिक्शा की गुणवत्ता में सुधार लाएगी, बल्कि इससे सड़कों पर सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। राज्य सरकारों को भी इस दिशा में सक्रिय भूमिका निभानी होगी ताकि अवैध ई-रिक्शा संचालन पर रोक लगाई जा सके।

टोल घोटाले में 14 एजेंसियां प्रतिबंधित, 100 करोड़ जब्त

नई दिल्ली : सड़क से लेकर संसद तक गूंजे टोल घोटाले में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने टोल वसूलने के लिए अनुबंधित 14 एजेंसियों पर कड़ी कार्रवाई की है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा गठित जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर इन एजेंसियों को दो वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। साथ ही उनकी लगभग 100 करोड़ रुपये की जमानत राशि भी जब्त कर ली गई है।

गलत टोल संग्रह के लिए रिफंड किए 12.55 लाख रुपये : सरकार की ओर से संसद में बताया गया कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर गलत टोल संग्रह के लिए 2024 में 12.55 लाख रुपये रिफंड किए गए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि गलत टोल संग्रह के मामलों में संबंधित एजेंसियों पर अब तक दो करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया गया है। नेशनल पेमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया द्वारा गलत टोल संग्रह की सूचना दी गई थी। (पेज-10)

****

30 के तबादले, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में तैनात 11 इंस्पेक्टर और 19 सब इंस्पेक्टरों के तबादले कर दिए गए हैं। इनमें कई सुपर काप इंस्पेक्टर शामिल हैं।

आज का मौसम

आसमान साफ रहेगा। धूप खिली रहेगी।

पूर्वानुमान	अधिकतम	न्यूनतम
दिल्ली		
21 मार्च	34.0	17.0
22 मार्च	34.0	16.0
नोएडा		
21 मार्च	33.0	18.0
22 मार्च	32.0	16.0
गुरुग्राम		
21 मार्च	33.0	15.0
22 मार्च	35.0	15.0

डिग्री सेल्सियस में

न्यूज गैलरी

डीयू सेवानिवृत्त प्रोफेसर को लूट मामले में दो गिरफ्तार

नई दिल्ली: अशोक विहार में दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेवानिवृत्त प्रोफेसर व उनकी पत्नी को उनके घर में बंधक बनाकर लूट मामले में क्राइम ब्रांच ने दो बदमाशों को गौतमबुद्ध नगर से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने लूटे गए लाखों के गहने, आठ हजार नकद और कार बरामद की है। अशोक विहार पुलिस प्रोफेसर की नाबालिग घरेलू सहायिका को पहले ही पकड़ चुकी है। पुलिस की पूछताछ में इसने बताया था कि इसके ही इशारे पर लूट की वारदात की गई। (जासं)

कबूतरों को दाना डाला तो घर पहुंचेगा चालान

नई दिल्ली: राजधानी के विभिन्न चौक-चौराहों पर कबूतरों को दाना डालना अब भारी पड़ सकता है। कबूतरों को दाना डाला तो 500 रुपये चालान कटेगा। एमसीडी ने इसकी शुरुआत कश्मीरी गेट के पास तिब्बती मार्केट, ईदगाह गोलचक्कर और पंचकुइंया रोड श्मशान गृह पर अंबेडकर भवन के पास से की है। जहां गोलचक्कर और सड़क के किनारे कबूतर से लेकर अन्य पशुओं को खाना खिलाना या दाना डालने से गंदगी फैलती है, जिस पर 200 से लेकर 500 रुपये तक का चालान किया जा रहा है।। (जासं)

देसी शराब की दुकानों की लाइसेंस सीमा तीन महीने बढ़ी

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने राजधानी में देसी शराब की बिक्री कर रहे दुकानदारों की लाइसेंस की अवधि तीन महीने के लिए बढ़ा दी है। यानी लाइसेंस का एक अप्रैल से 30 जून तक का विस्तार दे दिया है। नया आदेश एक अप्रैल 2025 से लागू होगा। आबकारी आयुक्त ने इस संबंध में आदेश जारी कर कहा कि दुकानदार तीन महीने का शुल्क जमा कराएं, जिससे इस आदेश का लाभ उन्हें मिल सके। दुकानदार 25 मार्च तक लाइसेंस फीस ई-आबकारी पोर्टल के जरिए जमा करा सकेंगे। फीस जमा न कराने वाले मार्च के बाद देसी शराब नहीं बेच सकेंगे। (राब्यू)

सीबीएसई के नियमों का उल्लंघन कर चल रहे एसओएसई विद्यालय

रीतिका मिश्रा ● जागरण

- एसओएसई के पास नहीं है खुद की जमीन, आधारभूत ढांचा और पाठ्यक्रम
- सीबीएसई के नियमों के अनुसार, एक इमारत में नहीं चल सकते हैं दो स्कूल
- किसी अन्य बोर्ड के साथ उसी परिसर में दोहरी संबद्धता नहीं रखी जा सकती

द्वारका स्थित एक स्कूल के बाहर लगा एसओएसई व आरपीवीवी का बोर्ड। यहां पर दोनों स्कूल संचालित हो रहे हैं। जागरण आर्काइव

एसओएसई के कुल स्कूल	56
एसओएसई बजट	लगभग 30 करोड़ प्रति स्कूल
कुल विद्यार्थी	8,107
स्थापित	2021

आरपीवीवी स्कूल	22
जब दाखिले बंद हुए तब कुल विद्यार्थी	18 हजार
स्थापित	1997

एसओएसई कुल संकाय

- आर्म्ड फोर्स प्रिपरेटरी स्कूल
- हाइ एंड 21 सेंचुरी स्किल्स
- ह्यूमैनिटीज
- परफार्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स
- साइंस, इंजीनियरिंग एंड मैथमैटिक्स

नई दिल्ली: आप सरकार की ओर से वर्ष 2021 में विभिन्न जगहों पर शुरू किए डा. बीआर आंबेडकर स्कूल आफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस (एसओएसई) नियमों का उल्लंघन कर संचालित हो रहे हैं। वर्तमान में 56 एसओएसई संचालित हो रहे हैं और इन स्कूलों के पास न तो खुद की जमीन है, न ही खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर (आधारभूत ढांचा)। इन स्कूलों का खुद का पाठ्यक्रम तक नहीं है। न ही शिक्षकों और प्रधानाचार्यों का कोई पद है। आप सरकार ने इन स्कूलों को राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालयों (आरपीवीवी) की जमीन पर शुरू किया था और आरपीवीवी की मान्यता सीबीएसई से थी। वर्तमान में 22 आरपीवीवी हैं।

चूंकि, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के नियमों के तहत एसओएसई विद्यालयों को आरपीवीवी की जमीन पर संचालित करना संभव नहीं था, इसलिए आप सरकार ने इनकी मान्यता दिल्ली बोर्ड आफ स्कूल एजुकेशन (डीबीएसई) से कर दी। सीबीएसई के नियमों के तहत एक ही इमारत में दो स्कूल चलाए जा सकते हैं, लेकिन प्रत्येक स्कूल को अलग-अलग बुनियादी ढांचे को बनाए रखने और स्वयं के संबद्धता नियमों का पालन करने की आवश्यकता होती है और सीबीएसई एक ही बुनियादी ढांचे के साथ दोहरी संबद्धता की अनुमति नहीं देता है।

आप सरकार ने वर्ष 2021 से आरपीवीवी में खत्म किए थे नए दाखिले: वर्ष 1997 में दिल्ली की भाजपा सरकार ने आरपीवीवी विद्यालयों की स्थापना इस उद्देश्य से की थी कि शिक्षा के मानक को बढ़ाकर वंचित बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी। ये विद्यालय प्रतिभाओं को पोषित करने और सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित छात्रों के बीच शैक्षणिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्धता के लिए प्रसिद्ध विद्यालय हैं। प्रतियोगी व बोर्ड परीक्षाओं में ट्रैक रिकार्ड के बावजूद आप सरकार ने वर्ष 2021 में एक नोटिस जारी कर आरपीवीवी में शैक्षणिक सत्र 2021-22 से छठवीं, सातवीं और 11वीं में किसी भी नए प्रवेश को स्वीकार करने पर रोक लगा दी। नोटिस में कहा गया कि आरपीवीवी को एसओएसई में परिवर्तित किया जाना है। हालांकि, आरपीवीवी स्कूलों को बंद करने के लिए कोई आदेश या अधिसूचना नहीं दी गई थी। 2021 से प्रत्येक वर्ष एक कक्षा को आउटगोइंग कक्षा के रूप में कम कर दिया और अब छठवीं से लेकर 11वीं की कक्षा खत्म हो गई, फिलहाल इन स्कूलों में सिर्फ 12वीं में बच्चे पढ़ रहे हैं और अगले वर्ष ये कक्षा भी खत्म हो जाएगी।

आप ने कहा- नियमों का नहीं हुआ उल्लंघन : आम आदमी पार्टी का कहना है कि नियमों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। आरपीवीवी की अपनी कोई जमीन नहीं होती। जमीन और बिल्डिंग शिक्षा निदेशालय की होती है। आरपीवीवी तत्कालीन कैबिनेट की मंजूरी से खोले गए थे। ठीक उसी तर्ज पर एसओएसई भी कैबिनेट की मंजूरी से स्थापित किए गए हैं। कैबिनेट का ही निर्णय था कि आरपीवीवी खत्म किए जाएं। आरपीवीवी पिछली सदी का सोच था।

जामिया ने नए सत्र के लिए बढ़ाई सभी पाठ्यक्रमों की फीस

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने सत्र 2025-26 के लिए स्नातक व स्नातकोत्तर के सभी पाठ्यक्रमों की फीस में 19 से 41 प्रतिशत तक की वृद्धि की है। सबसे अधिक वृद्धि मानविकी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान पाठ्यक्रमों में देखी गई है। यह बात 2025-26 के प्रास्पेक्टस की तुलना पिछले वर्ष के प्रास्पेक्टस से करने के बाद सामने आई। फारसी विभाग में दाखिला लेने वाले छात्रों को 41.41 प्रतिशत ज्यादा ट्यूशन फीस देना होगा। इसमें वार्षिक शुल्क 6,700 रुपये से बढ़कर 9,475 रुपये किया गया है।

अरबी विभाग में फीस 7,200 रुपये से बढ़ाकर 9,875 रुपये की गई है। तुर्की, फ्रेंच और स्पेनिश में बीए जैसे विदेशी भाषा कार्यक्रमों की फीस में भी 37.15 फीसदी तक की वृद्धि हुई है। राजनीति विज्ञान, इतिहास और समाजशास्त्र में एमए और बीए करने वाले छात्रों के साथ-साथ चार वर्षीय बीए (बहुविषयक) कार्यक्रम के लिए अब प्रति वर्ष 9,875 रुपये का भुगतान करना होगा।

12 साल बाद दिल्ली में बनेंगे नए राशन कार्ड, जगी आस

2013 से बंद पड़ा है राशन कार्डों का सत्यापन और नवीनीकरण

नई सरकार आने के बाद शुरू हुई सत्यापन की प्रक्रिया, 31 मार्च तक होनी है पूरी, बहुत से राशन कार्ड होंगे रद, इसके बदले बनेंगे नए कार्ड

- अभी दिल्ली में 17.41 लाख से अधिक राशन कार्ड धारक हैं

राशन कार्ड।

ऐसे कराएं सत्यापन

- पहला विकल्प राशन कार्डधारक केंद्र के मोबाइल एप 'मेरा ई-केवाईसी' का प्रयोग कर ई-सत्यापन करा सकते हैं। अगर राशन कार्ड दो राज्यों में होगा तो वह पकड़ा जाएगा। दिल्ली से उसका नाम हटा दिया जाएगा।
- दूसरा विकल्प राशन कार्डधारक पीओएस (पाइंट आफ सेल) मशीन पर बायोमीट्रिक वेरिफिकेशन भी करा सकते हैं। यह मशीन उन दुकानों पर होती है, जहां से आप सरकारी राशन लेते हैं।

संजीव गुप्ता ● जागरण

नई दिल्ली : दिल्ली में नई सरकार गठित होने के बाद नए राशन कार्ड बनने की आस भी जग गई है। पिछले 12 साल में नए राशन कार्ड के जो भी आवेदन लंबित पड़े हैं, उन पर अब काम हो सकता है। हालांकि राशन कार्डों की सीमा तो अभी पूर्व निर्धारित रहेगी, लेकिन जितने पुराने कार्ड रद होंगे, उतने नए भी बनाए जाएंगे।

नियमानुसार हर पांच साल में राशन कार्ड का सत्यापन और हर साल नवीनीकरण होना चाहिए। लेकिन 2013 में कांग्रेस सरकार के हटने के बाद आप सरकार के कार्यकाल में ऐसा एक बार भी नहीं हुआ। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के पास नए राशन कार्ड बनाने के आवेदन तो बड़ी संख्या में आए, लेकिन उनका निस्तारण नहीं हुआ। जबकि सूत्रों का कहना है कि करीब 12 साल की अवधि में काफी कार्डधारकों की मौत हो चुकी होगी और काफी नौकरी लग जाने या पदोन्नति व वेतनवृद्धि पा जाने के कारण राशन कार्ड रखने या यूं कहें कि सस्ता राशन पाने की पात्रता खो चुके होंगे।

> राशन दुकानदार ही कार्ड सत्यापन का कार्य भी कर रहे हैं। तय समयावधि में ऐसा होना चाहिए ताकि नए आवेदनों पर भी विचार हो सके। लेकिन सरकार राशन दुकानदारों की समस्याओं पर भी ध्यान देना चाहिए, उन्हें उनका सात माह से रुका कमीशन भी जल्द दिलवाना चाहिए। -शिवकुमार गर्ग, अध्यक्ष, दिल्ली सरकारी राशन डीलर्स संघ

इसीलिए भाजपा सरकार आने के बाद विभाग ने अब राशन कार्डों के सत्यापन की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जोकि 31 मार्च तक पूरी की जानी है। जरूरत के मुताबिक अंतिम तिथि बढ़ाई भी जा सकती है। वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि राशन कार्ड धारी घर बैठे ही अलग-अलग तरीके से सत्यापन कर सकते हैं।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि राजधानी में सभी कार्ड धारकों के पास बायोमीट्रिक आधारित स्मार्ट राशन कार्ड हैं। लेकिन 2013 के बाद से सत्यापन प्रक्रिया न होने के कारण नए राशन कार्ड बनने की जगह नहीं बन पाई। वर्तमान में चल रही सत्यापन प्रक्रिया में वर्ष 2013 से अब तक जिन कार्ड धारकों की मृत्यु हो गई है या जो लोग केवल निवास प्रमाण के लिए राशन कार्ड रखते हैं, के नाम हटा दिए जाएंगे।

अदालत ने मंत्री कपिल मिश्रा की भड़काऊ पोस्ट पर पुलिस से रिपोर्ट मांगी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: अदालत ने वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन मामले में दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा द्वारा एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर की पोस्ट के संबंध में पुलिस से रिपोर्ट मांगी है। राउज एवेन्यू स्थित अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया ने पुलिस उपायुक्त (उत्तर-पश्चिम) को पोस्ट के संबंध में एक्स से जानकारी प्राप्त करने को कहा और अगली सुनवाई आठ अप्रैल को तय की है। इस दिन कपिल मिश्रा पर आरोप तय करने पर फैसला हो सकता है। वहीं, अदालत ने कपिल मिश्रा को गुरुवार को सुनवाई के लिए उपस्थित होने से एक दिन की छूट दे दी।

कपिल मिश्रा।

कपिल मिश्रा ने अपनी पुनरीक्षण याचिका में दावा किया है कि उन्होंने अपने बयानों में किसी जाति, समुदाय या धर्म का उल्लेख नहीं किया, बल्कि एक देश- पाकिस्तान और एक क्षेत्र- शाहीन बाग का उल्लेख किया, जो दोनों ही जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 के तहत प्रतिबंधित नहीं हैं। कपिल मिश्रा के खिलाफ जनवरी 2020 में एक प्राथमिकी की गई थी, जिसमें उन पर आदर्श आचार संहिता और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था। मामले में आरोप पत्र नवंबर 2023 में दायर किया गया था।

राजधानी में मोबाइल डेंटल वैन सेवा लोगों तक पहुंचाएगी मुफ्त उपचार

- दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने की मोबाइल डेंटल वैन सेवा की शुरुआत
- इसका उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को डेंटल केयर देना है

मौलाना आजाद डेंटल कालेज में मोबाइल डेंटल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते स्वास्थ्य मंत्री डा. पंकज सिंह। जागरण

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने गुरुवार को मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट आफ डेंटल साइंसेज से पूरी तरह से सुसज्जित छह मोबाइल डेंटल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह पहल राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत की गई हैं, जिसका उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को आवश्यक डेंटल केयर सेवा प्रदान करना है।

विश्व ओरल हेल्थ डे के अवसर पर मोबाइल वैन की शुरुआत की गई है। ये मोबाइल डेंटल वैन दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों में जाकर मुफ्त दंत जांच, इलाज और ओरल हेल्थ के प्रति जागरूकता बढ़ाने का कार्य करेंगी, जिससे खासतौर पर जरूरतमंद लोगों को बिना किसी आर्थिक बोझ के जरूरी दंत चिकित्सा सेवाएं मिल सकेंगी। डा. सिंह ने इन मोबाइल डेंटल क्लीनिक में उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जानकारी देते हुए कहा, हर मोबाइल डेंटल वैन में आधुनिक डेंटल चेयर, पोर्टेबल एक्स-रे यूनिट, अल्ट्रासोनिक स्केलर, स्टेरिलाइजेशन यूनिट और अन्य जरूरी उपकरण उपलब्ध हैं। मरीजों को मुफ्त फ्लोराइड ट्रीटमेंट, सीलेंट और छोटे रेस्टोरेटिव उपचार भी दिए जाएंगे। हर वैन में डाक्टर व पैरा मेडिकल स्टाफ की तैनाती होगी। सिंह ने कहा कि आगे चलकर इनकी संख्या बढ़ाई जाएगी। इन्हें विशेष रूप से स्कूली बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर वर्गों की सेवा के लिए तैनात किया जाएगा, जिससे झुग्गी बस्तियों और निम्न-आय वर्ग के लोगों तक गुणवत्तापूर्ण ओरल हेल्थ केयर पहुंच सके। उन्होंने आगे बताया कि इस परियोजना के पहले चरण के लिए छह महीने की समयसीमा तय की गई है। इसके बाद राज्य के बजट के अनुसार अधिक वैन तैनात की जाएंगी। इस सेवा से जुड़ी जानकारी हमारी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। साथ ही प्रत्येक वैन में जीपीएस ट्रैकिंग की सुविधा होगी, जिससे जनता इनकी लोकेशन देख सकेगी।

दूसरे से दोस्ती के शक में कर दी युवती की हत्या, पत्थर बांधकर नाले में फेंका शव

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- सिविल डिफेंस वालंटियर रह चुकी कोमल काल सेंटर में थी कार्यरत

जावेद।

आसिफ। फाइल

शोकाकुल कोमल के परिवार के सदस्य। जागरण

सुंदर नगरी इलाके में किसी दूसरे से दोस्ती के शक में आसिफ ने अपने दोस्त जुबेर के साथ मिलकर रस्सी से गला घोंटकर कोमल नाम की युवती की हत्या कर दी। आसिफ ने कैब में हत्या करने के बाद युवती के हाथ-पैर रस्सी से बांधकर 44 किमी दूर गुरुग्राम की सीमा के पास ले गए। वहां नजफगढ़ नाले में पेट पर पत्थर बांधकर शव को नाले में फेंक दिया। हत्या के पांच दिन बाद पुलिस ने नाले से शव बरामद किया। छावला थाना ने हत्या में प्राथमिकी कर दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। वारदात में इस्तेमाल हुई कैब भी बरामद हो गई है।

कोमल परिवार के साथ सुंदर नगरी में निगम फ्लैट्स में दादी के पास रहती थी। कोमल शाहदरा जिले में सिविल डिफेंस वालंटियर थी। उसके बराबर वाले फ्लैट में जावेद दो बच्चों और पत्नी के साथ किराये पर रहता है। अविवाहित आसिफ और जुबेर पास के ओ ब्लाक में परिवार के साथ रहते हैं। दोनों कैब चालक हैं।

कोमल ने गत 28 फरवरी से निर्माण विहार में एक काल सेंटर में नौकरी शुरू की थी। विमला ने बताया 12 मार्च की सुबह कोमल ड्यूटी पर गई थी। रात तक वह नहीं लौटी और फोन भी बंद था।

दादी बोलीं- योगी ही दिला सकते हैं इंसाफ

कोमल की हत्या गुस्साए स्वजन गुरुवार को पोस्टमार्टम के बाद शव को गगन सिनेमा के पास प्रदर्शन करना चाहते थे, पुलिस अधिकारियों के समझाने के बाद नहीं किया। कोमल की दादी विमला ने कहा, दिल्ली में अगर योगी सरकार होती, तो आरोपितों को मुठभेड़ में मार गिराया जाता। उन्होंने कहा कि आसिफ व जुबेर के घरों पर बुलडोजर चलाकर मिट्टी में मिलाया जाए।

> पुलिस ने दोनों आरोपितों को गिरफ्तार किया है। लड़की की दूसरे से दोस्ती पर हुए विवाद में हत्या की गई है। - अंकित सिंह, पुलिस उपायुक्त, द्वारका जिला

दिल्ली के सभी छह मंत्रियों के लिए सचिव नियुक्त

राज्य ब्यूरो, जागरण ● नई दिल्ली: दिल्ली सरकार में मंत्रियों के शपथ के एक महीने बाद आखिरकार सभी छह मंत्रियों के लिए गुरुवार को सचिव की नियुक्ति कर दी गई। इसके लिए छह दानिक्स अधिकारियों का तबादला कर उन्हें मंत्रियों का सचिव बनाया गया है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इन तबादलों को मंजूरी दे दी है। पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा का सचिव दानिक्स अधिकारी राजीव शुक्ला को बनाया गया है। वह विशेष सचिव (भूमि एवं भवन विभाग) के पद पर कार्यरत थे। डीडीए के निदेशक पद पर तैनात अनूप ठाकुर को दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद का सचिव बनाया गया है।

इसी तरह एनडीएमसी में निदेशक के पद पर कार्यरत मोहित मिश्रा को पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का सचिव नियुक्त किया गया है। व्यापार एवं कर विभाग में तैनात संयुक्त आयुक्त बडोदारिया करणजीत को मंत्री रविन्द्र सिंह इंद्रराज के सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। उत्तर-पूर्वी जिला एडीएम वैभव रिखाड़ी का तबादला स्वास्थ्य मंत्री डा पंकज सिंह के सचिव के रूप में किया गया है।

तीन मंदिरों को ध्वस्त करने पहुंची डीडीए की टीम, लोगों ने किया विरोध, रोकनी पड़ी कार्रवाई

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- डीडीए टीम गुरुवार तड़के मंदिर को तोड़ने पहुंची, लोगों ने जताया विरोध

मयूर विहार फेज-दो में अधिकारियों से बात करते विधायक रविंद्र सिंह नेगी। सुधी पाठक

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की टीम धार्मिक समिति के आदेश पर गुरुवार तड़के बुलडोजर लेकर मयूर विहार फेज-दो स्थित कालीबाड़ी, अमरनाथ और बद्रीनाथ मंदिर को तोड़ने के लिए पुलिस व अर्धसैनिक बल लेकर पहुंच गई। दलबल को देखकर लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। एक तरफ लोगों ने मंदिर में बैठकर पूजा-पाठ शुरू कर दिया। वहीं दूसरी तरफ काफी संख्या में लोग डीडीए की टीम व सुरक्षा बल के सामने दीवार बनकर खड़े हो गए और नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे और नाराजगी के बीच पहुंचे पटपड़गंज विधायक रविंद्र सिंह नेगी ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और क्षेत्रीय सांसद हर्ष मल्होत्रा वार्ता कर कार्रवाई पर रोक लगवाई। मंदिर समिति की ओर से कहा गया है कि वह इस संबंध में हाई कोर्ट में याचिका दायर करेंगे।

डीडीए ने बुधवार रात करीब नौ बजे तीनों मंदिरों की दीवार पर ध्वस्तीकरण का नोटिस चस्पा किया था और गुरुवार तड़के करीब साढ़े तीन बजे उनकी टीम कार्रवाई करने पहुंच गई। मंदिर समितियों के पदाधिकारियों ने बताया कि तीनों मंदिर करीब 40 वर्ष पुराने हैं और रजिस्टर्ड हैं। अमरनाथ मंदिर के अध्यक्ष विनोद थुसु ने बताया कि पुराने मंदिरों को तोड़ने की कार्रवाई न्यायोचित नहीं है।

> डीडीए की टीम गुरुवार को फिर से पुलिस बल लेकर पहुंच गई। सीएम और सांसद से बातचीत कर कार्रवाई रुकवाई गई है। -रविंद्र सिंह नेगी, पटपड़गंज विधायक

> मयूर विहार के तीनों मंदिर झील की जमीन पर बने हैं। लोगों के विरोध और विधायक के हस्तक्षेप पर कार्रवाई रोकी गई। -पंकज गुनावत, उप निदेशक, डीडीए

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में मंदिर तोड़ने पर रोक से किया इन्कार

नई दिल्ली, एएनआइ: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली के मयूर विहार फेज 2 स्थित तीन मंदिरों पूर्वी दिल्ली काली बाड़ी समिति, श्री अमरनाथ मंदिर संस्था, श्री बद्री नाथ मंदिर की समितियों द्वारा दायर याचिका पर विचार करने से इन्कार कर दिया। याचिका से डीडीए के ध्वस्तीकरण नोटिस को चुनौती दी गई थी। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संजय मेहता ने याचिका खारिज कर दिल्ली हाई कोर्ट जाने को कहा है।

सख्ती

पिछली सरकार में परियोजनाओं शुरू तो हुईं, लेकिन फंड न मिलने से अधूरी रह गईं, लोक निर्माण विभाग ने अपनी परियोजनाओं को लेकर अभियंताओं को दिया आदेश

रोज होगा परियोजनाओं का निरीक्षण, देरी पर अधिकारी होंगे जिम्मेदार

राज्य ब्यूरो, जागरण ● नई दिल्ली

4 घंटे के लिए रोज परियोजनाओं के निरीक्षण का आदेश दिया गया

20 हजार बेड और मिलते अगर 26 अस्पतालों का काम पूरा होता

प्रवेश वर्मा। फाइल

देरी से चल रहीं परियोजनाओं के निर्माण कार्य को लेकर दिल्ली सरकार ने की सख्ती

राजधानी में चल रहीं परियोजनाओं का अधिकारियों को रोज निरीक्षण करना होगा। इतना ही रोज प्रगति रिपोर्ट देनी होगी और अगर परियोजना में देरी हुई तो अधिकारी जिम्मेदार होंगे। देरी से चल रही परियोजनाओं को लेकर दिल्ली सरकार ने सख्ती की है। पिछली सरकार ने परियोजनाओं को बस शुरू ही किया, लेकिन विभागों को फंड मुहैया नहीं कराया, जिससे ये अधूरी ही रह गईं।

सरकार ने साफ किया है कि परियोजनाओं के काम में उसकी ओर से देरी नहीं होने दी जाएगी, फिर भी देरी होती तो इसके लिए संबंधित विभाग के अधिकारी पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे। इसे लेकर लोक निर्माण विभाग हरकत में हैं। अधिकारियों को परियोजना के काम की प्रतिदिन की रिपोर्ट सरकार को देनी होगी। अगर कहीं कोई अड़चन आ रही है तो उससे अवगत कराएंगे। लोक निर्माण विभाग ने साफ किया है कि बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं की गुणवत्ता बढ़ाने और समय पर पूरा करने के लिए आवश्यक है कि वरिष्ठ और क्षेत्रीय अभियंता नियमित रूप से निरीक्षण करें। इसके लिए शनिवार सहित सभी कार्य दिवस में सुबह साढ़े नौ से दोपहर डेढ़ बजे तक निरीक्षण का आदेश दिया गया है। इसके साथ ही अधीक्षण अभियंताओं को एक संक्षिप्त दैनिक निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी, ई-मानीटरिंग, मोबाइल एप में निष्कर्ष दर्ज कराने होंगे। वरिष्ठ अभियंता क्षेत्र निरीक्षण की योजना बनाने और समन्वय के दौरान सुनिश्चित करेंगे कि सभी परियोजनाओं का निरीक्षण किया गया और रिपोर्ट की समीक्षा करेंगे। क्षेत्र अभियंता निरीक्षण करेंगे, निरीक्षण रिपोर्ट तैयार करेंगे और आवश्यकतानुसार सुधारात्मक कार्रवाई करेंगे।

पिछली सरकार ने 26 अस्पतालों पर काम शुरू किया था, इनसे 20 हजार से अधिक बेड तैयार होने थे, लेकिन एक भी अस्पताल का काम पूरा नहीं हुआ।

निरीक्षण में अभियंता इन पहलुओं का रखेंगे ध्यान

परियोजना प्रगति : मौजूदा परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी करेंगे और बाधाओं की पहचान कर सुधारात्मक कार्रवाई करेंगे।

गुणवत्ता नियंत्रण: सुनिश्चित करेंगे कि निर्माण आवश्यक मानकों को पूरा करें और घटिया निर्माण होने पर कार्रवाई की जाए।

सुरक्षा अनुपालन : सत्यापित करेंगे कि सुरक्षा प्रोटोकाल का पालन हो, किसी भी चूक के मामले में सुधारात्मक कार्रवाई की जाए।

> पिछली सरकार ने केवल श्रेय लेने के लिए अस्पतालों में अतिरिक्त निर्माण के नाम पर इमारतें बनवाने का काम शुरू किया था, मगर ये भी प्लान नहीं किया कि स्टाफ कहां से आएगा? कैसे ये अस्पताल चल पाएंगे? जनता के पैसे बर्बाद करने की कोशिश की गई, मगर अब हम जनता के इस पैसे को बर्बाद नहीं होने देंगे और जितने भी अस्पताल निर्माणाधीन हैं, उनका काम पूरा किया जाएगा। साथ ही भ्रष्टाचार करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। - प्रवेश वर्मा, लोक निर्माण मंत्री, दिल्ली सरकार

अधिकारी नहीं उठा रहे विधायकों के फोन, न ही दे रहे पत्रों का जवाब

राज्य ब्यूरो, जागरण ● नई दिल्ली

- अध्यक्ष ने मुख्य सचिव को प्रोटोकाल पालन कराने का दिया निर्देश

दिल्ली सरकार के अधीन विभागों के अधिकारी विधायकों के फोन नहीं उठा रहे हैं और न ही उनके पत्रों का जवाब दे रहे हैं। इस पर विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि विधायकों से जुड़े प्रोटोकाल का सख्ती से पालन कराया जाए। विधानसभा अध्यक्ष ने मुख्य सचिव धर्मेंद्र को पत्र लिखा, जिसमें अधिकारियों की ओर से निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ प्रोटोकाल का पालन न करने पर चिंता जताई।

मुख्य सचिव को लिखे पत्र में विधानसभा अध्यक्ष ने कई उदाहरण दिए। जहां विधायकों के पत्र, फोन काल और संदेशों का संबंधित अधिकारियों ने जवाब नहीं दिया। इसे गंभीर मुद्दा बताते हुए उन्होंने सामान्य प्रशासन विभाग और भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से जारी दिशानिर्देश का सख्ती से पालन करने की जरूरत पर बल दिया। विधानसभा अध्यक्ष ने इस मामले में कार्रवाई के लिए भी मुख्य सचिव से अनुरोध किया है। जिससे कि सभी प्रशासनिक सचिव, विभागाध्यक्ष, दिल्ली पुलिस, दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) और अन्य विभागों के अधिकारियों को इन प्रोटोकाल की जानकारी दी जाए। उन्होंने कहा कि निर्वाचित प्रतिनिधियों का सम्मान बने रहना चाहिए और सुशासन के लिए अधिकारियों की जवाबदेही जरूरी है। इसके साथ ही मुख्य सचिव से तुरंत सुधारात्मक कदम उठाने और इस पर की गई कार्रवाई की जल्द जानकारी देने के लिए कहा गया है।

****

465 जीपीएस हस्तक्षेप और स्पूफिंग की घटनाएं नवंबर 2023 और फरवरी 2025 के बीच सीमावर्ती क्षेत्र में ज्यादातर अमृतसर और जम्मू क्षेत्रों में दर्ज की गई हैं। यह जानकारी नागरिक उड्डयन राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोल ने लोकसभा में दी।

परिसीमन के मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा

परिसीमन विरोधी नारे लिखी टी-शर्ट पहनकर आए द्रमुक सदस्य

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

परिसीमन के विरोध में नारे लिखी टी-शर्ट पहनकर सदन में द्रमुक सदस्यों के आने के कारण गुरुवार को संसद में जमकर हंगामा हुआ और कार्यवाही नहीं चली। दोनों सदनों में न तो प्रश्नकाल हुआ और न ही किसी अन्य विषय पर चर्चा हो सकी।

नियमों और परंपराओं का हवाला देकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला द्रमुक सदस्यों से ड्रेस बदलने का आग्रह करते रहे, किंतु किसी पर कोई असर नहीं हुआ और हंगामा जारी रहा तो प्रारंभ के कुछ मिनट के भीतर ही कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। थोड़े-थोड़े अंतराल के बाद स्पीकर ने तीन बार सदन चलाने का प्रयास किया गया, लेकिन कामयाबी नहीं मिली तो कार्यवाही को शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दिया।

बाद में द्रमुक सदस्यों ने संसद परिसर में भी विरोध प्रदर्शन किया। वे प्रस्तावित जनगणना के बाद आबादी के अनुसार परिसीमन का विरोध कर रहे हैं। दलील है कि इससे दक्षिण के राज्यों की सीटें कम हो जाएंगी, क्योंकि वहां जनसंख्या नियंत्रण पर काफी काम हुआ है, जिससे उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण की आबादी कम बढ़ी है। इसी मुद्दे पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने 22 मार्च को चेन्नई में बैठक भी बुलाई है।

नई दिल्ली में बजट सत्र के दौरान संसद परिसर में गुरुवार को 'निष्पक्ष परिसीमन-तमिलनाडु लड़ेगा, तमिलनाडु जीतेगा' लिखी टी-शर्ट पहने द्रमुक सदस्यों ने प्रदर्शन किया। प्रेट्र

टी-शर्ट पर अंग्रेजी में लिखे संदेश का मतलब है, 'निष्पक्ष परिसीमन-तमिलनाडु लड़ेगा, तमिलनाडु जीतेगा।' सदन में कांग्रेस एवं समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने भी द्रमुक को मौन समर्थन दिया। सदन के बाहर अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार पर उन्हें भरोसा नहीं। किसी भी स्तर पर बेईमानी हो सकती है।

राज्यसभा में गृह मंत्रालय एवं उससे संबद्ध विभागों के कामकाज पर विमर्श होना था। अंत में गृह मंत्री अमित शाह को जवाब देना था। लेकिन हंगामे के चलते उसे भी टाल दिया गया।

चर्चा की शुरुआत एक दिन पहले हो चुकी थी। यहां तक कि दोनों पक्षों के कुछ सदस्यों ने अपनी बात भी रखी थी। किंतु गुरुवार को जब जवाब की बारी आई तो टी-शर्ट का मुद्दा गर्म हो गया। सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन में सभी पार्टियों के नेताओं से चर्चा कर सदन चलाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी सदन नहीं चल सका।

पीएम मोदी की जून 2023 में हुई अमेरिकी यात्रा पर करीब 23 करोड़ खर्च हुए

नई दिल्ली, प्रेट्र: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की जून 2023 में हुई अमेरिका यात्रा पर करीब 23 करोड़ रुपये खर्च हुए थे। विदेश राज्यमंत्री पबित्र मार्गेरिटा ने राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे की ओर से पूछे गए एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी। खरगे ने सरकार से पूछा था कि पिछले तीन वर्षों में प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं की व्यवस्था पर भारतीय दूतावासों द्वारा कुल कितना खर्च किया गया है। उन्होंने होटल व्यवस्था, सामुदायिक स्वागत, परिवहन व्यवस्था और अन्य विविध व्यय जैसे प्रमुख मदों के अंतर्गत किए गए यात्रा-वार व्यय का विवरण भी मांगा।

इसके जवाब में मार्गेरिटा ने प्रधानमंत्री द्वारा 2022, 2023 और 2024 में किए गए विदेश यात्राओं पर देश-वार खर्च के आंकड़ों को साझा किया। आंकड़ों के अनुसार, जून 2023 में प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा पर 22.89 करोड़ रुपये का खर्च हुआ था, जबकि सितंबर 2024 में इसी देश की यात्रा पर 15.33 करोड़ रुपये खर्च हुए थे। ये आंकड़े मई 2022 में जर्मनी की यात्रा से लेकर दिसंबर 2024 में कुवैत यात्रा तक 38 से अधिक यात्राओं से संबंधित थे। मई 2023 में प्रधानमंत्री की जापान यात्रा से संबंधित आंकड़ों के अनुसार उस पर 17.19 करोड़ रुपये खर्च हुए थे, जबकि मई 2022 में नेपाल यात्रा पर 80 लाख रुपये खर्च हुए थे। मंत्री ने अपने जवाब में 2014 से पहले के वर्षों के कुछ आंकड़े भी साझा किए।

आनलाइन पोर्नोग्राफी को लेकर सरकार सख्त, 24 घंटे में प्लेटफार्म से हटाना होगा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- इलेक्ट्रानिक्स एवं आइटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद को दी जानकारी
- आइटी एक्ट में इलेक्ट्रानिक रूप से अश्लील सामग्री दिखाने पर किया गया है सजा का प्रविधान

इलेक्ट्रानिक्स एवं आइटी मंत्रालय का कहना है कि नए आइटी नियमों के तहत आनलाइन पोर्नोग्राफी एवं हानिकारक सामग्री को शीघ्रता से हटाना अनिवार्य है। इलेक्ट्रानिक्स एवं आइटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद को बताया कि नए आइटी नियम के तहत इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म को 24 घंटे के भीतर किसी भी ऐसे सामग्री को हटाना होगा, जो पहली दृष्टि में किसी व्यक्ति के निजी हिस्से को दर्शाती है। किसी व्यक्ति को पूरी तरह से या आंशिक रूप से नग्न दिखाने या यौन क्रिया दिखाने वाली सामग्री को भी हटाना होगा। शिकायतकर्ता अपनी शिकायत पर इंटरनेट मीडिया कंपनी के शिकायत अधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई से संतुष्ट नहीं होने पर अपील कमेटी में भी जा सकता है।

आइटी एक्ट 2000 में इलेक्ट्रानिक रूप से अश्लील सामग्री दिखाने पर सजा का प्रविधान किया गया है। एक्ट के तहत इंटरनेट मीडिया कंपनी अपने प्लेटफार्म पर अश्लील सामग्री को रोकने में असमर्थ पाई जाती है तो उन्हें मिलने वाली छूट समाप्त हो जाएगी। अगर कोई प्लेटफार्म मैसेजिंग की सेवा प्रदान करता है तो मूल मैसेज का सृजन कहां से हुआ, इसका पता लगाने में उसको सक्षम होना चाहिए, ताकि दुष्कर्म, यौन उत्पीड़न या यौन चित्रण से जुड़े मैसेज के सृजनकर्ता का पता आसानी से चल सके।

अश्विनी वैष्णव। फाइल/एएनआइ

मंत्रालय के मुताबिक आइटी नियम के तहत ओटीटी प्लेटफार्म या क्यूरेटेड आनलाइन प्रकाशकों के लिए आचार संहिता तय किए गए हैं। इस संहिता के अंतर्गत ओटीटी प्लेटफार्म को निर्दिष्ट उम्र और उपयुक्त श्रेणी में सामग्री को वर्गीकृत करने के साथ अनुचित सामग्री तक बच्चों की पहुंच को प्रतिबंधित करना आवश्यक है।

बता दें कि इंटरनेट मीडिया पर पोर्न कंटेंट की आसान उपलब्धता के खिलाफ शिकायतें मिलती रहती हैं।

अब तक अमेरिका से 588 पुरावशेष भारत वापस लाए गए

नई दिल्ली, प्रेट्र: : सरकार ने संसद को बताया कि अब तक अमेरिका से 588 पुरावशेष भारत वापस लाए जा चुके हैं, जिनमें से 297 2024 में प्राप्त हुए। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारतीय पुरावशेषों की तस्करी को रोकने के लिए अमेरिका के साथ सांस्कृतिक संपदा समझौते (सीपीए) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। समझौता निवारक प्रकृति का है, इसलिए इसमें कोई समयसीमा या लक्ष्य संख्या नहीं है।

2018 से नियुक्त 715 हाई कोर्ट जजों में से 22 अनुसूचित जाति के : 2018 से नियुक्त 715 हाई कोर्ट के जजों में से 22 अनुसूचित जाति के और 16 अनुसूचित जनजाति के हैं, 89 ओबीसी श्रेणी के हैं और 37 अल्पसंख्यक हैं। राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट और 25 हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्तियां संविधान के प्रविधानों के तहत की जाती हैं, जिसमें किसी भी जाति या वर्ग के व्यक्तियों के लिए आरक्षण का प्रविधान नहीं है।

'पाकिस्तान में हिंदुओं सहित अन्य अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार'

नई दिल्ली, प्रेट्र: सरकार ने गुरुवार को संसद में कहा कि पाकिस्तान में हिंदुओं सहित विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ अत्याचार के मामले बढ़े हैं। विदेश राज्यमंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

कीर्तिवर्धन सिंह। एएनआइ

विदेश मंत्रालय से पूछा गया था कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पड़ोसी देश पाकिस्तान में हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसा और भेदभाव के कारण अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय सिंध प्रांत से लगातार पलायन कर रहा है। जवाब में मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ अत्याचार की खबरें आई हैं, जिनमें हिंदू समुदाय के सदस्य भी शामिल हैं। धमकी, अपहरण, उत्पीड़न, जबरन धर्मांतरण और जबरन विवाह जैसी घटनाएं समय-समय पर सामने आई हैं, जो उन्हें पलायन करने के लिए मजबूर करती हैं। एक अन्य प्रश्न के लिखित जवाब में कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय तेल खरीद पर भारत का फैसला विभिन्न कारकों पर आधारित है, जिसमें देश के राष्ट्रीय हित सबसे ऊपर हैं।

राज्यसभा में विदेश मंत्रालय से पूछा गया कि क्या यह सच है कि अमेरिका ने भारत को रूस से तेल नहीं लेने के लिए कहा है और इसके लिए समयसीमा तय की है।

यूएई में 25, सऊदी अरब में 11 भारतीयों को मौत की सजा

नई दिल्ली, आइएएनएस : सरकार ने गुरुवार को संसद को बताया कि संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में 25 और सऊदी अरब में 11 भारतीय नागरिकों को मौत की सजा सुनाई गई है, लेकिन फैसले पर अभी तक अमल नहीं किया गया है। इसके अलावा मलेशिया में छह, कुवैत में तीन और इंडोनेशिया, कतर, अमेरिका तथा यमन में एक-एक भारतीय नागरिक को मौत की सजा सुनाई गई है।

कीर्ति वर्धन सिंह ने राज्यसभा में एक प्रश्न का लिखित उत्तर देते हुए कहा कि विदेश मंत्रालय के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, वर्तमान में विदेशी जेलों में विचाराधीन कैदियों सहित भारतीय कैदियों की संख्या 10,152 है।

प्रेट्र के अनुसार, मंत्री ने बताया कि विदेश स्थित भारतीय मिशन उन भारतीय नागरिकों को हरसंभव सहायता प्रदान करते हैं, जिन्हें विदेशी अदालतों द्वारा मृत्युदंड सहित अन्य सजा सुनाई जाती है।

विशेष दर्जा के साथ बिहार ने मांगा करों में 50 प्रतिशत हिस्सा

राज्य ब्यूरो, जागरण • पटना : विशेष राज्य के दर्जा के साथ बिहार ने 16वें वित्त आयोग से केंद्रीय करों में 50 प्रतिशत की हिस्सेदारी मांगी है। इसके साथ ही करों के बंटवारे में बहुआयामी गरीबी सूचकांक को भी एक मानक बनाने का आग्रह किया है। गुरुवार को आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया ने बताया कि विशेष दर्जा वित्त आयोग के अधिकार क्षेत्र का विषय नहीं। वैसे भी योजना आयोग के दौरान ही ऐसी व्यवस्था का समापन हो चुका है।

उल्लेखनीय है कि 15वें वित्त आयोग ने कर हस्तांतरण की सीमा 41 प्रतिशत निर्धारित कर रखी है, जिसकी समय-सीमा वित्तीय वर्ष 2025-26 के साथ समाप्त हो जानी है। उसके बाद अगले पांच वित्तीय वर्ष के लिए 16वें वित्त आयोग की अनुशंसाएं प्रभावी होंगी। पनगढ़िया के नेतृत्व में 12 सदस्यीय टीम कर बंटवारे के संदर्भ में बिहार की अपेक्षाओं और सुझावों से अवगत होने के लिए तीन दिवसीय दौरे पर बुधवार रात पटना पहुंची थी।

डीएसी ने दी 54 हजार करोड़ रुपये के सैन्य उपकरणों की खरीद की मंजूरी

नई दिल्ली, प्रेट्र: भारत सरकार ने गुरुवार को 54 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा कीमत के तमाम सैन्य उपकरणों की खरीद प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की स्वीकृति दे दी। तीनों सेनाओं की ताकत को मजबूती देने के लिए इनमें समयपूर्व हवाई हमले की चेतावनी और नियंत्रण (एईडब्ल्यूएंडसी) की अत्याधुनिक विमान प्रणाली, स्वदेशी वरुणास्त्र टारपीडो और टी-90 टैंक के ज्यादा ताकतवर इंजन समेत कई साजो-सामान शामिल हैं।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली रक्षा खरीद परिषद (डीएसी) ने इन खरीद प्रस्तावों को स्वीकृति दी। रक्षा मंत्रालय के अनुसार, डीएसी ने पूंजी अधिग्रहण प्रक्रिया यानी खरीदारी के विभिन्न चरणों की समयसीमा को कम करने के दिशानिर्देशों को भी स्वीकृति दी है, जिससे यह प्रक्रिया ज्यादा तेज, असरदार और कुशल हो जाए। खरीदारी प्रक्रिया को ज्यादा असरदार बनाने का निर्णय '2025 को सुधारों के वर्ष' के रूप में मनाने की रक्षा मंत्रालय की पहल के अनुरूप है।

- रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली रक्षा खरीद परिषद का निर्णय
- तीनों सेनाओं को मजबूती देने के लिए कई हथियारों की खरीदारी

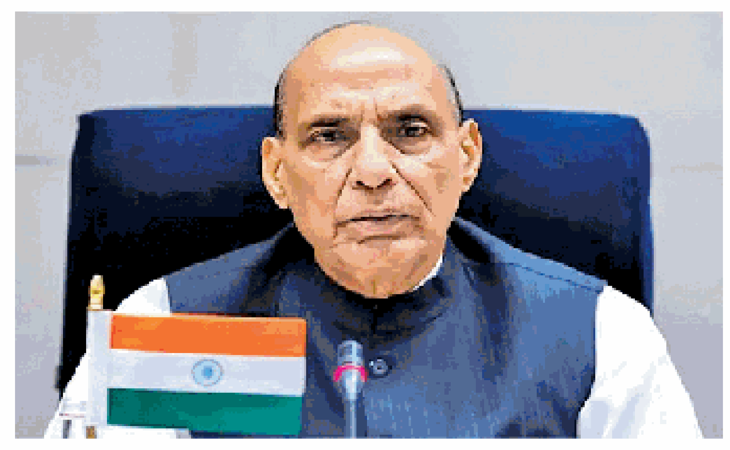

राजनाथ सिंह। फाइल

मंत्रालय ने बताया कि एईडब्ल्यूएंडसी विमान प्रणाली से वायुसेना की ताकत में इजाफा होगा। इससे लड़ाई के पूरे तरीके बदल सकते हैं और विभिन्न हथियारों वाली प्रणालियों से लड़ाई में ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। जबकि सेना में टी-90 टैंक के लिए मौजूदा 1,000 एचपी के इंजन की जगह 1,350 एचपी इंजन का अपग्रेड, विशेष रूप से ऊंचाई वाले इलाकों में वजन की तुलना में ताकत का अनुपात बढ़ाने से युद्ध के मैदान में इन टैंकों की रफ्तार बढ़ाएगा।

मंत्रालय के अनुसार, भारतीय नौसेना के लिए जहाज से छोड़ी जा सकने वाली पनडुब्बी-रोधी टारपीडो वरुणास्त्र काफी महत्वपूर्ण साबित होगी। स्वदेश में बनी इस टारपीडो की ज्यादा संख्या पनडुब्बियों के खतरे से नौसेना को मजबूत बनाएगी।

गुजरात हाई कोर्ट में आठ जजों की नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम की मंजूरी

नई दिल्ली, प्रेट्र: प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम ने आठ न्यायिक अधिकारियों को गुजरात हाई कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किए गए एक बयान में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने गुजरात हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के रूप में लियाकाथुसैन शम्सुद्दीन पीरजादा, रामचंद्र ठाकुरदास वच्छानी, जयेश लखंशीभाई ओडेद्रा, प्रणव महेशभाई रावल, मूल चंद त्यागी, दीपक मनसुखलाल व्यास, उत्कर्ष ठाकोरभाई देसाई और रोहनकुमार कुंदनलाल चुडावल की नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

एक अलग बयान में कहा गया कि कोलेजियम ने अतिरिक्त न्यायाधीशों जस्टिस सुमित गोयल, जस्टिस सुदीप्ति शर्मा और जस्टिस कीर्ति सिंह को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

मतदाता सूची को अपडेट करने की प्रक्रिया मजबूत की जाएगी : आयोग

नई दिल्ली, प्रेट्र : मतदाता सूचियों की शुद्धता पर जारी बहस के बीच चुनाव आयोग ने गुरुवार को कहा कि मतदाता सूची को नियमित रूप से अपडेट करने की प्रक्रिया को जन्म-मृत्यु पंजीकरण अधिकारियों के साथ करीबी समन्वय से मजबूत बनाया जाएगा। आयोग ने एक बयान में कहा कि मतदाता सूची और आधार को जोड़ने पर यूआइडीएआइ और आयोग के विशेषज्ञों के बीच तकनीकी चर्चा जल्द शुरू होगी। साथ ही कहा, चूंकि एक मतदाता सिर्फ निर्धारित मतदान केंद्र पर ही मतदान कर सकता है, अन्य कहीं नहीं, आयोग ने देशभर में डुप्लीकेट नाम हटाने और इस दशकभर पुराने मुद्दे को तीन महीने में खत्म करने का संकल्प लिया है।

राजनीतिक दलों के साथ चुनाव आयोग की चर्चाओं में यह स्पष्ट किया गया कि मसौदा मतदाता सूची में नाम शामिल करने या हटाने का काम जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 में सभी राजनीतिक दलों के लिए उपलब्ध दावे व आपत्तियां दाखिल करने के लिए प्रासंगिक कानूनी प्रविधानों के तहत अपील प्रक्रिया द्वारा नियंत्रित होगा। ऐसी अपीलें नहीं होने पर निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) द्वारा तैयार सूची ही मान्य होगी। चुनाव आयोग ने स्मरण कराया कि जनवरी में स्पेशल समरी रिवीजन एक्सरसाइज पूरी होने के बाद सिर्फ 89 फर्स्ट अपील और सिर्फ एक सेकेंड अपील दायर की गई थी। आयोग ने यह भी कहा कि उसने चुनाव प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए साहसिक कदम उठाए हैं। निचले स्तर पर मुद्दों का समाधान करने के लिए लगभग 5,000 चुनाव अधिकारी 31 मार्च तक राजनीतिक दलों के साथ नियमित बैठकें करेंगे। इन अधिकारियों में राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी और निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी शामिल हैं।

- कहा, जन्म-मृत्यु पंजीकरण अधिकारियों के साथ किया जाएगा करीबी समन्वय
- मतदाता सूची को आधार को जोड़ने पर जल्द शुरू होगी तकनीकी चर्चा

लोकपाल जांच निदेशक व अभियोजन निदेशक की नियुक्ति करेगा

सरकार ने संसद में बताया कि जांच निदेशक और अभियोजन निदेशक के दो प्रमुख पदों को लोकपाल द्वारा भरा जाना अभी बाकी है। राज्यसभा में एक लिखित प्रश्न के जवाब में केंद्रीय कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत जांच निदेशक और अभियोजन निदेशक की नियुक्ति, लोकपाल द्वारा की जानी होती है। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में जितेन्द्र सिंह ने कहा कि सीबीआइ ने इंटरपोल अलर्ट के आधार पर मादक पदार्थ ले जाने के संदेह में पिछले वर्ष विशाखापत्तनम बंदरगाह पर एक शिपिंग कंटेनर को रोका था, जिसमें सूखा खमीर पाया गया था। इसके साथ ही एक और प्रश्न के जबाब में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने आनलाइन प्रणाली सीपीजीआरएएमएस पर एक महीने में एक व्यक्ति द्वारा दर्ज की जाने वाली शिकायतों की संख्या सीमित कर दी है, ताकि बार-बार होने वाली शिकायतों पर लगाम लगाई जा सके। केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) नागरिकों को ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने की सुविधा देती है।

जितेंद्र सिंह। एएनआइ

सरकारी कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित पेंशन संबंधी अधिसूचना हुई जारी

नई दिल्ली, प्रेट्र: पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने गुरुवार को एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को अमल में लाने वाली अधिसूचना जारी कर दी। योजना के तहत सेवानिवृत्ति से पहले के 12 महीनों में मिले औसत मूल वेतन की 50 प्रतिशत राशि को सुनिश्चित पेंशन के तौर पर देने का प्रविधान है। यह अधिसूचना राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत आने वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार द्वारा 24 जनवरी, 2025 को जारी यूपीएस अधिसूचना का अनुसरण करती है। पीएफआरडीए ने बयान में कहा कि यूपीएस से संबंधित नियम एक अप्रैल, 2025 से लागू हो जाएंगे।

ये नियम एक अप्रैल, 2025 तक सेवा में मौजूदा केंद्र सरकार के एनपीएस में आने वाले कर्मचारी और केंद्र सरकार की सेवाओं में अप्रैल, 2025 को या उसके बाद भर्ती होने वाले कर्मचारियों समेत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के नामांकन को सक्षम करते हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों की इन सभी श्रेणियों के लिए नामांकन और दावा फार्म एक अप्रैल, 2025 से आनलाइन उपलब्ध होंगे। फार्म भौतिक रूप से जमा करने का भी विकल्प है। कर्मचारी को सेवा से हटाए जाने या बर्खास्त किए जाने या इस्तीफे के मामले में यूपीएस या सुनिश्चित भुगतान विकल्प उपलब्ध नहीं होगा।

- यूपीएस से संबंधित नियम एक अप्रैल, 2025 से होंगे लागू, पिछले साल 24 अगस्त को सरकार ने दी थी इस पेंशन योजना को मंजूरी

प्रतीकात्मक

यूपीएस और एनपीएस चुनने का मिलेगा विकल्प

अधिसूचना से 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को यूपीएस और एनपीएस के बीच चयन करने का विकल्प मिलेगा। एनपीएस एक जनवरी, 2004 को लागू हुआ था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 अगस्त, 2024 को यूपीएस लाने को मंजूरी दी थी। जनवरी, 2004 से पहले प्रभावी पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) के तहत कर्मचारियों को उनके कार्यकाल के अंतिम मूल वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में मिलता था। ओपीएस के उलट यूपीएस अंशदायी प्रकृति की है। इसमें कर्मचारियों को अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत योगदान करना होगा, जबकि नियोक्ता (केंद्र सरकार) का योगदान 18.5 प्रतिशत होगा।

कूटनीति

थाईलैंड में तीन-चार अप्रैल को बिम्सटेक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे दोनों नेता, दोनों के बीच हो सकती है अनौपचारिक मुलाकात, आधिकारिक की संभावना नहीं

मोदी-यूनुस 'मुलाकात' पर भारत ने नहीं दिखाया उत्साह

जयप्रकाश रंजन • जागरण

नई दिल्ली: बांग्लादेश की तरफ से एक बार फिर इच्छा व्यक्त की गई है कि अगले महीने वहां की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस के साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मुलाकात हो जाए, लेकिन भारत की तरफ से इस बारे में कोई उत्साह नहीं दिखाया गया है। दोनों नेता तीन-चार अप्रैल, 2025 को थाईलैंड में बिम्सटेक (बे आफ बंगाल इनीशिएटिव फार मल्टी सेक्टोरल टेक्नीकल एंड इकोनमिक कोआपरेशन) के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। जानकारों का कहना है कि भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया के साथ प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात को लेकर कोई संकेत नहीं दिया है। बैठक के दौरान दोनों नेताओं के बीच अनौपचारिक मुलाकात हो सकती है, लेकिन आधिकारिक मुलाकात की संभावना नहीं है। बांग्लादेश सरकार ने पूर्व में भी मोदी और यूनुस की मुलाकात की इच्छा जताई थी, लेकिन भारत ने उसे तवज्जो नहीं दी थी।

- शीर्ष नेताओं की औपचारिक मुलाकात के लिए बेहतर अवसर का इंतजार करेगा भारत

मोहम्मद यूनुस। फाइल

नरेन्द्र मोदी। फाइल

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में विदेश मामलों के सलाहकार (विदेश मंत्री के समकक्ष) मोहम्मद तौहीद होसैन ने एक समाचार एजेंसी एएनआइ से बातचीत में कहा कि उनकी सरकार की तरफ से भारत को यह राजनयिक संदेश भेजा गया है कि बिम्सटेक सम्मेलन से इतर दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय मुलाकात हो। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि बिम्सटेक सम्मेलन से पहले मोहम्मद यूनुस 26 मार्च को बीजिंग की यात्रा पर जा रहे हैं। 28 मार्च को उनकी राष्ट्रपति शी चिनफिंग के साथ मुलाकात संभव है। भारत की इस मुलाकात पर भी नजर होगी। चीन की तरफ से बांग्लादेश में नए निवेश की घोषणा किए जाने की संभावना है। भारत सिर्फ इस बात से चिंतित नहीं है कि मोहम्मद यूनुस की सरकार का रवैया पूरी तरह से भारत विरोधी है, बल्कि बांग्लादेश में जिस तरह से चीन व पाकिस्तान की सक्रियता बढ़ी है, वह ज्यादा चिंताजनक है।

सूत्रों का कहना है, 'भारत ने बांग्लादेश के साथ संवाद की निरंतरता को बनाकर रखा है। लेकिन भारत सरकार शीर्ष नेताओं के बीच मुलाकात को लेकर आगे बढ़ने से पहले कुछ और इंतजार करना चाहती है।

हसीना सरकार के हटने के बाद से दोनों देशों में तनाव

अगस्त, 2024 में लोकतांत्रिक तरीके से गठित तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से बेदखल करने के बाद भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में काफी तनाव आ चुका है। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले को लेकर भारत लगातार चिंता जताता रहा है। बांग्लादेश इसे अपने आंतरिक मामलों में दखल बता रहा है। यूनुस सरकार भारत में शरणार्थी के तौर पर रह रहीं पूर्व प्रधानमंत्री हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर रही है। दूसरी तरफ, यूनुस सरकार पाकिस्तान के साथ रिश्तों को सुधारने में जुटी हुई है। सार्क संगठन को नए सिरे से आगे बढ़ाने की बात भी बांग्लादेश कर रहा है जो पाकिस्तान चाहता है। हालांकि भारत ने इसे खारिज कर दिया है। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच सैन्य सहयोग बढ़ाने के लिए वार्ता का दौर भी शुरू हो चुका है।

****

कह कर रहेंगे

माधव जोशी

1.5 लाख रुपये प्रति माह करने का प्रस्ताव है कर्नाटक में मुख्यमंत्री का वेतन। वहीं मंत्री का वेतन 1,25,000 रुपये प्रति माह और विधायकों और एमएलसी का वेतन हजार प्रति माह करने का प्रस्ताव है।

दमखम से राज्यों के चुनावी मैदान में उतरने की कसरत में जुटी कांग्रेस

दिल्ली चुनाव के बाद बीते एक महीने में हाईकमान ने चुनावी राज्यों संग की आधा दर्जन बैठकें

संजय मिश्र • जागरण

नई दिल्ली: अपने संगठनात्मक ढांचे को दुरुस्त करने की पहल के बाद कांग्रेस ने सियासत बदलने के भरोसे और तेवरों के साथ दमखम से राज्यों के चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी हाईकमान ने चुनावी राज्यों के कांग्रेस नेताओं के साथ चुनाव की तैयारियों और रणनीति पर मंत्रणाओं का सिलसिला शुरू कर दिया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद बीते एक महीने में पंजाब, केरल, बंगाल और मणिपुर जैसे राज्यों के पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर शीर्ष नेतृत्व ने चुनावी चर्चा की है। इन चर्चाओं में कांग्रेस नेतृत्व ने राज्य इकाइयों को स्पष्ट संदेश दिया है कि पार्टी अपने चुनावी हितों से किसी तरह का समझौता नहीं करेगी। बिहार कांग्रेस के नए अध्यक्ष राजेश कुमार की नियुक्ति के बाद बिहार के नेताओं की भी हाईकमान के साथ जल्द बैठक बुलाए जाने के संकेत हैं।

राज्यों के चुनाव में पार्टी की सियासी जमीन मजबूत करने को लेकर कांग्रेस नेतृत्व की इस रणनीति का संकेत बुधवार को बंगाल के नेताओं के साथ हुई बैठक से मिलता है। सूत्रों के अनुसार पार्टी हाईकमान ने राज्य के कांग्रेस नेताओं को ममता बनर्जी सरकार की खामियों-नीतियों के खिलाफ निडर और मुखर होकर आलोचना करने की हरी झंडी दी है। तृणमूल कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी गठबंधन आइएनडीआइए का हिस्सा है, और ऐसे में बंगाल के नेताओं ने ममता सरकार पर प्रहार करने की अपनी दुविधाओं का मुद्दा बैठक में उठाया। इस पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा मुख्य प्रतिद्वंदी है, मगर बंगाल में टीएमसी की सरकार है और राज्य इकाई को उसकी गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी खरगे की राय का समर्थन किया। बंगाल कांग्रेस के नेताओं को यह स्पष्ट कर दिया गया कि संसद में आपसी सहयोग-समन्वय का मसला राज्य के चुनाव से बिल्कुल अलग है। आइएनडीआइए गठबंधन राज्यों के चुनाव के लिए नहीं है।

हरियाणा और महाराष्ट्र में हार के बाद राज्यों के चुनाव को लेकर कांग्रेस के दृष्टिकोण में बदलाव के संकेत नजर आने लगे हैं। दिल्ली चुनाव में पहली झलक दिखी जब कांग्रेस ने विपक्षी खेमे के तमाम दबावों को नकारते हुए आम आदमी पार्टी के खिलाफ मजबूती से चुनाव लड़ा। चाहे सीट एक भी नहीं मिली, मगर पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ा और 14 सीटों पर आप की हार में कांग्रेस को मिले वोट निर्णायक रहे। बंगाल में टीएमसी पर पार्टी के इस रुख का संकेत साफ है कि कांग्रेस अगले साल वहां होने वाले विधानसभा चुनाव को केवल टीएमसी बनाम भाजपा का मुकाबला नहीं बनने देना चाहती।

केरल में भी अगले साल ही चुनाव हैं, जहां कांग्रेस सत्ता की दावेदारी में है, मगर प्रदेश नेताओं की गुटबाजी हाईकमान के लिए चुनौती है। खरगे और राहुल गांधी ने बीते 28 फरवरी को केरल के तमाम वरिष्ठ नेताओं, जिसमें शशि थरूर भी शामिल थे, की बैठक बुलाकर गुटबाजी खत्म कर चुनावी तैयारी में कूदने का निर्देश दिया था। मणिपुर के वरिष्ठ नेता पूर्व सीएम इबोबी सिंह और प्रदेश के नए पार्टी प्रभारी सप्तगिरि उलाका ने भी दो हफ्ते पहले एआइसीसी में आकर चुनाव के लिए कमर कस कर तैयारी करने का भरोसा दिया था।

▸ **बंगाल कांग्रेस के नेताओं को ममता सरकार पर निशाना साधने की खरगे-राहुल ने दी हरी झंडी**

मल्लिकार्जुन खरगे। फाइल

आप की दिल्ली में हार को पंजाब में कांग्रेस बड़ा मौका मान रही

आम आदमी पार्टी की दिल्ली की हार के बाद कांग्रेस पंजाब के अगले चुनाव में बड़ा मौका देख रही है। पिछले तीन हफ्ते के दौरान सूबे के नेताओं संग पंजाब के नए प्रभारी महासचिव और छग के पूर्व सीएम भूपेश बघेल की दो दौर की बैठकें हो चुकी हैं। पिछले हफ्ते कांग्रेस के नए मुख्यालय में पंजाब कांग्रेस नेताओं की बैठक में चुनावी तैयारियों की शुरुआती रणनीति पर लंबी चर्चा हुई।

एलआइसी ने राहुल के दावों को किया खारिज, कहा-हम प्रतिबद्ध

नई दिल्ली, प्रेट्र: भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआइसी) ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के दावों को खारिज करते हुए कहा कि वह अपने पालिसीधारकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने और अपने सभी एजेंटों की भलाई के लिए प्रतिबद्ध है। इससे पहले बुधवार को एलआइसी एजेंटों के एक प्रतिनिधिमंडल ने राहुल से मुलाकात की थी। एलआइसी प्रबंधन की ओर से पिछले कुछ समय में नियमों में किए गए बदलावों को इस बीमा कंपनी के लिए चिंताजनक और खतरनाक बताते हुए राहुल ने कहा कि आम लोगों के हितों का संरक्षण करने के लिए एलआइसी को सुदृढ़ करना जरूरी है।

एलआइसी के सीईओ एवं प्रबंध निदेशक सिद्धार्थ मोहंती ने गुरुवार को एक बयान में कहा, 'हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि एलआइसी ने ऐसे उत्पाद पेश किए हैं, जो इरडा द्वारा निर्धारित नए उत्पाद विनियमों के अनुरूप हैं। इसमें पालिसीधारकों के हितों को सर्वोपरि रखा गया है। ये बदलाव एक अक्टूबर, 2024 से प्रभावी हुए हैं।' एलआइसी ने लगातार ग्रामीण क्षेत्रों और आर्थिक व सामाजिक रूप से वंचित वर्गों तक पहुंचने पर ध्यान केंद्रित किया है, क्योंकि वह जीवन बीमा के दायरे को व्यापक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

ओबीसी की हिस्सेदारी की लड़ाई जारी रहेगी: राहुल: राहुल गांधी ने गुरुवार को पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों के एक संगठन के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और कहा कि वह अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) की हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ते रहेंगे। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग कर्मचारी कल्याण महासंघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने राहुल से संसद भवन परिसर में उनसे मुलाकात की। इसके बाद राहुल ने अपने वाट्सएप चैनल पर एक पोस्ट में कहा, 'ओबीसी वर्ग भारत में सबसे बड़ी आबादी है, जिनका हर क्षेत्र में बड़ा योगदान है। उनकी समृद्धि और हिस्सेदारी की लड़ाई पूरी ताकत के साथ लड़ता रहूंगा।'

▸ **कहा, पालिसीधारकों और एजेंटों के प्रति प्रतिबद्ध, राहुल ने नियमों में बदलाव को लेकर जताई थी चिंता**

▸ **बुधवार को एलआइसी एजेंटों के एक प्रतिनिधिमंडल ने राहुल से मुलाकात की थी**

राहुल गांधी। फाइल

जम्मू-कश्मीर में आप विधायक ने हिंदुओं को शराब का आदी बताया

राज्य ब्यूरो, जागरण, जम्मू : जम्मू-कश्मीर विधानसभा में गुरुवार को आम आदमी पार्टी के विधायक मेहराज मलिक के शराब को लेकर हिंदुओं पर आपत्तिजनक बयान से हंगामा हो गया। मलिक ने यह कहकर विवाद पैदा कर दिया कि जम्मू में भाजपा शराब को शह दे रही है। जम्मू में हिंदू शराब पीता है व हिंदू ही शराब पिला रहा है। उन्होंने उपराज्यपाल पर भी गंभीर आरोप लगाए। इसका भाजपा विधायकों ने उन पर कार्रवाई की मांग की। कहा कि ये बयान लोगों का ध्यान बांटने के लिए दंगे कराने का प्रयास हो सकते हैं। बता दें कि प्रदेश में आप नेकां सरकार को समर्थन दे रही है। वहीं, युवा राजपूत सभा ने आप विधायक के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।

विधानसभा में गुरुवार को उपराज्यपाल के विभागों के अनुदान पर चर्चा चल रही थी। मेहराज ने कहा कि जम्मू में तीन वर्षों में शराब की दुकानें 200 से 300 हो गईं। करोड़ों रुपये में शराब की दुकानें बेची जा रही हैं। उन्होंने उपराज्यपाल के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए कहा कि उन्होंने (उपराज्यपाल) शराब को बढ़ावा दिया। उन्होंने उपराज्यपाल को माफिया भी कहा। भाजपा विधायकों की ओर देखते हुए उन्होंने कहा कि आप शराब की दुकानों को बंद नहीं करेंगे।

उपराज्यपाल और हिंदुओं को लेकर आपत्तिजनक बयान पर भाजपा विधायकों ने प्रदर्शन किया, बलवंत सिंह मनकोटिया ने तो अपना माइक उठाकर सदन में फेंक दिया।

झारखंड में परिसीमन के मुकाबले घुसपैठ के मुद्दे को धार देगी भाजपा

राज्य ब्यूरो, जागरण, रांची: झारखंड में विधानसभा और लोकसभा सीटों के परिसीमन की चर्चा विधानसभा से प्रारंभ होकर सड़क तक पहुंच चुकी है। झामुमो-कांग्रेस गठबंधन केंद्र सरकार में बैठी भाजपा पर आरोप लगा रहा है कि इससे राज्य में आदिवासी सुरक्षित सीटों की संख्या कम हो जाएगी। आदिवासी मतों के लिए भाजपा की लगातार कोशिशों को झामुमो-कांग्रेस गठबंधन सामाजिक-सांस्कृतिक मुद्दे उठाकर बेअसर करता रहा है।

सीएनटी, सरना कोड जैसे मुद्दे पर विरोधी दल भाजपा को आदिवासियों के खिलाफ बताते रहे हैं। अब परिसीमन का नया विवाद खड़ा हो गया है, जिससे भाजपा को आदिवासियों का विरोधी बताया जा रहा है, लेकिन इस बार प्रदेश से लेकर केंद्र तक का भाजपा नेतृत्व सक्रिय है। विधानसभा में प्रदेश अध्यक्ष सह नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य में आदिवासियों की संख्या घट रही है। बांग्लादेशी घुसपैठिए आदिवासियों की संस्कृति पर हमला कर रहे हैं।

कर्नाटक में 100% बढ़ेगा सीएम, मंत्रियों और विधायकों का वेतन

बेंगलुरु, एएनआइ : कर्नाटक की आर्थिक हालत खराब है। सरकार चलाने के लिए फंड जुटाने में मुश्किल आ रही है। बिजली उपभोक्ताओं पर बोझ डाला जा रहा है वहीं कर्नाटक सरकार ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों का वेतन 100 प्रतिशत बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। सरकार ने इससे संबंधित दो संशोधन विधेयकों को मंजूरी दे दी है। बताया जा रहा है कि विधेयकों में मुख्यमंत्री का वेतन 1,50,000 रुपये प्रति माह, मंत्री का वेतन 1,25,000 रुपये प्रति माह और विधायकों और एमएलसी का वेतन हजार रुपये प्रति माह करने का प्रस्ताव है।

गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने बढ़ते खर्चों का हवाला देते हुए बढ़ोतरी को उचित ठहराया। मंत्री एमबी पाटिल ने भी प्रस्ताव का बचाव करते हुए कहा कि विधायकों के वेतन और भत्ते बढ़ाने में कुछ भी गलत नहीं है। स्वतंत्र समिति की सिफारिश पर यह निर्णय लिया गया है।

बिजली उपभोक्ताओं को झटका, चुकाना होगा अधिक शुल्क : कर्नाटक में बिजली उपभोक्ताओं को अधिक बिजली बिल चुकाना होगा। कर्नाटक विद्युत विनियामक आयोग (केईआरसी) ने बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी कर उपभोक्ताओं को झटका दिया है। एक अप्रैल से बिजली पर प्रति यूनिट 36 पैसे अतिरिक्त अधिभार या सरचार्ज के रूप में देना होगा। यह कदम केईआरसी द्वारा बिजली आपूर्ति कंपनियों (ईएससीओएम) को पेंशन और ग्रेच्युटी (पीएंडजी) योगदान में सरकार का हिस्सा उपभोक्ताओं से वसूलने की अनुमति देने के बाद उठाया गया है। भाजपा ने इस फैसले जनविरोधी करार देते हुए विरोध किया है। सरचार्ज एक अप्रैल 2025 से वित्त वर्ष 2027-28 तक लागू रहेगा।

राज्य भाजपा अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र ने कहा कि जब से कर्नाटक में ''जनविरोधी'' कांग्रेस सरकार सत्ता में आई है, उसने जो एकमात्र गारंटी लागू की है वह ''महंगाई'' है।

▸ **सरकार ने इससे संबंधित दो संशोधन विधेयकों को दी मंजूरी, गृह मंत्री जी. ने वेतन बढ़ोतरी को ठहराया उचित**

'मोबाइल पर रोक नहीं लगी तो 10 साल में समाप्त होगी धरती'

राज्य ब्यूरो, जागरण • पटना

बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के दौरान गुरुवार को विधानसभा में राजद के विधायक कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव को मोबाइल पर प्रश्न पढ़ते देख मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नाराज हो गए। अपनी सीट पर खड़े होकर उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव से आग्रह किया कि सदन में मोबाइल को प्रतिबंधित कीजिए। पहले लोग इसे लेकर नहीं आते थे। परामर्श दिया कि जो मोबाइल लेकर आए उसे बाहर निकाल दिया जाए। नसीहत दी कि यदि मोबाइल पर प्रतिबंध नहीं लगा तो 10 साल में धरती समाप्त हो जाएगी। सुदय यादव की ओर देखते हुए कहा कि आप खुद बोलो। मोबाइल में देखकर क्यों बोलते हैं?

मुख्यमंत्री ने कहा कि वह भी 2019 से पहले खूब मोबाइल देखते थे, पर अब छोड़ दिया है। मुख्यमंत्री के गुस्से का असर यह हुआ कि आमतौर पर मोबाइल से प्रश्न करने वाली एक महिला विधायक ने मोबाइल से परहेज करते हुए अपना प्रश्न कागज पर लिखकर पढ़ा। मुख्यमंत्री ने सदन के बाहर भी पूर्व में कई सरकारी कार्यक्रमों में अपने अधिकारियों की इस बात पर सार्वजनिक रूप से क्लास लगाई थी कि वह मोबाइल पर व्यस्त थे। जनता दरबार के दौरान मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में भी यह वाकया एक बार आया था, उस समय भी मुख्यमंत्री ने मोबाइल पर लगे अधिकारी को डपटा था। मोबाइल के उपयोग के संदर्भ में उन्होंने कई बार कहा है कि धरती समाप्त हो जाएगी।

कानून-व्यवस्था को लेकर पक्ष-विपक्ष आमने-सामने : विधानपरिषद में पहली पाली में कानून-व्यवस्था को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने आ गए। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के नेतृत्व में विपक्ष ने विधि-व्यवस्था पर सवाल उठाया और वेल में आकर नारेबाजी की। संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी और फिर खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संज्ञान लेते हुए विपक्ष को आश्वासन दिया कि सरकार मामले की गंभीरता से जांच कर कार्रवाई सुनिश्चित कराएगी। सभापति अवधेश नारायण सिंह ने विपक्षी सदस्यों को पहली पाली के लिए सदन से बाहर जाने को कहा। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही राजद के अब्दुल बारी सिद्दीकी ने केंद्रीय राज्यमंत्री नित्यानंद राय के संबंधियों की हत्या और होली के दौरान हुई घटनाओं को लेकर विधि-व्यवस्था पर सवाल उठाया। विपक्ष के सभी सदस्य खड़े होकर नारेबाजी करने लगे। विपक्ष के वेल में आने पर मुख्यमंत्री नीतीश खुद खड़े हो गए। उन्होंने कहा- मैं आग्रह करता हूं कि आप सभी बैठ जाएं। हत्या की जांच कराई जाएगी। अपराधी जो भी होगा, सजा मिलेगी। राबड़ी देवी को देखते हुए सीएम ने कहा कि बैठिए न, आप क्या जानती हैं। इनके पति का सस्पेंशन हुआ तो यह सीएम बन गईं। हंगामे के बीच ही श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह ने सदन में कहा कि 2007 में मेरे बेटे का अपहरण हुआ था। राजद के एक बड़े नेता फिरौती मांगने आए थे। ऐसे विपक्षी सदस्यों को अपराध पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। राबड़ी देवी ने विरोध करते हुए कहा कि फिरौती तो अशोक चौधरी वसूलते हैं। राबड़ी देवी ने कहा- बैइठ जा! कितना पानी में बाड़अ जाना तानी।

शराबबंदी के मुद्दे पर आमने-सामने हुए पक्ष-विपक्ष के नेता : विधानसभा की कार्यवाही प्रारंभ होने के पूर्व उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री रत्नेश सदा ने राजद नेताओं के साथ ही पूर्व मंत्री सर्वजीत पर शराब का कारोबार करने के आरोप लगाए। तो राजद ने पलटवार करते हुए कहा, एनडीए के सभी नेता शराब का सेवन करते हैं। मंत्री रत्नेश ने कहा कि राजद के नेता पूर्व मंत्री सर्वजीत शराब के कारोबार में शामिल हैं। कहा कि विपक्ष के लोग शराब का धंधा कर रहे हैं। राज्य में शराबबंदी कानून लागू है और लागू रहेगा। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। मंत्री के आरोप के बाद राजद विधायक मुकेश रोशन ने कहा कि एनडीए सरकार के सभी विधायक व मंत्री शराब पीते हैं।

▸ **मुख्यमंत्री ने विधानसभा अध्यक्ष को सदन के भीतर मोबाइल पर प्रतिबंध लगाने की सलाह दी**

नीतीश कुमार और राबड़ी। फाइल

आइयूएमएल के इफ्तार में सोनिया, अखिलेश व जया...

इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आइयूएमएल) ने गुरुवार को नई दिल्ली में इफ्तार का आयोजन किया। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव एवं सपा नेता जया बच्चन ने भी इसमें भाग लिया। एएनआइ

हनी ट्रैप के साए में कर्नाटक, विस में उछला मामला

बेंगलुरु, प्रेट्र : कर्नाटक में पार्टी सीमाओं से परे विधायकों और मंत्रियों ने आरोप लगाया कि कर्नाटक में राजनीतिक लक्ष्य साधने के लिए 'हनी ट्रैप' का सहारा लिया जा रहा है। कर्नाटक के लोक निर्माण मंत्री सतीश जारकीहोली ने दावा किया कि राज्य के एक वरिष्ठ मंत्री पर दो बार हनी ट्रैप के असफल प्रयास किए गए। इसकी पुष्टि सहकारिता मंत्री केएन राजन्ना ने यह कह कर की कि उन पर भी 'हनी ट्रैप' में फंसाए जाने के दो विफल प्रयास हो चुके हैं। उन्होने मामले की पुलिस से जांच कराने की मांग की।

कर्नाटक के गृह मंत्री जी.परमेश्वरा ने गुरुवार को बजट सत्र के दौरान विपक्ष के दावे का समर्थन करते हुए कहा कि ऐसे मामलों की उच्चस्तरीय जांच होगी। आरोपों के जवाब में परमेश्वरा ने कहा कि ऐसी प्रवृत्तियों को खत्म करने की जरूरत है। गृह मंत्री ने विधानसभा में बताया कि अपने सदस्यों की गरिमा की रक्षा के लिए ऐसी घटनाओं पर विराम लगाना पड़ेगा। यह बहुत गंभीर मामला है।

प्रदेश के बजट सत्र पर चर्चा के दौरान भाजपा विधायक बासव गौड़ा पाटिल यतनाल ने दावा किया कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के चलते ब्लैकमेल करने की चालें चली जा रही हैं। इस बीच, सहकारिता मंत्री केएन राजन्ना ने सदन को बताया कि प्रदेश में 48 लोग 'हनी ट्रैप' के शिकार हुए हैं। उनके अश्लील वीडियो हर ओर पहुंच रहे हैं। राजन्ना ने कहा कि बहुत लोगों का कहना है कि कर्नाटक सीडी व पेन ड्राइव की फैक्ट्री बन चुका है। उन्होंने बताया कि तुमाकुरु से एक प्रभावशाली मंत्री को 'हनी ट्रैप' का शिकार बनाया जा चुका है। गृहमंत्री को इस बार में आवश्यक जांच करनी चाहिए। इस पर लोक निर्माण मंत्री सतीश जारकीहोली ने कहा, 'दो प्रयास किए गए, लेकिन वे सफल नहीं हुए। यह कर्नाटक में हनी ट्रैप की पहली घटना नहीं है। उन्होंने कहा कि राजनीति में इस तरह की रणनीति नहीं होनी चाहिए।' उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने भी मामले में पुलिस शिकायत की मांग का समर्थन किया। उन्होंने मीडिया से कहा, पहले पुलिस थाने में शिकायत दी जाए, फिर इसकी जांच कराई जाए। पूर्व भाजपा मंत्री वी. सुनील कुमार ने विधानसभा में यह मुद्दा उठाया था।

▸ **मंत्री जारकीहोली का आरोप, राज्य के वरिष्ठ मंत्री पर दो बार असफल प्रयास**

▸ **राजन्ना बोले-कर्नाटक सीडी व पेन ड्राइव की फैक्ट्री बना, जांच हो**

कर्नाटक विधानसभा। फाइल

गोहत्या मामले में बार-बार अपराध करने वालों पर लगेगा मकोका : फडणवीस

मुंबई, प्रेट्र : महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को विधानसभा में कहा कि गोहत्या और गो तस्करी के मामले में बार-बार अपराध करने वालों के खिलाफ महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।

गृह राज्य मंत्री (ग्रामीण) पंकज भोयर ने आश्वासन दिया कि कुरैशी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उसके खिलाफ अहिल्यानगर जिले में गो तस्करी के 20 मामले दर्ज हैं।

मंत्री पंकज भोयर ने कहा कि उसे 20 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था और एक मार्च को जमानत पर छोड़ दिया गया। गृह विभाग का प्रभार संभालने वाले फडणवीस ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि इन मामलों में बार-बार अपराध करने वालों के खिलाफ मकोका के तहत कार्रवाई होगी।

राष्ट्रीय फलक

याचिका में बार-बार 'रजामंदी से संबंध' लिखने के लिए वकील को फटकारा

नई दिल्ली, प्रेट्र : नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपित अपने मुवक्किल की जमानत याचिका में बार-बार 'रजामंदी से संबंध' शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक वकील को कसकर फटकार लगाई।

जस्टिस सूर्य कांत ने कहा, 'याचिका पढ़ने के बाद हमारा दिमाग परेशान हो गया है। विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) में आपने कम से कम 20 बार रजामंदी से संबंध लिखा है। लड़की की उम्र क्या है? आपने खुद याचिका में कहा है कि वह नाबालिग है।' पीठ वकील को समझाना चाहती थी कि अगर पीड़िता नाबालिग है तो सहमति का कोई मायने नहीं है।

जस्टिस एन. कोटिस्वर के साथ पीठ में शामिल जस्टिस कांत ने कहा, 'हर पैरे में आपने रजामंदी से संबंध लिखा है। रजामंदी से संबंध से आपका क्या आशय है? आपको कानून की एबीसीडी भी नहीं आती... आप एसएलपी दायर कर रहे हैं।' पीठ ने सवाल किया, 'क्या आप एओआर (एडवोकेट आन रिकार्ड) हैं?' एओआर वे वकील होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में मामले दायर करने और मुकदमा लड़ने के लिए अधिकृत होते हैं। शीर्ष अदालत ही वकीलों के लिए एओआर परीक्षाओं का आयोजन करती है। पीठ ने कहा, 'ये लोग पास (एओआर परीक्षा में) कैसे हो रहे हैं? आपको बुनियादी कानून भी नहीं पता... आपने 20 बार रजामंदी से संबंध लिखा है... कल आप कहेंगे कि आठ महीने के बच्चे के साथ रजामंदी से संबंध था।' इस पर वकील ने पीठ से माफी मांग ली और अदालत ने भी जमानत याचिका पर पुलिस व अन्य को नोटिस जारी कर दिए।

▸ **वकील ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपित मुवक्किल के लिए दायर की है याचिका**

▸ **कोर्ट ने कहा, आपको कानून की एबीसीडी भी नहीं आती और कर रहे एसएलपी दायर**

कार्बन मोनोआक्साइड शरीर के अंदर लेकर दी जान

पालघर, प्रेट्र : पालघर जिले में एक व्यक्ति ने कथित तौर पर ट्यूब के जरिये कार्बन मोनोआक्साइड शरीर के अंदर लेकर आत्महत्या कर ली। वसई क्षेत्र में उसके किराये के बंगले के अंदर पांच सिलेंडर मिले हैं। सुसाइड नोट के अनुसार वह गंभीर बीमारी से पीड़ित था।

पुलिस अधिकारी ने गुरुवार को कहा, कार्बन मोनोआक्साइड के सिलेंडर की आपूर्ति किसने की इसकी जांच शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा, श्रेय अग्रवाल का शव बुधवार शाम को मिला था। उसने खिड़कियों और दरवाजों को चिपकने वाली टेप से सील कर दिया था ताकि गैस बाहर न निकले। दीवार पर चिपकाए गए सुसाइड नोट में लिखा है कि श्रेय एक गंभीर बीमारी से पीड़ित था, जिसके कारण उसने यह कदम उठाया।

नायगांव पुलिस स्टेशन के अधिकारी ने कहा, श्रेय ने हेलमेट पहन रखा था और एक नोट भी छोड़ा था, जिसमें प्रवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति को अन्य सुरक्षा निर्देशों के साथ-साथ लाइट न जलाने के लिए कहा गया था। उन्होंने कहा, बंगले के प्रवेश द्वार पर छोड़े गए अंग्रेजी में नोट में अंदर कार्बन मोनोआक्साइड की मौजूदगी के बारे में बताया गया था। हमने अंदर प्रवेश पाने के लिए हाइड्रोलिक कटर-स्प्रेडर का इस्तेमाल किया। पीपीई किट से लैस अग्निशामक अंदर गए।

अधिकारी ने कहा, श्रेय ने खुद को कार्बन मोनोआक्साइड सिलेंडर से बांध लिया था, जबकि दो सिलेंडर उसके हाथ में थे। उसने हेलमेट पहन रखा था और सिलेंडर से जुड़ी एक नेबुलाइजर ट्यूब का उपयोग करके अपने मुंह के माध्यम से गैस खींची थी। उसका शरीर, जो पूरी तरह से सूज गया है को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि गैस बंगले के बाहर लीक न हो, दरवाजे और खिड़कियों को चिपकने वाली टेप के साथ-साथ लकड़ी के तख्तों से सील कर दिया गया था। अधिकारी ने बताया कि एक स्थानीय बढ़ई से पूछताछ की जा रही है, जिसने दो दिन पहले यह काम किया था।

घटना तब सामने आई जब श्रेय की बहन, जो पिछले कुछ दिनों से उससे संपर्क नहीं कर पा रही थी, ने मुंबई पुलिस आयुक्त को ईमेल भेजकर मदद मांगी। मुंबई क्राइम ब्रांच ने तकनीकी खुफिया जानकारी का उपयोग करके उस जगह का पता लगाकर हमें सतर्क किया। आसपास के लोगों ने हमारी टीम को बताया कि श्रेय एक साल से वहां किराये पर रह रहा था। वह अकेले रहता था। हमें घर में पांच कार्बन मोनोआक्साइड सिलेंडर मिले। यह पता लगाने के लिए जांच शुरू हो गई है कि उसे ये कहां से मिले।

▸ **किराये के बंगले के अंदर मिले पांच सिलेंडर, खिड़कियों, दरवाजों को टेप से कर दिया था सील, सिलेंडर की आपूर्ति किसने की इसकी जांच शुरू**

▸ **श्रेय ने एक नोट भी छोड़ा था, जिसमें प्रवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति को अन्य सुरक्षा निर्देशों के साथ-साथ लाइट न जलाने के लिए कहा गया था**

समीर वानखेड़े पर जांच रिपोर्ट में तथ्यों को छिपाने का आरोप

प्रथम पृष्ठ से आगे

वकील नीलेश ओझा ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद कई महीने चली एनसीबी (नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो) की जांच में एक महत्वपूर्ण तथ्य छिपाए जाने की बात भी कही। कहा कि एनसीबी के तत्कालीन अधिकारी समीर वानखेड़े ने अपनी जांच रिपोर्ट में यह बात छुपाई है कि अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती और शिवसेना (यूबीटी) के नेता आदित्य ठाकरे एक-दूसरे को पहले से जानते थे। इसलिए, सतीश सालियान की याचिका में समीर वानखेड़े को भी प्रतिवादी बनाया गया है।

उद्धव ने मेरे पिता को फोन कर आदित्य ठाकरे को बचाने के लिए मांगी थी मदद : नीतेश राणे: नीतेश राणे ने यह दावा भी किया कि आदित्य के पिता एवं तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दिशा की मौत के बाद मेरे पिता नारायण राणे को फोन कर आदित्य ठाकरे को बचाने के लिए मदद मांगी थी। भाजपा विधायक अमित साटम ने भी आरोप लगाया है कि दिशा सालियान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद उस समय उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में चल रही महाविकास आघाड़ी सरकार ने इस मामले को दबाने का प्रयास किया था। वहीं, दिशा सालियान के मुद्दे पर गुरुवार को विधानभवन परिसर में भी जमकर हंगामा हुआ।

भाजपा यदि असत्य को तथ्य के रूप में पेश करेगी तो यह उल्टा पड़ेगा : उद्धव

मुंबई, प्रेट्र : शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने दिशा सालियान की संदिग्ध मौत के मामले में बेटे आदित्य ठाकरे का नाम लिए जाने पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि लगाए जा रहे आरोपों में कोई दम नहीं है। उन्होंने भाजपा को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि वह असत्य बातों को तथ्य के रूप में पेश करना चाहती है तो यह उल्टा पड़ेगा। वह विधान भवन में मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे।

****

120 अंडे दिए हैं मध्य प्रदेश के सीधी जिले में स्थित सोन घड़ियाल अभयारण्य में चार घड़ियालों ने। बता दें कि इस दिनों सोन अभयारण्य में एक नर, 18 वयस्क, 10 अवयस्क घड़ियाल मौजूद हैं।

नागपुर हिंसा के मास्टरमाइंड फहीम व पांच अन्य के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज

फहीम ने औरंगजेब के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के वीडियो को संपादित और प्रसारित किया

300 से ज्यादा इंटरनेट मीडिया अकाउंट की जांच, 140 अकाउंट में आपत्तिजनक पोस्ट और वीडियो पाए गए

राज्य ब्यूरो, जागरण ● मुंबई

पुलिस ने 17 मार्च को नागपुर में हुई हिंसा के मास्टरमाइंड फहीम खान और पांच अन्य के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया है। खान को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। अदालत ने उसे 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

नागपुर साइबर क्राइम के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) लोहित मतानी के अनुसार, फहीम खान समेत छह लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया है। कुछ लोगों ने पुलिस के खिलाफ हिंसा का समर्थन किया और उसकी प्रशंसा की। यह संख्या और बढ़ सकती है। इस हमले का समर्थन करते हुए कुछ टिप्पणियां की गईं, जिससे हिंसा हुई। टिप्पणियां करने वाले लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया है।

उन्होंने बताया कि नागपुर हिंसा के संबंध में 300 से ज्यादा इंटरनेट मीडिया अकाउंट की जांच की गई है। इनमें से 140 अकाउंट में आपत्तिजनक पोस्ट और वीडियो पाए गए हैं। मतानी के अनुसार, फहीम खान ने औरंगजेब के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के वीडियो को संपादित और प्रसारित किया, जिस कारण हिंसा हुई।

डीसीपी ने बताया कि आपत्तिजनक सामग्री नागपुर के बाहर के अकाउंट से प्रसारित की गई। इनमें कुछ पोस्ट के जरिये दंगों के लिए समर्थन जताया गया है। इन सभी अकाउंट की जांच की जा रही है और यह भी देखा जा रहा है कि ये अकाउंट देश के बाहर के हैं या नहीं।

गुरुवार को नागपुर के मोमिनपुरा में गश्त पर सुरक्षा बल के जवान। प्रेट्र

हिंसा में बांग्लादेश कनेक्शन की भी जांच

पुलिस नागपुर हिंसा में बांग्लादेश का हाथ होने की जांच भी कर रही है। इससे पहले, महाराष्ट्र राज्य साइबर विभाग के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के कार्यालय ने बुधवार रात को जारी एक विज्ञप्ति में कहा था कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और यूट्यूब पर आपत्तिजनक सामग्री के 140 से अधिक मामलों की पहचान की गई है। इन खातों को संचालित करने वाले व्यक्तियों की वास्तविक पहचान को उजागर करने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 94 के तहत नोटिस जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी भड़काऊ सामग्री फैलाने के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

कांस्टेबल से छेड़छाड़ करने वालों पर हो कार्रवाई : मुस्लिम धर्मगुरु

अलीगढ़ के एक मुस्लिम धर्मगुरु ने महिला कांस्टेबल से छेड़छाड़ करने वाले अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। इफराहीम हुसैन ने नागपुर हिंसा के दौरान महिला पुलिसकर्मी के साथ छेड़छाड़ की निंदा की और कड़ी कार्रवाई की मांग की।

आक्रांताओं का महिमा मंडन करने वाले देशद्रोही : योगी

जागरण संवाददाता, बहराइच

▸ सीएम ने कहा–जल्द होगा महाराजा सुहेलदेव के स्मारक का उद्घाटन

औरंगजेब और सालार मसूद गाजी पर विवाद के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को बहराइच में कहा कि आक्रांता का महिमा मंडन, मतलब देशद्रोह है। भारत के महापुरुषों के सम्मान का भाव प्रत्येक नागरिक का दायित्व होना चाहिए। जो भारत के महापुरुषों को अपमानित करता है और उन आक्रांताओं को महिमा मंडन करता है, जिन्होंने सनातन संस्कृति को रौंदने व बहन-बेटियों की इज्जत पर हाथ डालने का काम किया, उसे आज का नया भारत स्वीकार नहीं कर सकता है।

मुख्यमंत्री बहराइच के मिहींपुरवा तहसील के नए भवन का शुभारंभ करने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि बहराइच ऐसी ऐतिहासिक जगह है, जहां विदेशी आक्रांता को हराते हुए महाराज सुहलदेव ने भारत की विजय पताका को फहराया था। बहराइच में आक्रमणकारी महमूद गजनवी के सेनापति व भांजे सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह है, जहां प्रति वर्ष गाजी मियां उर्स (मेला) होता है। इस साल 15 मई को यह मेला प्रस्तावित है। संभल के नेजा मेले को प्रशासन की ओर से अनुमति न दिए जाने के बाद बहराइच में भी गाजी मियां के उर्स को रोकने व इसके स्थान पर सालार मसूद गाजी को युद्ध में हराकर मौत के घाट उतारने वाले राजा सुहेलदेव राजभर के नाम पर मेला आयोजित करने की मांग की जा रही है। महाराज सुहलदेव ने शौर्य का जो परिचय दिया था, उसी की परिणति हुई कि 150 वर्ष तक कोई विदेशी आक्रांता भारत पर हमला करने का दुस्साहस नहीं कर पाया। जल्द ही महाराजा सुहेलदेव की स्मारक का उद्घाटन करने की बात कहते हुए उन्होंने कहा कि लोग वीरों के शौर्य को कतई न भूलें। महर्षि बालार्क का एक विश्व प्रसिद्ध आश्रम बहराइच में था और बहराइच की पहचान उन्हीं के नाम पर है। बहराइच जिले में एक नए बाईपास निर्माण की मंजूरी देने की बात कहते हुए कहा कि ऐसे में जंगल और महाराजा सुहेलदेव के स्मारक में आने वाले पर्यटक एक घंटे में लखनऊ से बहराइच पहुंच सकेंगे।

योगी आदित्यनाथ। फाइल

बरेलवी मौलाना ने दंगे के लिए 'छावा' फिल्म को माना दोषी

जागरण संवाददाता, बरेली : चैंपियंस ट्राफी के दौरान भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को रोजा न रखने पर शरीयत का अपराधी बताने वाले बरेलवी मौलाना ने अब 'छावा' फिल्म पर टिप्पणी कर दी। बुधवार को आल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने नागपुर दंगे के लिए 'छावा'' को दोषी ठहरा दिया। उन्होंने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को पत्र भेजकर फिल्म पर प्रतिबंध लगाने एवं कानूनी कार्रवाई कराने की मांग की। जब रजवी से सवाल किया गया कि वह औरंगजेब पर क्या विचार रखते हैं तो इसके उत्तर में उन्होंने कहा कि भारत का मुसलमान औरंगजेब को अपना आदर्श नहीं मानता है। पत्र में रजवी ने लिखा कि फिल्म छावा जब से रिलीज हुई है, तब से देश का माहौल खराब हो रहा है। इसमें औरंगजेब को हिंदू विरोधी दर्शाकर हिंदू नौजवानों को भड़काया गया है। यही वजह है कि जगह-जगह हिंदू संगठनों के नेता औरंगजेब के संबंध में हेट स्पीच दे रहे हैं। इसी कारण 17 मार्च को नागपुर में सांप्रदायिक दंगा हो गया। इसके बाद नागपुर के उलमा और मस्जिदों के इमाम से रातभर संपर्क करके माहौल को शांत करने में लगे रहे।

शहाबुद्दीन रजवी।

भ्रष्टाचार के मामले में इन्वेस्ट यूपी के सीईओ निलंबित

राज्य ब्यूरो, जागरण ● लखनऊ

▸ भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टालरेंस नीति के तहत हुई सख्त कार्रवाई

▸ सोलर ऊर्जा संयत्र स्थापित करने के लिए मांगे गए कमीशन में मिली थी संलिप्तता

सोलर उद्योग लगाने के लिए रिश्वत मांगने के आरोप पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ी कार्रवाई करते हुए इन्वेस्ट यूपी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) अभिषेक प्रकाश को निलंबित कर दिया है। एसएईएल सोलर पी6 प्राइवेट लिमिटेड के विश्वजीत दत्ता ने इन्वेस्ट यूपी में भ्रष्टाचार की शिकायत की थी। इसकी जांच रिपोर्ट आने के बाद यह कठोर कार्रवाई की गई। वर्ष 2006 बैच के आइएएस अभिषेक प्रकाश औद्योगिक विकास विभाग के सचिव व इन्वेस्ट यूपी के सीईओ पद पर तैनात थे। इससे पहले वह लखनऊ के जिलाधिकारी भी रह चुके हैं। पुलिस ने कमीशन मांगने वाले मेरठ निवासी 40 वर्षीय बिचौलिए निकान्त जैन को गिरफ्तार कर लिया है।

एसएईएल के विश्वजीत दत्ता ने आरोप लगाया था कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा के कलपुर्जे बनाने का संयंत्र स्थापित करने के लिए इन्वेस्ट यूपी को आनलाइन आवेदन किया था। मूल्यांकन समिति की बैठक में उनके आवेदन को स्वीकृति प्रदान की गई थी। इससे पहले इन्वेस्ट यूपी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने निजी व्यक्ति निकान्त जैन का नंबर दिया था और कहा था कि उससे बात कर लें। निकान्त ने उनके आवेदन पर पांच प्रतिशत का कमीशन मांगा था लेकिन उन्होंने कमीशन देने से मना कर दिया था। दत्ता ने यह आरोप भी लगाए हैं कि उनके आवेदन को संस्तुति मिलने के बाद पत्रावली पर टालमटोल किया जाता रहा। निकान्त ने उनसे कहा था कि काम कमीशन देने के बाद ही होगा। साथ ही कहा कि कमीशन देने पर इंपावर्ड कमेटी व कैबिनेट से तुरंत आवेदन को स्वीकृति दिला दी जाएगी। इसके बाद उन्होंने 20 मार्च को मामले की शिकायत की थी।

बिहार में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के भांजों ने एक-दूसरे को मारी गोली, एक की मौत

जागरण संवाददाता, भागलपुर

▸ दोनों भाइयों को बचाने में मां को लगी गोली, दूसरे भाई की हालत गंभीर

▸ घर को लेकर भी दोनों भाइयों में दो दिनों से बढ़ा था विवाद

बिहार के नवगछिया में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय के दो भांजे जयजीत यादव और विश्वजीत यादव उर्फ विकल यादव ने गुरुवार को मामूली विवाद में एक ही पिस्टल से एक-दूसरे को गोली मार दी। इसमें छोटे भाई विकल यादव की मौत हो गई, जबकि जयजीत यादव की हालत गंभीर है। घटना में इनकी मां हिना देवी के हाथ में भी गोली लगी है। सूचना पर पहुंचे नवगछिया एसपी ने घटनास्थल का जायजा लिया। फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम ने घटनास्थल से आवश्यक साक्ष्य जमा किए हैं। पुलिस को एक खोखा मिला है। नवगछिया एसपी प्रेरणा कुमार ने बताया कि मौके से कोई हथियार नहीं मिला है। जांच की जा रही है।

विश्वजीत यादव। (फाइल फोटो) जागरण

जानकारी के अनुसार, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के बहनोई भागलपुर जिले के नवगछिया प्रखंड स्थित जगतपुर गांव निवासी रघुनंदन यादव उर्फ गुल्लो यादव के घर पर गुरुवार सुबह नल जल की टोंटी (नल) से पानी लेने को लेकर दोनों भाइयों जयजीत और विश्वजीत में कहासुनी होने लगी। इसके बाद विश्वजीत घर से पिस्टल ले आया और जयजीत के मुंह पर सीधे गोली चला दी। गोली जबड़े को क्षतिग्रस्त करते हुए निकल गई। जयजीत पहले तो जमीन पर गिर गए, लेकिन चंद मिनटों बाद उठे व विश्वजीत से पिस्तौल छीन ली। जयजीत ने विश्वजीत को करीब से सीने व पेट में गोली मार दी। इससे विश्वजीत की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों भाइयों को छुड़ाने में इनकी मां हिना देवी के हाथ में भी गोली लग गई।

अधिक खून बहने के कारण जयजीत की हालत गंभीर बनी हुई है। जयजीत और उनकी मां को उपचार के लिए निजी क्लीनिक में ले जाया गया। यहां से उन्हें पटना रेफर कर दिया गया।

बिहार के नवगछिया में घटनास्थल पर विलाप करती मृतक की पत्नी। जागरण

पुजारी पर हमला अपराध के साथ पाप भी, दोषियों को उम्रकैद

जागरण संवाददाता, बरेली

▸ बरेली के मंदिर व आश्रम में 13 वर्ष पुरानी वारदात में कोर्ट का निर्णय

▸ कहा–धर्मस्थलों पर शराब पीने की स्वतंत्रता दी तो होगा धर्म का नुकसान

मंदिर परिसर में शराब पीने के विरोध पर पुजारी पर जानलेवा हमले के दोषी सत्यवीर और ओमपाल को उम्रकैद की सजा दी गई। 13 वर्ष पुरानी घटना में अपर सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय प्रथम) रवि कुमार दिवाकर ने निर्णय सुनाया। उन्होंने पुजारी के महत्व को भी उल्लेखित किया कि उन पर हमला भारतीय विधान में अपराध है ही, साथ ही यह पाप की श्रेणी में आता है। यह क्षमा योग्य नहीं है। भारत सदैव ऋषि, मुनियों का देश रहा है। इन्हीं लोगों ने समय-समय पर धर्म की रक्षा की। यदि किसी व्यक्ति को मंदिर जैसे धर्मस्थल में मदिरापान की स्वतंत्रता दे दी गई तो निश्चित रूप से धर्म को नुकसान होगा।

बरेली के सिरौली की संत साधना कुटी शिवधाम के पुजारी सिया दुलारे शरण 25 अप्रैल 2012 की रात को कुटी में थे। मुकदमे के अनुसार, गांव के कन्हई लाल के घर सत्यवीर, ओमपाल व गुड्डी आया था। रात 10 बजे वे तीनों मोटरसाइकिल से मंदिर-आश्रम परिसर पहुंचे। वे वहां बैठकर शराब पीने का प्रयास करने लगे। पुजारी ने इसका विरोध किया तो उन्हें गोली मारकर घायल कर दिया। सरकारी वकील संतोष श्रीवास्तव ने बताया कि सुनवाई के दौरान गुड्डू की मौत हो चुकी है। कोर्ट ने सत्यवीर व ओमपाल को पुजारी पर जानलेवा हमले का दोषी मानते हुए उम्रकैद और एक लाख, 30 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया, जिसमें 50 प्रतिशत धनराशि पुजारी को दी जाएगी।

प्रतीकात्मक

हिमाचल प्रदेश में खालिस्तान समर्थकों के विरोध में प्रदर्शन

जागरण संवाददाता, कुल्लू : हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला मुख्यालय में गुरुवार को मणिकर्ण घाटी के लोगों ने पंजाब से आने वाले खालिस्तान समर्थकों के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान रोष रैली भी निकाली। रथ मैदान से लेकर उपायुक्त कार्यालय तक स्थानीय लोगों ने खालिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने सरकार से कुल्लू में आकर नियमों का उल्लंघन करने वालों व हुड़दंग मचाने वालों पर कार्रवाई करने की मांग की।

विरोध कर रहे लोगों ने उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। लोगों की मांग है कि होली के दौरान हर वर्ष पंजाब से मणिकर्ण स्थित गुरुद्वारा साहिब में दर्शन के लिए श्रद्धालु आते हैं। इनमें से कुछ पर्यटक यहां पर आकर हुड़दंग मचाते हैं और स्थानीय लोगों के साथ मारपीट करते हैं। तीन-चार साल से इस प्रकार की घटनाएं पेश आ रही हैं। स्थानीय निवासी अमन सूद ने कहा कि इस प्रकार की घटना हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।

संभल में सद्भावना मेले के नाम से भी नहीं मिलेगी अनुमति

जागरण संवाददाता, संभल

▸ मुस्लिम प्रधानों ने एसडीएम को पत्र देकर नाम बदलकर मांगी थी अनुमति

▸ नेजा मेले के मामले में शहर में चौकसी बरकरार, मेला स्थलों पर निगरानी

नेजा मेला पर आपत्ति के बाद पुलिस-प्रशासन सद्भावना मेला लगवाने के भी पक्ष में नहीं हैं। कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका की वजह से इसके लिए भी अनुमति नहीं दी जाएगी। मुस्लिम प्रधानों ने एसडीएम को पत्र देकर सद्भावना मेला की अनुमति देने की मांग की थी। एसडीएम ने इस पत्र को रिपोर्ट के लिए पुलिस के पास भेज दिया है। एएसपी श्रीश्चंद्र का कहना है कि कानून व्यवस्था सर्वोपरि है।

सोमनाथ मंदिर के लुटेरे मुस्लिम आक्रमणकारी महमूद गजनवी के सेनापति और भांजे सैयद सालार मसूद गाजी के नाम से लगने वाले मेले को लेकर एएसपी ने सोमवार को सख्त रुख अपनाया था। उन्होंने कमेटी पदाधिकारियों से साफ कहा था कि सोमनाथ मंदिर के लुटेरे की याद में मेला नहीं लगने दिया जाएगा। वर्षों से चली आ रही कुरीति को बदलने की जरूरत है। ऐसे लुटेरे-हत्यारे, देशद्रोही की याद में मेला लगाने वाले भी देशद्रोही होंगे। इसके बाद शहर में चौकसी बरती जा रही है। कोतवाली के सामने गड्ढे को भी पाट दिया गया। इसी गड्ढे में नेजा मेले का झंडा लगाया जाता रहा है। नेजा मेला होली के बाद दूसरे मंगलवार से तीन दिन अलग-अलग स्थानों पर लगता रहा है। हालांकि, 2024 में मेला नहीं लगा था। 2023 में सद्भावना मेले के नाम से लगा था। इस बार नेजा मेले नहीं लगने की संभावना देख मुस्लिम प्रधान नाम बदलकर मेले की अनुमति मांगी थी।

धार्मिक नगर नेजा मेला कमेटी के अध्यक्ष शाहिद हुसैन मसूदी सहित तीन पदाधिकारियों को पुलिस ने पांच-पांच लाख रुपये के मुचलके में पाबंद किया है। एसडीएम वंदना मिश्रा ने बताया कि शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए यह कदम उठाया गया है।

सौरभ का सिर काटकर तंत्र क्रिया के लिए ले गया था साहिल

जागरण संवाददाता, मेरठ

▸ साहिल के कमरे में डरावने चित्र, मुस्कान को अंधविश्वास में फंसाया

▸ डाटा रिकवरी के लिए फोरेंसिक लैब भेजे गए हत्यारोपितों के मोबाइल फोन

सौरभ हत्याकांड के तार तांत्रिक क्रिया से जुड़ते नजर आ रहे हैं। कमरे की दीवारों पर डरावने और अबूझ चित्र, ड्रैगन का रेखा चित्र और साहिल के पहनावे व हुलिया से साफ हो गया कि उसने प्रेमिका मुस्कान को काले जादू की गिरफ्त में ले रखा था। तीन मार्च की रात सौरभ की हत्या के बाद उसका कटा सिर लेकर मुस्कान के साथ साहिल अपने कमरे में पहुंचा। तंत्र क्रिया पूरी करने के बाद सुबह कटा सिर लेकर फिर दोनों मुस्कान के घर लौट गए। मुस्कान की मां कविता रस्तोगी और पिता प्रमोद रस्तोगी ने भी साफ कर दिया कि अंधविश्वास से ही मुस्कान को साहिल ने अपने कब्जे में किया हुआ था। उधर, पुलिस ने मुस्कान और सौरभ को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजने के साथ ही उनका मोबाइल डाटा रिकवरी के लिए फोरेंसिक लैब भेज दिया है। तीन मार्च की रात मुस्कान ने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर पति सौरभ की हत्या कर उसका शव चार टुकड़ों में कर ड्रम में डाला और सीमेंट से सील कर दिया था। मुस्कान ने जब यह बात अपनी मां को बताई तो उसने उसे पुलिस के हवाले कर दिया और पुलिस ने वह ड्रम बरामद कर लिया, जिसमें सौरभ के शव के टुकड़े थे। मुस्कान के पिता प्रमोद रस्तोगी ने कहा कि ऐसी बेटी समाज में रहने योग्य नहीं है। उसे फांसी पर लटकाना चाहिए। साहिल के कमरे में भगवान शंकर के चित्र के अलावा कई अन्य डरावने चित्र भी बनाए गए हैं। साहिल ने एक बिल्ली भी पाल रखी है। रूम में बीयर की खाली बोतलें मिलीं। आसपास के लोगों का कहना है कि सिर्फ बिल्ली को खाना खिलाने के लिए साहिल बाहर निकलता था। उसके कमरे की लाइट रोजाना बंद रहती थी। तीन मार्च की रात सुबह तक लाइट जलती रही। बिल्ली की आवाज से ही आसपास के लोग छत पर चढ़कर देखने लगे थे।

सौरभ।

प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या, शव बाइक पर लेकर घूमती रही पत्नी

जागरण संवाददाता, जयपुर

▸ जयपुर का मामला, हत्यारोपित महिला व उसका प्रेमी गिरफ्तार किया गया

राजस्थान के जयपुर में एक महिला द्वारा प्रेमी के साथ मिलकर पति की गला दबाकर हत्या करने और शव को बोरे में डालकर बाइक से शहर में घूमने और जंगल में ले जाकर जला देने का मामला सामने आया है। पुलिस ने हत्यारोपित महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस उपायुक्त दिगंत आनंद ने बताया कि 16 मार्च को शहर के मुहाना क्षेत्र में रिंग रोड के निकट जला शव मिला था। शव की पहचान सब्जी बेचने वाले धन्नालाल के रूप में हुई।

पुलिस को बाइक पर मृतक का शव ले जाने की सीसीटीवी फुटेज मिली तो शक पत्नी गोपाली की ओर गया और उसे व उसके प्रेमी दीनदयाल को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में सामने आया है कि गोपाली के पिछले 15 वर्षों से दीनदयाल से प्रेम संबंध थे। उसने उसके एक दुकान पर नौकरी करने की बात पति को बता रखी थी। पति को गोपाली के चरित्र पर पिछले कुछ समय से शक होने लगा तो वह 15 मार्च को गोपाली का पीछा करते सांगानेर स्थित कपड़ों की दुकान पहुंचा, जो दीनदयाल की है। गोपाली और दीनदयाल को आपत्तिजनक अवस्था में देख धन्नालाल नाराज हुआ तो दोनों आरोपित बातचीत करते उसे दुकान की छत पर ले गए।

बातचीत के दौरान मौका देख दीनदयाल ने धन्नालाल पर लोहे के पाइप से हमला कर दिया। वह घायल होकर गिर गया तो दोनों ने रस्सी से गला दबाकर धन्नालाल की हत्या कर दी। हत्या के बाद धन्नालाल के शव को प्लास्टिक के बोरे में डाला और बाइक से जंगल में ले जाकर जला दिया।

नई पहचान

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मारीशस के राष्ट्रपति और अमेरिका की गबार्ड को गंगाजली में दिया संगम का जल

महाकुंभ से मुरादाबाद के गंगाजली कारोबार को नई दिशा

अमन कुमार शर्मा ● जागरण

मुरादाबाद : पीतल उत्पाद से विश्वभर में पहचान बनाने वाले मुरादाबाद के कारोबार को महाकुंभ से बढ़ावा मिला है। महाकुंभ की वजह से प्रयागराज, काशी और अयोध्याजी में पूजा उत्पादों की रिकार्ड बिक्री हुई। शहर में बनी गंगाजली को भी नई पहचान मिली है। उत्तर प्रदेश के संस्कृति विभाग ने भी इसकी खरीदारी की है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 11 मार्च को मारीशस में वहां के राष्ट्रपति धर्मबीर गोखूल को संगम का जल गंगाजली में ही भेंट किया था। अब उन्होंने नई दिल्ली में अमेरिका की शीर्ष खुफिया एजेंसी नेशनल इंटेलीजेंस की निदेशक तुलसी गबार्ड को गंगाजली में जल भेंट किया है। यह गंगाजली मुरादाबाद की होने का अनुमान है। हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसीएच) के वाइस चेयरमैन नीरज खन्ना का कहना है कि इस तरह की गंगाजली मुरादाबाद में बनती है। हालांकि, यहां से सीधे खरीदने की जानकारी नहीं है। करीब 150 कारीगर गंगाजली बना रहे हैं। महाकुंभ की वजह से गंगाजली की बिक्री दोगुने के आसपास हो गई है। पूर्व में करीब एक लाख गंगाजली एक साल में बिकती थीं। महाकुंभ में ही इतनी बिक गई। इसके बाद लगातार मांग आ रही है। शहर के बर्तन व्यवसायी अनुभव अग्रवाल का कहना है कि उन्होंने लखनऊ के व्यापारी को 1100 कलश और तीन हजार गंगाजली की सप्लाई की थी। वहां से करीब 1200 गंगाजली संस्कृति विभाग ने खरीदी हैं, जिन्हें दिल्ली भी भेजे जाने की जानकारी मिली है। गंगाजली तीन से 12 इंच तक ऊंची हैं। ऊंचाई के हिसाब से कीमत है। सबसे छोटी गंगाजली 50 रुपये और सबसे बड़ी गंगाजली 1500 रुपये की है। इनमें 50 ग्राम से लेकर दो लीटर तक जल आता है।

तीन तरह की गंगाजली: उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के महानगर महामंत्री अमरीश अग्रवाल का कहना है कि एक गंगाजली प्लेन, दूसरी एंब्रोस (इसमें हल्की नक्काशी होती है) और तीसरी टोटीदार (इसमें टोटी निकली होती है) होती है।

मुरादाबाद के बर्तन बाजार स्थित दुकान में रखी गंगाजली। जागरण

मुरादाबाद में करीब 150 कारोबारी गंगाजली बनाते हैं। कोई गंगाजली को ढाल देता है, कोई पालिश और कोई उस पर नक्काशी करता है। गंगाजली मुरादाबाद से लखनऊ भेजी गई और वहां से दिल्ली।
–योगेश कुमार, संयुक्त आयुक्त, उद्योग

महाकुंभ से बर्तन बाजार को रफ्तार मिली है। पूजा उत्पादों की काफी मांग बढ़ी है। गंगाजली, कलश, पूजा थाली, घंटी सहित अन्य उत्पादों की मांग रहती है। कई कारीगर मिलकर एक गंगजली तैयार करते हैं। प्रधानमंत्री के मुरादाबाद की गंगाजली में संगम का जल भेंट करने से मुरादाबाद को नई पहचान मिली है।
–अजय अग्रवाल, महानगर अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल

बिहार में अपने मालिक को बचाने के लिए कुत्ते ने दे दी जान

जागरण संवाददाता, सरायरंजन (समस्तीपुर)

▸ बदमाशों की फायरिंग पर सामने आ गया कुत्ता, शोर मचाने पर जुटे ग्रामीणों ने एक बदमाश को पकड़ लिया, पिटाई कर पुलिस को सौंपा

बिहार में समस्तीपुर जिले के मुसरीघरारी थाना क्षेत्र में अपने मालिक को बचाने के लिए कुत्ते ने जान दे दी। दरअसल मालिक की हत्या करने के लिए तीन बदमाश उसके घर पहुंचे थे। बदमाशों ने फायरिंग की इसी दौरान उनका पालतू कुत्ता मालिक के सामने आ गया। बदमाशों की फायरिंग में गोली कुत्ते को लगी और उसकी मौत हो गई। शोर मचाने पर जुटे ग्रामीणों ने एक बदमाश को पकड़ लिया। उसकी पिटाई कर पुलिस के हवाले कर दिया। दो की तलाश में पुलिस लगी है।

बताया गया कि गंगापुर वार्ड में गुरुवार की सुबह एक बाइक पर तीन बदमाश राकेश पासवान के घर पहुंचे। उनकी हत्या की नीयत से गोली चलाई। राकेश के पास ही बैठा उनका पालतू कुत्ता सामने आ गया और गोली उसे लग गई। हल्ला करने पर ग्रामीणों ने एक बदमाश को पकड़ लिया। जबकि दो अन्य मोटर साइकिल छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने घटनास्थल से एक खोखा बरामद किया। मृत कुत्ते को समस्तीपुर पशुपालन अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इस संबंध में राकेश ने बताया कि उनका पड़ोसी से भूमि विवाद चल रहा था। पंचायत के बाद विवाद खत्म हो गया था। आरोपित गांव में शराब का धंधा करता है। उसी ने साथियों के साथ मिलकर उन पर जानलेवा हमला किया। थानाध्यक्ष ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।

****

10 आरोपितों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल है पुलिस ने अभिनेता मुश्ताक अपहरण केस में। सीसीटीवी फुटेज, बरामदगी और अभिनेता के बयान अहम साक्ष्य बनाए गए हैं। सभी आरोपित जेल में हैं।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शुक्रवार 21 मार्च, 2025

'एसिड हमलों के पीड़ित मुआवजे को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करें'

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि यदि तेजाबी हमलों के पीड़ितों को मुआवजा मिलने में देरी होती है, तो वे अपने संबंधित राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क कर सकते हैं। प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने मुंबई स्थित गैर सरकारी संगठन "एसिड सर्वाइवर्स साहस फाउंडेशन" के वकील की इस दलील का संज्ञान लिया कि ऐसे पीड़ितों को महाराष्ट्र में अधिकारियों से मुआवजा प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है।

प्रधान न्यायाधीश ने कहा, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करें। मुआवजे के भुगतान में देरी होने पर पीड़ितों को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों से संपर्क करने की स्वतंत्रता होगी। पीठ ने कहा कि एसिड हमलों के पीड़ितों को मुआवजा देने में देरी को उसके संज्ञान में लाया जाएगा। शीर्ष अदालत ने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को एक चार्ट बनाने का भी निर्देश दिया, जिसमें उस समय का विवरण शामिल हो, जब पीड़ित या उसके परिवार के सदस्यों ने मुआवजा मांगा था तथा जिस दिन उन्हें मुआवजा मिला था।

बीएचयू का कुलपति तय करने के लिए सरकार के पास 16 अप्रैल तक का समय

संग्राम सिंह • जागरण

वाराणसी: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) में कुलपति नियुक्त करने के लिए केंद्र सरकार को 16 अप्रैल तक का समय दिया है। मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने बीते 12 मार्च को यह निर्देश देते हुए कहा था कि केंद्र सरकार नए कुलपति की नियुक्ति को लेकर अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने में नाकाम रही है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा कुलपति के पद के लिए आवेदन मंगाया जाता है। मंत्रालय द्वारा गठित सर्च कमेटी आवेदकों का साक्षात्कार करती है और योग्य उम्मीदवारों को शार्टलिस्ट करती है। अंतिम रूप से चुने गए इन उम्मीदवारों का नाम राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और वह अंतिम रूप से मुहर लगाता है। इस साल छह जनवरी को प्रो. सुधीर कुमार जैन का तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद से बीएचयू में कुलपति नहीं हैं व अस्थायी रूप से रेक्टर कार्यभार संभाल रहे हैं।

- इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तय की आखिरी समय सीमा
- बार-बार व्यक्तिगत समस्याओं का हवाला देकर तारीख बढ़वाने से कोर्ट नाराज
- सात जनवरी 2025 से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति का पद है रिक्त

2021 से नहीं हुआ कार्यपरिषद का गठन

हरिकेश बहादुर सिंह।

याचिकाकर्ता हरिकेश सिंह ने कहा कि कार्यकारिणी परिषद (ईसी) का गठन जून 2021 से नहीं हुआ है। प्रो. सुधीर कुमार जैन ने कार्यकारिणी परिषद की अनुपस्थिति में इमरजेंसी पावर का दुरुपयोग किया और विभिन्न समितियों में अपने लोगों को नियुक्त कर उन्हें लाभान्वित किया। शिक्षा मंत्रालय से शिकायत की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि कार्यकाल के दौरान प्रो जैन यह दोहराते रहे हैं कि उन्होंने कार्यपरिषद के गठन के लिए शिक्षा मंत्रालय से कई बार पत्राचार किया था। इधर, बीएचयू प्रबंधन इस बारे में कुछ भी कहने से इन्कार किया।

दो बार समय मांगने के बाद भी नियुक्ति नहीं कर पाया शिक्षा मंत्रालय

- शिक्षा मंत्रालय ने आठ जनवरी को एक सप्ताह का समय मांगा था। अदालत ने पांच फरवरी का समय दिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ
- मंत्रालय की ओर से फिर समय मांगा तो अदालत ने पांच मार्च तक का समय दिया, लेकिन नियुक्ति नहीं हो पाई
- 12 मार्च को हुई सुनवाई में हाई कोर्ट ने अंतिम तारीख देते हुए आगे समय देने से मना किया

> प्रतिवादियों की ओर से नियुक्ति को लेकर हुई प्रगति के बारे में कोई जानकारी दिए बिना बार-बार समय मांगा जा रहा है। केंद्र सरकार की ओर से पेश वकील व्यक्तिगत समस्याओं का हवाला देकर समय मांग रहे हैं। पिछली तीन सुनवाई में आश्वासन देने के बाद भी कोई कदम नहीं उठाया गया।
> – इलाहाबाद हाई कोर्ट की टिप्पणी

वाराणसी के रहने वाले आरटीआइ कार्यकर्ता हरिकेश बहादुर सिंह ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर बीएचयू के पूर्व कुलपति प्रो. सुधीर कुमार जैन पर अपने पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया था। अदालत ने 12 मार्च को सुनवाई में शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय की ओर से पेश वकीलों विवेक सिंह, एसपी सिंह और हेम प्रताप सिंह से कुलपति की नियुक्ति को लेकर हुई प्रगति के बारे में पूछा था। वकीलों ने जवाब देने के लिए समय मांगा, जिस पर अदालत ने नाराजगी जताते हुए आखिरी समय सीमा 16 अप्रैल तय कर दी।

देश के 11 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अब खाली है कुलपति की कुर्सी

नई दिल्लीः सिर्फ बीएचयू ही नहीं, बल्कि देश के 56 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से 11 में स्थायी कुलपति की कुर्सी खाली है। इनमें कवि गुरु रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित 104 साल पुराना विश्व भारती विश्वविद्यालय, बिहार का ख्यात नालंदा विश्वविद्यालय भी शामिल है। लंबे इंतजार के बाद मार्च महीने में वर्धा स्थित हिंदी विश्वविद्यालय, लखनऊ स्थित बाबा भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय और पुडुचेरी केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्थायी कुलपति की नियुक्ति हुई। इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय (दिल्ली), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय (मप्र), गढ़वाल विश्वविद्यालय (उत्तराखंड), केरल, सिक्किम, नगालैंड, लद्दाख व मणिपुर स्पोर्ट्स में अभी भी स्थायी कुलपति की कुर्सी रिक्त है। इन विश्वविद्यालयों में एक महीने से लेकर एक वर्ष से पद खाली पड़े हैं। वहीं शिक्षकों के 5100 से अधिक पद भी रिक्त हैं। रिक्त केंद्रीय विश्वविद्यालयों में सिर्फ कुलपति ही नहीं, बल्कि बड़ी संख्या में शिक्षकों के पद भी रिक्त हैं। 29 नवंबर 2024 को राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित जवाब में शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने बताया था कि शिक्षकों के 5,100 से अधिक पद रिक्त हैं।

शंभू, खनौरी के बाद सिंघु बार्डर से हटने लगे अवरोधक

सिंघु बार्डर स्थित कैरिजवे के बाकी बचे हिस्से से तीन से चार दिन में हटा लिए जाएंगे सभी अवरोधक

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

हरियाणा से सटे पंजाब के शंभू और खनौरी बार्डर के खुलने के बाद अब सिंघु बार्डर से भी अवरोध हटने शुरू हो गए हैं। करीब 13 महीने पहले किसानों के दिल्ली कूच एलान के बाद वाहनों की आवाजाही के लिए बंद किए गए सिंघु बार्डर की दोनों कैरिजवे को अब पूरी तरह से खोलने का काम गुरुवार से शुरू हो गया। हालांकि इस कैरिजवे के दोनों तरफ के दो-दो लेन व सर्विस लेन को 27 फरवरी 2024 को खोल दिया गया था। अवरोधकों के हटने से स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है। वहीं, दिल्ली से कुंडली आने-जाने कारोबारी भी इस कार्रवाई से काफी खुश हैं, क्योंकि अब उन्हें जाम में नहीं फंसना पड़ेगा।

बाहरी-उत्तरी जिला के एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि कैरिजवे के बाकी बचे हिस्से से सीमेंट के जर्सी बैरियर को हटाने का काम अगले तीन से चार दिनों में पूरा हो जाएगा। 11 फरवरी 2024 को सिंघु सीमा से पूरी तरह से वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई थी। कंटीले तार, सीमेंट के जर्सी बैरियर, बैरिकेड्स से सीमा सील होने से पैदल यात्रियों का भी एक ओर से दूसरे ओर तक पहुंचना मुश्किल हो गया था। 27 फरवरी 2024 को सिंघु बार्डर स्थित दोनों सर्विस रोड को वाहनों के आवाजाही के लिए खोल दिया गया था, लेकिन यहां स्थित कैरिजवे के दोनों तरफ के दो-दो लेन ही खोले गए थे। दो-दो लेन तभी से बंद थे।

सिंघु बार्डर स्थित कैरिज वे से अर्थमूवर से जर्सी बैरियर हटाते कर्मचारी। जागरण

केजरीवाल ने किसानों के खिलाफ रची साजिश: रवनीत बिट्टू

जागरण संवाददाता, लुधियाना: केंद्रीय रेल एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू ने किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल, सरवन सिंह पंधेर सहित अन्य किसान नेताओं व किसानों की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा की है। उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब के दौरे पर आए अरविंद केजरीवाल ने किसानों के खिलाफ साजिश रची है। आरोप लगाया कि लुधियाना पश्चिम सीट पर आगामी उपचुनाव के मद्देनजर शहरी लोगों को खुश करने के लिए किसानों के खिलाफ कार्रवाई की गई।

किसानों के खिलाफ कार्रवाई पर भड़की कांग्रेस ने आप को बताया किसान विरोधी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : कांग्रेस ने पंजाब में शंभू और खनौरी बार्डर पर लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे किसानों पर पुलिस कार्रवाई का विरोध करते हुए राज्य की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार के साथ ही भाजपा पर सियासी हमला बोला है। संसद परिसर में पंजाब के कांग्रेस सांसदों ने मान सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए हिरासत में लिए गए किसान नेताओं को तत्काल रिहा करने की मांग की। वहीं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने किसान नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की निंदा करते हुए आम आदमी पार्टी तथा भाजपा दोनों के बीच किसानों के खिलाफ अंदरूनी सांठगांठ होने का आरोप लगाया।

एमएसपी समेत किसानों की कुछ अन्य मांगों को लेकर काफी समय से शंभू तथा खनौरी बार्डर पर जारी धरना प्रदर्शन को पुलिस बल के सहारे हटाए जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए खरगे ने एक्स पर बयान जारी किया और कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि दो किसान विरोधी पार्टियों ने देश के अन्नदाता के विरोध में अब सांठगांठ कर ली है। पहले किसानों को पंजाब सरकार ने बातचीत के लिए बुलाया फिर उन्हें जबरन धरना स्थल से हटाया। खरगे ने कहा कि पंजाब पुलिस द्वारा वरिष्ठ किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल और सरवन सिंह पंधेर की जबरन हिरासत में लिए जाने की जितनी निंदा की जाए कम है। सत्ता के अहंकार में चूर भाजपा-आप दोनों ही किसानों की अपराधी रही हैं।

मान सरकार ने लुधियाना उपचुनाव के चलते खत्म कराया किसानों का मोर्चा

इन्द्रप्रीत सिंह • जागरण

- एक वर्ष से शंभू और खनौरी बार्डर पर चल मोर्चे को सिर्फ दो घंटे में हटा दिया गया

चंडीगढ़: 13 महीने से चुप बैठी पंजाब सरकार ने अचानक बुधवार को दो घंटे में खनौरी और शंभू बार्डर पर लगे किसानों के मोर्चे को जबरन हटा दिया। माना जा रहा है कि लंबे समय से धरना-प्रदर्शन के कारण किसानों के खिलाफ बना माहौल, व्यापारियों में बढ़ती नाराजगी और लुधियाना उपचुनाव के चलते सरकार ने इसे खत्म कराने का फैसला लिया।

जानकार बता रहे हैं कि यह फैसला एक दो दिन में नहीं लिया गया, बल्कि इस पर चार-पांच महीने से काम चल रहा था। गत तीन मार्च को भी दिल्ली कूच के लिए अड़े संयुक्त किसान मोर्चा (राजनीतिक) के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री भगवंत मान पहुंचे, लेकिन जब किसान नहीं माने तो वह बैठक बीच में छोड़कर चले गए थे। बाद में मुख्यमंत्री के निर्देशों पर उन्हें चंडीगढ़ कूच ही नहीं करने दिया गया। बड़े किसान नेता पहले ही हिरासत में ले लिए गए। इसका पंजाब भर में अच्छा रिस्पांस आया, क्योंकि राज्य भर में आम लोग, व्यापारी और उद्योगपति किसानों के धरनों से तंग आ चुके थे।

इसी बीच अरविंद केजरीवाल लुधियाना आए। लुधियाना पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र में इस समय उपचुनाव है। यहां पार्टी ने अपने राज्यसभा सदस्य संजीव अरोड़ा को मैदान में उतार दिया है। ऐसे में जीत का मार्ग प्रशस्त करने के लिए किसानों का मोर्चा खत्म करके रास्तों को खुलवाना जरूरी था।

तेजी से सिमटता लाल गलियारा

देश में नक्सलियों को खत्म करने के लिए जारी अभियान में केंद्र सरकार को बड़ी कामयाबी मिली है और अब लाल गलियारा सिकुड़ कर सिर्फ 38 जिलों में सीमित हो गया है। इन 38 जिलों में से 15 जिले छत्तीसगढ़ के हैं जो नक्सलवाद से प्रभावित हैं। 2010 से 2024 के बीच वामपंथी उग्रवाद की हिंसा में 73 प्रतिशत तक कमी आई है। केंद्र सरकार का दावा है कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद का पूरी तरह से सफाया हो जाएगा।

1,46,007 किलोमीटर सड़कें बनाई गई हैं नक्सल प्रभावित इलाकों में

₹1,120.32 करोड़ खर्च किए गए 2014 से 2025 के बीच सुरक्षा संरचना को मजबूत बनाने के लिए

178 एकलव्य माडल आवासीय विद्यालय शुरू किए गए हैं जनजातीय इलाकों में

89 थानों में बचे नक्सली

गृह मंत्रालय की 2024 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2010 में देश के 96 जिले और उनके 465 थाने घनघोर नक्सलवाद की चपेट में थे, वहीं 2024 में देश के 38 जिलों के 89 पुलिस स्टेशनों में नक्सलियों का प्रभाव बचा है।

नौ राज्यों में फैला था लाल गलियारा

लाल गलियारा यानी ऐसा क्षेत्र जहां नक्सली सक्रिय हैं। 2013 में लाल गलियारा उत्तर प्रदेश से लेकर आंध्र प्रदेश तक देश के नौ राज्यों में फैला था और नक्सलियों का प्रभाव करीब 8,80,000 वर्ग किलोमीटर में था। इस क्षेत्र में करीब 50 करोड़ आबादी रहती थी।

106 जिले थे नक्सलवाद से बुरी तरह प्रभावित 2013 में

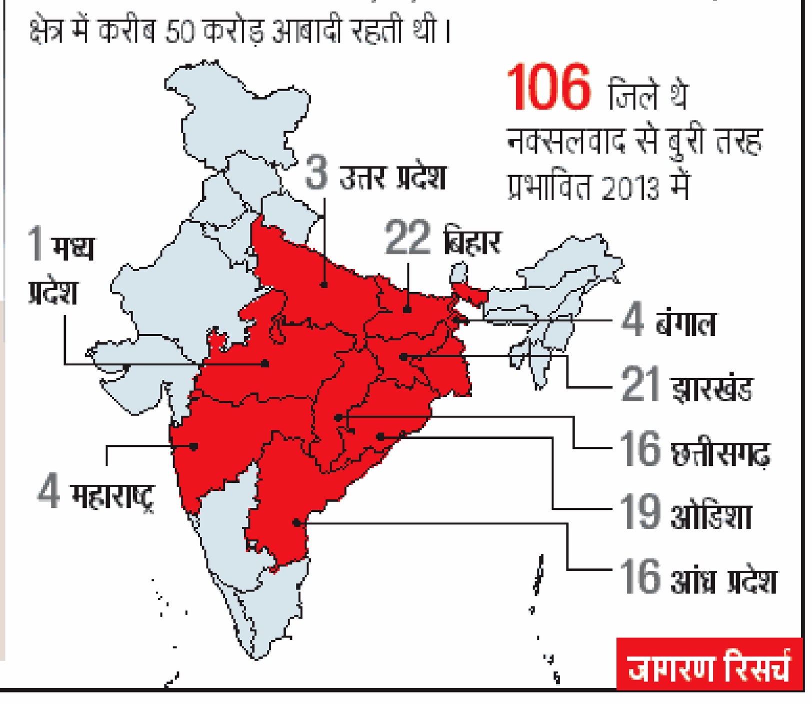

जागरण रिसर्च

... शंभू से राजपुरा तक की सड़क की हालत दयनीय

प्रथम पृष्ठ से आगे

13 महीने एक सप्ताह तक शंभू बार्डर पर चले किसान आंदोलन के दौरान किसानों की ओर से सड़क पर टेंट लगाने के लिए गड्ढे खोदने से नेशनल हाईवे की सड़क को दोनों तरफ से काफी नुकसान पहुंचा है। शंभू बार्डर से लेकर राजपुरा की तरफ करीब ढाई किलोमीटर तक की सड़क की हालत बेहद दयनीय है।

बुधवार को गिरफ्तार किए गए किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को बुधवार देर रात पहले जालंधर स्थित मेडिकल कालेज पिम्स में दाखिल कराया गया। गुरुवार को उन्हें भारी सुरक्षा के बीच जालंधर कैंट स्थित पीडब्ल्यूडी के गैस्ट हाउस में शिफ्ट कर दिया गया। यहां डल्लेवाल ने उपचार करवाने से इनकार कर दिया है। उधर, किसान नेता सरवन सिंह पंधेर सहित गिरफ्तार किए गए 101 किसानों को पटियाला सेंट्रल जेल भेजा गया है। इनमें 12 महिलाएं शामिल हैं। इसी तरह खनौरी से गिरफ्तार किए गए किसानों को खनौरी के हनुमान मैरिज पैलेस में खुली जेल में रखा गया है।

कुशीनगर : अवैध निर्माण पर एक और मस्जिद को नोटिस

जागरण संवाददाता, कुशीनगर

उत्तर प्रदेश में कुशीनगर के हाटा में नक्शे के विपरीत बनी मदनी मस्जिद के एक हिस्से को गिराए जाने के चर्चित मामले के बाद अब तमकुही के गड़हिया चिंतामन गांव में भी इसी तरह का एक मामला सामने आया है। यहां ग्राम पंचायत की भूमि पर अतिक्रमण कर मस्जिद और ईदगाह का निर्माण करा लिया गया है। प्रशासन ने गुरुवार को इसे ध्वस्त कराने के लिए नोटिस चस्पा किया। इसमें कहा गया है कि पक्षकार अवैध रूप से निर्मित मस्जिद और ईदगाह को स्वयं ध्वस्त करा लें, अन्यथा इसको ध्वस्त कराने के साथ ही व्यय होने वाली धनराशि की वसूली की जाएगी।

ग्रामवासी अरविंद किशोर शाही ने 23 सितंबर 2024 को जन सूचना अधिकार के तहत मस्जिद और ईदगाह निर्माण के संबंध में सूचना मांगी तो यह बात सामने आई कि जिस भूमि पर इसका निर्माण कराया गया है, वह गाटा संख्या 645 व 648, राजस्व अभिलेख में सार्वजनिक भूमि और रास्ते के रूप में अंकित है। उन्होंने सार्वजनिक स्थान को खाली कराने के लिए वाद दायर किया। 27 जनवरी 2025 को एसडीएम कोर्ट तमकुही की ओर से बेदखली का आदेश दिया गया। इसी आदेश के तहत तहसील कर्मियों ने गुरुवार को मस्जिद पर नोटिस चस्पा किया। इसमें 15 दिन के अंदर मस्जिद और ईदगाह को स्वयं गिरा लेने की बात कही गई है। मस्जिद के पक्षकार हाफिज साबिर अली ने कहा कि 15 वर्ष पूर्व तत्कालीन ग्राम प्रधान इस्लाम द्वारा निर्माण कराया गया था। इसको जल्द ध्वस्त करा लिया जाएगा। तीन नोटिस के बाद मस्जिद व ईदगाह को ध्वस्त करा दिया जाएगा।

ग्राम सभा की भूमि पर बनी अवैध मस्जिद व ईदगाह। जागरण

कठपुतली कला को बनाया माध्यम, बच्चों में बो रहे शिक्षा का संस्कार

जागरण विशेष
कठपुतली दिवस (21 मार्च)

सरकारी शिक्षक अतन शुक्ल का अध्यापन में नवाचार, तीन हजार से अधिक बच्चों का कर चुके हैं शैक्षिक संवर्धन

विनीत पांडेय • जागरण

सीतापुर: अंगुली के इशारे पर नाचती कठपुतली जब बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ का संदेश देती है तो बच्चे ही नहीं अभिभावक और ग्रामीण भी बेटियों की शिक्षा के महत्व को समझते हैं। गीत और कहानियों के माध्यम से कठपुतली गणित और विज्ञान जैसे कठिन विषयों को भी सहज तरीके से समझा देती है। कठपुतली से शैक्षिक गतिविधियों को रोचक बनाने का हुनर ही है कि सरकारी स्कूल के अध्यापक अतन शुक्ल कठपुतली वाले सरजी बन गए हैं।

बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षक अतन शुक्ल सीतापुर जिले के महोली विकासखंड में गणित विषय से एआरपी (अकेडमिक रिसोर्स पर्सन) हैं। यानी इस विषय के विशेषज्ञ शिक्षक जो विभिन्न स्कूलों में जाकर बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन, उनकी पहचान कठपुतली शिक्षक के रूप में है। उन्होंने कठपुतली को नवाचार का माध्यम बना लिया है। वह किसी स्कूल में बतौर प्रशिक्षक जाते हैं तो वहां कठपुतली के माध्यम से ही संवाद करना पसंद करते हैं। बच्चे भी कठपुतली की भाषा व भावों को बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। गीत, कहानी, इतिहास, विज्ञान, गणित आदि सभी कुछ बच्चे बहुत ही आसानी से समझ जाते हैं। स्थिति यह है कि उनके स्कूल में पहुंचते ही बच्चे कठपुतली वाले सर आ गए कहते हुए झूम उठते हैं। अतन शुक्ल बताते हैं कि 2019 में जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान में कठपुतली का प्रशिक्षण लिया। फिर तो यही माध्यम बन गया। एआरपी होने के कारण शुक्ल क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों में जाकर कठपुतली के माध्यम से पढ़ाने, अध्यापकों को प्रेरित करने लगे। अतन शुक्ल को विज्ञान व गणित पढ़ाने का व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए सरकार ने गुजरात भेजा, जहां से कठपुतली शिक्षा की विशेषज्ञता हासिल की।

विस्तार से पढ़ने के लिए स्कैन करें।

सीतापुर के महोली जूनियर हाई स्कूल में बच्चों को कठपुतली बनान सिखाते एआरपी अतन शुक्ल • साभार स्वयं

शिक्षा का हुआ सरलीकरण

जिला बेसिक शिक्षक अधिकारी अखिलेश प्रताप सिंह का कहना है कि नवाचार होने से शिक्षा का सरलीकरण हो रहा है। बच्चों में शिक्षा के प्रति रुचि पढ़ी है हमारे जनपद के एआरपी अतन शुक्ल, शिक्षिका सुचिता शर्मा व रुचि अग्रवाल ने शिक्षा के सरलीकरण के साथ-साथ जनजागरुकता का काम भी किया है। यह सराहनीय है। सरकारी स्कूलों के बच्चे भी कठपुतली शिक्षकों के व्यवहार के मुरीद हैं। पढ़ाई से बचने वाले बच्चे भी इनकी कक्षा में आने के लिए लालायित रहते हैं।

बच्चों को भी सिखाते कठपुतली बनाना

कठपुतली से पढ़ते बच्चे।

अतन शुक्ल बच्चों को कठपुतली बनाने व संचालन के बारे में भी बता चुके हैं। अब तक तीन हजार से अधिक बच्चों को विभिन्न कार्यशालाओं के माध्यम से प्रशिक्षित भी कर चुके हैं। कंपोजिट विद्यालय महोली प्रथम में छठी की रिमझिम व कक्षा सात की संजीवनी ने भी कठपुतली बनाना सीखा है।

कठपुतली से बच्चों ने किया 'अधूरा पुल' का मंचन

सीतापुर जिले में परिषदीय विद्यालय मदारपुर की शिक्षिका सुचिता शर्मा, बेहटा के पिडुरिया की रुचि अग्रवाल भी कठपुतली के माध्यम से जागरूक कर रही हैं। दोनों लोगों ने जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान से ही कठपुतली का प्रशिक्षण प्राप्त किया और इस कार्य को पूरी लगन से करने में जुट गईं। यूनीसेफ की ओर से आयोजित कार्यक्रम में वह कठपुतली को चलाने के लिए बच्चों को भी साथ ले गई थीं। बच्चों ने कठपुतली चलाते हुए संवाद भी बोले और 'अधूरा पुल' नाटक का मंचन किया। इसके अलावा अभिभावक शिक्षक संघ की बैठकों में भी बालिका शिक्षा जैसे मुद्दों को उठाकर प्रेरित करती हैं। कठपुतली का सहारा लेते हुए मीना मंच की विविध कहानियों के माध्यम से किशोरियों को महावारी, शिक्षा के महत्व जैसे गंभीर मुद्दों को समझाती हैं और उनको जागरूक करती हैं। अभिभावकों ने भी बेटियों की शिक्षा व उनके स्वास्थ्य संबंधी विषयों को गंभीरता से समझा और उस पर अमल भी कर रहे हैं। यूनीसेफ की टीम ने विद्यालय जाकर पोडकास्ट भी शूट किया था।

गरीब, मजबूर और भूखों के दर्द को समझने का महीना है रमजान

रमजान माह में दुनियाभर के करोड़ों मुसलमान दिनभर भूखे प्यासे रहकर अल्लाह की इबादत करते हैं। उपवास (रोजा) रखकर इंसान भूखे-प्यासे लोगों के दर्द को समझता है। उनके दुख को समझने का महीना रमजान है। इस महीने की इबादत से किसी अन्य महीने से कई गुना अल्लाह की दुआ हासिल होती है। हर मुसलमान इस महीने का एहतराम करता है। रमजान का मकसद यह है कि जब एक दौलतमंद, एक अमीर व्यक्ति जिसने कभी भूख और प्यास देखी नहीं, जब वह रमजान में रोजे रखेगा तो उसे एहसास-ए-भूख और प्यास होगा। जब उसे भूख और प्यास का एहसास होगा तो वह गरीब, मजबूर और भूखों के दर्द को समझेगा। इसीलिए इस्लाम ने रमजान में रोजे रखने के बाद फितरा देने का हुक्म दिया। गरीब दौलत वाले के घर उसे लेने नहीं जाता है। रोजे रखने के बाद फितरा देने का हुक्म इसलिए दिया गया है कि दौलत वालों को गरीब का दरवाजा दिखाया जा सके, जिससे वह उसकी मदद करता रहे, यही रमजान और इस्लाम का संदेश है। 11 महीने बाद रमजान का एक महीना आता है जिसमे ईमान वाला अपने ईश्वर को राजी करने व उसके कहे पर अमल करने के लिए रोजा रखता है।

मौलाना इरफान मियां फरंगी महली
काजी-ए-शहर

****

3 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है पिछले 24 घंटों के भीतर मणिपुर में सुरक्षा बलों ने। इनमें से दो के पास से हथियार और गोला-बारूद बरामद किया गया है।

पकड़ा गया छात्राओं के यौन शोषण का आरोपित असिस्टेंट प्रोफेसर

राष्ट्रीय महिला आयोग के निर्देश पर दर्ज हुई थी प्राथमिकी

कंप्यूटर पर स्पाई कैम लगाकर करता था रिकार्डिंग

जागरण संवाददाता, हाथरस

पुलिस की हिरासत में छात्राओं के यौन शोषण का आरोपित डा. रजनीश(मध्य में)। जागरण

उत्तर प्रदेश के हाथरस में पीसी बागला कालेज की छात्राओं का यौन शोषण करने का आरोपित असिस्टेंट प्रोफेसर व चीफ प्राक्टर डा. रजनीश को पुलिस ने प्रयागराज से गिरफ्तार किया है। सात दिन से पुलिस उसकी तलाश में लगी थी। पूछताछ में उसने छात्राओं का यौन उत्पीड़न कर वीडियो बनाने की बात स्वीकार की है। वह न्यायालय से अग्रिम जमानत प्राप्त करने के लिए प्रयागराज पहुंचा था। पुलिस आरोपित को स्थानीय न्यायालय में पेश करेगी, जहां से जेल भेजा जाएगा।

एसपी चिरंजीव नाथ सिन्हा ने बताया कि डा. रजनीश की शादी 1996 में हुई थी, लेकिन कोई संतान नहीं हुई। दूसरी शादी के लिए उसने अन्य लड़कियों से संपर्क किया। एक लड़की से रिश्ते की बात शुरू हुई। एक दिन वह रजनीश के घर पर आई। उसने लड़की के साथ संबंध बना लिए, मगर उससे रजनीश का विवाह नहीं हो सका। यह घटना उसने कंप्यूटर के वेबकैम में कैद कर ली। उसने कंप्यूटर व मोबाइल फोन में एक साफ्टवेयर अपलोड किया है, जिससे स्क्रीन पर रिकार्डिंग नहीं दिखती थी, जबकि स्पाई कैम के जरिये घटना रिकार्ड हो जाती थी। इसके बाद से उसने छात्राओं व अन्य महिलाओं से संबंध बनाना और उसे रिकार्ड करना शुरू कर दिया। उसने कालेज की एक चतुर्थ श्रेणी महिला कर्मचारी को भी अपना प्रभाव दिखाकर जाल में फंसाया और कई बार यौन शोषण कर वीडियो बनाया। इसके बाद छात्राओं को उच्चतर कोर्स में दाखिला दिलाने, नौकरी लगवाने व परीक्षा में अच्छे अंक से पास कराने का प्रलोभन देकर फंसाता था। बदले में महंगे गिफ्ट और पैसे भी देता था। अपने कालेज के आफिशियल चेंबर में शारीरिक संबंध बनाता था और छात्राओं की जानकारी के बगैर साफ्टवेयर की मदद से अश्लील वीडियो बनाता था।

डा. रजनीश पर 13 मार्च को दुष्कर्म समेत अन्य धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। आयोग को गुमनाम छात्रा ने शिकायती पत्र और सीडी भेजी थी। छात्रा का आरोप था कि डा. रजनीश प्रयोगात्मक परीक्षाओं में फेल करने का डर व नौकरी लगवाने का प्रलोभन देकर यौन शोषण और दुष्कर्म करता है।

देश के अनेक विश्वविद्यालयों की फर्जी मार्कशीट बनाने वाला पकड़ा गया

जागरण संवाददाता, आगरा

▸ ओपन यूनिवर्सिटी की आड़ में बनाता था फर्जी मार्कशीट-डिग्री, ढाई लाख फीस लेकर दी जाती थी सत्यापन की गारंटी, एसटीएफ ने किया भंडाफोड़

देश के अनेक विश्वविद्यालयों की फर्जी मार्कशीट बनाने वाला गिरोह पकड़ा गया है। ओपन यूनिवर्सिटी की आड़ में नकली मार्कशीट-डिग्री बनाने का खेल चल रहा था। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय ओपन यूनिवर्सिटी (इग्नू) समेत देश की नामचीन प्राइवेट यूनिवर्सिटी की मार्कशीटें बनाई जा रही थीं। युवाओं को सत्यापन की गारंटी भी दी जाती थी। सरगना ने पूछताछ में स्वीकार किया है कि नकली मार्कशीट बनवाने वाले 300 से ज्यादा युवा सरकारी नौकरी पा चुके हैं।

धनेश मिश्रा। सौ. पुलिस

विभिन्न प्रदेशों के 40 विश्वविद्यालयों की 900 से ज्यादा तैयार मार्कशीट-डिग्री बरामद हुई हैं। नोटपैड एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के आफिस में फर्जी मार्कशीट बनाई जा रही थीं। यहां मेरठ स्थित सुभारती विश्वविद्यालय, अलीगढ़ स्थित मंगलायतन विश्वविद्यालय और सिक्किम ओपन यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशन और परीक्षा फार्म भरवाए जाते हैं। बुधवार रात एसटीएफ इंस्पेक्टर हुकुम सिंह के नेतृत्व में टीम ने छापा मारकर कंपनी के सीईओ धनेश मिश्रा को गिरफ्तार किया। आफिस में देशभर के निजी विश्वविद्यालयों की तैयार 944 मार्कशीट और 104 खाली मार्कशीट बरामद हुई। धनेश ने बताया कि वह डिमांड पर निजी विश्वविद्यालयों की मार्कशीट और डिग्री बनाकर देता है। अब तक आठ हजार से अधिक मार्कशीट और डिग्री बना चुका है। प्रोफेशनल कोर्स बीफार्मा, डीफार्मा, एमबीए आदि की मार्कशीट और डिग्री दो से ढाई लाख रुपये में दी जाती थी। बीए-बीकाम की मार्कशीट की 20 से 50 हजार रुपये फीस थी। फर्जी अंकपत्र व डिग्री के सहारे अब तक 300 से अधिक युवा सरकारी नौकरी कर रहे हैं। बरामद मार्कशीट में एक मनीष कुमार के नाम से साबरमती विश्वविद्यालय की तैयार डिग्री, सोमेश उपाध्याय सहित अन्य के नाम से महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी का अंकपत्र व डिग्री, रवींद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय का तैयार माइग्रेशन प्रमाणपत्र मिले।

मिनी ब्राजील की असली कहानी : फिर छिड़ी बात तो छलक पड़ा खिलाड़ियों का दर्द

पांवों के जोर से बदलते 'विचारपुर' की पहचान को नहीं लगे पंख

विनोद कुमार शुक्ला ● नईदुनिया

स्टेडियम का सपना दिखाया गया था खिलाड़ियों को... ऊबड़-खाबड़ मैदान में करना पड़ रहा है अभ्यास। नईदुनिया

100 से अधिक खिलाड़ी स्कूल गेम और ओपन में राष्ट्रीय स्तर तक खेल चुके हैं, लेकिन उसके आगे नहीं पहुंच पा रहा है कोई

शहडोल: मध्य प्रदेश के शहडोल संभागीय मुख्यालय से पांच किलोमीटर दूर स्थित आदिवासी बहुल गांव विचारपुर एक बार फिर चर्चा में आ गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हाल ही में पाडकास्ट को दिए एक इंटरव्यू में विचारपुर गांव के फुटबाल खिलाड़ियों की तारीफ करते हुए विचारपुर को फुटबाल की नर्सरी और मिनी ब्राजील बताया। गांव के खिलाड़ियों, खासकर बेटियों को खूब सराहा। निश्चित रूप से पांवों के जोर से विचारपुर गांव की पहचान बदल रही है, लेकिन प्रधानमंत्री के संज्ञान आने के बाद जो बदलाव की उम्मीद थी, वह नहीं हो पाई जिससे खिलाड़ियों में निराशा है।

एक जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री शहडोल के पकरिया गांव में आदिवासियों के बीच चौपाल शामिल में हुए थे, तभी विचारपुर के खिलाड़ियों से मुलाकात की थी। उसके बाद अगस्त 2024 में यहां खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने खेलो इंडिया स्माल सेंटर चालू तो किया, लेकिन यहां सुविधाओं की भारी कमी है। सेंटर में खिलाड़ियों को फुटबाल और किट भी नहीं मिल रही है। यहां स्थानीय स्तर पर अस्थाई कोच लक्ष्मी सहीश को नियुक्त किया गया है। वर्तमान में यहां चालीस खिलाड़ी असुविधाओं के बीच प्रशिक्षण ले रहे हैं, जिसमें 20 बालक व 20 बालिकाएं शामिल हैं। वह खुद भी मानती हैं कि इतनी नैसर्गिक प्रतिभा होने क बावजूद खिलाड़ियों को न उस स्तर का मार्गदर्शन मिल रहा है न ही मौका।

विचारपुर गांव को फुटबाल खिलाड़ियों की पौधशाला के नाम से जाना जाता है, इस गांव के 100 से अधिक खिलाड़ी स्कूल गेम और ओपन में राष्ट्रीय स्तर तक खेल चुके हैं, लेकिन इस बात का मलाल सभी को है कि आज तक एक भी खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख टीम तक नहीं पहुंच पाया है। इसका सबसे बड़ा कारण सुविधाओं की कमी है। इससे आगे बढ़ने के लिए उन्हें फुटबाल का मैदान और राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण की जरूरत है। पीएम जब शहडोल के दौरे पर आए थे, तो उस समय विचारपुर में फुटबाल स्टेडियम बनाए जाने की बात शुरू हुई और इसके लिए सात एकड़ जमीन भी चिह्नित कर ली गई है, लेकिन अभी मैदान पुरानी स्थिति में ही है। जब खिलाड़ी मैदान से बाहर होते हैं, तो वहां मवेशियों का जमघट रहता है। ऊबड़-खाबड़ मैदान है, जिसमें खिलाड़ी अभ्यास कर रहे हैं। जमीन आवंटित होने के बाद भी प्रदेश सरकार स्टेडियम की घोषणा नहीं कर पाई। खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने स्टेडियम का प्रस्ताव सरकार को भेज दिया और कई बाद पत्राचार भी किया गया पर अभी तक कोई पहल नहीं हुई है। राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर किसी खिलाड़ी को प्रशिक्षण के लिए भेजने की कोई योजना भी नहीं बनी है।

प्रतिभा को नहीं मिल रही राह

750 की आबादी वाले गांव में 100 फुटबाल खिलाड़ी

20 बालक और 20 बालिकाएं वर्तमान में ले रहीं हैं ट्रेनिंग

- मप्र खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने स्टेडियम का प्रस्ताव सरकार को भेजा लेकिन अभी तक कोई पहल नहीं

उत्साह में कोई कमी नहीं ...कोई राह तो दिखाए।

प्रधानमंत्री ने विचारपुर गांव के फुटबाल खिलाड़ियों की सराहा, जिससे बहुत खुशी हो रही है। यदि विचारपुर को मिनी ब्राजील बनाना है तो खेल मैदान और खान-पान व प्रशिक्षण की सुविधाएं बढ़ानी होंगी। सुविधाओं की कमी के कारण यहां के खिलाड़ी स्कूल गेम नेशनल व राज्य स्तर तक ही खेल पा रहे हैं। आगे बढ़ाना है तो सुविधाएं भी बढ़ानी होंगी।

-लक्ष्मी सहीश, खेलो इंडिया सेंटर की कोच

असुविधाओं के बीच खेलते हुए हम लोग प्रदेश की टीम तक पहुंच रहे हैं। स्टेडियम सहित अन्य सभी सुविधाएं यदि यहां पर मिलने लगे तो विचारपुर के खिलाड़ी राष्ट्रीय टीम में पहुंच सकते हैं।

-रोशनी सिंह, राष्ट्रीय खिलाड़ी

प्रधानमंत्री ने विचारपुर के खिलाड़ियों का नाम पूरी दुनिया में फैला दिया, इससे अपार खुशी है। यह खुशी और ज्यादा हो जाएगी, जब अच्छे प्रशिक्षण की वजह से हम सब राष्ट्रीय स्तर पर खेल सकेंगे।

-दिव्या सिंह, राष्ट्रीय खिलाड़ी

विचारपुर खेल मैदान में सुविधा तो दूर चेंजिंग रूम तक नहीं बना है। मैं देश के लिए खेलना चाहता हूं, लेकिन सुविधाओं के अभाव में उस स्तर पर तैयारी नहीं कर पा रहा हूं। कैसे देश की टीम में पहुंच पाऊंगा?

-हेमचंद्र गजिया, राष्ट्रीय खिलाड़ी

मैं चार साल से नियमित फुटबाल की विभिन्न प्रतियोगिताओं में खेल रहा हूं। एक नेशनल भी खेल चुका हूं। विचारपुर में खेल मैदान तक व्यवस्थित नहीं है। यहां सुविधाओं की कमी के कारण खिलाड़ी पूरी तरह प्रशिक्षण प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। - दुर्गेश सिंह, राष्ट्रीय खिलाड़ी

- सात एकड़ जमीन चिह्नित, लेकिन अब तक नहीं बन पाया फुटबाल स्टेडियम
- ऊबड़-खाबड़ जमीन पर खिलाड़ियों को करना पड़ रहा है अभ्यास

यहां खेल मैदान के निर्माण व अन्य सुविधाओं के लिए लगातार प्रस्ताव भेजे गए हैं। तत्कालीन कमिश्नर राजीव शर्मा जब तक थे तो कुछ उम्मीद बंधी थी कि फुटबाल का स्टेडियम बनेगा। उनके प्रयास से जमीन आवंटित हुई, लेकिन उसके बाद वे चले गए और अब सब काम रुका है।

-अजय सोंधिया, ब्लाक समन्वयक सोहागपुर, खेल एवं युवा कल्याण विभाग

2002 से विचारपुर के खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देते आ रहा हूं और कई खिलाड़ी प्रदेश की टीम में खेल चुके हैं। विचारपुर के खिलाड़ियों को खेल मैदान और बेहतर प्रशिक्षण की सुविधाएं मिले तो अच्छे खिलाड़ी निकलेंगे। अभी तो सिर्फ चर्चा हो रही है जमीनी हकीकत अलग है। आगे योजनाएं सरकार के निर्णय पर निर्भर हैं। हम तो लगातार प्रस्ताव भेज रहे हैं।

-रईस खान, कोच एवं सहायक संचालक शिक्षा विभाग, शहडोल, मध्य प्रदेश

फुटबाल क्रांति का प्रथम चरण सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया। अब अगले चरण के लिए सरकार समाज सभी को मिलकर आगे आना चाहिए। विचारपुर के लिए सरकार को विशेष प्रोजेक्ट लाना चाहिए ताकि वहां के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिले। फुटबाल क्रांति तब सफल होगी जब मध्यप्रदेश के युवाओं को सम्मान और रोजगार के अवसर मिलेंगे।

-राजीव शर्मा, सेवानिवृत्त संभागायुक्त

फ्रांसीसी महिला के यौन उत्पीड़न में पर्यटक गाइड गिरफ्तार

तिरुवन्नामलई, प्रेट्र : तमिलनाडु के तिरुवन्नामलई शहर में एक फ्रांसीसी महिला से यौन उत्पीड़न के आरोप में एक पर्यटक गाइड को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपित की पहचान 42 वर्षीय वेंकटेशन के रूप में हुई है, जो फ्रांसीसी नागरिक को ध्यान करने के लिए अरुणाचला पहाड़ी की चोटी पर ले गया था और वहां कथित तौर पर उसका यौन उत्पीड़न किया।

46 वर्षीय पीड़िता ने शोर मचाया तो वहां से गुजर रहे श्रद्धालुओं ने उसकी मदद की। पीड़िता ने फ्रांसीसी वाणिज्य दूतावास को घटना की सूचना दी, जिसने स्थानीय अधिकारियों के समक्ष यह मामला उठाया।

इसके बाद महिला पुलिस ने बुधवार को वेंकटेशन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ से पता चला है कि वह जनवरी में आध्यात्मिक यात्रा पर आई थी और गाइड उसे विभिन्न आश्रमों में ले गया। पुलिस ने बताया कि वह यहां एक प्राइवेट लाज में रह रही थी।

'वक्ष स्पर्श करना दुष्कर्म नहीं' पर बढ़ा विवाद

जागरण संवाददाता, प्रयागराज

▸ राज्यसभा सदस्य रेखा शर्मा ने कहा- सुप्रीम कोर्ट जाए महिला आयोग

▸ हाई कोर्ट के एक न्यायाधीश ने कहा था कि यह गंभीर यौन उत्पीड़न है

इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक न्यायाधीश के इस निर्णय पर कि नाबालिग के वक्ष का स्पर्श और वस्त्र का नाड़ा तोड़ना दुष्कर्म का अपराध नहीं है, पर राज्यसभा सदस्य रेखा शर्मा ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा कि यह गलत है और राष्ट्रीय महिला आयोग को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। गुरुवार को समाचार एजेंसी एएनआइ से बात करते हुए उन्होंने कहा-'अगर न्यायाधीश संवेदनशील नहीं हैं, तो महिलाएं और बच्चे क्या करेंगे? उन्हें इस कृत्य के पीछे की मंशा को देखना चाहिए। यह पूरी तरह से गलत है और मैं इसके खिलाफ हूं।''

इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्र की एकल पीठ ने इसे दुष्कर्म का अपराध न मानते हुए 'गंभीर यौन उत्पीड़न' माना है। कासगंज के स्पेशल जज (पाक्सो कोर्ट) का समन आदेश संशोधित करते हुए नए सिरे से समन करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि दुष्कर्म के आरोप में जारी समन विधिसम्मत नहीं है। कासगंज के पटियाली थाने में आइपीसी की धारा 376 और पाक्सो अधिनियम की धारा 18 के तहत मुकदमे का सामना करने के लिए याची आकाश, पवन व अशोक को तलब किया गया था। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि आरोपितों के खिलाफ धारा 354-बी आइपीसी (निर्वस्त्र करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग) के मामूली आरोप के साथ पाक्सो अधिनियम की धारा 9/10 (गंभीर यौन हमला) के तहत मुकदमा चलाया जाए।

कोर्ट ने आपराधिक पुनरीक्षण याचिका आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए कहा, 'पवन और आकाश के खिलाफ लगाए गए आरोप और मामले के तथ्य इस मामले में दुष्कर्म का अपराध नहीं बनाते हैं।' अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपियों ने 11 वर्षीय पीड़िता के वक्ष पकड़े, उसका नाड़ा तोड़ दिया और उसे पुलिया के नीचे खींचने की कोशिश की, लेकिन राहगीरों/गवाहों के हस्तक्षेप के कारण उसे छोड़ कर मौके से भाग निकले।

इलाहाबाद हाई कोर्ट।

इंटरनेट मीडिया यूजर ने भी निर्णय को आड़े हाथों लिया

इंटरनेट मीडिया यूजर ने भी इस निर्णय को आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस की इंटरनेट मीडिया प्रभारी सुप्रिया श्रीनेत ने सवाल उठाया कि 11 साल की उस बच्ची के साथ क्या यह न्याय है? एक यूजर ने एक्स प्लेटफार्म पर लिखा, 'अब हम भरोसा किसपे करें'। एक यूजर ने कहा कि ये बिल्कुल न्यायोचित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेते हुए इस फैसले को खारिज करना चाहिए। इसी तरह की अन्य प्रतिक्रियाएं हैं।

72 वर्ष के बुजुर्ग को दुष्कर्म के मामले में सश्रम आजीवन कारावास

राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता : बंगाल की उत्तर 24 परगना के बारासात की पाक्सो अदालत ने किशोरी से दुष्कर्म के मामले में 72 वर्ष के बुजुर्ग को दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जिसका भुगतान नहीं करने पर और छह महीने की सजा होगी। दोषी व्यक्ति का नाम अरुण दास है। यह वारदात 12 फरवरी, 2017 को कोलकाता से सटे उत्तर 24 परगना जिले के हाबरा इलाके में हुई थी। पीड़िता वहां अपने एक रिश्तेदार के घर घूमने गई थी। घटना वाले दिन घर में कोई नहीं था। मौके का फायदा उठाकर पड़ोस में रहने वाले अरुण दास ने उसे अपने घर बुलाया और फिर बहला-फुसलाकर एक बगान में ले गया, वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बारे में किसी को बताने पर उसे जान से मारने की धमकी दी। डर के मारे किशोरी ने किसी को नहीं बताया। दो दिन बाद उसकी तबीयत खराब हो गई। रिश्तेदारों को संदेह हुआ। उन्होंने जोर देकर पूछा तो किशोरी ने सारी बातें बता दी।

सट्टेबाजी एप के प्रमोशन में दग्गुबती, प्रकाश राज, देवरकोंडा पर केस

▸ मांचू लक्ष्मी व निधि अग्रवाल का भी नाम शामिल, 19 इंटरनेट मीडिया इंफ्लूयेंसरों के खिलाफ भी पुलिस ने केस दर्ज किया

हैदराबाद, प्रेट्र : सट्टेबाजी के ऐप के विज्ञापन कर उसे बढ़ावा देने के आरोप में दक्षिण भारत के कई फिल्मी सितारों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। आनलाइन सट्टेबाजी को बढ़ावा देने में तेलुगु सिनेस्टार राणा दग्गुबती, प्रकाश राज व विजय देवरकोंडा समेत छह तेलुगु फिल्मी सितारों, 19 इंटरनेट मीडिया इंफ्लूयेंसरों के खिलाफ भी पुलिस ने केस दर्ज किया है।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार साइबराबाद की मियांपुर पुलिस ने सट्टेबाजी ऐप्स को बढ़ावा देने के आरोप में राणा दग्गुबती, प्रकाश राज, विजय देवरकोंडा, अभिनेत्री मांचू लक्ष्मी और निधि अग्रवाल सहित कई तेलुगु कलाकारों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

जिन प्रभावशाली लोगों पर मामला दर्ज किया गया है उनमें अनन्या, श्रीमुखी, सिरी हनुमंथु, श्यामला, वर्षिनी, शोभा, नेहा, पांडु, पद्मावती, इमरान खान, विष्णु प्रिया, हर्ष साई, सनी यादव, टेस्टी तेजा और रितु शामिल हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि पुलिस ने उन पर धारा 318(4), 112 आर/डब्ल्यू 49 बीएनएस, 3, 3(ए), 4 टीएसजीए और आइटी अधिनियम, 2000 की 66डी के तहत आरोप लगाए हैं।

राणा दग्गुबती, प्रकाश राज व विजय देवरकोंडा।

शिकायतकर्ता व 32 वर्षीय व्यवसायी फणीन्द्र शर्मा ने कहा कि अभिनेता और इंटरनेट मीडिया के प्रभावशाली लोग जानबूझकर सट्टेबाजी में लिप्त होने का समर्थन कर रहे हैं, जिससे युवाओं का नैतिक पतन और भ्रष्टाचार हो रहा है। इससे कई लोग गंभीर वित्तीय संकट में घिरे हैं। इससे मध्यम वर्ग के परिवार तबाह हो रहे हैं।

कैंसर और जेनेटिक रोगों के स्वदेशी इलाज होगा संभव

हैदराबाद, रायटर : कैंसर और गंभीर जेनेटिक रोगों का स्वदेशी थेरेपी से कम खर्च में इलाज संभव हो सकेगा। वैक्सीन बनाने वाली भारतीय कंपनी भारत बायोटेक ने तेलंगाना में पहली सेल और जीन थेरेपी (सीजीटी) केंद्र की शुरुआत की है। कंपनी ने इसके लिए साढ़े सात करोड़ डालर निवेश किया है। भारत बायोटेक ने गुरुवार को कहा, अगले तीन वर्षों में भारतीय बाजार में थेरेपी की दवा आने की उम्मीद है। कंपनी जटिल सेल और जीन थेरेपी क्षेत्र पर जोर दे रही है, क्योंकि बाजार अनुसंधान कंपनी प्रेसेडेंस रिसर्च के अनुसार सेल और जीन थेरेपी के बाजार के 2024 में 21.28 अरब डालर से पांच गुना से अधिक बढ़कर 2034 तक 117.46 अरब डालर तक पहुंचने का अनुमान है। कंपनी के चीफ डेवलपमेंट आफिसर राचेस एला ने कहा कि यह केंद्र, जिसमें कंपनी और अधिक निवेश कर सकती है, अगले तीन महीनों में चालू हो जाएगी। एला के मुताबिक, कंपनी दो सेल थेरेपी और तीन जीन थेरेपी पर काम कर रही है।

हाई कोर्टकी फटकार के बाद बदले नियम, अनुसूचित जाति के लोगों ने की पूजा

राज्य ब्यूरो, जागरण ● कोलकाता

▸ पूर्व बर्द्धमान के बाद नदिया जिले के एक शिव मंदिर में मिला पूजा करने का अधिकार

बंगाल के पूर्व बर्द्धमान के बाद अब नदिया जिले के एक शिव मंदिर में अनुसूचित जाति (एससी) के लोगों को पूजा करने का अधिकार मिला है। कलकत्ता हाई कोर्ट की फटकार के बाद वहां के एक शिव मंदिर के नियम बदल दिए गए, दशकों बाद इस वर्ग के लोगों ने मंदिर में पूजा-अर्चना की। पूर्व बर्द्धमान के कटवा अंचल के गिद्धग्राम में दास समुदाय के लोगों को शिव मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था। प्रशासन के हस्तक्षेप से वह मामला सुलझा था, जिसके बाद दास समुदाय के पांच लोगों ने मंदिर के गर्भगृह में जाकर पूजा-अर्चना की थी। अब नदिया के बैरमपुर स्थित शिव मंदिर में अनुसूचित जाति के लोगों को पूजा नहीं करने देने का मामला हाई कोर्ट के हस्तक्षेप से सुलझा है।

मालूम हो कि अनुसूचित जाति के लोगों ने हाई कोर्ट में मामला कर कहा था कि उन्हें गाजन त्योहार के दौरान मंदिर में प्रवेश करने और संन्यासी बनने के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। हाई कोर्ट ने कहा कि इस तरह का भेदभाव मानवाधिकारों का उल्लंघन है। अदालत ने पुलिस को भी फटकार लगाई थी। कोर्ट की फटकार के बाद मंदिर के नियम बदल दिए गए।

कलकत्ता हाई कोर्ट।

गुरुवार को रजक व धोपा समुदाय के सदस्यों ने पुलिस सुरक्षा में मंदिर में पूजा-अर्चना की। जया दास ने कहा-'मेरे दादा-दादी मंदिर में प्रवेश नहीं कर सके। आज हमने इतिहास रच दिया। यह हमारी गरिमा की लड़ाई की जीत है।' सीमा दास ने कहा-'आज पहली बार मुझे लगा कि हम भी इस समाज का हिस्सा हैं।'

बिहार में शिक्षा विभाग ने दो मृत शिक्षकों से अनुपस्थिति पर मांगा स्पष्टीकरण

जासं, धमदाहा (पूर्णिया) : बिहार में एक शिक्षक का चार माह तो एक का छह माह पूर्व निधन हो गया। स्वजन ने उनका संस्कार भी कर दिया है, लेकिन शिक्षा विभाग इन्हें मृत मानने को तैयार नहीं है। विभाग ने दोनों मृत शिक्षकों से स्पष्टीकरण मांगा है कि वह स्कूलों से अनुपस्थित क्यों चल रहे हैं। इस संबंध में संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक भी उदासीन बने हुए हैं। उन्होंने भी अधिकारियों को मृत शिक्षकों के बारे में सूचना देना जरूरी नहीं समझा। यही हाल जेल में बंद एक अन्य शिक्षक का भी है। उनसे भी अनुपस्थिति को लेकर विभाग ने जवाब तलब किया है।

जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) प्रफुल कुमार मिश्र ने बताया कि इस संबंध में संबंधित विद्यालयों के प्रधानों द्वारा विभाग को सूचना नहीं दी गई है। इस कारण यह स्थिति पैदा हुई है। जल्द ही इसमें सुधार किया जाएगा। पूर्णिया जिले के धमदाहा प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय गछकट्टा के शिक्षक अखिलेश मंडल का निधन चार माह पूर्व हो चुका है।

****

रुपये नहीं दिए तो किन्नरों ने युवक को ट्रेन में पीटकर मार डाला

नईदुनिया प्रतिनिधि, विदिशा

▸ भोपाल से विदिशा जा रहे युवक के साथ गोंडवाना एक्सप्रेस में अंजाम दी गई वारदात

▸ वीडयो बहुप्रसारित हुआ तो स्वजन को हुई घटना की जानकारी, पुलिस के पास पहुंचे

गोंडवाना एक्सप्रेस ट्रेन के अंदर मध्य प्रदेश के विदिशा के युवक की किन्नरों ने रुपये न देने पर पीटकर हत्या कर दी और शव को गंजबासौदा में नीचे फेंक दिया। ट्रेन के अंदर युवक की पिटाई का वीडियो बहुप्रसारित हुआ तो उसके स्वजन को सच्चाई का पता चला। वीडियो में कुछ किन्नर युवक को बर्थ से नीचे गिराकर उसके ऊपर कूदते दिख रहे हैं। कपड़े उतारकर उसके ऊपर बैठ रहे हैं। 13 मार्च को अंजाम दी गई वारदात में हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग स्वजन ने पुलिस अधीक्षक से की है।

आदर्श। स्वजन

युवक की पहचान विदिशा की अयोध्या बस्ती के आदर्श विश्वकर्मा के रूप में हुई है। गुरुवार को उसके भाई सोहन ने स्वजन के साथ पुलिस अधीक्षक को बताया कि आदर्श भोपाल में हमीदिया रोड पर इलेक्ट्रिक दुकान में काम करता था। वह ट्रेन से भोपाल और विदिशा आता-जाता था। स्वजन ने कहा है कि 13 मार्च की रात आदर्श भोपाल से गोंडवाना एक्सप्रेस से विदिशा घर लौट रहा था, तभी भोपाल से ट्रेन में चढ़े किन्नरों ने सलामतपुर, सांची के पास उससे रुपये मांगे।

आदर्श ने इन्कार किया तो किन्नरों ने उसकी जेब में हाथ डाल दिया। उसने विरोध किया तो आठ से 10 किन्नरों ने उस पर हमला कर पिटाई शुरू दी। ट्रेन विदिशा में रुकी तो उसे उतरने भी नहीं दिया और गंजबासौदा के पास पवई तरफ ट्रेन से नीचे फेंक दिया। स्वजन अगले दिन गंजबासौदा पहुंचे। वहां जीआरपी से पता चला कि पवई के पास शव पड़ा है।

बीआरएस विधायक को हाई कोर्ट से राहत, फोन टैपिंग मामला रद

हैदराबाद, प्रेट्र : बीआरएस के वरिष्ठ नेता और विधायक टी. हरीश राव को तेलंगाना हाई कोर्ट ने गुरुवार को बड़ी राहत दी। हाई कोर्ट ने फोन टैपिंग के आरोपों पर पिछले साल उनके खिलाफ दर्ज किए गए दर्ज मामले को रद कर दिया। शिकायतकर्ता जी. चक्रधर गौड़ के आरोप पर पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन में हरीश राव और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

शिकायतकर्ता ने पिछली बीआरएस सरकार के दौरान मंत्री और पूर्व सीएम के.चंद्रशेखर राव के भतीजे हरीश पर उनकी और उनके सहयोगियों और परिवार के सदस्यों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए राज्य की खुफिया जानकारी का ''दुरुपयोग'' करने का आरोप लगाया था। बाद में हरीश ने प्राथमिकी को अवैध और राजनीति से प्रेरित बताते हुए इसे रद करने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अदालत ने दलीलें सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था और गुरुवार को प्राथमिकी रद कर दी।

दैनिक जागरण
जिज्ञासा ही ज्ञान की दिशा में उन्मुख करती है

हठधर्मी का नतीजा

पंजाब-हरियाणा सीमा पर एक वर्ष से अधिक समय तक दो प्रमुख रास्तों को रोककर धरना दे रहे किसानों को जबरन हटाकर पंजाब सरकार ने वही किया, जो उसे बहुत पहले करना चाहिए था। किसानों के इस धरने के कारण न केवल आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, बल्कि व्यापारियों को अच्छा-खासा नुकसान भी उठाना पड़ रहा था। चूंकि किसान नेता सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद भी अपना हठ छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार के पास रास्ते खाली कराने के अलावा और कोई उपाय नहीं रह गया था। यह वही आम आदमी पार्टी है, जिसने एक समय कृषि कानूनों के विरोध में जबरन दिल्ली घेर कर बैठे किसानों का हर तरह से समर्थन किया था। यह अच्छा है कि उसने मजबूरी में ही सही, अपने राजधर्म को समझा। यह समय की मांग है कि किसान नेता भी यह समझें कि हठधर्मिता दिखाने से उनकी समस्याओं का समाधान होने वाला नहीं है। उन्हें यह भी समझना होगा कि यदि कोई अपनी मांगें मनवाने के लिए जानबूझकर लोगों को परेशान करने वाले तौर-तरीके अपनाता है तो वह जनता की सहानुभूति खो देता है और सरकारों के लिए उनकी मांगों पर विचार करना भी कठिन हो जाता है।

किसान संगठन अपनी अन्य अनेक मांगों समेत सभी फसलों की एमएसपी पर खरीद की गारंटी वाला कानून चाहते हैं। उनका मानना है कि सरकार के लिए ऐसा कानून बनाना संभव है, लेकिन केंद्र सरकार बार-बार कह रही है कि ऐसा कानून बनाना संभव नहीं और यदि उनके दबाव में वह बना भी दिया जाए तो उसके दुष्परिणाम किसानों को ही भुगतने होंगे। किसान नेताओं के पास ऐसे सवालों का कोई जवाब नहीं कि यदि व्यापारी एमएसपी पर खरीद से पीछे हट जाते हैं तो क्या होगा? इस पर हैरानी नहीं कि किसान नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों के बीच सातवें दौर की वार्ता किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। यह ठीक है कि पंजाब सरकार की ओर से किसान संगठनों को सड़क से हटा देने से किसान नेता नाराज हैं, लेकिन उचित यह होगा कि उनके और केंद्र सरकार के बीच बातचीत का सिलसिला कायम रहे। बातचीत किसी सकारात्मक नतीजे पर तभी पहुंच सकती है, जब दोनों ही पक्ष बीच का कोई रास्ता तलाशने की कोशिश करेंगे। जहां सरकार के लिए ऐसे उपाय करने आवश्यक हैं, जिनसे खेती की लागत कम हो और किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले, वहीं किसान नेताओं को भी अपनी मांगों को लेकर जिद पकड़ने से बचना होगा। केंद्र सरकार को यह जिम्मेदारी अपने सिर लेनी होगी कि वह किसान नेताओं के समक्ष वे तथ्य रखे, जिनसे यह स्पष्ट हो सके कि एमएसपी पर खरीद की गारंटी वाला कानून किस तरह की समस्याएं पैदा करेगा।

निष्पक्ष जांच जरूरी

झारखंड में लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। झारखंड विधानसभा के वर्तमान बजट सत्र में पेयजल विभाग की योजनाओं में घोटाले को लेकर आवाज बुलंद हुई। कारण है कि योजनाओं में तरह-तरह की गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। सरकार भी मान रही है कि वित्तीय अनियमितता हुई है। विपक्ष के साथ-साथ सत्ता पक्ष के विधायक भी इन गड़बड़ियों को लेकर मुखर हैं। इसी कड़ी में स्वर्णरेखा परियोजना के रांची प्रमंडल में हुए लगभग 22 करोड़ रुपये के घोटाले में चार कोषागार पदाधिकारी को निलंबित करने का आदेश दिया गया है। हालांकि गड़बड़ियों की फेहरिस्त लंबी है। स्वर्णरेखा परियोजना ही नहीं, बल्कि कई पेयजल प्रमंडलों में घोटाले हुए हैं, जिसकी निष्पक्ष जांच आवश्यक है। तभी गड़बड़ी करने वाले सामने आएंगे और उन्हें दंडित किया जा सकेगा। पेजयल विभाग के कई प्रमंडलों में स्वच्छता मिशन के तहत खरीद में भी गड़बड़ी की गई है। मनचाही एजेंसियों से खरीद कर मनमाने तरीके से भुगतान भी किया है। वित्तीय अनियमितता की सूचना मिलने पर सरकार जांच करा रही है। अनियमितता की गंभीरता से जांच करानी चाहिए। क्योंकि जांच रिपोर्ट को दबाने और दोषियों को बचाने के आरोप विभाग और अधिकारियों पर लगते रहे हैं। भ्रष्टाचार कैंसर जैसा रोग है। यह बीमारी देश की व्यवस्था को खोखला कर रही है। इसका निदान समय की मांग है।

> सरकार भी मान रही है कि वित्तीय अनियमितता हुई है। विपक्ष के साथ-साथ सत्ता पक्ष के विधायक भी इन गड़बड़ियों को लेकर मुखर हैं

अंतरिक्ष को नए आयाम देता निजी क्षेत्र

अजय कुमार

लागत में कटौती करने वाले तमाम नवाचारों के द्वारा निजी क्षेत्र ने अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियों में क्रांति की लहर पैदा कर दी है

सुनीता विलियम्स और उनके सहयोगी के अंतरिक्ष में लंबे प्रवास के बाद धरती पर आगमन से भारत के अंतरिक्ष अभियानों को लेकर भी लोगों की उत्सुकता बढ़ी है। इसलिए और भी, क्योंकि भारत में अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियां बढ़ी हैं। भारत की अंतरिक्ष यात्रा 1962 में इन्कोस्पार, 1969 में इसरो और 1972 में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना के साथ शुरू हुई। न केवल भारत में, बल्कि दुनिया में कई सरकारों ने अंतरिक्ष क्षेत्र को बढ़ावा दिया है। इस क्रम में नासा, ईएसए और रोस्कोमास जैसी एजेंसियां अग्रणी हैं। एरियनस्पेस ने पिछली सदी के नौवें दशक में पहला निजी उपग्रह प्रक्षेपित किया। 1984 में यूएस कामर्शियल स्पेस लांच एक्ट आया और 1988 में निजी दूरसंचार उपग्रह लांच हुआ। निजी निवेश में, खासकर अमेरिका में अंतरिक्ष गतिविधियां बढ़ने लगीं। 2002 के बाद स्पेसएक्स ने लागत में कटौती करने वाले बहुत सारे नवाचारों द्वारा इस क्षेत्र में क्रांति की लहर को जन्म दिया। सुनीता विलियम्स की वापसी में मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के सहयोग की अहम भूमिका रही।

आज अंतरिक्ष निवेश में निजी क्षेत्र का हिस्सा 80 प्रतिशत तक पहुंच गया है। कुछ साल पहले तक इसरो द्वारा हासिल अंतरिक्ष डाटा सीमित रूप में ही साझा किया जाता था। 2009 में इस नीति में बदलाव आया। 2020 में भारत में अंतरिक्ष क्षेत्र के खुलने से इस क्षेत्र में लोकतंत्रीकरण की एक नई लहर आई है। आज इस क्षेत्र में स्टार्टअप की संख्या 260 से अधिक हो गई है।

भारतीय स्टार्टअप इसरो के पीएसएलवी आर्बिटल एक्सपेरिमेंटल माड्यूल के साथ स्पेसएक्स के ट्रांसपोर्टर और फ्रांस के एरियन राकेट का उपयोग कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त भारत में 15 से अधिक निजी उपग्रह लांच किए जा चुके हैं और आने वाले वर्षों में यह संख्या और बढ़ेगी। अंतरिक्ष क्षेत्र के लोकतंत्रीकरण की दूसरी विशेषता लागत में आई कमी है। नासा के अंतरिक्ष यान की लागत लगभग 54,500 डालर प्रति किलोग्राम थी, जबकि स्पेसएक्स के फाल्कन 9 की कीमत लगभग 2,720 डालर प्रति किलोग्राम है। भारत में यह लगभग 30,000 डालर है। निजी भागीदारी उपग्रह प्रक्षेपण की लागत को लगभग 30-40 प्रतिशत कम कर सकती है। स्टार्टअप्स वाणिज्यिक सप्लाई चेन माड्यूलर डिजाइनों और राइड-शेयर विकल्पों के उपयोग का लाभ उठाकर कम लागत में सैटेलाइट बना पाते हैं। इसके अतिरिक्त स्टार्टअप छोटे सैटेलाइट बनाते हैं, जिससे लागत कम हो जाती है।

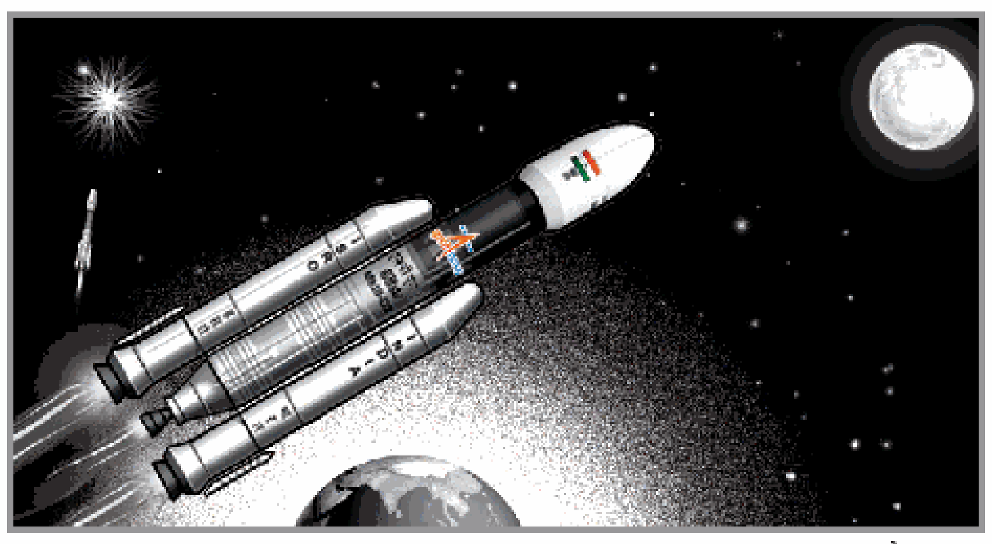

अवधेश राजपूत

पिछली सदी के अंतिम दशक में 10-20 टन के जियो उपग्रह की कार्यक्षमता अब एक छोटे 800 किलोग्राम के उपग्रह में प्राप्त की जा सकती है। इसरो का बड़े उपग्रह बनाने का इतिहास रहा है। इसके विपरीत, भारतीय स्टार्टअप छोटे उपग्रहों के विकास पर ध्यान दे रहे हैं। उदाहरण के लिए पिक्सल हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग उपग्रह का वजन लगभग 15 किलोग्राम है। अतीत के विपरीत जहां अधिकांश उन्नत तकनीकें इसरो द्वारा विकसित की गई थीं, वहीं स्टार्टअप अब नवाचार की सीमाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। अंतरिक्ष क्षेत्र में राज्य सरकारों की भूमिका बढ़ रही है। कई राज्य अपने अधिकार क्षेत्र में निवेश और अनुप्रयोगों को आकर्षित करने और अपने स्वयं के उपग्रहों को लांच करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। कर्नाटक भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का 50 प्रतिशत हिस्सा हासिल करना चाहता है। केरल ने केस्पेस और स्पेस पार्क की स्थापना की है। आंध्र प्रदेश ने एक स्पेस इनोवेशन सेंटर बनाया है। तेलंगाना ने स्पेसटेक फ्रेमवर्क बनाया है और तमिलनाडु कुलसेकरपट्टिनम स्पेसपोर्ट के पास स्पेस बे और एक प्रोपेलेंट पार्क स्थापित करने जा रहा है। गुजरात इनस्पेस के साथ साझेदारी में एक स्पेस क्लस्टर बना रहा है। अन्य राज्य भी अंतरिक्ष गतिविधियों का बढ़ावा दे रहे हैं।

सरकारों और व्यवसायों द्वारा उपग्रह डाटा का बढ़ता उपयोग इसके बढ़ते विकेंद्रीकरण को दर्शाता है। महाराष्ट्र में 10,000 से अधिक गांवों में फसल बीमा के लिए उपग्रह डाटा का उपयोग हो रहा है। कर्नाटक में छह लाख हेक्टेयर कृषि भूमि की निगरानी, रक्षा मंत्रालय द्वारा भूमि का सर्वेक्षण पूरा किया जाना, राजस्थान और हरियाणा द्वारा 90 प्रतिशत से अधिक भूसंपदा के भूमि रिकार्ड बनाना, असम में 30 जिलों में बाढ़ की चेतावनी देना, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में साइक्लोन की चेतावनी का समय 50 प्रतिशत घटना, स्मार्ट शहरों में प्रापर्टी टैक्स में सुधार और मध्य प्रदेश में 77,000 वर्ग किमी वन भूमि की निगरानी के लिए उपग्रह इमेजरी का उपयोग किया जा रहा है। स्टार्टअप नई डाटा-आधारित सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, स्टेटस्योर कृषि ऋण देने वाले बैंकों को मूल्यवर्धित सेवाएं प्रदान कर रहा है। उम्मीद है कि भविष्य में सैटेलाइट डाटा का उपयोग न केवल सरकारों और संस्थाओं द्वारा किया जाएगा, अपितु कारोबारियों और छोटे व्यवसायों द्वारा भी किया जाएगा।

भारत के अंतरिक्ष निर्यात पर अब तक इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का एकाधिकार था। अब स्टार्टअप्स उसके पूरक बन रहे हैं। उनके योगदान के कारण भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में निर्यात का हिस्सा 0.3 अरब डालर से बढ़कर 11 अरब डालर होने का अनुमान है। बदलते परिदृश्य में केंद्र सरकार की भूमिका कार्यान्वयनकर्ता से बदलकर इसरो और स्टार्टअप सहित निजी खिलाड़ियों के बीच प्रमोटर, सुविधाकर्ता और मध्यस्थ की हो गई है। इसरो ने अपनी सुविधाओं को स्टार्टअप और निजी क्षेत्र के उपयोग के लिए खोल दिया है। इस दिशा में केंद्र सरकार ने 1,000 करोड़ रुपये का वेंचर फंड भी बनाया है। इस समय भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र ऐतिहासिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, जो सरकार के नेतृत्व वाले क्षेत्र से एक गतिशील एवं विकेंद्रीकृत इकोसिस्टम में बदल रहा है। स्टार्टअप द्वारा नवाचार को बढ़ावा देने, राज्य सरकारों द्वारा क्षेत्रीय केंद्रों को बढ़ावा देने और निजी निवेश द्वारा लागत कम करने के साथ, अंतरिक्ष अब हमसे दूर नहीं। हममें से हर कोई इससे लाभान्वित होने वाला है।

(लेखक पूर्व रक्षा सचिव एवं आइआइटी कानपुर में विजिटिंग प्रोफेसर हैं)

response@jagran.com

अपने दायित्व को समझें शिक्षा संस्थान

बद्री नारायण

विकसित भारत के लक्ष्य में शिक्षा की भूमिका इसलिए अहम है, क्योंकि वही प्रगति की आकांक्षा को जन्म देती है

आज भारत तीव्र परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजर रहा है। यह परिवर्तन सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनीतिक सभी दिशाओं में हो रहा है। इन क्षेत्रों में परिवर्तन हम कई बार देखते हैं, पर उन्हें समझ नहीं पाते, जबकि यह 'परिवर्तन का दौर' है। भारतीय समकालीन आधुनिक इतिहास को तीन रूपांतरकारी दौर में बांटा जा सकता है। पहला, महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम का दौर। दूसरा, आजादी के बाद देश को बनाने के लक्ष्य को पाने की चाहतों का दौर और तीसरा, विकसित भारत का आज का दौर। विकसित भारत का यह मिशन समाज के प्रत्येक वर्ग से स्वतंत्रता आंदोलन जैसी प्रतिबद्धता की मांग करने के साथ यह हम सबसे अपने को नए परिवर्तनों से जोड़ने की भी अपेक्षा करता है। विकसित भारत के इस दौर में हमें व्यक्तिगत और संस्थागत, दोनों ही स्तरों पर अपने को पुनर्नवा करने की जरूरत है, तभी प्रधानमंत्री मोदी द्वारा परिकल्पित इस लक्ष्य को पाया जा सकता है।

बीते दिनों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के नेतृत्व में भारतीय शिक्षा एवं शिक्षण संस्थानों के वर्तमान एवं भविष्य पर गहन चिंतन हुआ। उसमें देश भर के विश्वविद्यालयों के कुलपति, आइआइटी, आइआइएम एवं एनआइटी के निदेशक तथा शिक्षा मंत्रालय से जुड़े नीति निर्माता एवं अधिकारियों ने भाग लिया। उसमें शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि उम्मीद है कि हमारे शिक्षण संस्थान भारत में विकास के प्रकाश स्तंभ बनेंगे एवं प्रधानमंत्री द्वारा परिकल्पित विकसित भारत के लिए 'एंकर' का कार्य करेंगे। उनके इस वक्तव्य में भविष्योन्मुखी अपेक्षा निहित है। इसमें यह अपेक्षा है कि भारतीय शिक्षण संस्थान केवल चहारदीवारी के भीतर रहकर पढ़ाने, किताबी ज्ञान देने एवं डिग्री देने वाली संस्था के रूप में ही सीमित न रहें, बल्कि इनसे आगे निकल 'विकास एवं सामाजिक परिवर्तन' के चिंतन केंद्र के रूप में स्वयं को विकसित करें। इस प्रकार ये संस्थाएं अपने शोध, आंकड़ों, विकास समीक्षा एवं चिंतन के माध्यम से विकसित भारत के इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए दिशा एवं दृष्टि देंगी। राष्ट्रपति की तरह प्रधानमंत्री भी विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने में शिक्षा संस्थानों की भूमिका का उल्लेख कर चुके हैं। एक बार साइंस कांग्रेस में उन्होंने देश के शिक्षण संस्थानों से समाज को भी अपनी प्रयोगशाला बनाने का आग्रह किया था। भारतीय शिक्षा एवं शिक्षण संस्थान जब 'भारतीय समाज एवं अपने आसपास हो रहे परिवर्तनों से नाभिनाल का संबंध बना पाएंगे, तभी वे विकसित भारत के प्रकाश स्तंभ की भूमिका निभा पाएंगे।

नई पीढ़ी पर भविष्य निर्माण का दायित्व। फाइल

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने वाली है। वह भारतीय शिक्षा के पारंपरिक स्वरूप को तोड़ते हुए एक प्रगतिशील रूपांतर के लिए नीति-नियम रचती है। इस शिक्षा नीति के तहत लचीलापन, अंतर अनुशासनिकता, समाज के विविध प्रयासों के साथ अंतः संवाद तथा समरस एवं विकासोन्मुखी गतिशीलता प्रदान करने की कोशिश दिखाई पड़ती है, ताकि भारतीय शिक्षा में संस्थागत एवं वैयक्तिक स्तर पर आधारभूत परिवर्तन हो सके। भारतीय शिक्षा एवं शिक्षण संस्थानों के समक्ष यह चुनौती भी है कि वे अपनी पारंपरिक प्रकृति, सुविधाभोगी बौद्धिकता एवं अनेक तरह के रूढ़ बंधनों से मुक्त होकर सामाजिक बदलावों, विकास के लिए चल रहे अनगिनत प्रयासों से स्वयं को जोड़ें। आज देश को ऐसे बुद्धिजीवियों की जरूरत है, जो अपने ज्ञान से समाज में सकारात्मक नेतृत्व को दिशा-दृष्टि दे सकें। महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि ऐसे ही जुड़ाव से हम अपने समाज में निहित पारदर्शी देवत्व को देख और सुन पाएंगे। इस संदर्भ में दूसरी जरूरत है कि समाज एवं शिक्षा के साथ ही राज्य एवं शिक्षा के बीच भी संवाद गहन हो। यह संवाद ऐसा हो, जो दोनों में भेद न पैदा करे, बल्कि दोनों को समृद्ध कर सके। हमारे शिक्षा संस्थान एवं बौद्धिक जगत राज्य द्वारा चलाई जा रही अनेक विकासपरक योजनाओं एवं किए जा रहे कार्यों का सम्यक मूल्यांकन कर उनमें व्याप्त कमियों से उसे अवगत कराए। हमारे यहां योजनाओं के कार्यान्वयन के मूल्यांकन तो होते हैं, पर उन्हें बौद्धिक ज्ञान में बदलने के उपक्रम में हम पीछे रह जाते हैं।

पिछले दिनों शिक्षा मंत्रालय की पहल पर देश के 20 केंद्रीय विश्वविद्यालयों, आइआइएम, आइआइटी इत्यादि ने मिलकर भारत में चल रहे विकास कार्यों के सामाजिक प्रभावों का अध्ययन किया था, जो अब अनेक खंडों में प्रकाशित होकर आ गया है। आज ऐसे ही विविध स्तरों पर अनेक प्रयासों की जरूरत है। बीते दिनों मैं उत्तर प्रदेश के एक राज्य विश्वविद्यालय गया था। वहां के छात्रों ने अनौपचारिक बातचीत में कहा कि विकसित भारत अब हमारे लिए विकास मंत्र है। उस युवा छात्र की यही दृष्टि अगर हमारे शिक्षकों, छात्रों एवं कर्मचारियों में आ जाए तो विकसित भारत के इस लक्ष्य को पाने में हमें सुविधा होगी। भारत की आजादी में जिस भावना से देश के लोग जुटे थे, आज उसी प्रतिबद्ध भाव से विकसित भारत के लक्ष्य से हमें जुड़ना होगा। इस महायज्ञ में शिक्षा संस्थानों, बौद्धिकों, शोधार्थियों एवं छात्रों की महती भूमिका है। शिक्षा की भूमिका विकसित भारत के संदर्भ में इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षा हममें आगे बढ़ने एवं विकसित होने की आकांक्षा को जन्म देती है। यही आकांक्षा वह उत्प्रेरक शक्ति है, जो भारत के सामान्यजन को विकसित भारत के मिशन से जोड़ सकती है।

(लेखक जीबी पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान, प्रयागराज के निदेशक हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

निष्ठा

निष्ठा का अर्थ है-किसी व्यक्ति, सिद्धांत या कर्तव्य के प्रति वफादारी, समर्पण एवं दृढ़ता, जो किसी के प्रति सच्ची और निरंतर प्रतिबद्धता का विश्वास दिलाए। आज की आधुनिकता और आगे बढ़ने की होड़ में निष्ठा और कर्तव्यपरायणता आदि मानवीय गुण लोगों के लिए अपवाद होते जा रहे हैं। लोगों में अनास्था एवं कर्तव्य विमुखता एक उपचारविहीन व्याधि के समान फैलती जा रही है। हैरत की बात है कि लोगों को इसमें किसी तरह की बुराई भी नजर नहीं आ रही है। कई नौजवान तो निष्ठा, कर्तव्यपरायणता, समर्पण को निरर्थक एवं बेजा मानने लगे हैं। माता-पिता अपनी संतान को पालने-पोसने में बड़ा संघर्ष करते हैं। जितना संभव होता है उन्हें निष्ठा, बड़ों का सम्मान करने का पाठ पढ़ाते हैं। अपने स्वयं के जीवन से उन्हें निष्ठावान बनने को प्रेरित करते हैं, लेकिन जब वे बड़े होने के बाद इससे विमुख हो जाते हैं तो उन्हें दुख होता है।

निष्ठा के अभाव में सारा ज्ञान व्यर्थ है। किसी व्यक्ति को उसकी निष्ठा को लेकर हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। जब बालक निष्ठा, धर्मपरायणता और उच्च व्यवहार लिए आगे बढ़ता है तो यही गुण उसे समाज की एक अग्रणी इकाई बनाते हैं। हमें अपनी निजी प्राथमिकताओं को त्याग दूसरों के लिए जीने की कला में पारंगत होना चाहिए। अपने सहयोगी और अधीनस्थ के प्रति निष्ठा रखनी और दिखानी भी चाहिए, तभी हम उनकी निष्ठा के पात्र बन सकते हैं। निष्ठा में विश्वास एक बड़ा मंत्र है। फिर वह माता-पिता के प्रति हो, अपने कार्य के प्रति हो, देश के प्रति हो या ईश्वर के प्रति हो, अन्यथा व्यवस्था में दरार पड़ जाती है और वह टूट जाती है। निष्ठावान व्यक्ति को आत्मसंतोष तो होता ही है वह समाज और राष्ट्र के लिए एक संपत्ति जैसा होता है। समय के साथ खुद की विसंगतियों में सुधार कर हम दुख में टूटने, बिखरने से बच सकते हैं।

छाया श्रीवास्तव

बनावटी तस्वीरों से बढ़ता अवसाद

डा. मोनिका शर्मा

> मौजूदा दौर में तकनीक के सधे-सार्थक इस्तेमाल की समझ हमें कई समस्याओं से बचा सकती है

सामाजिक आयोजन, पारिवारिक समारोह, सांस्कृतिक सम्मेलन या व्यक्तिगत भेंट। सुखद वाकया हो या किसी के संसार छोड़ जाने का पीड़ादायी प्रसंग। सब कुछ तस्वीरों तक सिमट रहा है। छवियां, जो कभी स्मृतियां सहेजने का माध्यम समझी जाती थीं, अब साझे पलों को वर्चुअल संसार में साझा करने के उद्देश्य से ली जाने लगी हैं। संवाद का दायरा घटा है तो लोग डिजिटल मेकअप के भी लती हो रहे हैं। तकलीफदेह है कि फिल्टर यानी तस्वीर को सुंदर बनाने की तकनीक का इस्तेमाल करने की आदत अवसाद के घेरे में भी ला रही है।

वस्तुतः तकनीकी सुविधाओं से मिला नकलीपन ओढ़ने का यह व्यवहार कई मोर्चों पर पीड़ादायी भी बन गया है। लोगों पर आम आयोजनों में भी सज-धजकर पहुंचने का मानसिक दबाव बढ़ा है। हर पल चौकन्ने रहने की एक बाध्यता मिलने-बैठने की सहजता पर भारी पड़ रही है। हर पल को कैमरे में कैद करने की मनोवृत्ति ने सामाजिकता के भाव को ही बदल दिया है। फिल्टर्ड तस्वीरों ने अपने ही चेहरे की असली छवि भुला दी है। हर आयु वर्ग के लोग इस वर्चुअल निखार-संवार के जाल में फंस रहे हैं। कुछ समय पहले गूगल द्वारा किए गए एक वैश्विक अध्ययन में सामने आया था कि अच्छी सेल्फी लेने के लिए अमेरिका और भारत में फिल्टर इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। अध्ययन के मुताबिक भारतीय महिलाएं अपनी तस्वीरों को सुंदर बनाने के लिए अधिक उत्साहित रहती हैं। इसके लिए वे कई फिल्टर एप और एडिटिंग माध्यमों का इस्तेमाल करती हैं।

विडंबना यह भी है कि मेल-मुलाकात की यादगार के तौर पर ली जा रही तस्वीरें वास्तव में याददाश्त को कमजोर करने लगी हैं। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के एक अध्ययन के अनुसार लोग सोचते हैं कि फोटो लेने से उन्हें कुछ बेहतर याद रखने में मदद मिलेगी, लेकिन वास्तव में यह बिल्कुल विपरीत है। अध्ययनकर्ता जूलिया सोरोस का कहना है कि 'मैं यह नहीं कह रही हूं कि लोगों को कभी भी तस्वीरें नहीं लेनी चाहिए, लेकिन उन्हें ऐसा कब करना चाहिए इसके प्रति सजगता आवश्यक है।' बावजूद इसके सब कुछ दूसरों तक पहुंचाने की रुग्ण मानसिकता के चलते मृतक स्वजन के साथ तस्वीरें लेकर इंटरनेट मीडिया पर डालने के उदाहरण भी कम नहीं। सब कुछ स्क्रीन में सहेजने की आदत दुर्घटनाओं का भी कारण बन रही है। हार्वर्ड सहित अन्य प्रमुख विश्वविद्यालयों के शोध बताते हैं कि एक तस्वीर लेने की इच्छा उसी तस्वीर को इंटरनेट मीडिया मंचों पर साझा करने की इच्छा से और बढ़ जाती है। समझना कठिन नहीं कि अपने असली व्यक्तित्व के बजाय फिल्टर्ड छवियों में सुंदर दिखने की चाहत इस लत को और बढ़ाती है। मौजूदा दौर में तकनीक के सधे-सार्थक इस्तेमाल की समझ ही इस खुद आमंत्रित किए जा रहे अवसाद से हमें बचा सकती है।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

इतिहास के नाम पर दासता

'आक्रांता के महिमामंडन की बीमारी' शीर्षक से प्रकाशित आलेख में प्रवीण लखेरा ने संदेश दिया है कि आक्रांताओं का महिमामंडन एक मानसिक दासता है और सभ्यता को अपने सांस्कृतिक मूल्यों व सत्य के आधार पर इतिहास का मूल्यांकन करना चाहिए, न कि दमनकारियों के प्रतीकों से गौरव खोजना चाहिए। इतिहास केवल घटनाओं का लेखा-जोखा नहीं, बल्कि एक सभ्यता की आत्मा का प्रतिबिंब होता है। जब उस इतिहास में आक्रांताओं का महिमामंडन किया जाता है, तो वह केवल तथ्यात्मक विकृति नहीं होती, बल्कि वह मानसिक पराजय होती है। औरंगजेब जैसे अत्याचारी शासकों को 'न्यायप्रिय' या 'धार्मिक सहिष्णु' सिद्ध करने का प्रयास इसी बौद्धिक भ्रम का प्रतीक है। जिस शासक का शासन मंदिरों के विध्वंस, मतांतरण, कर उत्पीड़न और सांस्कृतिक विघटन पर आधारित हो, उसका गुणगान करना ऐतिहासिक विवेक का नहीं, वैचारिक गुलामी का प्रमाण है। यह न केवल ऐतिहासिक असत्य है, बल्कि पीड़ित जनस्मृति का अपमान भी। चिंतन का विषय यह है कि इतिहास में उन व्यक्तित्वों को आदर्श स्थान क्यों दिया जाए, जिन्होंने समाज में समावेश नहीं, बल्कि विखंडन का बीज बोया? क्या हम स्मृति की सत्ता को सच्चाई पर रखेंगे या प्रतीकों की सत्ता को भ्रम पर टिकाए रखेंगे? इतिहास का उद्देश्य स्मारक बनाना नहीं, मूल्य देना होना चाहिए। जो शासक भय और हिंसा के बल पर सत्ता स्थापित करें, वे इतिहास में सबक हो सकते हैं, आदर्श नहीं। सभ्यता की सांस्कृतिक चेतना तभी जीवंत रह सकती है, जब वह अपने मूल्यों, आदर्शों और आत्मसम्मान की नींव पर खड़ी हो, न कि उन आक्रांताओं की विरासत में गौरव की खोज करे, जिन्होंने उसके आत्मा को रौंदा था। यदि स्मृति को दिशा नहीं दी गई, तो इतिहास प्रेरणा नहीं बनेगा, बल्कि भ्रम का दर्पण बनकर सभ्यता को आत्मविस्मृति की ओर धकेल देगा। आक्रांताओं का महिमामंडन एक मानसिक दासता है। सभ्यता को अपने सांस्कृतिक मूल्यों व सत्य के आधार पर इतिहास का मूल्यांकन करना चाहिए, न कि दमनकारियों के प्रतीकों से गौरव खोजना चाहिए।

awanishg30@gmail.com

मेलबाक्स

नशे का बढ़ता प्रयोग चिंता का विषय

हरियाणा के विभिन्न हिस्सों में युवाओं एवं वयस्कों के बीच शराब, ड्रग्स और अन्य नशीले पदार्थों का सेवन तेजी से बढ़ रहा है। यह न केवल स्वास्थ्य और शिक्षा पर विपरीत प्रभाव डाल रहा है, बल्कि समाज के नैतिक मूल्यों और सामाजिक ताने-बाने को भी कमजोर कर रहा है। प्रशासन, पुलिस और संबंधित विभागों द्वारा नशे के दुष्प्रभावों पर रोक लगाने के लिए कड़े कदम उठाए जाने की अत्यंत आवश्यकता है। जागरूकता अभियान, सख्त कानूनों का प्रवर्तन और नशामुक्ति केंद्रों की स्थापना इस समस्या के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। नशा और नाश एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। नशा चाहे कोई भी क्यों न हो, यह हमेशा शरीर, धन का नाश ही करता आ रहा है।

गुनगुन, फरीदाबाद

आधार लिंकिंग के साथ मतदान हो अनिवार्य

चुनाव आयोग द्वारा सभी मतदान पहचान पत्रों का आधार से लिंकिंग स्वागत योग्य और प्रशंसनीय है और साथ ही फर्जी मतदाताओं को निष्क्रिय करने के लिए आवश्यक भी। इसके साथ फर्जी मतदाताओं की पहचान के साथ उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई भी की जानी चाहिए। जब सरकार और चुनाव आयोग टेक्नोलाजी के माध्यम से सभी मतदाताओं के मतदान पहचान पत्रों को आधार से जोड़ने की प्रक्रिया सुनिश्चित हो रही है, तो इसके प्रभाव से किसी भी मतदाता के पहचान पत्र की राष्ट्रीय स्तर पर उपयोगिता स्थापित हो सकेगी। इसलिए सभी मतदाताओं द्वारा किसी भी चुनाव में मतदान भी अनिवार्य करने की कानूनी प्रक्रिया पर भी विचार किया जा सकता है। किसी भी मतदाता द्वारा चुनाव तिथि पर देश के किसी भी क्षेत्र में मतदान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कम से कम जिला स्तर पर बहुपयोगी मतदान केंद्र स्थापित हो सकते हैं। यह प्रक्रिया आनलाइन भी हो सकती है।

विनोद जौहरी, दिल्ली

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।
अपने पत्र इस पते पर भेजें:
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: response@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।
****

58 स्थायी पदों को मंजूरी दी गई थी वर्ष 1999 में अपर यमुना रिवर बोर्ड में, जबकि अब इसमें केवल दो ही सदस्य हैं। उल्लेखनीय है कि अपर यमुना रिवर बोर्ड का गठन 1995 में किया गया था।

आजकल

पुराने घाव फिर से हरे करता नागपुर

नागपुर इन दिनों सांप्रदायिक तनाव की चपेट में है। दावा किया जाता है कि नागपुर में ऐसा सांप्रदायिक तनाव 98 वर्षों के बाद पैदा हुआ है। इससे पहले 1927 में नागपुर में हुए सांप्रदायिक दंगों के समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आयु दो वर्ष भी नहीं हुई थी। लेकिन उस समय संघ के संस्थापक डा. केशव बलिराम हेडगेवार द्वारा एकत्र की गई खुफिया सूचनाओं एवं अन्य तैयारियों के कारण समाज कैसे दंगाइयों का मुकाबला कर सका, आज इस तथ्य को भी समझना हमारे लिए कहीं अधिक प्रासंगिक है

दंगों की आग में एक बार फिर झुलसा नागपुर। फाइल

हिंदू-मुसलमानों के वास्तविक संबंध संपूर्ण देश में स्पष्ट होने लगे थे। मोपला-विद्रोह से सबक लेकर जिन स्वामी श्रद्धानंद ने हिंदू-संगठन का मंत्र जन-जन में फूंका, उनकी 23 दिसंबर, 1926 को निर्मम हत्या कर दी गई। हिंदू होकर भी 'हिंदी' कहलानेवाले नेता स्तब्ध रह गए। पर मुसलमानों ने हत्यारे अब्दुल रशीद को 'गाजी' कहना शुरू कर दिया। पिछले तीन-चार वर्षों की घटनाओं से नागपुर का वातावरण भी दूषित हो गया था। वर्ष 1924 से नागपुर में मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार होने के कारण उनका पारा और भी चढ़ गया था। सतरंजीपुरा, हंसापुरी तथा जुम्मा मस्जिदों के सामने से हिंदुओं की निकलनेवाली शोभायात्राएं उनके मन को रह-रहकर कचोटती थीं। अतः उन्होंने हिंदुओं को नाना प्रकार से सताने का प्रयत्न शुरू कर दिया। अकेला-दुकेला हिंदू मिल गया तो उसे पकड़कर पीटते थे तथा हिंदू मोहल्लों में से लड़कियों को भगाकर ले जाते थे। इस प्रकार की घटनाएं बढ़ती गईं। किंतु अब ये ज्यादतियां पचाई नहीं जा सकती थीं। डाक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, गोविंदराव चोलकर, रामचंद्र कोष्टी, भाऊजी कावरे, अण्णा सोहोनी, बालाजी सुखदेव तथा कृष्णाजी जोशी आदि सप्तऋषि जब पट्ठेदार खादी की ऊंची काली टोपी, सफेद कमीज, खाकी कोट, काछा लगाए हुए धोती, और हाथ में सोटा लेकर घूमते तो गुंडों का दिल कांपने लगता। एकाध बार तो उनके जाने मात्र से भालदारपुरा के मुसलमानों ने भगाई हुई एक हिंदू लकड़ी को वापस कर दिया।

संघ की शाखाओं का विस्तार : डाक्टरजी केवल कल और आज का विचार न करते हुए समाज के शाश्वत स्थैर्य के लिए भविष्य में दूर तक देखते थे तथा उसके लिए तरुणों के साथ बाल और शिशुओं को भी संस्कारित करने की उन्होंने तैयारी की थी। मोहिते बाड़े में लगनेवाली संघ शाखा का 1927 के प्रारंभ में स्वरूप विस्तृत होने लगा। अब उसमें आयु के अनुसार शिशु, बाल, तरुण तथा प्रौढ़ स्वयंसेवकों के अलग-अलग पथक बनाकर उन्हें लव, चिलया, कुश, ध्रुव, प्रह्लाद, अभिमन्यु, भीम तथा भीष्म नाम दिए गए। 'भीष्म' पथक में संघ से संबंधित प्रौढ़, 'भीम' में बड़े तरुण, 'कुश' तथा 'प्रह्लाद' में तरुण, किशोर तथा बाल और 'लव' एवं 'चिलया' पथक में दस वर्ष से नीचे के शिशुओं का वर्गीकरण किया गया था। सत्तर-अस्सी तरुणों के लाठी के कार्यक्रम से वातावरण इतना उत्साहपूर्ण दिखाई देता था कि उससे वीरभाव का संचार हुए बिना नहीं रहता। नागपुर में वातावरण गरम होते हुए भी डाक्टरजी ने कुछ तरुणों का गर्मियों में ही एक प्रशिक्षण-वर्ग लगाया। वे उन्हें इस योग्य बना देना चाहते थे कि कहीं भी संघ का कार्य कर सकें।

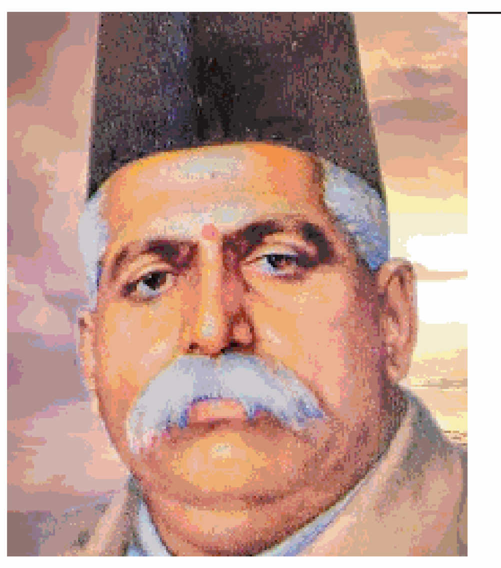
डा. केशव बलिराम हेडगेवार।

वर्ग के दिनों में ही डाक्टरजी के घर पर पथराव का प्रमाण अधिक बढ़ गया तथा बीच-बीच में डाक्टरजी एवं कई अन्य हिंदू नेताओं के पास गुमनाम पत्र आने लगे जिनमें धमकी दी गई कि 'सावधान रहिए, हम लोग आपका खून करने वाले हैं।' डाक्टरजी को मिले धमकी भरे पत्रों में से एक पत्र 15 मई के 'महाराष्ट्र' में अब्दुल करीम के हस्ताक्षर से प्रकाशित हुआ है। उसकी भाषा से पता चलता है कि वह किसी सिरफिरे गुंडे की करतूत थी। उसमें लिखा था, 'आप नागपुर के मुसलमानों का बड़ा दोस्त हो ('दोस्त' शब्द व्यंग्यात्मक था)। आपने रामटेक में मुसलमानों से शरारत की है। वह शरारत आपको मौत नजदीक लाने का तरीका है। अपना ध्यान रखना, एक बरस के अंदर तुम मुरगी सरीखे काटे जावेंगे और तुम्हारी हड्डी मुसलमान बांट के चूसेंगे।'

डाक्टरजी को स्पष्ट दिखने लगा था कि अब संघर्ष होकर रहेगा। अतः उन्होंने मुसलमानों के मोहल्लों में आक्रमण की तैयारी करने के लिए चलनेवाली गुप्त बैठकों की टोह लेने की व्यवस्था की थी। जून-जुलाई से ही हिंदू बस्तियों में मुसलमानों की टोलियां कुछ देखभाल करती हुई घूमती नजर आती थीं तथा मस्जिद में बार-बार होनेवाली बैठकों के समाचार भी आगे आनेवाले संकट की सूचना दे रहे थे। दुर्योग से उस समय महाराष्ट्र में सर्वत्र ब्राह्मण-अब्राह्मण के बीच बड़ी कटुता निर्मित हो गई थी। इससे मुसलमानों को आशा थी कि इस कटुता का लाभ लेकर हिंदू-संगठन की तैयारी करनेवाले तथा मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करनेवाले सफेदपोश लोगों को अच्छा सबक सिखाया जा सकेगा। किंतु समय रहते उनके षड्यंत्र का सुराग संघ को मिल चुका था। संघ के प्रारंभ में तथा 1927 के संघर्ष के पूर्व डाक्टरजी ने बैठकों तथा सभाओं में अनेक बार बताया था कि 'मैं अकेला हूं' की भावना कितनी आत्मघाती तथा हास्यास्पद है।

डाक्टरजी जहां एक ओर अपने समाज को जाग्रत एवं सुसज्जित करने का प्रयत्न कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर मुसलमानों के द्वारा अपने मोहल्लों में आक्रमण का व्यूह किस प्रकार रचा जा रहा है, इसकी भी खोज-खबर रखते थे। इसी कारण गणेशोत्सव में महालक्ष्मी तथा गौरी के प्रसाद के दिन महाल क्षेत्र में दंगा करने की मुसलमानों की योजना का उन्हें पहले ही पता लग गया था। अतः झगड़े के संभाव्य क्षेत्र में स्थान-स्थान पर उन्होंने लाठियां इकट्ठी करके रखवा दीं। साथ ही असुरक्षित दिखनेवाले क्षेत्रों में डाक्टरजी ने स्वयं जाकर लोगों को सचेत रहने की सूचना दी। चार सितंबर को निकलनेवाले एक जुलूस के हस्तपत्रक बांटे गए। इसमें मुसलमानों को आह्वान किया गया था कि उपरोक्त तारीख को नवाबपुरा मस्जिद में इकट्ठा हों।

महालक्ष्मी उत्सव : इस 'पुण्यप्रद' यात्रा के लिए महालक्ष्मी उत्सव के दिन दोपहर दो बजे का समय निश्चित करने के पीछे मुसलमानों की चाल थी। नागपुर-बरार भाग में महालक्ष्मी का उत्सव बड़े वैभव तथा साज-बाज के साथ मनाया जाता है। लोग दोनों देवी-प्रतिमाओं का रेशमी तथा जरी के कीमती वस्त्रों से श्रृंगार करते हैं तथा घर के हीरे, मोती, सोने आदि के मूल्यवान गहनों से उन्हें अलंकृत कर घर-घर पूजा की जाती है। नैवेद्य के लिए इतने प्रकार की चीजें पकाई जाती हैं कि 'चौंसठ व्यंजन छत्तीस भोग' की उक्ति अक्षरशः चरितार्थ होती है। दोपहर दो बजे से सायंकाल तक देवी पधारती हैं। मुसलमानों के नेताओं ने यह योजना बनाई थी कि दोपहर को भोजन की दौड़धूप में यदि हिंदू मोहल्लों पर हमला बोल दिया तो सभी भोजन-भट्टों में भगदड़ मच जाएगी तथा उस स्थिति का लाभ उठाते हुए महालक्ष्मी को तोड़-फोड़कर उसके अलंकार लूटने का स्वर्ण-अवसर हाथ लग जाएगा। इसी योजना के साथ दिन के बारह बजे नवाबपुरा की मस्जिद के पास मुसलमानों का इकट्ठा होना शुरू हो गया था।

उस दिन डाक्टर हेडगेवार नागपुर में नहीं थे। वह प्रतिवर्ष की भांति गणेशोत्सव में भाषण देने के लिए चांदा, वर्धा आदि स्थानों के दौरे पर गए थे। किंतु जाने से पहले वह झगड़ा हुआ तो क्या करना है, इस संबंध में सभी निर्देश देकर गए थे। उन्होंने मुसलमानों की तैयारी का तो पता लगा लिया था, किंतु हिंदुओं की सजगता का पता नहीं चलने दिया था। डाक्टरजी की सूचना के अनुसार अण्णा सोहोनी के नेतृत्व में स्वयंसेवक मोहिते बाड़े की टूटी दीवार की आड़ में 12 बजे दोपहर से ही इकट्ठा होने लगे। अण्णाजी ने उनको ठीक प्रकार से बांट दिया तथा डा. मुंजे के घर से महाल तक सभी गली-कूचों में उन्हें सावधानी के साथ छिपकर बैठने की सूचना दी। कुल 16 टुकड़ियां बनाई गई थीं। सब मिलाकर सौ-सवा सौ तरुण होंगे। जैसा कि निश्चित हुआ था रविवार, दिनांक चार सितंबर को दोपहर के दो बजे मुसलमानों का जुलूस निकला। 'अल्ला हो अकबर' तथा 'दीन दीन' के नारे जोर-जोर से लगाए जा रहे थे। अंग्रेजों के राज्य में एक प्रांत की राजधानी में इस जुलूस में बड़ी संख्या में मुसलमान लाठी, तलवार, भाला, छुरिका आदि शस्त्रास्त्र से सज्ज अत्यंत उन्मत्त बर्ताव करते हुए जा रहे थे।

डटकर किया मुकाबला : वह अत्यंत डरावना दृश्य था। वाईकर गली, केलीबाग, सिटी हाई स्कूल का प्रवेशद्वार, डा. हरदास का अस्पताल आदि सभी क्षेत्रों में घरों में बैठे हुए हिंदू 'दीन-दीन' के गगनभेदी स्वर को सुनकर डर के मारे कांप रहे थे। जैसे-जैसे जुलूस निकट आता जाता था वैसे-वैसे लगता था कि मानो अब हृदय की धड़कन भी बंद हो जाएगी। परंतु दूसरी ओर इन्हीं गलियों में छिपे स्वयंसेवक भी निर्भयता से जुलूस की बाट देख रहे थे। आत्म संरक्षण का उनका निश्चय दृढ़ था। अपने पराक्रम और पुरुषार्थ पर उन्हें भरोसा था। थोड़ी ही देर में सड़क से जानेवाला जुलूस वाईकर की गली में गाली-गलौच तथा मारपीट करता हुआ घुसा। उसी समय गली में एक ओर चुपके से खड़े हुए स्वयंसेवकों ने उस संकरी गली में घुसे हुए गुंडों के ऊपर अपने प्रहार के हाथ दिखाने शुरू कर दिए। बस, मुसलमान आतताई लहुलुहान होकर उलटे पांव भागने लगे। 'दीन-दीन' करते तथा अपने होश-हवास खोकर कुछ गुंडों ने जुलूस को छोड़कर महाल-भाग की दूसरी गलियों में घुसने का प्रयत्न किया। लेकिन वहां भी वही रक्ताभिषेक होते ही जुलूस बिल्कुल तितर-बितर हो गया तथा मुसलमान अकेले-दुकेले हिंदू को मारते-पीटते चिटणीस पार्क की तरफ भागने लगे। उस समय उनकी बौखलाहट तथा गाली-गलौच से यह साफ दिखता था कि पहली ही झड़प में उनकी अपेक्षा भंग हो गई थी।

इतना बड़ा जुलूस थोड़े से तरुणों ने ही छिन्न-विच्छिन्न कर दिया, यह वार्ता बिजली की तरह सारे क्षेत्र में घर-घर में फैल गई। सुनते ही बाकी लोग भी भोजन-मिष्ठान छोड़कर रेशमी धोती बांधे ही लाठियां लेकर निकल आए तथा जुलूस पर टूट पड़े। अंत में अंधेरे का आश्रय लेकर अपने काले मुंह छिपाने के लिए भालदारपुरा की ओर भागने के सिवाय मुसलमानों के सम्मुख और कोई चारा नहीं बचा। रविवार रात्रि को सारे शहर में झड़पें होती रहीं। किंतु उनमें हिंदुओं का ही पलड़ा भारी था। रात-भर लोगों ने पहरा लगाया। इसके बाद तीन दिन मारधाड़ में ही बीते। लेकिन इस संघर्ष ने यह स्पष्ट कर दिया कि यदि डा. हेडगेवार ने समय रहते नागपुर के हिंदुओं को एकजुट एवं प्रशिक्षित न किया होता, तो चार सितंबर, 1927 को हिंदुओं के लिए स्थिति बहुत विकट होती।

(नाना पालकर द्वारा डा. केशव बलिराम हेडगेवार के जीवन पर लिखी गई पुस्तक 'डा. हेडगेवार' के एक अध्याय 'नागपुर का दंगा' का संपादित अंश) **(संकलन एवं प्रस्तुति : ओमप्रकाश तिवारी)**

खरी-खरी

एक नंबर के ईमानदार आदमी

पूरन सरमा

वे एक नंबर के ईमानदार आदमी थे। किसी का कार्य किए बिना कुछ नहीं लेते थे। लेकिन काम करवाने के बाद वे अपना हक छोड़ते नहीं थे। इसलिए उनके क्षेत्रों में इन्हीं कारणों से उन्हें एक नंबर का ईमानदार माना जाता था। नाम उनका मुक्तिदास और उम्र यही कोई पचास के आसपास। नगर निगम में काम करते थे। पद से बड़े नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी इसी ईमानदारी के आधार पर अच्छी-खासी धाक जमा रखी थी। ऊपर तक उनके हाथ थे। कानून को कभी हाथ में नहीं लेते, बल्कि कानून को वे भली प्रकार काम में लेते थे। वे अक्सर अपने 'क्लाइंट्स' को डराते रहते थे कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। कोई भी गलत काम करने वाला उससे बच नहीं सकता। ऐसी स्थिति से निजात पाने का रास्ता उनके पास है और जो उनके पास आता था तो कानून के हाथ छोटे हो जाते थे।

मेरा भी एक बार उनसे सामना पड़ा। मेरे मकान के पास से एक आम रास्ता था। मुझे आम आदमी और आम रास्ता पसंद नहीं है। मेरे पास से आम आदमी गुजरे, यह मुझे गवारा नहीं था। नगर निगम गया तो वहां सभी ने एकमत होकर कहा कि मुक्तिदास जी को पकड़ो। मैंने मालूम किया कि वे कहां मिलेंगे। पता चला कि वे कैंटीन में मिल जाएंगे। कैंटीन में पहुंचा तो वे गरमा-गरम समोसे खाते हुए किसी को नेक सलाह दे रहे थे। मुझे देखकर बोले- 'आओ भाई बैठो, समोसे खाओगे। वहीं दूसरी ओर साथ वाला व्यक्ति रुआंसा होकर बोला, 'अब कब तक मेरा काम पूरा होने की उम्मीद है।'

मुक्तिदास ने चाय को सुड़का और मटमैले दांत निकालकर बोले- 'भाई जल्दी हो तो तुम किसी और से मिल लो। अफसर को पकड़ लो। मेरी काम कराने की अपनी शैली है। हो जाएगा तो मैं तुमसे बात भी नहीं करूंगा। साथ वाला स्वयं ही चुप हो गया। चुपचाप उठा, चाय-समोसे का भुगतान कर रवाना हो गया। उसकी सीट मैंने ली तो वे बोले, 'किसने सताया है तुम्हें?' मैं बोला, 'मुझे आम आदमी और आम रास्ते ने परेशान कर दिया है। यह कैसे भी बंद होना चाहिए।'

X पोस्ट

क्या यह कोई संयोग है कि यूएसएड की सहायता बंद होने के कुछ ही दिन बाद कथित किसान आंदोलन बंद करा दिया गया। विक्रांत@vikrantkumar

पंजाब में किसानों को बलपूर्वक हटा दिया गया। इस बार वैसा हाहाकार क्यों नहीं हुआ, जैसा पहले हुआ था? क्या हाहाकार यह देखकर होता है कि सरकार किसकी है? सिवा कांग्रेस पार्टी के, कोई अन्य पार्टी इस पर कुछ बोल ही नहीं रही। अखिलेश शर्मा@akhileshsharma1

औरंगजेब की कब्र को तोड़ा जाना गलत है। एएसआइ को उसकी कब्र के बाहर उसके द्वारा तोड़े गए मंदिरों की लिस्ट का एक बड़ा सा बोर्ड लगा देना चाहिए। उसके द्वारा सतनामियों, सिखों, हिंदुओं के नरसंहारों की डिटेल्स के साथ भी एक बोर्ड लगा देना चाहिए। दिव्य कुमार सोती@DivyaSoti

रेवड़ी राजनीति के चलते महाराष्ट्र सरकार को कर्मियों को वेतन देने में मुश्किल आ रही है। राज्य के खस्ताहाल खजाने की चर्चा के बजाय वहां औरंगजेब पर बहस जारी है। वह एक खराब शासक था, पर उसकी मौत बहुत पहले हो चुकी है। तवलीन सिंह@tavleen_singh

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या मतदाता पहचान पत्रों को आधार से जोड़ना अनिवार्य होना चाहिए?

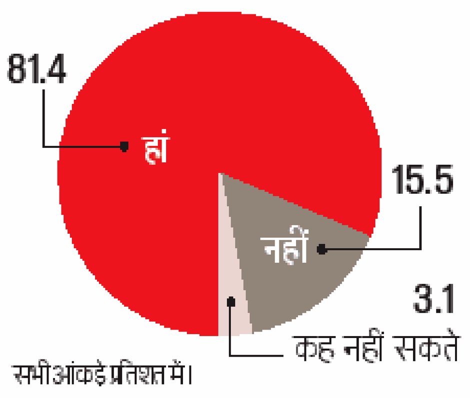

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या पंजाब सरकार ने किसान संगठनों से रास्ते खाली करा कर सही किया?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

योगी जी की राह पर चले महाशय मान,
बुलडोजर चलवा दिया साफ हुआ मैदान।
साफ हुआ मैदान कहीं भी दो अब धरना,
किंतु रोड के बीच न आकर बिल्कुल अड़ना।
कैसा भी हो रोग और कैसा भी रोगी,
सबका एक इलाज फार्मूला हैं बस योगी!
- ओमप्रकाश तिवारी

प्रदीप सिंह
राज्य ब्यूरो प्रमुख, झारखंड

झारखंड डायरी

सुरक्षित सीटें घटीं तो किसे लाभ-हानि

झारखंड में लोकसभा और विधानसभा सीटों की प्रकृति के साथ-साथ संख्या में भी बदलाव की संभावना है। इसकी वजह अगले वर्ष से राज्य में लागू होने वाला परिसीमन है। सीटों के नए सिरे से निर्धारण में आबादी के विस्तार की ज्यादा भूमिका होगी। जब सीटें निर्धारित की गई थी, तब उस हिसाब से उसकी संख्या तय की गई थी, लेकिन तेजी से आबादी बढ़ने के साथ जनसांख्यिकीय परिवर्तन हुए हैं और नए रिहायशी इलाकों का भी विस्तार हुआ है। प्रस्तावित परिसीमन को देखते हुए आरोप-प्रत्यारोप से लेकर नफा-नुकसान को लेकर राजनीतिक दांव खेले जा रहे हैं। राज्य में सत्तारूढ़ गठबंधन को आशंका है कि आबादी कम होने को आधार बनाकर राज्य में लोकसभा और विधानसभा की आदिवासी सुरक्षित सीटों की संख्या घटाई जा सकती है। हालांकि अभी यह केवल अनुमान है, लेकिन यह मसला राजनीति के केंद्र में आ गया है। अभी विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और इस दौरान सदन में अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री चमरा लिंडा ने यह आशंका जताई है कि आदिवासी सुरक्षित सीटें घटाई जा सकती हैं और ऐसा राज्य हित में नहीं होगा। जवाब में विपक्षी दल भाजपा ने आदिवासियों की कम होती आबादी को बदली जनसांख्यिकी (डेमोग्राफी) और घुसपैठ के आरोपों से जोड़ा, लेकिन फिलहाल सीटें घटने की आशंका प्रकट कर सत्तारूढ़ गठबंधन ने इससे पैदा होने वाली सहानुभूति को अपने पक्ष में करने की पहल की है।

राज्य में क्षेत्रीय दल झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के उभार और उसके नेतृत्व में चल रहे आइएनडीआइए गठबंधन की बढ़त ने भाजपा को पीछे धकेल रखा है। खासकर आदिवासी सुरक्षित सीटों पर गठबंधन का ऐसा प्रभाव है कि मुश्किल से भाजपा का खाता खुल पा रहा है। लोकसभा चुनाव के दौरान तो भाजपा को सभी पांच आदिवासी सुरक्षित सीटों पर हार का मुंह देखना पड़ा। परंपरागत सीटों पर दिग्गज आदिवासी नेताओं की एक नहीं चली। केंद्र में आदिवासी मामलों के मंत्रालय का मंत्री रहने के बावजूद अर्जुन मुंडा खूंटी लोकसभा क्षेत्र से पराजित हो गए तो भाजपा के भितरखाने इसे लेकर खलबली है कि कैसे इस परिस्थिति से निपटा जाए। विधानसभा चुनाव में भी आदिवासी सुरक्षित सीटों पर भाजपा की स्थिति कुछ ऐसी ही रही। 28 में से केवल एक आदिवासी सुरक्षित विधानसभा सीट भाजपा के हिस्से में आई, जबकि पार्टी ने पूरे तामझाम के साथ चुनाव से पहले ऐसे कई नेताओं को दल में शामिल किया था, जिन पर जीत दिलाने का दारोमदार था। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन इसमें प्रमुख थे। हालांकि चंपाई सिर्फ अपनी सीट ही निकाल पाए। अपने बेटे तक का राजनीतिक करियर आरंभ कराने में वे विफल रहे। वहीं, किसी आदिवासी सीट पर उनका प्रभाव नहीं दिखा।

भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा ने लोकसभा चुनाव के वक्त कांग्रेस छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया था। उनके पति की भी भाजपा में एंट्री हो गई, लेकिन कोड़ा अपनी परंपरागत सिंहभूम सीट बचाने में सफल नहीं हो पाए। सबसे ज्यादा झटका सीता सोरेन के प्रदर्शन से भाजपा को लगा। सीता सोरेन ने उस वक्त झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़ा, जब हेमंत सोरेन जेल में थे। बेहतर राजनीतिक भविष्य की आस में सोरेन परिवार को छोड़ वह न सिर्फ भाजपा में गईं, बल्कि कई संगीन आरोप भी लगाए। इससे लग रहा था कि भाजपा को लाभ होगा, लेकिन सीता सोरेन न तो लोकसभा चुनाव जीत पाईं न विधानसभा चुनाव। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि वह झामुमो में वापसी के लिए प्रयासरत हैं। ऐसी विकट परिस्थिति में परिसीमन के दौरान अगर आदिवासी सुरक्षित सीटें कम हुईं तो सत्तारूढ़ गठबंधन इसे अपने प्रभाव को कम करने की दिशा में की गई राजनीतिक कार्रवाई बताकर सहानुभूति पाने की भरसक कोशिश करेगा। इसका अहसास भाजपा को है, तभी तो पार्टी इस मसले पर फूंक-फूंककर कदम रख रही है। आदिवासी आबादी घटने को लेकर आरोप तो लगाए जा रहे हैं, लेकिन यह भी संदेश दिया जा रहा है कि सुरक्षित सीटें यथावत रखी जाएं, अन्यथा इसका और अधिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। एक मायने में भाजपा के आगे कुआं और पीछे खाई की स्थिति है। इसका दारोमदार अब प्रदेश नेतृत्व पर है कि वे किस हद तक अपनी बात रख पाते हैं। फिलहाल शानदार बहुमत के साथ सत्ता में वापस लौटे हेमंत सोरेन के पास भाजपा को निशाना बनाने के लिए ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जो असरकारक हो सकते हैं। इस परिस्थिति में संतुलन बनाए रखने की जिम्मेदारी भाजपा के समक्ष होगी।

पारंपरिक वाद्य यंत्र मांदर बजाते हेमंत सोरेन। फाइल

मंथन

डा. वेदप्रकाश
असिस्टेंट प्रोफेसर, किरोड़ीमल कालेज, दिल्ली विश्वविद्यालय

यमुना सफाई की व्यापक योजना

यमुना की बदहाली को ठीक करने के लिए यह आवश्यक है कि व्यापक स्तर पर योजनाएं बनें, उनका क्रियान्वयन हो एवं वे सतत चलें। साथ ही, समय समय पर उनकी समीक्षा भी की जाए

विभिन्न प्रकार के प्रदूषण, अतिक्रमण और अविरल प्रवाह के अभाव में यमुना नदी बदहाल हो चुकी है। दिल्ली में वजीराबाद से कालिंदी कुंज तक यमुना का लगभग 22 किमी बहाव क्षेत्र है जो गंभीर रूप से प्रदूषित है। इस प्रदूषण में लगभग 80 प्रतिशत हिस्सेदारी घरेलू सीवेज की है। दिल्ली में सीवेज को शोधित करने हेतु केवल 37 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं जिनमें से 16 ही मानकों के अनुरूप काम कर रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में प्रतिदिन 71 करोड़ गैलन सीवेज उत्पन्न होता है जिसमें से 60 करोड़ गैलन का ही शोधन हो रहा है और शेष अशोधित सीवेज सीधे यमुना में गिर रहा है।

ध्यातव्य है कि वर्ष 1993 में यमुना एक्शन प्लान बना था। भारत और जापान की सहभागिता से बनी इस योजना का उद्देश्य था- सीवेज उपचार संयंत्रों का निर्माण, कच्चे सीवेज को नदी में छोड़ने के लिए निगरानी और यमुना को प्रदूषण से मुक्त करने के उपाय करना आदि। लेकिन यह विडंबना ही कही जा सकती है कि हजारों करोड़ रुपये का बजट लगने के बाद भी धरातल पर परिणाम लगभग शून्य है। विदित है कि सीवेज ढांचे को मजबूत करना, नदियों को प्रदूषण मुक्त रखना एवं साफ-सफाई आदि के लिए राज्य और स्थानीय निकाय जिम्मेदार हैं, फिर इसमें लापरवाही करने वाले निकायों अथवा राज्यों पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? हाल ही में संसद की एक समिति ने जल परियोजनाओं में फंड का सही तरीके से उपयोग नहीं होने पर चिंता जताई है। समिति ने यह भी बताया कि दिल्ली के एक हिस्से में यमुना नदी की जीवन को बनाए रखने की क्षमता लगभग नगण्य पाई गई है। राष्ट्रीय राजधानी में 33 निगरानी स्थलों में से 23 स्थल प्राथमिक जल गुणवत्ता मानकों को पूरा नहीं करते।

हाल ही में एक समाचार से यह तथ्य सामने आया कि वर्ष 1999 में अपर यमुना रिवर बोर्ड में 58 स्थायी पदों को मंजूरी दी गई, जहां अब केवल दो ही सदस्य हैं। ध्यातव्य है कि अपर यमुना रिवर बोर्ड का गठन 1995 में किया गया था। इस बोर्ड का मुख्य कार्य यमुना का पानी लाभार्थी राज्यों हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड व राजस्थान के बीच बंटवारे के नियमन की जिम्मेदारी, न्यूनतम प्रवाह बनाए रखने के लिए उत्तरदायी एवं सतही व भूजल की गुणवत्ता की निगरानी है।

प्रश्न यह है कि क्या इस रिवर बोर्ड का काम समाप्त हो गया अथवा बिना पर्याप्त सदस्यों के यह बोर्ड कैसे काम कर रहा है? वर्ष 2015 में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने एक आदेश में यह कहा कि हरियाणा राज्य हथिनी कुंड बैराज से यमुना नदी की मुख्यधारा में सीधे 10 क्यूसेक पानी छोड़े और वजीराबाद तक नदी का प्रवाह बनाए रखे। लेकिन विडंबना है कि विगत लंबे समय से वजीराबाद से आगे यमुना में उसके हिस्से का प्राकृतिक जल आ ही नहीं रहा है।

नियमों की अनदेखी : हाल ही में दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने नालों से प्रदूषण की हिस्सेदारी पर एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें यह सामने आया है कि दिल्ली में यमुना को प्रदूषित करने में सबसे बड़ी हिस्सेदारी (59.9 प्रतिशत बायोकेमिकल आक्सीजन डिमांड) नजफगढ़ नाले की है। इसके बाद सबसे ज्यादा 27.48 प्रतिशत प्रदूषण शाहदरा ड्रेन से जाता है। इस रिपोर्ट के आधार पर अब पर्यावरण विभाग आगे की कार्ययोजना पर काम कर रहा है।

दिल्ली अथवा किसी भी महानगर में नाले बरसाती पानी की निकासी के लिए होते हैं। आबादी का सीवेज सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से होकर और औद्योगिक क्षेत्र का अपशिष्ट कामन एफ्लूएंट प्लान से पूरी तरह शोधित होकर ही किसी नदी में जाना चाहिए। किंतु यह विडंबना ही है कि राष्ट्रीय राजधानी में शासन-प्रशासन की मिलीभगत और नियमों की अनदेखी से छोटे-बड़े सभी नालों में सीवेज और औद्योगिक अपशिष्ट बह रहा है।

दिल्ली में कालिंदी कुंज के निकट यमुना नदी की स्थिति, जिसमें सुधार की आवश्यकता है। फाइल

यमुना सफाई के लिए जरूरी है कि हरियाणा, दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश में समुचित समन्वय हो। औद्योगिक क्षेत्र से भी समन्वय एवं निगरानी के प्रयास किए जाएं। नगरीय एवं अनधिकृत आबादी क्षेत्र में पर्याप्त सीवेज संशोधन प्लांट लगाए जाएं और उनकी निगरानी हो। वे बड़े नाले जो सीधे यमुना में गिरते हैं, उन पर जगह-जगह प्री फिल्टर व राक फिल्टर जैसी तकनीक से प्रदूषण को रोकने हेतु प्रयास किए जाएं। स्थानीय जल स्रोतों को वर्षा एवं बाढ़ के समय भरने के लिए यमुना बहाव क्षेत्र में भूजल पुनर्भरण प्रक्रिया अपनाते हुए यथाशीघ्र व्यवस्था बनाई जाए। नालों के पानी को जलाशयों में रोकते हुए नदी की ओर जाने दिया जाए। यमुना की सफाई में जन भागीदारी एवं जागरूकता हेतु समय-समय पर सामाजिक-सांस्कृतिक कार्यक्रम भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। यमुना के लिए व्यापक एवं सतत कार्य योजना तत्काल लागू करनी होगी। यमुना केवल एक नदी नहीं है, यह जीवनदायिनी है। इससे प्रकृति-पर्यावरण, संस्कृति, कृषि एवं आर्थिकी भी जुड़ी है। अतः इसके पुनरुद्धार हेतु विकल्पहीन प्रतिबद्धता आवश्यक है।

****

राष्ट्रीय संस्करण
शुक्रवार 21 मार्च, 2025
दैनिक जागरण
बिजनेस
www.jagran.com

स्थायी बांड के जरिये 1,247 करोड़ जुटाएगी इरेडा

नई दिल्ली : सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी इंडियन रिन्युएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (इरेडा) ने 1,247 करोड़ रुपये जुटाने के लिए अपना पहला स्थायी बांड जारी किया है। कंपनी ने कहा कि इस कदम उद्देश्य भारत के हरित ऊर्जा इन्फ्रास्ट्रक्चर के तेजी से विस्तार का समर्थन करने के लिए एक मजबूत वित्तीय आधार सुनिश्चित करना है। ये बांड 8.40 प्रतिशत की वार्षिक कूपन दर पर जारी किए जाएंगे। (प्रेट्र)

राजकोषीय स्थिरता का वादा करने वाले नए कानून लागू होने के बाद तेल और गैस कंपनियों को अप्रत्याशित लाभ कर जैसे किसी भी नए कर का सामना नहीं करना पड़ेगा।
— हरदीप सिंह पुरी, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री

सेंसेक्स	76,348.06	▲ 899.01
निफ्टी	23,190.65	▲ 283.05
सोना प्रति दस ग्राम	₹ 91,650	▼ ₹300
चांदी प्रति किलोग्राम	₹1,02,000	▼ ₹1,500
डालर	₹ 86.36	▼ ₹0.01
क्रूड (ब्रेंट) प्रति बैरल	$ 71.01	

एक नजर में

बीएमडब्ल्यू और रेनो के वाहन अप्रैल से महंगे होंगे

नई दिल्ली : बीएम डब्ल्यू समूह इंडिया ने गुरुवार को कहा कि एक अप्रैल 2025 से उसके सभी वाहन तीन प्रतिशत तक महंगे हो जाएंगे। बीएमडब्ल्यू की यह इस वर्ष की दूसरी मूल्य वृद्धि है। वहीं, रेनो इंडिया ने भी अप्रैल से अपनी सभी वाहनों के मूल्य में दो प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की घोषणा की है। रेनो ने फरवरी 2023 के बाद यह वृद्धि की है। (प्रेट्र)

बैंक आफ इंग्लैंड ने भी ब्याज दरों को स्थिर रखा

लंदन : फेडरल रिजर्व से सुर मिलाते हुए बैंक आफ इंग्लैंड ने भी गुरुवार को प्रमुख ब्याज दर को 4.50 प्रतिशत पर स्थिर रखने की घोषणा की। हालांकि, अमेरिकी की टैरिफ नीति की कारण ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है। बयान के अनुसार, मौद्रिक नीति समिति के नौ में से आठ सदस्यों ने ब्याज दर स्थिर रखने की वकालत की। (एपी)

ईपीएफओ से जनवरी में 17.89 लाख सदस्य जुड़े

नई दिल्ली: सेवानिवृत्ति कोष का प्रबंधन करने वाले निकाय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) से जनवरी में शुद्ध रूप से 17.89 लाख सदस्य जुड़े। श्रम मंत्रालय के अनुसार, इसमें सालाना आधार पर 11.67 प्रतिशत जबकि दिसंबर, 2024 की तुलना में 11.48 प्रतिशत की वृद्धि रही है। आंकड़ों के अनुसार, जनवरी में करीब 8.23 लाख नए सदस्य नामांकित हुए। (प्रेट्र)

इंद्रनील भट्टाचार्य बने आरबीआइ के ईडी

नई दिल्ली : आरबीआइ ने गुरुवार को कहा कि इंद्रनील भट्टाचार्य को नया कार्यकारी निदेशक (ईडी) नियुक्त किया गया है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि कार्यकारी निदेशक के तौर पर भट्टाचार्य आर्थिक एवं नीति शोध विभाग का कार्यभार देखेंगे। उनकी नियुक्ति 19 मार्च से प्रभावी हो गई है। वे अभी तक आरबीआइ के मौद्रिक नीति विभाग में सलाहकार के तौर पर सेवाएं दे रहे थे। (प्रेट्र)

खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने में बदलता मौसम बाधा

आरबीआइ ने क्षेत्रवार व फसलवार जरूरत के हिसाब से नई जल प्रबंधन नीति बनाने का दिया सुझाव

- मक्का, दलहन और तिलहन के के लिए मौसम के हिसाब से ज्यादा बदलाव करने की जरूरत
- जरूरत से ज्यादा बारिश वाले क्षेत्रों में निर्धारित समय से पहले बीजारोपण करने को कहा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: पिछले कुछ वर्षों से दुनिया के अन्य हिस्सों की तरह भारत में भी मौसम का मिजाज काफी बदल चुका है। भविष्य को लेकर भी कुछ निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता है। इसका सबसे ज्यादा असर फसल के उत्पादन पर साफ तौर पर दिख रहा है। यह स्थिति खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने को लेकर की जाने वाली कोशिशों पर पानी फेर सकता है। यह बात बुधवार को जारी की गई आरबीआइ की मासिक बुलेटिन में कही गई।

बुलेटिन में आरबीआइ ने सरकार से आग्रह किया है कि वह वह क्षेत्रवार और फसलवार आधार का व्यापक अध्ययन करते हुए सिंचाई व्यवस्था की नई नीति तैयार करे। खासतौर पर मक्का, दलहन और तिलहन के उत्पादन को लेकर मौसम के हिसाब से ज्यादा बदलाव करने की जरूरत है। यह माना जा सकता है कि दलहन और तिलहन उत्पादन का देश की सामान्य महंगाई दर पर काफी असर होता है, इसलिए केंद्रीय बैंक की तरफ से फसलों के उत्पादन को लेकर ज्यादा ध्यान आकर्षित कराया गया है।

आरबीआइ के शोधकर्ताओं ने देश के विभिन्न हिस्सों में खाद्यान्न उत्पादन के पैटर्न का लंबे समय तक काफी बारीक अध्ययन करने के बाद इस आलेख को प्रकाशित किया है। मोटे तौर पर अनाजों का उत्पादन काफी हद तक मौसम पर निर्भर करता है। कभी जरूरत से कम तो कभी जरूरत से ज्यादा बारिश इनके उत्पादन के सारे गणित को गड़बड़ा देते हैं। ऐसे में अगर क्षेत्रवार और फसलों को देखते हुए जल प्रबंधन की व्यवस्था की जाए तो मौसम की मार से बचा जा सकता है। उदाहरण के तौर पर जिन क्षेत्रों में जरूरत से ज्यादा बारिश हो रही है वहां निर्धारित समय से पहले फसलों का बीजारोपण करने का सुझाव दिया गया है। नीति निर्धारकों को मौसम के बदलाव के मुताबिक ही जल निकासी की व्यवस्था, फसलों के विविधीकरण आदि पर ध्यान देने की बात कही गई है।

121 जिलों में असामान्य रहा मानसून कैलेंडर वर्ष 2023 के दौरान पूरे देश में

96 रही असामान्य मानसून वाले जिलों की संख्या वर्ष 2024 के दौरान

सरकारी उपायों का तिलहन-दलहन पर नहीं दिखा असर

तिलहन और दलहन की पैदावार काफी हद तक सामान्य मानसून पर निर्भर होती है। यहां बताते चलें कि केंद्र सरकार की तरफ से पिछले एक दशक के दौरान देश में तिलहन और दलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए जो कदम उठाए गए हैं, उसका वांछित असर नहीं दिखा है। इन दोनों की आपूर्ति के लिए भारत काफी हद तक आयात पर निर्भर हैं। खाद्य मंहगाई दर को तय करने में भी इनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है।

सामान्य मानसून वाले जिलों की संख्या में आई कमी

आलेख में वर्ष 2023 और वर्ष 2024 में मौसम में बदलाव और खाद्यान्न उत्पादन का लेखा जोखा पेश किया गया है। इन दो वर्षों में ही जिन जिलों में सामान्य मानसून रहता था, उनकी संख्या में कमी आई है। वर्ष 2023 में 121 जिले ऐसे थे, जहां सामान्य मानसून था, लेकिन 2024 में इन जिलों को असामान्य मानसून वाले वर्ग में रखा गया। जबकि 96 जिले ऐसे हैं जिनमें असामान्य मानसून था लेकिन वर्ष 2024 में वहां मानसून रहा। अगर इन जिलों में खाद्यान्न उत्पादन की स्थिति को देखा जाए तो सिर्फ धान की पैदावार ही लक्ष्यों के मुताबिक रही है जबकि तिलहन व दालों का उत्पादन लक्ष्य से कम रहा।

वर्ष 2028 तक भारत में होंगे 77 करोड़ 5जी यूजर

नई दिल्ली, प्रेट्र: दूरसंचार उपकरण कंपनी नोकिया ने गुरुवार को कहा कि भारत में औसत 5जी डाटा खपत प्रति यूजर प्रति माह 40 जीबी तक पहुंच गई है। अगले तीन साल में 5जी के कुल ग्राहक आधार 2.65 गुना बढ़कर करीब 77 करोड़ पर पहुंचने की उम्मीद है। नोकिया की वार्षिक मोबाइल ब्राडबैंड सूचकांक (एमबीआइटी) रिपोर्ट के अनुसार, 4जी, 5जी आदि डाटा की खपत मिलकर पांच साल में 19.5 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर से बढ़कर 2024 में 27.5 जीबी हो गई। रिपोर्ट के अनुसार, 2024 में पूरे भारत में 5जी डाटा उपयोग में सालाना आधार पर तीन गुना की उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

नोकिया इंडिया के प्रौद्योगिकी एवं समाधान प्रमुख (मोबाइल नेटवर्क) संदीप सक्सेना ने रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि दिसंबर, 2024 में भारत में प्रति यूजर औसत 5जी डेटा खपत 40 जीबी दर्ज की गई। हमारा अनुमान है कि 5जी यूजर आधार 2024 में 29 करोड़ से बढ़कर 2028 तक लगभग 77 करोड़ हो जाएगा।

नोकिया ने कहा- 2024 में पूरे भारत में 5जी डाटा उपयोग में सालाना आधार पर तीन गुना की उल्लेखनीय वृद्धि हुई

रिपोर्ट के अनुसार, 5जी फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस (एफडब्ल्यूए) के निरंतर बढ़ने से डाटा उपयोग बढ़ रहा है। एफडब्ल्यूए यूजर अब औसत मोबाइल डाटा उपयोगकर्ता की तुलना में 12 गुना अधिक डाटा का उपभोग कर रहे हैं, जो आवासीय तथा व्यावसायिक दोनों ही क्षेत्रों में नई सेवाओं के दम पर हो रहा है। सक्सेना ने कहा कि सक्रिय 5जी उपकरणों की संख्या सालाना आधार पर दोगुनी होकर 2024 में 27.1 करोड़ तक पहुंच गई। इसमें तेजी आने आने की उम्मीद है।

43 लाख करोड़ के बकाया कर में से दो-तिहाई की वसूली मुश्किल

आयकर विभाग ने संसदीय समिति को बताया, कुछ कर मांग पिछली सदी के नौवें दशक से जुड़ीं

नई दिल्ली, प्रेट्र: आयकर विभाग ने संसदीय समिति को बताया कि 43 लाख करोड़ रुपए की बकाया प्रत्यक्ष कर मांग से दो-तिहाई को वसूलना मुश्किल है। सीबीडीटी चेयरमैन ने समिति को बताया, 'हमारे पास लगभग 43,00,000 करोड़ रुपये की बकाया कर मांग है, जो हमारे लिए चिंता का विषय है।' आंशिक तौर पर देखें तो कुछ कर मांग बहुत लंबे समय से बकाया हैं। कुछ कर मांग तो पिछली सदी के नौवें दशक से संबंधित हैं। समिति की रिपोर्ट गुरुवार को संसद में पेश की गई।

राजस्व सचिव ने समिति को बताया कि इस मांग का एक बड़ा हिस्सा काल्पनिक भी है। समिति ने पाया कि प्रत्यक्ष करों के मामले में 10,55,906 करोड़ रुपये का कर बकाया पांच या उससे अधिक वर्षों से लंबित है। समिति ने यह भी कहा कि कर अधिकारियों के अनुसार, 43,07,201 करोड़ रुपये के बकाया में से 28,95,851 करोड़ रुपये जो 67 प्रतिशत है, वसूलना मुश्किल है। समिति को यह भी बताया गया कि इस मांग बकाया एक बड़ा हिस्सा काल्पनिक है। प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण से पहले, एक मैनुअल रजिस्टर प्रणाली लागू थी, जिसमें ब्याज का हिसाब नहीं होता था। हालांकि, मौजूदा प्रणाली अब सालाना ब्याज की गणना करती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चूंकि आयकर जुर्माना बहुत भारी है, इसलिए हर साल की देरी से मांग बढ़ती रहेगी, जो किसी भी मामले में वसूली योग्य नहीं है।

एथनाल मिश्रित पेट्रोल से वाहनों के प्रदर्शन पर खास असर नहीं

नई दिल्ली, प्रेट्र: सरकार ने गुरुवार को संसद में बताया कि 20 प्रतिशत एथनाल मिश्रित पेट्रोल (ई20) का उपयोग करने से वाहन के प्रदर्शन, इंजन के कलपुर्जों पर कोई खास असर नहीं पड़ता है।

हाल ही में एक अंतर मंत्रालयी समिति की रिपोर्ट में कहा गया था कि 20 प्रतिशत एथनाल मिश्रित पेट्रोल के प्रयोग से ई10 के लिए डिजाइन और ई20 के लिए कैलिब्रेटेड चार पहिया वाहनों की ईंधन दक्षता में मामूली कमी आती है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्यमंत्री सुरेश गोपी ने लोकसभा में बताया कि सोसाइटी आफ इंडियन आटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने समिति को बताया है कि इंजन हार्डवेयर और ट्यूनिंग में संशोधन से मिश्रित ईंधन के चलते परफार्मेंस में होने वाली हानि को कम किया जा सकता है।

लगातार चौथे दिन सेंसेक्स 899 अंक बढ़ा

76,348 अंक पर जाकर बंद हुआ बीएसई सूचकांक

283 अंक बढ़कर 23,190 पर पहुंचा एनएसई निफ्टी

मुंबई, प्रेट्र: सभी क्षेत्रों में खरीदारी और अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की ओर से रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करने के बाद मिल-जुले संकेतों का घरेलू शेयर बाजारों पर अनुकूल असर रहा है और यह गुरुवार को लगातार चौथे दिन बढ़त के साथ बंद होने में कामयाब रहे। बीएसई का मानक सूचकांक 899.01 अंक की तेजी के साथ 76 हजार के स्तर को पार करते हुए 76,348.06 अंक पर बंद हुआ। दिनभर के कारोबार के दौरान इसमें 1,007.2 अंक तक की वृद्धि रही थी। इसी तरह, एनएसई का निफ्टी 283.05 अंक बढ़कर 23,190.05 अंक पर बंद हुआ।

मेहता इक्विटीज के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट प्रशांत ताप्से का कहना है कि निफ्टी में लगातार चौथे दिन बढ़ोतरी रही है और इस बढ़त के दो प्रमुख कारण रहे हैं। पहला कारण यह कि फेडरल रिजर्व ने 2025 के दौरान ब्याज दरों में दो बार कटौती का संकेत दिया है। दूसरा कारण यह है कि विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआइआइ) की बिकवाली रुकने की उम्मीद बढ़ गई है। फेडरल रिजर्व ने बुधवार को हुई बैठक में प्रमुख नीतिगत दरों को 4.25-4.50 प्रतिशत पर स्थिर रखने का फैसला किया था। सेंसेक्स में भारती एयरटेल के शेयरों में सबसे ज्यादा 4.17 प्रतिशत की वृद्धि रही है। इसके अलावा टाइटन, टीसीएस, एचयूएल, इन्फोसिस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, नेस्ले और टाटा मोटर्स के शेयर भी बढ़े हैं।

चार दिन में 17.43 लाख करोड़ बढ़ी निवेशकों की संपत्ति

घरेलू शेयर बाजारों में बीते चार दिनों से जारी तेजी से निवेशकों की संपत्ति भी बढ़ रही है। इस दौरान निवेशकों की संपत्ति में 17.43 लाख करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हो चुकी है। अब बीएसई में सूचीबद्ध सभी कंपनियों का बाजार पूंजीकरण बढ़कर 408.61 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा हो गया है। इन चार दिनों में बीएसई सेंसेक्स 2,519.15 अंक या 3.41 प्रतिशत बढ़ चुका है।

एम्मार इंडिया खरीदने के लिए वार्ता अंतिम दौर में : अदाणी समूह

नई दिल्ली, प्रेट्र: अदाणी समूह अपने संपत्ति कारोबार का विस्तार करने के लिए रियल एस्टेट कंपनी एम्मार इंडिया को करीब 1.4-1.5 अरब डालर के उद्यम मूल्य पर खरीदने के लिए बातचीत कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक, दुबई स्थित एम्मार प्रापर्टीज और अदाणी समूह के बीच सौदे को लेकर बातचीत अंतिम चरण में है। हालांकि, इस संबंध में दोनों ही पक्षों ने कोई टिप्पणी नहीं दी है।

सूत्रों ने कहा कि एम्मार प्रापर्टीज अपनी भारतीय इकाई में हिस्सेदारी बेचने की सोच रही है, लेकिन बेची जाने वाली शेयरधारिता की सीमा अभी तय नहीं हुई है। एम्मार के पास संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और प्रमुख बाजारों में लगभग 1.7 अरब वर्ग फुट का भूमि बैंक है। बुर्ज खलीफा का विकास एम्मार प्रापर्टीज ने ही किया है।

राष्ट्रीय फलक

कुछ राज्यों के साथ रायल्टी व कर बकायों की वसूली मुद्दे के हल के प्रयास जारी : केंद्र

- सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी जानकारी, झारखंड ने कहा- सुनवाई में नहीं हो देरी

नई दिल्ली, प्रेट्र: केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह अपने और कई खनिज संपन्न राज्यों के बीच खनिज अधिकारों व खनिज युक्त भूमि पर रायल्टी व कर बकाया की वसूली के मुद्दे को सुलझाने का प्रयास कर रहा है। शीर्ष अदालत ने इस बीच झारखंड जैसे कई खनिज समृद्ध राज्यों की याचिकाओं पर सुनवाई 24 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी, जिसमें केंद्र और खनन कंपनियों से हजारों करोड़ रुपये मूल्य के खनिज अधिकारों व खनिज युक्त भूमि पर रायल्टी और कर बकाया वसूलने की मांग की गई है।

जस्टिस अभय एस ओका, एमएम सुंद्रेश व उज्जल भुइयां की विशेष पीठ ने कहा, वह खनिज समृद्ध राज्यों की याचिकाओं पर सुनवाई का क्रम तय करेगी। केंद्र की ओर से सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, इस मुद्दे का समाधान निकालने के प्रयास जारी हैं और याचिकाएं मई के पहले हफ्ते में सूचीबद्ध की जा सकती हैं। झारखंड की ओर से अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने कहा, समाधान किसी भी स्तर पर निकाला जा सकता है और सुनवाई में देरी नहीं की जानी चाहिए।

25 जुलाई, 2024 को तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ (अब सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता वाली नौ जजों की पीठ ने 8:1 के बहुमत से फैसला सुनाया था कि खनिज अधिकारों पर कर लगाने की विधायी शक्ति राज्यों के पास है, संसद के पास नहीं। बाद में 14 अगस्त को एक आदेश में शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया था कि फैसला बाद की तिथि से प्रभावी नहीं होगा और खनिज संपन्न राज्यों को एक अप्रैल, 2005 से 12 वर्षों की अवधि की केंद्र व खनन फर्मों से हजारों करोड़ रुपये के खनिज अधिकारों और खनिज युक्त भूमि पर रायल्टी व कर बकाया वसूलने की अनुमति दे दी थी। तत्पश्चात कई राज्यों और केंद्र के बीच विवाद सुलझाने के लिए जस्टिस ओका की अध्यक्षता में विशेष पीठ गठित की गई थी।

कई खनिज समृद्ध राज्यों की याचिकाओं पर सुनवाई 24 अप्रैल तक टली

द्विवेदी ने पीठ से आग्रह किया था कि बकाया राशि की वसूली में आने वाली कानूनी बाधाओं से संबंधित राज्यों की याचिकाएं पीठ को आवंटित की जाएं।

25 जुलाई, 2024 के फैसले के बाद द्विवेदी ने खनिजों और खनिज युक्त भूमि पर कर लगाने में झारखंड के रास्ते में आने वाली कानूनी बाधाओं का उल्लेख किया था। कहा था, एक मुद्दा अभी भी बना हुआ है और वह है खनिजों व खनिज युक्त भूमि पर रायल्टी वसूलने का झारखंड का कानून, जिसे पहले खारिज कर दिया गया था, अब बरकरार रखने की जरूरत है। द्विवेदी का कहना था, ''जब तक कानून को वैध घोषित नहीं किया जाता, हम खनिजों और खनिज युक्त भूमि पर कर नहीं वसूल सकते।'' उन्होंने पटना हाई कोर्ट की रांची पीठ के 22 मार्च, 1993 के निर्णय का हवाला दिया था, जिसमें खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1992 की धारा-89 को निरस्त कर दिया था।

धारा-89 ने तत्कालीन अविभाजित बिहार की राज्य सरकार को न केवल खनिज युक्त भूमि पर, बल्कि वाणिज्यिक या औद्योगिक उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि पर भी कर लगाने का अधिकार दिया था। 25 जुलाई, 2024 के फैसले ने 1989 के उस फैसले को खारिज कर दिया था। इसके बाद कुछ खनिज समृद्ध राज्यों ने केंद्र द्वारा लगाई गई रायल्टी और खनन कंपनियों से लिए गए करों की वापसी की मांग की।

मूर्तिकार राम सुतार को दिया जाएगा महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार : फडणवीस

मुंबई, प्रेट्र: महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को विधानसभा में कहा, प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार को राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान महाराष्ट्र भूषण के लिए चुना गया है। गत माह अपना 100वां जन्म दिन मनाने वाले सुतार को पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। उन्होंने स्टैच्यू आफ यूनिटी का डिजाइन तैयार किया है। यह सबसे ऊंची प्रतिमा है। फडणवीस ने कहा, वह शतायु हो चुके हैं, पर अभी भी मुंबई में इंदु मिल स्मारक परियोजना में आंबेडकर प्रतिमा पर काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र भूषण के तहत 25 लाख रुपये व स्मृति चिह्न प्रदान किया जाता है।

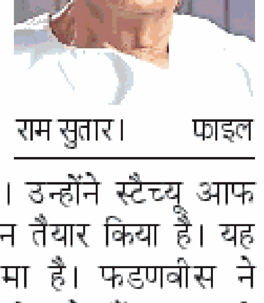

राम सुतार। फाइल

टोल घोटाले में 14 एजेंसियां प्रतिबंधित, 100 रुपये करोड़ जब्त

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- एनएचएआइ ने घोटाले के लिए जिम्मेदार एजेंसियों पर की सख्त कार्रवाई, जमानत राशि भी कुर्क की

सड़क से लेकर संसद तक गूंजे टोल घोटाले में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) ने टोल वसूलने के लिए अनुबंधित 14 एजेंसियों पर कड़ी कार्रवाई की है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा गठित जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर इन एजेंसियों को दो वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। साथ ही, अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन के कारण उनकी लगभग 100 करोड़ रुपये की जमानत राशि भी जब्त कर ली गई है।

सरकार की टोल संग्रह प्रणाली को आधुनिक और पारदर्शी बनाने के दावे को उस समय झटका लगा, जब उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने मीरजापुर के अतरैला शिव गुलाम टोल प्लाजा पर छापा मारा। आरोप था कि देश के लगभग 42 टोल प्लाजा पर अवैध टोल वसूली हो रही थी, जिससे सरकार को 120 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ। टोल प्लाजा पर बिना फास्टैग या प्रतिबंधित फास्टैग वाले वाहनों से कलेक्शन के लिए अनुबंधित एजेंसियों के कर्मी फर्जी साफ्टवेयर का उपयोग कर अवैध वसूली कर रहे थे। इस मामले में कानूनी कार्रवाई के साथ ही सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने तीन सदस्यीय जांच समिति गठित की। सरकार का दावा है कि रिपोर्ट में इलेक्ट्रानिक टोल कलेक्शन सिस्टम में कोई खामी नहीं पाई गई है। 98 प्रतिशत टोल संग्रह ईटीसी सिस्टम से ही हुआ है। चूंकि, कारण बताओ नोटिस का संतोषजनक जवाब टोल संग्रह एजेंसियां नहीं दे सकी हैं, इसलिए एनएचएआइ ने उन पर कार्रवाई करते हुए दो वर्ष के लिए प्रतिबंधित करते हुए उनकी जमानत राशि भी जब्त कर ली है। अब इन टोल प्लाजा पर टोल संग्रह का काम नई एजेंसियों को सौंपने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही मंत्रालय ने संसद में जानकारी दी है कि सटीक आंकड़ा जुटाने के लिए प्रमुख टोल प्लाजाओं पर एआइ का उपयोग करते हुए आडिट कैमरे भी लगाए जाने पर विचार किया जा रहा है।

गलत टोल संग्रह के लिए रिफंड किए 12.55 लाख रुपये : सरकार की ओर से संसद में यह भी बताया गया कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर गलत टोल संग्रह के लिए 2024 में 12.55 लाख रुपये रिफंड किए गए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि गलत टोल संग्रह के मामलों में संबंधित एजेंसियों पर अब तक दो करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया गया है। नेशनल पेमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया द्वारा गलत टोल संग्रह की सूचना दी गई थी। ऐसे कुल 410 करोड़ फास्टैग लेनदेन थे, जो सभी फास्टैग लेनदेन का 0.03 प्रतिशत है। मंत्री ने बताया कि यदि टोल एजेंसियां गलत यूजर चार्ज वसूलने की जिम्मेदार पाई जाती हैं तो अनुबंध के अनुसार उस अतिरिक्त यूजर चार्ज पर 30-50 गुणा जुर्माना लगाया जाता है। दरअसल, कभी-कभी वाहनों से राष्ट्रीय राजमार्ग या एक्सप्रेसवे पर यात्रा किए बिना भी टोल शुल्क वसूल लिया जाता है। ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि एजेंसियां मैन्युअल रूप से वीआरएन-आधारित लेनदेन बनाते समय सिस्टम में गलत वाहन पंजीकरण संख्या (वीआरएन) दर्ज कर देती हैं। कभी-कभी फास्टैग रीडर द्वारा कई बार रीडिंग लेने के कारण दोगुना शुल्क ले लिया जाता है।

प्रतीकात्मक

बुजुर्ग महिला ने डिजिटल अरेस्ट धोखाधड़ी में गंवा दिए 20 करोड़

- जालसाजों ने महिला से स्वयं को बताया था सीबीआइ अधिकारी
- मामला सामने आने के बाद पुलिस ने तीन आरोपितों को किया गिरफ्तार

मुंबई, प्रेट्र : दक्षिण मुंबई की 86 वर्षीय एक महिला ने डिजिटल गिरफ्तारी धोखाधड़ी के दौरान दो महीने में 20 करोड़ रुपये से अधिक गंवा दिए। जालसाजों में से एक ने महिला से पैसे ठगने के लिए स्वयं को सीबीआइ अधिकारी बताया था।

पुलिस के अनुसार, 26 दिसंबर 2024 से इस साल तीन मार्च के बीच हुए इस अपराध के मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक अधिकारी के अनुसार, आरोपितों ने पीड़िता को दो माह तक घर पर ही रहने के लिए विवश किया। हर तीन घंटे में फोन कर प्रतिदिन उसकी लोकेशन जानते रहे। साइबर पुलिस ने उन बैंक खातों की पहचान कर महिला के 77 लाख रुपये निकालने पर रोक लगाई, जिनमें धन हस्तांतरित किया गया था।

इस माह के शुरुआत में महिला द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, उसे एक व्यक्ति का फोन आया। उसने स्वयं के सीबीआइ अफसर होने का दावा किया। उसे बताया कि उसके आधार कार्ड के जरिये एक बैंक खाता खोला गया है। उसका इस्तेमाल मनी लांड्रिंग के लिए किया जा रहा है। इसके बाद उस व्यक्ति ने महिला से कहा कि इस मामले की जांच सीबीआइ कर रही है। उसे अपने कमरे में ही रहना चाहिए। उसने उसे 'डिजिटल गिरफ्तारी' की धमकी भी दी। उसने महिला के परिवार के सदस्यों को भी गिरफ्तार करने की धमकी दी। महिला के घर पर काम करने वाली एक घरेलू सहायिका ने उसके व्यवहार में बदलाव आने की जानकारी उसकी बेटी को दी। महिला केवल खाना खाने के लिए ही अपने कमरे से बाहर निकलती थी। पुलिस ने मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है।

पाक के लिए जासूसी करने वाला गाजियाबाद निवासी इंजीनियर गिरफ्तार

बेंगलुरु, प्रेट्र : भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड (भेल) के एक वरिष्ठ इंजीनियर दीपराज चंद्र को पाकिस्तानी हैंडलर्स को संवेदनशील जानकारी साझा करने के आरोप में खुफिया एजेंसियों ने गिरफ्तार किया है। दीपराज ने संचार और रडार सिस्टम सहित महत्वपूर्ण जानकारी लीक की थीं। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

परमेश्वर ने बताया कि हमारे खुफिया अधिकारियों और सैन्य खुफिया अधिकारियों ने उसे पाकिस्तान के खुफिया अधिकारियों के संपर्क में रहने पर पकड़ा है। सूत्रों के अनुसार, गाजियाबाद निवासी दीपराज भेल की अनुसंधान टीम में कार्यरत था और उसने बिटकाइन के बदले कार्यालयों की संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान को लीक की हैं। आरोप है कि दीपराज ने कार्यालय लेआउट, अधिकारियों व उत्पादन प्रणालियों से संबंधित जानकारी भी साझा की। समें जानकारी में संचार और रडार सिस्टम आदि शामिल हैं।

बदले की नीयत से पुणे में चालक ने ही लगाई थी बस में आग

- चालक का कंपनी के कुछ कर्मचारियों से था विवाद, वेतन कटौती से भी था परेशान
- घटना में चार कर्मचारियों की हुई थी मौत, लेकिन चालक का उनसे नहीं था विवाद

पुणे, प्रेट्र : पुणे के पास एक निजी कंपनी की मिनीबस में लगी आग के बारे में पुलिस ने गुरुवार को बताया कि बदला लेने की नीयत से चालक ने ही यह आग लगाई थी। इस घटना में कंपनी के चार कर्मचारियों की मौत हो गई। चालक का कुछ कर्मचारियों के साथ विवाद था और वह वेतन में कटौती से भी परेशान था।

पिंपरी चिंचवाड़ के डिप्टी पुलिस कमिश्नर विशाल गायकवाड़ ने बताया, जांच में पता चला है कि आग दुर्घटना नहीं, बल्कि तोड़फोड़ थी। आरोपित बस चालक जनार्दन हंबरडेकर का कुछ कर्मचारियों के साथ विवाद था और वह बदला लेना चाहता था। लेकिन जिन कर्मचारियों से उसका विवाद था, वे मृतकों में शामिल नहीं हैं। गौरतलब है कि बुधवार सुबह पुणे शहर के पास हिंजवाड़ी इलाके में व्योमा ग्राफिक्स की बस में आग लग गई। बस में 14 कर्मचारी सवार थे। डीसीपी ने बताया, ''आरोपित ने बेंजीन (अत्यधिक ज्वलनशील रसायन) खरीदा था। उसने बस में टोनर पोंछने वाला कपड़ा भी रखा था। जब बस हिंजवाड़ी के पास पहुंची तो उसने माचिस जलाई और कपड़े में आग लगा दी। आरोपित चलती बस से कूद गया, जो लगभग सौ मीटर आगे जाकर रुक गई। बाहर निकलने से पहले ही हंबरडेकर जल चुका था। उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है और बाद में उसे गिरफ्तार किया जाएगा। चार कर्मचारियों - 63 वर्षीय शंकर शिंदे, 42 वर्षीय राजन चव्हाण, 45 वर्षीय गुरुदास लोकरे व 44 वर्षीय सुभाष भोसले की मौत हो गई क्योंकि वे पीछे बैठे थे और समय पर आपातकालीन निकास द्वार नहीं खोल पाए। छह अन्य कर्मचारी झुलस गए हैं। आगे की जांच जारी है।

****

434 दिन बाद अंतरिक्ष से लौटा अमेरिका का गुप्त विमान एक्स-37बी 434, अमेरिकी स्पेस फोर्स इसे एक्स-37बी कार्यक्रम में एक नए और रोमांचक अध्याय की शुरुआत के रूप में देख रही है।

हमास के साथ संबंध रखने पर अमेरिका में भारतीय छात्र हिरासत में, होगा डिपोर्ट

न्यूयार्क, प्रेट्र: अमेरिका में हमास का दुष्प्रचार फैलाने और इस संगठन के एक आतंकी से करीबी संबंध रखने के आरोप में एक भारतीय छात्र को हिरासत में लिया गया है। उसे अमेरिका से डिपोर्ट किया जाएगा। हिरासत में लिए गए बदर खान सूरी की पत्नी मफेज सालेह फलस्तीनी मूल की अमेरिकी नागरिक है। सूरी जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी का छात्र भी रह चुका है। यह मामला ऐसे समय सामने आया है, जब हमास का समर्थन करने पर भारतीय छात्रा रंजनी श्रीनिवासन का वीजा रद कर दिया गया था। इसके बाद छात्रा ने 11 मार्च को खुद को अमेरिका से डिपोर्ट कर लिया था।

अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग के प्रवक्ता ने कहा, सूरी का एक संदिग्ध आतंकी से घनिष्ठ संबंध है, जो हमास का वरिष्ठ सलाहकार है। सूरी हमास का दुष्प्रचार करता है और इंटरनेट मीडिया पर यहूदी विरोधी भावना को बढ़ाता है।

- अमेरिका में पोस्टडाक्टरल फेलो बदर खान सूरी की पत्नी फलस्तीनी मूल की
- सूरी ने दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी से कर रखी है पीएचडी
- हमास का समर्थन करने पर हाल ही में छात्रा रंजनी का रद किया गया वीजा

बदर खान सूरी। फाइल/जार्जटाउन.एजु

ये गतिविधियां निर्वासन योग्य हैं। वहीं, सूरी के अधिवक्ता हसन अहमद ने कहा, उनके मुवक्किल को सिर्फ इसलिए दंडित किया जा रहा है, क्योंकि उसकी पत्नी फलस्तीनी मूल की है। सूरी वाशिंगटन स्थित जार्जटाउन यूनिवर्सिटी के एडमंड ए वाल्श स्कूल आफ फारेन सर्विस में 'अलवलीद बिन तलाल सेंटर फार मुस्लिम-ईसाई अंडरस्टैंडिंग' में पोस्टडाक्टरल फेलो है। सूरी ने 2020 में दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी से पीएचडी की।

डिजिटल अखबार पालिटिको के अनुसार, अमेरिकी विदेश नीति का विरोध करने वाले छात्रों पर कार्रवाई के बीच संघीय आव्रजन अफसरों ने सूरी को हिरासत में लिया है। वह छात्र वीजा पर पढ़ाई व अध्यापन कर रहा है। नकाब पहने एजेंटों ने सोमवार रात वर्जीनिया में सूरी को उसके घर के बाहर से हिरासत में लिया। हसन अहमद ने कहा, सूरी का आपराधिक रिकार्ड नहीं है। उसे वर्जीनिया के सेंटर में ले जाया गया है। उसे टेक्सास के हिरासत केंद्र भेजा जा सकता है।

इजरायली हमलों से थर्राया गाजा, 91 फलस्तीनी मारे गए

देइर-अल-बलाह, एपी : गाजा पट्टी में रात भर हुए इजरायली हमलों में 91 फलस्तीनी मारे गए, जबकि बड़ी संख्या में लोग घायल हो गए। आधी रात को कई घरों को निशाना बनाया गया। मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। हवाई हमला शुरू होने के कारण फलस्तीनियों को जान बचाने के लिए फिर से घर छोड़कर भागना पड़ा है। इजरायली सेना ने कहा कि उसने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है। हमास ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए इजरायल पर राकेट दागे।

इजरायली विमानों ने आवासीय इलाकों में पर्चे गिराए और लोगों को उत्तर में बेत लाहिया और बेत हनून कस्बों, गाजा शहर के शेजैया और दक्षिण में खान यूनिस के पूर्वी बाहरी इलाकों के कस्बों से बाहर निकलने का आदेश दिया। सेना ने फलस्तीनियों को दक्षिण से उत्तरी गाजा में प्रवेश करने से भी रोक दिया है। लोगों को उत्तर की ओर जाने या वहां से बाहर निकलने के लिए मुख्य उत्तर-दक्षिण राजमार्ग का उपयोग न करने की चेतावनी

- सेना ने फलस्तीनियों के दक्षिण से उत्तरी गाजा जाने पर लगाई रोक
- युद्धविराम समाप्त होने के बाद पहली बार हमास ने इजरायल पर दागे राकेट

गाजा पट्टी में इजरायली हमले में क्षतिग्रस्त घर के पास शोकाकुल महिलाएं। रायटर »

दी है और कहा है कि गाजा के तटीय मार्ग के साथ केवल दक्षिण की ओर जाने की अनुमति होगी।

इस बीच, इजरायल में पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। घरेलू खुफिया सेवा के प्रमुख रोनेन बार को हटाने के कदम के खिलाफ तीसरे दिन भी प्रदर्शन जारी रहा। इजरायली कैबिनेट शुक्रवार को रोनेन बार की बर्खास्तगी को औपचारिक रूप से मंजूरी देने के लिए बैठक करने वाली है। उनके साथ वे लोग भी शामिल हो गए हैं जो युद्धविराम टूटने का विरोध कर रहे हैं।

इजरायल ने गाजा में संयुक्त राष्ट्र कार्यकर्ता की मौत पर दुख जताया: इजरायल ने गाजा पट्टी में संयुक्त राष्ट्र कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे बुल्गारियाई नागरिक की मौत पर दुख जताया। इजरायली विदेश मंत्रालय ने कहा कि घटना की परिस्थितियों के बारे में जांच की जा रही है। सेना घायलों को निकालने में सहायता कर रही है। उनका इजरायल के अस्पतालों में इलाज किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने युद्धविराम की आवश्यकता पर बल दिया है।

हाउती का दावा, हाइपरसोनिक मिसाइल से इजरायली हवाई अड्डे पर बोला हमला

सना, आइएएनएस : यमन के हाउती समूह ने दावा किया कि उसने गुरुवार सुबह तेल अवीव में बेन गुरियन हवाई अड्डे पर लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। हाउती के सैन्य प्रवक्ता याह्या सरिया ने कहा कि यह हमला हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल द्वारा किया गया था और सफलतापूर्वक अपना लक्ष्य हासिल किया। हालांकि इजरायल के रक्षा बलों ने कहा कि उसके सतर्क जवानों ने यमन में आतंकवादियों द्वारा दागी एक मिसाइल को नष्ट कर दिया। हाउती समूह ने यह भी दावा किया है कि लाल सागर में यूएसएस हैरी ट्रूमैन विमानवाहक पोत पर नया हमला किया गया। इसमें कई बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। इस पर अमेरिका की ओर से कोई टिप्पणी नहीं की गई है।

खुशहाली के तराजू में भारत आठ स्थान ऊपर, अमेरिकी प्रसन्नता में भारी गिरावट

'वर्ल्ड हैपीनेस डे' 2025 की रिपोर्ट में भारत 118वें और अमेरिका 24वें स्थान पर

खुशहाली में युद्धग्रस्त फलस्तीन और यूक्रेन इस साल भारत से भी आगे

लंदन, प्रेट्र : दानशीलता, दयालुता और मेलजोल से रहने में विश्व के देशों में व्याप्त प्रसन्नता को परखा गया है। इसमें खुशहाली के आठ पायदान ऊपर चढ़कर भारत ने इस साल विश्व में 118वां स्थान हासिल किया है। लेकिन पाकिस्तान, नेपाल, फलस्तीन और यूक्रेन जैसे देश खुशहाली में भारत से आगे हैं। दूसरी तरफ, अमेरिका की खुशहाली अब तक के अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच कर 24वें स्थान पर है। फिनलैंड लगातार आठ सालों से विश्व का सबसे प्रसन्न देश बना हुआ है। जबकि डेनमार्क, आइसलैंड और स्वीडन चार सर्वोच्च प्रसन्न देशों में शामिल हैं।

'वर्ल्ड हैपीनेस डे' की ताजा रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल आठ स्थानों का सुधार करते हुए भारत को हैपीनेस इंडेक्स में 118वां स्थान मिला क्योंकि हमारे देश ने दान के मामले में 57वीं रैंक पाई, 10 रैंक स्वेच्छा से किसी काम के लिए आगे आने पर है। अजनबियों की मदद करने पर 76

10 वीं रैंक है भारत की स्वेच्छा से किसी काम के लिए आगे आने में

57 वीं रैंक पाई है भारत ने दान देने वालों की श्रेणी में

76 वें नंबर पर हैं हम लोग अजनबियों की मदद करने के मामले में

68 वें स्थान पर है चीन, खुशहाली के मामले में वह आठ पायदान नीचे आया है

- वेलबीइंग रिसर्च सेंटर और आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने यह रिपोर्ट तैयार की है

प्रतीकात्मक

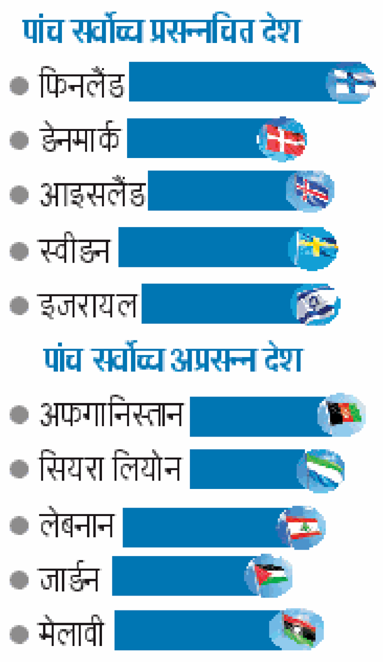

और किसी का बटुआ लौटाने में 115 (पड़ोसी), अजनबी (86) और पुलिस (93) है। जबकि भारत के कुछ पड़ोसी देश जैसे नेपाल (92), पाकिस्तान (109) हैपीनेस की रैंक में भारत से भी आगे रहे हैं। जबकि श्रीलंका (133) और बांग्लादेश (134) रैंक के साथ भारत से पीछे हैं। अफगानिस्तान सबसे अप्रसन्न देश है।

चीन में खुशहाली आठ पायदान घटकर 68वें स्थान पर है जबकि पिछले साल यह 60वें स्थान पर थी। आश्चर्यजनक रूप से खुशहाली में युद्धग्रस्त फलस्तीन और यूक्रेन इस साल भी भारत से आगे हैं। फलस्तीन की रैंक 108 और यूक्रेन की 111 है। इसी के साथ रिपोर्ट में कहा गया है कि 147 खुशहाल देशों की सूची में अब अमेरिका सबसे बीस खुशहाल देशों में भी शुमार नहीं हो सका है। इस बार उसकी रैंक 24 है जो अब तक के सभी सालों की न्यूनतम है। वह वर्ष 2012 में 11वें पायदान पर था। वहीं ब्रिटेन भी अमेरिका से एक पायदान ऊपर 23वें स्थान पर है।

20 मार्च को मनाए जाने वाले 'वर्ल्ड हैपीनेस डे' की 2025 की रिपोर्ट में बताया गया है कि वेलबीइंग रिसर्च सेंटर और आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने मिलकर यह रिपोर्ट तैयार की है। इसमें शामिल 147 देशों की प्रसन्नता का आधार संपत्ति और गाड़ी-बंगले से नहीं बल्कि लोगों के मददगार होने और मिल-बांटकर रहने की आदत से आंकी जाती है जिसका पैमाना सांस्कृतिक व संस्थागत विभेद के साथ ही दान, अजनबियों की मदद आदि करना होता है।

चिरंजीवी को ब्रिटिश संसद में लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड

नई दिल्ली, प्रेट्र: तेलुगु सिनेमा के सुपरस्टार चिरंजीवी कोनिडेला को ब्रिटिश सरकार से 'लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड' से सम्मानित किया है। ऐसा करने वाले वह पहले भारतीय अभिनेता बन चुके हैं। उन्हें लंदन में ब्रिटिश संसद में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

अभिनेता चिरंजीवी को सिनेमा और समाज में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 19 मार्च 2025 को लंदन स्थित ब्रिटेन की संसद के निचले सदन (हाउस आफ कामंस) में इस पुरस्कार से नवाजा गया है। यह विशेष सम्मान अभिनेता के अब तक के सफर और प्रभाव को दर्शाता है। ब्रिटेन की संसद में चिरंजीवी को मिला यह पुरस्कार भारतीय सिनेमा के लिए गर्व का पल है।

ब्रिज इंडिया नामक एक थिंकटैंक है जिसने पहली बार चिरंजीवी को 'लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड' से सम्मानित किया। यह पुरस्कार अभिनेता को सिनेमा, सार्वजनिक सेवा और परोपकार में उनके योगदान के लिए दिया गया। ब्रिटेन की लेबर पार्टी के सांसद नवेंदु मिश्रा, सांसद सोजन जोसेफ, बाब ब्लैकमैन इस सम्मान समारोह का हिस्सा थे। यह सम्मान प्राप्त करने के बाद चिरंजीवी के फैन पुरस्कार समारोह की फोटो और वीडियो इंटरनेट मीडिया पर साझा कर रहे हैं।

- तेलुगु सुपरस्टार यह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय बने

अभिनेता चिरंजीवी को ब्रिटिश संसद में आयोजित कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। इंस्टाग्राम/चिरंजीवी कोनिडेला

उल्लेखनीय है कि पिछले साल चिरंजीवी को भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार 'पद्म विभूषण' से सम्मानित किया गया। इसी साल अभिनेता का नाम 537 गानों और 156 फिल्मों में 24,000 डांस स्टेप्स के साथ सबसे सफल अभिनेता डांसर के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकार्ड में दर्ज हुआ। उन्हें अक्किनेनी इंटरनेशनल फाउंडेशन द्वारा 2024 में एएनआर शताब्दी वर्ष में एएनआर राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया।

एरिजोना की भारतवंशी सीनेटर प्रिया राइजिंग स्टार अवार्ड के लिए नामित

ह्यूस्टन, प्रेट्र : अमेरिका के एरिजोना राज्य की भारतवंशी सीनेटर प्रिया सुंदरेशन को प्रतिष्ठित गैब्रिएल गिफर्ड्स राइजिंग स्टार पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। मतदान अधिकार, पर्यावरण संरक्षण और प्रजनन अधिकार जैसे मुद्दों पर उनके साहसिक नेतृत्व के लिए इस सम्मान के लिए उनका चयन किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार इस साल के अंत में एमिलीज लिस्ट द्वारा दिया जाएगा। एमिलीज लिस्ट अमेरिकी पालिटिकल एक्शन कमेटी (पीएसी) है। एरिजोना के 18वें सीनेट जिले के प्रतिनिधि के रूप में प्रिया राज्य की राजनीति में शक्तिशाली आवाज के रूप में उभरी हैं। उन्होंने गर्भपात पर कड़े प्रतिबंधों का कड़ा विरोध किया है और गर्भनिरोधक तक पहुंच की रक्षा के लिए विधेयक पेश किया है। सीनेट में अल्पसंख्यक नेता के रूप में वह प्रमुख समितियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्हें 2023 में राइजिंग एनवायरनमेंटल लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2006 में एमआइटी से केमिकल इंजीनियरिंग में स्नातक करने के बाद प्रिया ने 2011 में एरिजोना विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में मास्टर की उपाधि प्राप्त की।

प्रिया। फाइल

इस्तांबुल के मेयर की गिरफ्तारी के बाद भड़काऊ पोस्ट करने में 37 गिरफ्तार

इस्तांबुल, एपी: तुर्किये में इस्तांबुल के मेयर एक्रेम इमामोग्लू की गिरफ्तारी के बाद इंटरनेट मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने के आरोप में 37 लोगों को हिरासत में लिया गया है।

आंतरिक मंत्री अली येरलिकाया ने कहा कि अधिकारियों ने 261 इंटरनेट मीडिया अकाउंट की पहचान की है, जो सार्वजनिक घृणा या अपराध को भड़काने वाले पोस्ट साझा कर रहे हैं। इनमें 62 ऐसे हैं जो विदेश में रहने वाले लोगों द्वारा चलाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अन्य संदिग्धों को हिरासत में लेने के प्रयास जारी हैं। इमामोग्लू को कथित भ्रष्टाचार और आतंकी संबंधों के आरोप में बुधवार को उनके आवास से गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा कई अन्य प्रमुख हस्तियों को भी हिरासत में लिया गया है।

मेयर एक्रेम को राष्ट्रपति राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन के प्रमुख प्रतिद्वंद्वी माना जाता है। उनकी गिरफ्तारी के बाद शहर में प्रदर्शनों पर चार दिन के प्रतिबंध और सड़क बंद किए जाने के बावजूद

इस्तांबुल में मेयर एक्रेम इमामोग्लू की गिरफ्तारी के विरोध में गुरुवार को भी प्रदर्शन हुए। रायटर

इस्तांबुल और अन्य जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुए। राजधानी अंकारा में छात्रों के प्रदर्शन के बाद कई लोगों को हिरासत में लिया गया।

भारत के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध, पर लगाता है सबसे अधिक टैरिफ : ट्रंप

न्यूयार्क, प्रेट्र: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उम्मीद जताई है कि भारत अमेरिकी वस्तुओं पर टैरिफ में कटौती करेगा। उन्होंने कहा कि भारत के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध है, लेकिन वह अमेरिकी उत्पादों पर सबसे अधिक टैरिफ लगाने वाले देशों में शामिल है। ट्रंप ने इसके साथ ही अपनी उस धमकी को दोहराया भी है कि वह दो अप्रैल से भारत पर पारस्परिक शुल्क लगाएंगे।

ट्रंप ने अमेरिकी न्यूज वेबसाइट ब्रेइटबार्ट न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में भारत के साथ अमेरिका के संबंधों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ पिछले महीने व्हाइट हाउस में हुई वार्ता के बारे में पूछे जाने पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि भारत के साथ उनके संबंध बहुत अच्छे हैं, लेकिन भारत के साथ एकमात्र समस्या यह है कि वह दुनिया में सबसे अधिक टैरिफ लगाने वाले देशों में एक है। उन्होंने कहा, 'मेरा मानना है

- दो अप्रैल से भारत पर पारस्परिक शुल्क लगाने की धमकी को दोहराया
- कहा, हम उन पर उतना ही टैरिफ लगाएंगे, जितना वे हम पर लगाते हैं

डोनाल्ड ट्रंप। फाइल

कि वे संभवतः उन शुल्कों को काफी हद तक कम करने जा रहे हैं, लेकिन दो अप्रैल से हम उन पर उतना ही टैरिफ लगाएंगे, जितना वे हम पर लगाते हैं।' भारत-पश्चिम एशिया-यूरोप आर्थिक गलियारे (आइएमईसी) के बारे में पूछे जाने पर ट्रंप ने खासतौर पर चीन का जिक्र नहीं किया, लेकिन कहा कि यह अद्भुत देशों का समूह है, जो व्यापार पर हमें नुकसान पहुंचाने वाले दूसरे देशों का मुकाबला करने के लिए एक साथ आ रहे हैं।' ट्रंप ने मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान आइएमईसी पर हस्ताक्षर किए थे।

बता दें कि इस महीने की शुरुआत में ट्रंप ने कहा था कि भारत अपने टैरिफ में काफी कटौती करने पर सहमत हो गया है। उन्होंने अपना यह दावा भी दोहराया था कि अमेरिका पर भारत बहुत अधिक टैरिफ लगाता है, जिससे वहां उत्पाद बेचना मुश्किल हो जाता है। हालांकि गत 10 मार्च को नई दिल्ली में वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल ने एक संसदीय समिति को बताया था कि वार्ता अब भी जारी है और भारत-अमेरिका के बीच व्यापार शुल्क पर अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ है।

टेक्सास की सीनेट ने प्रस्ताव पारित कर होली को दी मान्यता

ह्यूस्टन, प्रेट्र : टेक्सास की सीनेट ने होली को मान्यता देने वाला अपना पहला प्रस्ताव पारित किया। इसमें आधिकारिक तौर पर रंगों के त्योहार होली को महत्वपूर्ण सांस्कृतिक उत्सव के रूप में मान्यता दी गई है। यह औपचारिक रूप से होली को मान्यता देने वाला जार्जिया और न्यूयार्क के बाद तीसरा राज्य बन गया है। यह प्रस्ताव टेक्सास में भारतीय अमेरिकी समुदाय के बढ़ते सांस्कृतिक योगदान को मान्यता देने में मील का पत्थर है।

यह प्रस्ताव सीनेटर सारा एकहार्ट ने पेश किया था। इसे 14 मार्च को होली से ठीक पहले पारित किया गया था। यह होली के सांस्कृतिक व आध्यात्मिक महत्व पर प्रकाश डालता है। प्रस्ताव में कहा गया है कि इस उल्लासपूर्ण त्योहार की उत्पत्ति कई सहस्राब्दियों पहले की है और यह दुनिया भर में सभी पृष्ठभूमि के लोगों द्वारा मान्यता प्राप्त है। सीनेट ने सामुदायिक रिश्तों की मजबूती व टेक्सास की सांस्कृतिक विविधता की समृद्धि में

- इस त्योहार को मान्यता देने वाला यह अमेरिकी का तीसरा राज्य

होली की भूमिका पर जोर दिया। ह्यूस्टन, डीसी में भारत के महावाणिज्यदूत मंजूनाथ ने कहा, यह टेक्सास के लिए गौरवपूर्ण व ऐतिहासिक क्षण है। सीनेट द्वारा होली को मान्यता देना विविधता, एकता, मित्रता और सांस्कृतिक विरासत के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।

कनाडा का आरोप, चीन ने चार कनाडाई नागरिकों को दी मौत की सजा

टोरंटो, एपी: कनाडा के विदेश मंत्री मेलानी जोली ने बुधवार को कहा, चीन ने हाल के महीनों में चार कनाडाई नागरिकों को मौत की सजा दी है। जोली ने दोहरी नागरिकता वाले लोगों से जुड़े नशीले पदार्थों से संबंधित आरोपों में क्षमादान की मांग की है। ओटावा में चीनी दूतावास ने कहा, बीजिंग दोहरी नागरिकता को मान्यता नहीं देता। जोली ने कहा, हम सजा की कड़ी निंदा करते हैं। मैंने व्यक्तिगत रूप से नरमी बरतने की मांग की है।

वैश्विक मामलों की प्रवक्ता चार्लोट मैकलियोड ने कहा, वे परिवारों को कांसुलर मदद देना जारी रखते हैं और अनुरोध करते हैं कि मीडिया उनकी गोपनीयता का सम्मान करे। कहा कि ओटावा राबर्ट शेलेनबर्ग के लिए क्षमादान की वकालत करना जारी रखेगा, जो कनाडाई नागरिक है और जिसे ड्रग तस्करी के लिए मौत की सजा सुनाई गई थी। चीनी दूतावास ने कहा, चीन हमेशा नशीले पदार्थों से संबंधित अपराधों पर कठोर दंड देता है।

नवाज को बेटी की सरकार में मिली इमारतों के जीर्णोद्धार की जिम्मेदारी

लाहौर, प्रेट्र : पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को पंजाब प्रांत में अपनी बेटी मरियम नवाज की सरकार में नई जिम्मेदारी मिली है। तीन बार प्रधानमंत्री रह चुके नवाज अब लाहौर अथारिटी फार हेरिटेज रिवाइवल (एलएएचआर) के संरक्षक-इन-चीफ बन गए हैं। नवाज लाहौर में औपनिवेशिक काल की कई इमारतों के जीर्णोद्धार का काम देखेंगे।

जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी ने सत्तारूढ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज के अध्यक्ष का मजाक उड़ाया और कहा कि सरकारी नौकरी मिलने पर बधाई।

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वरिष्ठ नेता शौकत बसरा ने गुरुवार को से कहा कि नवाज शरीफ 2024 के चुनावों में अपनी पार्टी की अपमानजनक हार के बाद सेवानिवृत्त जीवन जी रहे हैं। इमरान खान का जनादेश चुराकर नवाज और जरदारी की पार्टियों पीएमएलएन (पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज) और पीपीपी (पाकिस्तान

- इमरान खान की पार्टी ने नवाज शरीफ का उड़ाया मजाक, कहा-सरकारी नौकरी मिलने पर बधाई

नवाज शरीफ। मरियम नवाज। फाइल

पीपुल्स पार्टी) को दे दिया गया। अब नवाज शरीफ की बेटी पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम ने उन्हें कुछ काम दिया है। नवाज के स्वास्थ्य के लिए बेहतर होगा कि वह सेवानिवृत्त राजनेता के रूप में पुरानी इमारतों की मरम्मत जैसे कुछ काम में खुद को व्यस्त रखें। उल्लेखनीय है कि लाहौर बहुत पुराना शहर है, यहां कई ऐतिहासिक इमारतें हैं, जो देखरेख के अभाव में बुरी हालत में हैं।

शिक्षा विभाग बंद करने के लिए कार्यकारी आदेश जारी करेंगे ट्रंप

वाशिंगटन, रायटर: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शिक्षा विभाग को बंद करने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करने वाले हैं। हालांकि कार्यकारी आदेश जारी होने से पहले ही यह मामला कोर्ट में पहुंच गया है।

डेमोक्रेटिक अटार्नी जनरलों के एक समूह ने कोर्ट में मुकदमा दायर किया है, जिसमें ट्रंप को विभाग खत्म करने से रोकने की मांग की गई है। नागरिक अधिकार समूह एनएएसीपी ने भी ट्रंप के संभावित कार्यकारी आदेश को असंवैधानिक करार दिया है। हालांकि ट्रंप संसद की मंजूरी के बगैर शिक्षा विभाग को बंद नहीं कर सकते। डेमोक्रेटिक सीनेटरों ने भी शिक्षा विभाग को बंद करने के कदम का समर्थन करने के लिए कोई संकेत नहीं दिया है। बता दें कि ट्रंप और उनके अरबपति सलाहकार एलन मस्क सरकारी खर्चों में कटौती के लिए तमाम सरकारी कार्यक्रमों और संस्थानों को बंद करने का प्रयास कर रहे हैं।

****

खालिदा की पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़े, एक की मौत

ढाका, आइएएनएस: बांग्लादेश में बढ़ती हिंसा के बीच पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की पार्टी के कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। इसमें एक की मौत हो गई और कई घायल हो गए। यह घटना बुधवार रात चटगांव जिले में हुई।

स्थानीय मीडिया के अनुसार, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के पूर्व सांसद गियासुद्दीन कादर चौधरी और चटगांव उत्तर के पार्टी संयोजक गुलाम अकबर के समर्थकों के बीच हिंसक झड़प हुई। यह घटना उस समय हुई, जब इफ्तार पार्टी चल रही थी। कुछ लोग पहुंचे और कार्यक्रम रोकने की मांग करने लगे, जिसके बाद बहस ने हिंसक झड़प का रूप ले लिया।

स्थानीय लोगों ने बताया कि उन्होंने गोलियों की आवाज सुनी। इसी तरह की एक घटना मंगलवार को सिराजगंज में भी हुई। यहां भी बीएनपी कार्यकर्ता आपस में टकरा गए थे और 11 घायल हुए थे। बांग्लादेश में गत पांच अगस्त को शेख

- चटगांव जिले में बुधवार रात इफ्तार पार्टी के दौरान हुआ संघर्ष
- लोगों ने झगड़े के दौरान गोलियां चलने की भी बात कही

हसीना की सरकार अपदस्थ होने के बाद बीएनपी के विभिन्न धड़ों में शक्ति प्रदर्शन के प्रयास में टकराव बढ़ गया है। बीएनपी को इस बात का भरोसा है कि वह देश के अगले चुनाव को जीतकर सत्ता में वापसी करेगी।

उल्लेखनीय है कि हिंसक छात्र आंदोलन और शेख हसीना सरकार के अपदस्थ होने के बाद से बांग्लादेश में हालात बहुत खराब हैं। हालांकि अंतरिम सरकार का गठन कर देश के शासन प्रशासन को चलाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन हालात सुधर नहीं रहे हैं। कट्टरपंथी मनमानी करने और अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित करने में जुटे हुए हैं।

11 वर्ष पहले लापता विमान की फिर तलाश कराएगा मलेशिया

कुआलालंपुर, एपी: मलेशिया की सरकार 11 वर्ष पहले हिंद महासागर में लापता हुए विमान की फिर से तलाश कराने जा रही है। सरकार ने टेक्सास स्थित एक मरीन रोबोटिक्स कंपनी को नई खोज शुरू करने की अंतिम मंजूरी दे दी है। मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट 370 हिंद महासागर में दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। आठ मार्च 2014 को बोइंग 777 विमान कुआलालंपुर से उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही रडार से गायब हो गया था। बीजिंग की इस उड़ान में 239 लोग सवार थे, जिनमें ज्यादातर चीनी नागरिक थे।

मलेशिया के परिवहन मंत्री एंथनी लोके ने कहा, कैबिनेट ने टेक्सास स्थित ओशन इंफिनिटी के साथ 'खोज नहीं, शुल्क नहीं' अनुबंध के लिए शर्तों व नियमों को मंजूरी दी है। इसके तहत कंपनी समुद्र में घटनास्थल के 15 हजार वर्ग किमी के दायरे में जांच शुरू करेगी। कंपनी को मलबा खोज निकालने पर ही सात करोड़ डालर का भुगतान किया जाएगा।

कोलकाता नाइटराइडर्स और चेन्नई सुपरकिंग्स का स्पिन अटैक सबसे मारक : पीयूष चावला

पीयूष चावला ● इंस्टाग्राम

साक्षात्कार

आइपीएल के दूसरे सफल गेंदबाज पीयूष चावला का कहना है कि 22 मार्च से शुरू हो रहे टूर्नामेंट में सभी टीमें अच्छी हैं, लेकिन सीएसके और केकेआर का स्पिन विभाग काफी संतुलित है। आइपीएल 18 में जियो स्टार विशेषज्ञ की भूमिका में दिखने वाले पीयूष ने कहा कि आइपीएल में कलाई के स्पिनर हमेशा ही कारगर होते हैं। **पीयूष चावला** से **नितिन नागर** ने विशेष बात की। पेश हैं प्रमुख अंश :-

● **क्या आपको लगता है कि टी-20 में अब भी क्लासिक लेग स्पिनर्स के लिए उतनी ही जगह है, जितनी पहले थी?**

-देखिए, कलाई के स्पिनर की जगह तो उतनी ही अहम रहती है क्योंकि बीच के ओवरों में विकेट चटकाना बहुत जरूरी होता है। न सिर्फ बीच के ओवर में बल्कि मैच के किसी भी चरण में, चाहे वो शुरू के छह ओवर हों या बीच के आठ ओवर हो या फिर आखिर के आठ ओवर हों। तो स्पिनर की जरूरत हमेशा ही पड़ती है क्योंकि उसके पास वैरिएशन होते हैं और उन वैरिएशन में जब बल्लेबाज जोखिम लेता है तो विकेट मिलने का मौका होता है। अगर आप आइपीएल में भी देखें तो सबसे ज्यादा विकेट लेने वालों में शीर्ष दो स्थानों पर लेग स्पिनर ही हैं।

● **किस टीम का स्पिन अटैक आपको सबसे ज्यादा संतुलित दिख रहा है?**

-दो टीमों का स्पिन आक्रमण काफी संतुलित दिख रहा है। एक है सीएसके क्योंकि अगर आप देखें तो उनके पास तीन क्वालिटी स्पिनर हैं अश्विन, जडेजा और नूर अहमद। ये तीनों आपको अंतिम एकादश में खेलते नजर आ सकते हैं। दूसरी टीम है केकेआर, वहां सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती हैं। साथ ही उनके पास मयंक मार्कंडेय भी हैं। हालांकि उन्हें इतना अवसर नहीं मिलेगा, लेकिन वह काफी समय से आइपीएल खेल रहे हैं और उनका अनुभव टीम को मिलेगा।

● **हाल के दिना में किस स्पिनर ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया है और क्यों? इस आइपीएल में आपको किस से सबसे ज्यादा उम्मीदें होंगी?**

-जिस तरह से वरुण चक्रवर्ती ने प्रदर्शन किया है, वह शानदार है। वह लंबे समय तक टीम से बाहर थे और उसके बाद भारतीय टीम में वापसी की। वह गेंदबाजी में काफी असरदार नजर आए हैं। अनकैप्ड में एक स्पिनर हैं, सुयश शर्मा, जिन पर इस बार काफी जिम्मेदारी होगी। अब वह उस दबाव में निखर कर आते हैं या दब जाते हैं यह देखना होगा। सुयश अब आरसीबी की टीम में हैं और वहां मुख्य स्पिनर की भूमिका में होंगे। केकेआर में उन्हें वरुण और सुनील का पूरा साथ मिला था, तो दबाव थोड़ा कम था। सुयश अच्छे गेंदबाज हैं, लेकिन दबाव किस तरह झेलते हैं, यह बहुत अहम होगा।

● **बीसीसीआइ ने आइपीएल में गेंद पर लार (स्लाइवा) लगाने से रोक हटा दी है। ऐसे में गेंदबाजों को कितना लाभ होगा?**

-मैं इस कदम से खुश हूं क्योंकि आपको आइपीएल जैसे टूर्नामेंट में गेंदबाजों को भी कुछ तो देना ही पड़ेगा। अब गेंद पर लार का इस्तेमाल करने से गेंदबाजों को जरूर रिवर्स स्विंग मिल सकता है। हालांकि डे नाइट मैच में इतना असर नहीं पड़ता है, लेकिन जहां दिन का मैच है और ड्राई कंडीशन होती है तो गेंद हरकत करती है। ये गेंदबाजों के नजरिये से एक बेहतर कदम है।

● **आप तीनों चैंपियन टीम मुंबई इंडियंस, सीएसके और केकेआर से खेल चुके हैं। क्या इन टीमों को दूसरी फ्रेंचाइजियों से विशेष बनाता है?**

-देखिए, टीम का जो माहौल होता है वह बहुत निर्भर करता है टीम की सफलता में। आप केवल ग्राउंड पर क्रिकेट नहीं खेलते हो। आप ढाई-तीन महीने साथ रहते हो और किस तरह से खिलाड़ियों के बीच बांडिंग हो रही है, वो काफी महत्वपूर्ण होता है। ये तीन टीमें ऐसी हैं, जो खिलाड़ियों को जिस तरह से साथ रखती हैं। हर चीज का ख्याल रखा जाता है। टीम बांडिंग में बहुत सारे क्रिकेट पर चर्चाएं होती हैं। जब इस तरह का खुशनुमा माहौल मिलता है तो आप मैदान में बिना दबाव के खेलते हो। हालांकि खुद खिलाड़ियों पर प्रदर्शन करने का दबाव रहता है, लेकिन टीम जब उनके ऊपर कोई दबाव नहीं बनाती है तो खिलाड़ी और खुलकर खेलता है।

● **इस बार प्लेआफ में आपके चार दावेदार कौन होंगे?**

-जिस तरह से टीमें बनकर आई हैं, उसमें मुंबई की टीम काफी अच्छी है। नीलामी में पंजाब किंग्स ने जिस तरह की टीम बनाई है, वह भी प्लेआफ की दावेदार है। इसके अलावा सीएसके को आपको नजरअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि उसके पास अनुभव है। सीएसके को अच्छा क्रिकेट खेलकर क्वालीफाई करने की आदत है और वह टीम काफी अच्छी नजर आ रही है। चौथी टीम कोई भी हो सकती है।

दूसरी पारी में मिलेंगी दो गेंद, लार से रोक हटी

मुंबई में हुई आइपीएल कप्तानों की बैठक में बीसीसीआइ ने किए कई अहम बदलाव, इंपैक्ट प्लेयर नियम अभी जारी रहेगा

कप्तानों की बैठक में हुए निर्णय

- बीसीसीआइ ने कप्तानों की सहमति के बाद गेंद पर लार लगाने से रोक हटाई
- ओस को देखते हुए अब दूसरी पारी में 11वें ओवर के बाद मिल सकेगी नई गेंद
- धीमी ओवर गति उल्लंघन के लिए कप्तानों पर नहीं लगेगा प्रतिबंध
- बोर्ड ने इंपैक्ट प्लेयर नियम को बरकरार रखने का निर्णय किया

ट्राफी के साथ संजू सैमसन, रिषभ पंत, रहाणे, शुभमन, श्रेयस, पैट कमिंस, रुतुराज, रजत पाटीदार, हार्दिक और अक्षर पटेल ● बीसीसीआइ

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली: बीसीसीआइ ने 22 मार्च से शुरू हो रहे इंडियन प्रीमियर लीग (आइपीएल) के 18वें संस्करण से पहले गुरुवार को कई अहम बदलावों को मंजूरी दी। मुंबई में बीसीसीआइ मुख्यालय पर हुई आइपीएल की सभी कप्तानों की बैठक में सबसे बड़ा फैसला गेंद पर लार (स्लाइवा) लगाने पर रोक हटाने को लेकर किया गया। अधिकांश कप्तान गेंद से लार लगाने पर लगे प्रतिबंध को हटाने के पक्ष में थे।

आइसीसी ने कोविड-19 महामारी के दौरान एहतियात के तौर पर गेंद को चमकाने के लिए लार लगाने की सदियों पुरानी प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था और बाद में 2022 में विश्व संस्था ने इस प्रतिबंध को स्थायी कर दिया था। आइपीएल ने भी कोविड-19 महामारी के बाद लीग में खेल की शर्तों में आइसीसी प्रतिबंध को शामिल किया, लेकिन इसके दिशा-निर्देश खेल की संचालन संस्था के दायरे से बाहर हैं। इस तरह गुरुवार को लिए गए इस फैसले से आइपीएल कोविड-19 महामारी के बाद लार के उपयोग को फिर से शुरू करने वाला पहला बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट बन गया है। हाल में भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने चैंपियंस ट्राफी के दौरान गेंद पर लार लगाने की रोक को हटाने की वकालत की थी।

इसके साथ ही बीसीसीआइ ने मैच की दूसरी पारी में दूसरी गेंद के नियम को भी लागू करने का निर्णय किया है। बीसीसीआइ के एक अधिकारी ने बताया कि यह नियम दिन रात के मैचों में ओस को देखते हुए लिया गया है। ओस के कारण गेंद करने में काफी मुश्किल होती है। ऐसे में दूसरी पारी में 11वें ओवर से गेंदबाज नई गेंद ले सकेंगे। दूसरी गेंद का इस्तेमाल होने से अब टास जीतने वाले कप्तान को मिलने वाला लाभ समाप्त हो जाएगा।

इसके साथ ही अब धीमी ओवर गति के लिए कप्तानों पर लगने वाले प्रतिबंध को भी हटा लिया गया है। इससे पहले तीन मैचों में धीमी ओवर गति के लिए कप्तान पर एक मैच का प्रतिबंध लगाया गया था। पिछले सत्र में दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान रिषभ पंत पर एक मैच का प्रतिबंध लगा था और पिछले सत्र में उल्लंघन के लिए मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या पर सीएसके के विरुद्ध होने वाले मैच के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। बीसीसीआइ अधिकारी ने बताया, अब कप्तानों को डिमेरिट अंक के साथ जुर्माना लगाया जाएगा, लेकिन उन पर प्रतिबंध नहीं लगेगा। लेवल 1 के अपराध के लिए डिमेरिट अंक के साथ 25 से 75 प्रतिशत मैच फीस का जुर्माना लगेगा। लेवल 2 अपराध के लिए चार डिमेरिट अंक दिए जाएंगे। हर चार डिमेरिट अंक के लिए मैच रेफरी जुर्मान लगाएंगे। इसमें मैच फीस का 100 प्रतिशत जुर्माना या डिमेरिट अंक शामिल होंगे। इन डिमेरिट अंकों के लिए भविष्य में मैच प्रतिबंध लगाया जा सकता है, लेकिन धीमी ओवर गति के लिए नहीं। इसके साथ ही बीसीसीआइ ने इंपैक्ट प्लेयर नियम को लागू रखा है। हालांकि 2027 संस्करण के बाद इस नियम की समीक्षा की जाएगी।

पहले तीन मैचों में रियान होंगे रायल्स के कप्तान

नई दिल्ली, प्रेट्र : रियान पराग पहले तीन आइपीएल मैचों में राजस्थान रायल्स के कप्तान होंगे क्योंकि नियमित कप्तान संजू सैमसन को अंगुली की सर्जरी के बाद बीसीसीआइ ने विकेटकीपिंग से मना किया है जिसके मायने है कि वह इन मैचों में सिर्फ बतौर बल्लेबाज ही उपलब्ध होंगे। सैमसन की अंगुली में फ्रैक्चर हो गया था जिसके बाद उन्हें छोटी सर्जरी करानी पड़ी। उन्हें बल्लेबाजी की अनुमति मिल गई है लेकिन बेंगलुरु में उत्कृष्टता केंद्र की मेडिकल और खेल विज्ञान टीमों ने उन्हें अंगुली को आराम देने की सलाह दी है।

केकेआर-एलएसजी के बीच छह अप्रैल का मैच अब गुवाहाटी में होगा

राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता: कोलकाता नाइटराइडर्स व लखनऊ सुपरजायंट्स के बीच आगामी छह अप्रैल को होने वाला मैच अब कोलकाता की जगह गुवाहाटी में होगा। कोलकाता पुलिस ने रामनवमी का हवाला देते हुए उस दिन मैच के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने में असमर्थता जताई थी, जिसके बाद बंगाल क्रिकेट संघ (कैब) ने बीसीसीआइ को जानकारी दी।

सूत्रों के अनुसार केकेआर टीम प्रबंधन अपने घरेलू मैदान ईडन गार्डेंस स्टेडियम में ही यह मैच खेलना चाहता था। उसने मैच की तिथि बदलने का प्रस्ताव दिया था, हालांकि बीसीसीआइ ने इन्कार कर दिया और गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में मैच कराने का निर्णय लिया। पिछले साल भी ईडन में 17 अप्रैल को रामनवमी के दिन कोलकाता-राजस्थान का दिन बदला गया था।

नए सत्र की शुरुआत से पहले पंजाब किंग्स ने की पूजा

पंजाब किंग्स की टीम ने आइपीएल के नए सत्र से पहले गुरुवार को न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर के पीसीए स्टेडियम में पूजा की। पंजाब अपना अभियान 25 मार्च को अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस के विरुद्ध करेगी ● पंजाब किंग्स

चैंपियंस ट्राफी विजेता भारतीय टीम को मिलेंगे ₹58 करोड़

बीसीसीआइ ने टीम की सफलता पर घोषित किया इनाम, भारतीय टीम ने फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर जीता था खिताब

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली: बीसीसीआइ ने दुबई में इस महीने आइसीसी चैंपियंस ट्राफी जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम के लिए 58 करोड़ रुपये नकद पुरस्कार की घोषणा की। रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम ने फाइनल में न्यूजीलैंड को चार विकेट से हराकर तीसरी बार चैंपियंस ट्राफी जीती। यह पुरस्कार खिलाड़ियों, कोचिंग और सहयोगी स्टाफ और अजित अगरकर की अध्यक्षता वाली चयन समिति समेत बीसीसीआइ अधिकारियों को मिलेगा।

बीसीसीआइ अध्यक्ष रोजर बिन्नी ने एक बयान में कहा ,'लगातार दो आइसीसी खिताब जीतना विशेष है। यह पुरस्कार विश्व स्तर पर टीम इंडिया की प्रतिबद्धता और उत्कृष्टता के लिए है।' बीसीसीआइ सचिव देवाजीत सैकिया ने कहा कि इस जीत से साबित होता है कि भारत सीमित गेंद के प्रारूपों में शीर्ष रैंकिंग का हकदार है। सैकिया ने कहा, 'विश्व क्रिकेट में भारत का दबदबा कड़ी मेहनत और कुशल रणनीति का परिणाम है। इस जीत से साबित होता है कि सीमित ओवरों के क्रिकेट में भारत शीर्ष रैंकिंग का हकदार है और हमें यकीन है कि आगे भी टीम यूं ही प्रदर्शन करती रहेगी।'

बीसीसीआइ उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा कि खिलाड़ियों ने आइसीसी टूर्नामेंट में दबाव के बीच शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा, 'खिलाड़ियों ने दबाव में भी शानदार प्रदर्शन किया। उनकी सफलता प्रेरणास्रोत बनेगी। टीम ने फिर साबित कर दिया कि भारतीय क्रिकेट कौशल, मानसिक दृढ़ता और जीत की मानसिकता की मजबूत नींव पर खड़ा है।'

ट्राफी के साथ रोहित शर्मा ● फाइल फोटो

किसे कितना मिलेगा

- 3-3 करोड़ रुपये टीम में शामिल सभी 15 खिलाड़ियों और मुख्य कोच गंभीर मिलेंगे
- 50-50 लाख रुपये बाकी कोचिंग स्टाफ को मिलेंगे
- 25-25 लाख रुपये बीसीसीआइ से जुड़े अन्य अधिकारी जैसे वीडियो एनालिस्ट, लायजन अफसर, मीडिया मैनेजर समेत अन्य सदस्य शामिल हैं
- 30 लाख रुपये चयन समिति के प्रमुख अजीत अगरकर को मिलेंगे
- 19.45 करोड़ रुपये आइसीसी ने भारतीय टीम को इनाम के रूप में मिला था, जिसमें प्रत्येक खिलाड़ी को 1.43 करोड़ रुपये मिले

खेलो इंडिया में दम दिखाएंगे 1300 पैरा एथलीट

खेलों का उद्घाटन करते केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया व अन्य ● हरीश कुमार

जासं, नई दिल्ली: केंद्रीय युवा मामले एवं खेल तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री डा. मनसुख मांडविया ने गुरुवार को इंदिरा गांधी स्टेडियम परिसर के केडी जाधव इंडोर हाल में खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया। आठ दिनों तक चलने वाले इस प्रतिष्ठित आयोजन में छह खेल विधाओं में 1300 से अधिक पैरा एथलीट अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे।

इस अवसर पर छह प्रमुख भारतीय पैरालिंपियन सिमरन शर्मा (एथलेटिक्स), प्रवीण कुमार (बैडमिंटन), नितेश कुमार (बैडमिंटन), नित्या (बैडमिंटन) और प्रीति पाल (एथलेटिक्स) ने केंद्रीय मंत्री डा. मनसुख मांडविया, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डा. वीरेंद्र कुमार, अरुणाचल प्रदेश के खेल और युवा मामलों के मंत्री केंटो जिनी, और भारतीय पैरालिंपिक समिति के अध्यक्ष देवेंद्र झाझरिया के साथ मिलकर एक मशाल ली के माध्यम से खेलों को औपचारिक रूप से हरी झंडी दिखाई।

डा. मनसुख मांडविया ने कहा, खेलो इंडिया कार्यक्रम भारतीय खेलों के लिए एक क्रांतिकारी पहल बन चुका है। चाहे वह खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो, स्कूल गेम्स, विंटर गेम्स या पैरा गेम्स। हमारे एथलीट हर मंच पर देश को गौरवान्वित कर रहे हैं।'' उन्होंने पेरिस पैरालिंपिक 2024 में भारत के 29 पदकों का जिक्र करते हुए कहा, जब कोई दृढ़ निश्चयी होता है, सही दिशा में आगे बढ़ता है और कड़ी मेहनत करता है, तो सफलता निश्चित होती है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स एथलीटों के लिए नए अवसर और सफलता की राहें खोल रहा है, जो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन का हिस्सा है।

बीएफआइ को अनुराग ठाकुर का नामांकन स्वीकार करने का निर्देश

अनुराग सिंह ठाकुर

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने निर्वाचन मंडल से नाम हटाने के फैसले पर रोक लगाई

विधि संवाददाता, जागरण, शिमला: हिमाचल हाई कोर्ट ने भारतीय मुक्केबाजी महासंघ (बीएफआइ) के निर्वाचक मंडल के लिए अनुराग सिंह ठाकुर के नामांकन को रद करने के आदेश पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने हिमाचल प्रदेश मुक्केबाजी संघ (एचपीबीए) की ओर से दायर याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के बाद बीएफआइ को आगामी चुनाव का लेकर अनुराग का नामांकन स्वीकार करने का निर्देश किया।

एचपीबीए ने अनुराग सिंह ठाकुर को महासंघ के चुनाव के लिए नामित किया था। बीएफआइ के अध्यक्ष ने सात मार्च को नोटिस जारी कर शर्त लगाई थी कि बीएफआइ से संबद्ध राज्य इकाइयों के केवल वास्तविक और विधिवत रूप से निर्वाचित सदस्य ही चुनाव में संबंधित राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकृत होंगे। इस नोटिस के आधार पर अनुराग सिंह ठाकुर के नामांकन को रद कर दिया गया था। कोर्ट ने बीएफआइ को आदेश दिया कि वह अनुराग के नामांकन को राजेश भंडारी के नामांकन के साथ निर्वाचक मंडल के लिए वैध नामांकन मानें।

राष्ट्रीय चैंपियनशिप में खेलेंगी नीतू और पूजा रानी

नीतू घणघस

ग्रेटर नोएडा में आज से शुरू होंगी आठवीं एलीट महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप, ओलिंपियन पूजा रानी और जैस्मीन भी करेंगी चुनौती पेश

पूजा रानी

नई दिल्ली, जेएनएन : भारतीय मुक्केबाजी संघ (बीएफआइ) में चल रही खींचतान के बीच शुक्रवार से ग्रेटर नोएडा के शहीद विजय सिंह पथिक स्टेडियम में होने वाली आठवीं एलीट महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में विश्व चैंपियन नीतू घणघस और ओलिंपियन मुक्केबाज पूजा रानी, जैस्मीन भी हिस्सा लेंगी। गुरुवार को चैंपियनशिप के लिए ड्रा घोषित किए गए।

24 राज्य संघों के कुल 188 मुक्केबाज 10 भार श्रेणियों में प्रतिस्पर्धा करेंगे। ओलिंपियन जैस्मीन (57 किग्रा), 48 किग्रा भार वर्ग में विश्व चैंपियन नीतू घणघस, दो बार की विश्व युवा चैंपियन साक्षी (54 किग्रा), पूर्व राष्ट्रीय चैंपियन पूनम पूनिया (57 किग्रा), 2018 विश्व चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता सिमरनजीत कौर (65 किग्रा), पूर्व विश्व चैंपियन पदक विजेता सोनिया लाथेर (60 किग्रा) और अनामिका (51 किग्रा) अपने-अपने भार वर्ग में चुनौती पेश करेंगी।

भारी भार वर्ग में हरियाणा का प्रतिनिधित्व करने वाली ओलिंपियन पूजा रानी और आरएसपीबी की स्ट्रैंडजा मेमोरियल रजत पदक विजेता अनुपमा भी इस टूर्नामेंट में खेलेंगी। इन स्थापित सितारों को सिक्किम की पेमा भूटिया, आल इंडिया पुलिस की प्रीति, तमिलनाडु की पूर्व राष्ट्रीय पदक विजेता कलेवानी एस और अन्य चुनौती देंगी। शुक्रवार को सभी 10 श्रेणियों में प्रतियोगिताएं शुरू होंगी, जिसमें दोपहर तीन बजे से शुरू होने वाले दो सत्रों में कुल 44 मुकाबले खेले जाएंगे। मैचों का लाइव प्रसारण बीएफआइ के यूट्यूब चैनल पर किया जाएगा। विश्व चैंपियन और शीर्ष महिला मुक्केबाज निकहत जरीन, आइओए अध्यक्ष पीटी उषा के साथ-साथ कई ओलिंपियन मुक्केबाजों का हौसला बढ़ाने के लिए मौजूद रहेंगे।

जिंबाब्वे की क्रिस्टी कावेंट्री बनीं आइओसी की नई अध्यक्ष

क्रिस्टी कावेंट्री ● एक्स

कोस्टा नवारिनो (ग्रीस), एपी: जिंबाब्वे की खेल मंत्री और दो बार की ओलिंपिक स्वर्ण पदक विजेता तैराक क्रिस्टी कावेंट्री को गुरुवार को अंतरराष्ट्रीय ओलिंपिक समिति (आइओसी) की नई अध्यक्ष चुना गया। कावेंट्री इस पद पर चुनी जाने वाली पहली महिला और संभवतः पहली अफ्रीकी हैं। गुरुवार को हुए आइओसी चुनाव में कावेंट्री के पक्ष में 97 सदस्यों ने 49 ने वोट किया। 41 वर्षीय कावेंट्री 2033 तक आइओसी अध्यक्ष पद पर रहेंगी और वह इस पद पर चुनी जाने वाली सबसे युवा हैं। क्रिस्टी निवर्तमान अध्यक्ष थामस बाक की जगह लेंगी, जिनका कार्यकाल 23 जून को समाप्त होगा।

अध्यक्ष पद की दौड़ में ब्रिटेन के सेबेस्टियन को, स्पेन के जुआन एंटोनियो, फ्रांस के डेविड लेपार्टियंट, जार्डन के प्रिंस फैजल, स्वीडन जोहान इलियाश और जापान के मोरीनारी वातानाबी भी थे।

मुक्केबाजी लास एंजिल्स ओलिंपिक में शामिल: इससे पहले आइओसी के 144वें सत्र की बैठक के दौरान सभी सदस्यों ने 2028 में होने वाले लास एंजिलिस ओलिंपिक खेलों में मुक्केबाजी को शामिल करने के पक्ष में मतदान किया।

लड़कियों के प्रति सोच बदलने के लिए चुना एमएमए : पूजा

यूएफसी में कल आयरलैंड की शाउना बैनन से भिड़ेंगी भारतीय फाइटर पूजा तोमर

अंशुल मामले में रेफरी ने की थी जल्दबाजी

बीते महीने क्विलियान सालकिल्ड के विरुद्ध भारतीय फाइटर अंशुल जुबली को नाकआउट करार देते हुए रेफरी ने फाइट को केवल 19 सेकेंड के भीतर रोक दिया था। इस पर पूजा ने कहा कि मुझे लगता है कि रेफरी ने जल्दबाजी में उन्हें नाकआउट दे दिया।

पूजा तोमर ● एक्स

खेल संवाददाता, नई दिल्ली: अल्टीमेट फाइट चैंपियनशिप (यूएफसी) में भारत की पहली महिला फाइटर पूजा तोमर शनिवार को आयरलैंड की शाउना बैनन से भिड़ेंगी। यूपी के मुजफ्फरनगर के छोटे से गांव से निकलकर यूएफसी जैसे बड़े मंच तक पहुंची पूजा ने कहा कि मेरी प्रतिद्वंद्वी ताइक्वांडो और जिजुत्सु में पारंगत है, लेकिन मैंने भी विशेष तैयारी की है। मैं भी अपने वुशू बैकग्राउंड का पूरा लाभ उठाऊंगी और इस फाइट को जीतकर दिखाऊंगी। लंदन में होने वाली इस फाइट का प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा।

रिंग में द साइक्लोन के नाम से प्रख्यात पूजा ने कहा, मैं यूपी के मुजफ्फरनगर के एक छोटे से गांव बुढ़ाना से आती हूं। वहां हमेशा ही लड़कों को ज्यादा सपोर्ट किया जाता था, लड़कियों को लेकर वहां बहुत ही छोटा सोच था। मेरे दिमाग में हमेशा यही बात चलती थी कि मुझे इसे बदलना है। मैं बचपन में टीवी पर जैकी चेन की फिल्में देखती थी और उनसे स्टंट सीखती थी और सोचती थी कि ये सीखकर मैं लड़कों को मारूंगी। मैं दिखाना चाहती थी कि लड़की भी किसी से कम नहीं है। मैं वुशू खेलती थी जो मार्शल आर्ट से काफी मिलता है। उसमें भी किक मार सकते हो, प्रतिद्वंद्वी को गिरा सकते हैं। इससे मुझे बहुत मदद मिली। इसके बाद मैंने मिक्स्ड मार्शल आर्ट (एमएमए) को चुना। मुझे यहां तक पहुंचाने में मेरी बहनों और मां का बड़ा योगदान रहा है। महिला के रूप में काम्बैट स्पोर्ट्स चुनने को लेकर आई चुनौतियों पर पूजा ने कहा कि मेरा परिवार तो शुरू से इसके विरोध में था, लेकिन मां चाहती थी कि मैं मार्शल आर्ट जारी रखूं। ताऊ-चाचा को लगता था कि कहीं चोट लग गई तो शादी कौन करेगा, लेकिन मां को भरोसा था कि बेटी जरूर कुछ करेगी।

****

चहल-धनश्री का हुआ तलाक

कोर्ट पहुंचे युजवेंद्र चहल ● एक्स

मुंबई, प्रेट्र: पारिवारिक अदालत ने गुरुवार को क्रिकेटर युजवेंद्र सिंह चहल और धनश्री वर्मा की आपसी सहमति से तलाक के लिए दायर संयुक्त याचिका को मंजूरी दे दी। लंबे समय से दोनों के बीच चल रहे मतभेदों के बाद यह फैसला आया, जिससे उनका वैवाहिक जीवन आधिकारिक रूप से समाप्त हो गया। बांद्रा स्थित अदालत में पेश हुए चहल और धनश्री ने तलाक की सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया। चहल के वकील नितिन गुप्ता ने जानकारी देते हुए कहा कि अदालत ने यह सुनिश्चित किया कि दोनों पक्षों ने सहमति की शर्तों का पालन किया है। इसके बाद अदालत ने तलाक को मंजूरी दे दी।

चहल और धनश्री ने दिसंबर 2020 में शादी की थी, लेकिन दोनों जून 2022 से अलग रह रहे थे। बुधवार को बांबे हाई कोर्ट ने दोनों के बीच छह महीने की अनिवार्य कूलिंग आफ अवधि को भी माफ कर दिया था और आइपीएल में चहल की व्यस्तता को देखते हुए पारिवारिक अदालत को गुरुवार को करने का आदेश दिया था। गुरुवार को कोर्ट पहुंचे चहल ने जो टी-शर्ट पहनी थी, उसको लेकर इंटरनेट मीडिया पर काफी चर्चा हुई।

रैपिड फायर

लिट्टी चोखा का स्वाद जुबां पर चढ़ा

धाकड़, द आर्चीज और विजय 69 फिल्मों के अभिनेता मिहिर आहूजा विविधतापूर्ण भूमिकाओं को महत्व दे रहे हैं। हालिया प्रदर्शित फिल्म हिंदी विंदी में अभिनेत्री नीना गुप्ता के साथ वह युवा संगीतकार की भूमिका में नजर आए। मूलत: जमशेदपुर से ताल्लुक रखनेवाले मिहिर से कुछ चटपटे सवालों के फटाफट जवाब :

● **अगर किसी संगीतकार या गायक के घर पर दिनभर बिताने का मौका मिले तो वह कौन होगा?**
-मैं सोनू निगम जी के घर पर दिन बिताना चाहूंगा। उनकी दिनचर्या और रियाज को देखना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात होगी।

● **कौन सा गाना दिनभर सुन सकते हैं?**
-यह तो मूड पर निर्भर करता है। फिलहाल, फिल्म तमाशा का गाना अगर तुम साथ हो...सुनता रहता हूं।

● **अगर किसी हस्ती के सामने गाना गाने का मौका मिले तो वो कौन होगी?**
-मैं शाह रुख सर (शाह रुख खान) के सामने उनका कोई रोमांटिक गाना गाकर उन्हें प्रभावित करना चाहूंगा।

● **अगर कोई लड़की पसंद हो तो उसे कौन सा गाना गाकर प्रभावित करना चाहेंगे?**
-(मुस्कुराते हुए) अगर तुम साथ हो...।

● **कोई नई भाषा सीखनी हो तो कौन सी होगी?**
-फिलहाल मैं स्पैनिश भाषा सीख रहा हूं। भारतीय भाषाओं में बांग्ला और मराठी बहुत मीठी लगती हैं।

● **फोन में तीन सबसे जरूरी ऐप?**
-इंस्टाग्राम, वाट्सएप और जीमेल।

● **बालीवुड में कौन सी अभिनेत्री पर दिल आया है?**
-मुझे बचपन में सोनाली बेंद्रे मैम बहुत पसंद थीं। द अर्चीज के प्रीमियर पर उनसे मिला था, लेकिन उन्हें यह बात बताने की हिम्मत नहीं हुई।

● **पहली कमाई और उसका खर्च क्या था?**
-एक विज्ञापन के लिए 15 हजार रुपये मिले थे। जिसमें से मैंने पांच हजार रुपये कालेज की फीस दी थी।

● **जमशेदपुर की कौन सी चीजें याद आती हैं?**
-वहां का शांतिपूर्ण माहौल और लिट्टी चोखा। वहां की लिट्टी चोखा का स्वाद तो जैसे जुबां पर चढ़ गया है।

● **किस कलाकार के सामने शूटिंग करने में सबसे ज्यादा घबराहट हुई?**
-हर फिल्म शुरू करने से पहले घबराहट होती है। बाकी अनुपम खेर सर और नीना गुप्ता मैम के साथ काम करने का सबसे ज्यादा उत्साह रहा।

दीपेश पांडेय

चर्चा में

छावा ने खींची बड़ी लकीर

छावा में छत्रपति संभाजी महाराज की कहानी भारतीय राजनीति से लेकर आम दर्शकों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है, तो वहीं फिल्म से बाक्स आफिस पर पसरा सन्नाटा भी टूटा। साल की तिमाही पूरी होने वाली है, पर छावा के अलावा कोई फिल्म सिनेमाघरों में धमाल नहीं मचा सकी। क्या वजह है कि दर्शक सिनेमाघरों में चुनिंदा फिल्में ही देखने पहुंच रहे हैं, महंगे टिकट व ओटीटी पर सिनेमा की उपलब्धता ने उन्हें किस तरह प्रभावित किया है, सिनेमाघरों की रौनक बढ़ाने के लिए कौन से उपाय कारगर हो सकते हैं? इन पहलुओं की पड़ताल कर रही हैं स्मिता श्रीवास्तव...

छावा में छत्रपति संभाजी महाराज की कहानी के प्रति दर्शकों की जिज्ञासा अभी तक कायम है। फिल्म में छत्रपति संभाजी महाराज के शौर्य और मातृभूमि के प्रति उनके अगाध प्रेम व भक्ति की बातें हो रही हैं। कहानी से दर्शकों ने जुड़ाव महसूस किया, फिल्म की वैश्विक कमाई 750 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर चुकी है, इसके साथ ही इस साल सिनेमाघरों में पसरा सन्नाटा समाप्त हुआ। हिंदी सिनेमा इंडस्ट्री में हर साल करीब डेढ़ सौ से लेकर दो सौ फिल्में बनती हैं, पर साल दर साल सिनेमाघरों में प्रदर्शित होने वाली फिल्मों की संख्या में कमी आ रही है। कमाई की बात करें तो इस साल प्रदर्शित फतेह, इमजरेंसी, आजाद, स्काईफोर्स, देवा, लवयापा, सुपरब्वायज आफ मालेगांव, मेरे हसबैंड की बीवी सहित अन्य फिल्में बाक्स आफिस पर असफल रहीं। हिंदी फिल्मों के प्रति दर्शकों की उदासीनता को लेकर निर्देशक विक्रम भट्ट कहते हैं कि फिल्मकारों के लिए यह सोच-विचार का समय है। हमने व्यापक दर्शकों के साथ जुड़ाव खो दिया है। पहले फिल्मों का काला बाजार हुआ करता था, क्योंकि उत्सुकता होती थी कि थिएटर में सबसे पहले फिल्म देखनी है। हिंदी फिल्मों को लेकर दर्शकों में अब वह उत्साह कम दिखता है। वहीं दक्षिण भारतीय फिल्में वह उत्सुकता जगाने की लगातार कोशिश कर रही हैं। पुष्पा 2 : द रूल दो माह बाद ओटीटी पर आने वाली थी लेकिन लोग सिनेमाघर गए क्योंकि वो फिल्म को उसी समय ही देखना चाहते थे। छावा इसलिए चली क्योंकि उसकी कहानी व्यापक दर्शकों से जुड़ी। आजकल स्टार बहुत ओवर एक्सपोज हो गए हैं। वे इंटरनेट मीडिया पर रील बनाकर डाल रहे हैं, सब जगह सुलभ हैं। एक समय था जब बच्चन साहब को देखने के लिए उत्सुकता रहती थी। अब संभवत: अजय देवगन, रणबीर कपूर ही वो स्टार हैं जिन्होंने स्वयं को इस मामले में बहुत एक्सपोज नहीं किया है। उनके प्रति चार्म बना हुआ है।

महंगे टिकट ने बढ़ाई मुश्किल: फिल्मों के प्रति दर्शकों इस उदासीनता के कई अन्य कारण भी हैं। कंटेंट दमदार न होने के साथ टिकट के बढ़े दाम भी बड़ी वजह हैं। दक्षिण भारत में फिल्में चल जाती हैं, क्योंकि वहां सिनेमाघरों में टिकट के दामों को लेकर दिशा-निर्देश हैं। कर्नाटक सरकार ने सिनेमा के टिकटों के दाम की उच्चतम सीमा 200 रुपये प्रस्तावित की है, पर उत्तर भारत में टिकट के दामों में कोई एकरूपता नहीं दिखती। ट्रेड एनालिस्ट अतुल मोहन कहते हैं कि सिनेमा व्यापक दर्शकों के लिए होता है, ना कि किसी खास वर्ग के लिए। सिनेमा अपने उद्देश्य में तभी सफल है, जब ज्यादा संख्या में लोग उसे देखने आएं। हर वर्ग, हर दर्जे के दर्शक उसे देखने को आएं और उसका आनंद लें। अब सबसे बड़ी समस्या कंटेंट की है। सिनेमा में हमेशा लार्जर दैन लाइफ कहानियां पसंद की गई हैं। दक्षिण के फिल्मकार कल्कि 2898 एडी, पुष्पा 2, आरआरआर जैसे मास फिल्में बना रहे हैं। हमने अपने दर्शकों से दूरी स्वयं बना ली है। छावा इस साल अपवाद रही है। टिकट के दामों की वजह से भी लोगों का मोहभंग सिनेमाघरों से हुआ है। एक दौर था जब दर्शकों को पता होता कि फलां सिनेमाघर में फिल्म लगी है। तब दिन के सभी शो का सातों दिन रेट वही होता था। दर्शक सहूलियत के हिसाब से चले जाते थे। आज शो की संख्या बढ़ गई है, लेकिन टिकट के दामों में एकरूपता नहीं है। शाम का शो हो या वीकेंड में जाना है तो टिकट के दाम ज्यादा होते हैं।

ओटीटी का असर: अतुल आगे कहते हैं कि दर्शकों को लगता है कि महंगा टिकट लेकर सिनेमाघर में फिल्म क्यों देखूं, मेरे पास फलां ओटीटी है, उस पर फिल्म दो महीने बाद आ ही जाएगी। फिल्मों के प्रमोशन में आए बदलाव को भी अतुल हितकारी नहीं मानते हैं। वह कहते हैं पहले कलाकार मीडिया के साथ खुलकर बातचीत करते थे। फिल्म पर चर्चा होती थी। अब स्टार पाडकास्ट में खाना बना रहे हैं। कामेडी शो में जा रहे हैं, वहां पर दुनियाभर की बातें होती हैं, लेकिन फिल्म पर कोई बात नहीं होती है। यह प्रमोशन नहीं है। आप फिल्म को नहीं, बल्कि पाडकास्टर को प्रमोट कर रहे हैं।

दर्शकों की पसंद में बदलाव: वहीं फिल्म एग्जीबिटर अक्षय राठी कहते हैं कि अब मनोरंजन के ढेरों साधन हैं तो दर्शक बंट गए हैं। हालांकि कोरोनाकाल के बाद ही पांच सौ करोड़ क्लब आरंभ हुए। अगर हम अच्छी फिल्में लाएं तो बड़ी संख्या में दर्शक देखने आएंगे। दरअसल, दर्शक अब अधिक सजग हो गए हैं कि कौन सी फिल्में थिएटर में देखना चाहते हैं और कौन सी घर पर। पहले बहुत बारीक रेखा हुआ करती थी। आयुष्मान खुराना या राजकुमार राव की फिल्मों के लिए लोग सिनेमाघर आते थे। अब लोग अच्छे सिनेमाई अनुभवों के लिए आना चाहते हैं। महंगे टिकट को लेकर वह कहते हैं कि बात पैसा वसूल होने की है। छावा के टिकट के दाम अधिक थे फिर भी दर्शक आए। हम लोग यह भूल जाते हैं कि मल्टीप्लेक्स के अलावा भी सिनेमाघर हैं, जहां पर टिकटों के दाम किफायती होते हैं। आगामी दिनों में सलमान खान की सिंकदर, सनी देओल की जाट जैसी कई बड़ी फिल्में आ रही हैं। उम्मीद है कि लोग बड़ी संख्या में थिएटर आएंगे।

फिल्म सिकंदर में सलमान खान ● फोटो : जागरण आर्काइव

फिल्म छावा में विक्की कौशल

सिकंदर का इंतजार

सलमान खान की पिछली कुछ फिल्में नहीं चलीं। अब सिकंदर पर उनकी उम्मीदें टिकी हैं। फिल्म एग्जीबिटर अक्षय राठी कहते हैं साल 2008 में वांटेड आने से पहले सलमान ने कई फ्लाप फिल्में दी थीं। वांटेड के बाद उनकी हिट फिल्मों का सिलसिला चला। उनका स्टारडम 30 वर्ष में बना है। यह कुछ फ्लाप फिल्मों से बिगड़ नहीं जाता है। उन्हें सिर्फ एक अच्छी फिल्म का इंतजार है। हो सकता है कि सिकंदर के साथ ये इंतजार पूरा हो जाए।

चुनौती के साथ ही नए अवसर सामने

कोरोना काल के बाद जवान, पठान, गदर 2, स्त्री 2, छावा जैसी फिल्में ही बाक्स आफिस पर धमाल मचा पाई हैं। निर्माता सिद्धार्थ राय कपूर कहते हैं कि कई चीजें बदल रही हैं, जैसे बड़ी फिल्में कमाई के नए मानक कायम कर रही हैं। पहले यह तय था कि फलां स्टार है, तो इतना बाक्स आफिस कलेक्शन तो गारंटी के साथ होगा। आज ऐसा नहीं है। निर्माताओं के सामने चुनौती के साथ ही मौका भी है। यह दौर बता रहा है कि आपको बड़ा सुपरस्टार नहीं चाहिए। स्त्री 2 अच्छे कलाकारों के साथ बनी थी, लेकिन उसमें बड़े सुपरस्टार नहीं थे। ये कहा जा रहा है कि दर्शक थिएटर नहीं जा रहे हैं, लेकिन सच ये है कि डिजिटल प्लेटफार्म ने लोगों जो सहूलियतें दी हैं, उसके बाद आपको लोगों को सिनेमाहाल में लाने के लिए बेहतरीन सिनेमाई अनुभव देना होगा। अब चुनौती हम निर्माताओं के सामने है कि हम अपने कंटेंट को कैसे इतना दमदार बनाएं जो दोनों ही प्लेटफार्म पर लोगों को पसंद आए।

दिल से

कोई दबाव नहीं लेती

आगामी दिनों में फिल्म धक धक की सीक्वल में बाइक से एक नए सफर पर निकलने की तैयारी कर रही हैं संजना सांघी...

कलाकार अगर ज्यादा समय तक नजर न आएं, तो ऐसा माना जाता है कि लोग उसे भूलने लगते हैं। हालांकि राकस्टार फिल्म की अभिनेत्री संजना सांघी को फिल्म इंडस्ट्री की इन धारणाओं से डर नहीं लगता है। वह कहती हैं कि मैं गैर फिल्मी पृष्ठभूमि से हूं। मैंने सोचा ही नहीं था कि कभी हिंदी फिल्मों की हीरोइन बनूंगी। मुझे अभिनय से प्यार हो गया, क्योंकि इम्तियाज अली (निर्देशक) और मुकेश छाबड़ा (कास्टिंग डायरेक्टर) ने मुझे इस बात का एहसास कराया। उनकी वजह से मैं अपनी अभिनय प्रतिभा को जान सकी। मुझ पर फिल्में करते रहने का कोई दबाव नहीं है। मैं केवल वही रोल करती हूं, जिससे जुड़ पाती हूं। मैं इंडस्ट्री में किसी दौड़ में भाग लेने नहीं आई हूं, पर मेहनत भरपूर करूंगी, फिर चाहे धक धक फिल्म में बाइक राइडर बनकर हिमालय के पथरीले रास्तों पर बाइक चलाना ही क्यों न हो। ऐसे अवसरों के लिए बहुत मेहनत करनी होती है। अगर पात्र में कुछ करने के लिए ही नहीं है, बस कैमरा के सामने खड़े होना है, तो वह मुझसे नहीं हो पाएगा। लोग अब थिएटर ज्यादा नहीं जा रहे है, कठिन समय है। बतौर युवा कलाकार हमें थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। आगामी दिनों में मेरी फिल्म धक धक की सीक्वल आएगी। इस बार हम बाइक से नई जगह पर जाएंगे। डिजिटल प्लेटफार्म पर भी डेब्यू कर रही हूं।

क्या संजना को कभी लगा कि उनका डेब्यू ऐसे वक्त पर हुआ, जब कोरोना काल था। ऐसे में जो मौके मिलने चाहिए थे, वो नहीं मिले। इस पर संजना कहती हैं कि मैं हमेशा आगे की ओर देखती हूं। मुझे दिल बेचारा फिल्म से डेब्यू करने का मौका मिला, यही बड़ी बात थी। दिल बेचारा ओटीटी पर सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्मों में शामिल रही है। मैं दिल्ली के एक आम परिवार से ताल्लुक रखती हूं। कहीं जाती हूं, तो लोग केवल मुझे देखने के लिए खड़े रहते हैं। मैंने तो इसकी कल्पना भी नहीं की थी।

प्रियंका सिंह

म्यूजिक कार्नर

मजा सफर का है, मंजिल का नहीं

पिछले दिनों गायक **जुबिन नौटियाल** को फिल्म आर्टिकल 370 के गाने दुआ... के लिए सर्वश्रेष्ठ गायक के आइफा अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। अवार्ड मिलने की खुशी जताते हुए जुबिन कहते हैं कि मजा सफर का है, मंजिल का नहीं। मेरे जीवन का यही मंत्र रहा है। हमारे देश में सड़कों पर बहुत सारी गाड़ियां दौड़ती हैं, ठीक उसी तरह गायकी के पेशे में कई गायक हैं। हम सभी सही समय पर अपने गंतव्य पर पहुंच ही जाते हैं। मेरे लिए, अपने देश में रहकर संगीत बनाना सुखद अनुभव है। यहां लोगों को केवल फिल्मी गानों से ही नहीं, बल्कि हर तरह के संगीत से प्यार है। अगर एक आर्टिस्ट को अपने गाने के लिए प्रशंसा और पहचान मिल जाए, तो इससे बड़ी बात क्या होगी। मुझे वह मौका मिला है, यह बात खुशी देती है। जुबिन के गानों में मेरे घर राम आए हैं... समेत कई भक्ति गीत भी शामिल हैं। जब उन्हें भक्ति गीतों के गायक के तौर पर लोग पहचानते हैं, तो कैसा लगता है? इस पर वह कहते हैं कि देखिए बालीवुड के गाने तो बहुत लोग गा सकते हैं, लेकिन भक्ति गीत गाने का मौका बहुत कम गायकों को मिलता है। मैंने बालीवुड में गाने गाए हैं, कई स्वतंत्र और गैर फिल्मी गाने भी गाए हैं, लेकिन सच कहूं, आज भी जब कंसर्ट में मेरी चौखट पे चलके आज चारों धाम आए हैं...गाना गाता हूं तो जो प्रतिक्रिया मिलती है, वह देखकर दिल खुश हो जाता है। लोग कंसर्ट में भी भक्ति संगीत में रम जाते हैं।

प्रियंका सिंह

इस पेज के बारे में अपनी राय और सुझाव भेजें- feature@jagran.com

आज का भविष्यफल-21 मार्च 2025 शुक्रवार

पं. के. ए. दुबे पद्मेश

आज की ग्रहस्थिति: चैत्र मास कृष्ण पक्ष सप्तमी।
आज का राहुकाल: प्रात: 10:30 से 12 बजे तक।
आज का दिशाशूल: पश्चिम
आज का पर्व एवं त्योहार: शीतला सप्तमी
आज की भद्रा: दोपहर 03:35 बजे तक।

कल 22 मार्च 2025 का पंचांग

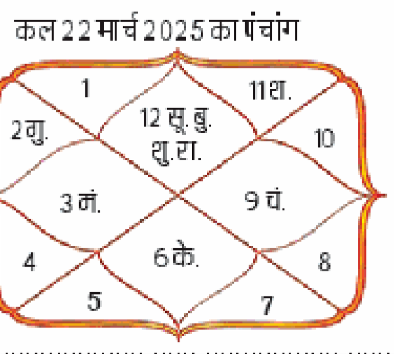

कल का दिशाशूल: पूर्व
कल का पर्व एवं त्योहार: शीतला अष्टमी
विशेष: शुक्र उदय
विक्रम संवत 2081 शके 1947 उत्तरायण, उत्तरगोल, बसंत ऋतु चैत्र मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तत्पश्चात नवमी मूल नक्षत्र तत्पश्चात पूर्वाआषाढ़ा नक्षत्र व्यतिपात योग 18 घंटे 37 मिनट तक, तत्पश्चात वरियान योग धनु में चंद्रमा।

मेष: पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी। आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। धन, यश, कीर्ति में वृद्धि होगी।
वृष: जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। किसी कार्य के संपन्न होने से आत्मविश्वास में वृद्धि होगी।
मिथुन: रचनात्मक प्रयास फलीभूत होंगे। दांपत्य जीवन सुखमय होगा। रिश्तों में निकटता आएगी।
कर्क: शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है।
सिंह: बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी।
कन्या: उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। मांगलिक या सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सेदारी रहेगी। भागदौड़ रहेगी।
तुला: स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। धन, यश, कीर्ति में वृद्धि होगी। भाई-बहिन का सहयोग मिलेगा।
वृश्चिक: आर्थिक मामलों में सुधार होगा लेकिन पिता या धर्म गुरु के कारण मन खिन्न हो सकता है।
धनु: पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। रिश्तों में निकटता आएगी। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें।
मकर: जीवनसाथी से तनाव मिल सकता है। व्यर्थ की भागदौड़ रहेगी। व्यावसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी।
कुंभ: आर्थिक मामलों में सुधार होगा। विरोधी परास्त होगा। व्यावसायिक मामलों में सफलता मिलेगी।
मीन: बहुप्रतीक्षित कार्य के संपन्न होने से आत्मविश्वास बढ़ेगा। सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी।

वर्ग पहेली-2930

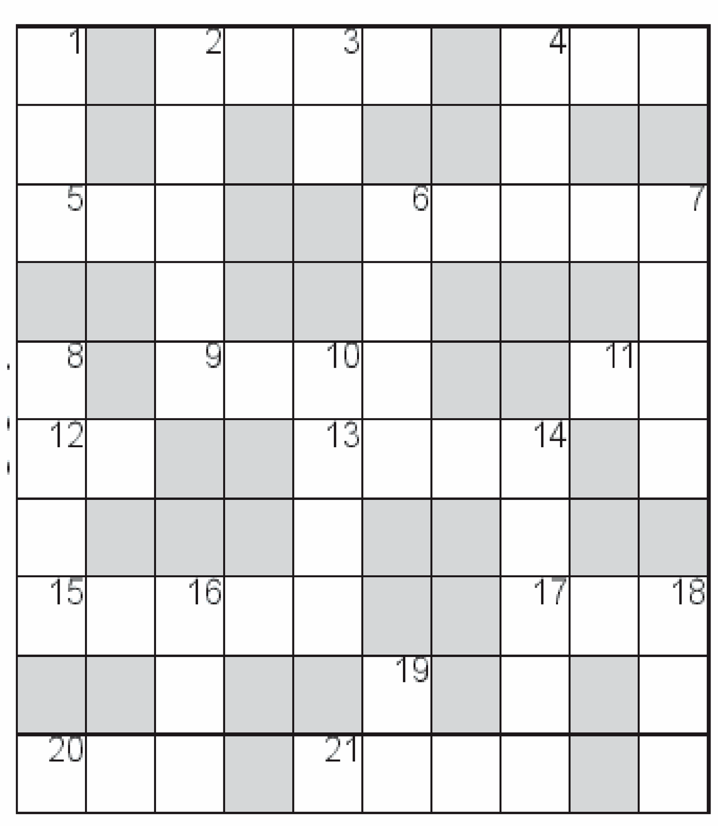

© Bird Features & Writing Agency

बाएं से दाएं
2. परतंत्र, दूसरे के अधीन (4)।
4. अलंकृत करना, आकर्षक बनाना (3)।
5. प्रवाह, धारा (3)।
6. उतावला होना (5)।
9. भेंट, उपहार (4)।
11. शरीर, देह (2)।
12. कक्षा, दर्जा, परिधि (2)।
13. जोश में आना, आवेश में आना (4)।
15. कुश्ती लड़ने वाला (5)।
17. भाग्य, किस्मत (3)।
20. अंटना, घुस जाना (3)।
21. ताजा, प्रफुल्ल (2,2)।

ऊपर से नीचे
1. अंधेर, संकट, विपत्ति (3)।
2. बदलाव, हेर-फेर (5)।
3. कम वेग वाला (2)।
4. कारण, हेतु (3)।
6. एक ही नाम का (4)।
7. मूर्खतापूर्ण आचरण करने वाला (4)।
8. काट कर हटा देना (4)।
10. हर समय, सदा, हमेशा, सर्वदा (2,2)। 14. हाव-भाव, मोहक-चेष्टा (2,3)। 16. शर्माना, संकोच करना (3)। 18. धारा में आगे बढ़ना (3)।
19. बिल्कुल ताजा और नया (2)।

कल का हल

■	ब	■	स	भा	ल	ना	■	मां	■
सं	क	ट	■	ला	■	ना	का	बि	ल
■	वा	■	■	■	■	प्र	■	लि	■
अ	स	मं	ज	स	■	का	■	■	वि
मा	■	■	■	क	रा	र	■	ता	ना
श	क	■	क	ल	श	■	■	■	श
य	■	■	ड़	■	न	त	म	स्त	क
■	बी	■	क	■	■	■	■	र	■
ज	मा	व	ड़ा	■	बी	■	मं	ही	न
■	र	■	नी	म	ज	द	■	न	■

जागरण सुडोकू-2930

	5		4			9	3	
					7			2
9		1		3		4		
3				6		7		9
		9			3		2	
8	2		5					3
	4		1					5
1				7		2		
		3		5			9	

कल का हल

4	5	6	2	3	9	8	7	1
3	9	2	7	8	1	6	5	4
7	1	8	6	4	5	2	9	3
6	8	4	5	2	3	7	1	9
2	3	9	1	7	8	4	6	5
5	7	1	4	9	6	3	8	2
9	6	3	8	5	2	1	4	7
1	2	7	9	6	4	5	3	8
8	4	5	3	1	7	9	2	6

राष्ट्रीय फलक

चारधाम यात्रा के लिए पहले ही दिन 1.65 लाख पंजीकरण

जागरण संवाददाता, देहरादून : 30 अप्रैल से प्रारंभ होने वाली चारधाम व हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए शुरू हुए आधार आधारित आनलाइन पंजीकरण में गुरुवार को पहले ही दिन शाम पांच बजे तक 1,65,292 श्रद्धालुओं ने पंजीकरण कराया। केदारनाथ के लिए सर्वाधिक 53,570 पंजीकरण हुए। बदरीनाथ के लिए 49,385 ने पंजीकरण कराया, जबकि गंगोत्री के लिए 30,933 और यमुनोत्री के लिए 30,224 पंजीकरण हुए। हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए 1,180 ने पंजीकरण कराया। पर्यटन विकास परिषद की ओर से चारधाम यात्रा-2025 में श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को गुरुवार सुबह सात बजे से आनलाइन आधार आधारित पंजीकरण शुरू किया गया। वेबपोर्टल के माध्यम से 1,62,125 पंजीकरण हुए, जबकि मोबाइल एप पर 3,167 श्रद्धालुओं ने पंजीकरण कराया। निजी वाहन से यात्रा में शामिल होने के लिए 1,750 पंजीकरण हुए।

मकराना के सफेद संगमरमर से बन रही राम दरबार की मूर्तियां

जागरण संवाददाता, जयपुर

- कुश के वंशजों की बनाई जयपुर नगरी में मूर्तियों को गढ़ने में जुटे हैं शिल्पकार
- अयोध्या में राम मंदिर के पहले तल पर राम दरबार में स्थापित होंगी मूर्तियां

धार्मिक नगरी अयोध्या में राम मंदिर के पहले तल पर स्थापित होने वाले राम दरबार की मूर्तियों का निर्माण गुलाबी नगरी जयपुर के प्रख्यात कारीगर कर रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के पुत्र कुश के वंशजों की ओर से बनाई गई जयपुर नगरी में शिल्पकारों को भी लाया गया था। वे अब भी अपनी कला के माध्यम से अयोध्या से जुड़े हुए हैं। जयपुर के प्रख्यात मूर्तिकार सत्य नारायण पांडे और उनके पुत्र प्रशांत पांडे टीम के साथ इन दिनों राम दरबार में स्थापित होने वाली सफेद संगमरमर की मूर्तियों को गढ़ने में जुटे हुए हैं।

चार पीढ़ियों से मूर्तियों को गढ़ने के काम में जुटे प्रशांत ने कहा कि राम दरबार में भगवान राम सहित कुल 20 मूर्तियों को गढ़ने का काम किया जा रहा है। इनमें भगवान राम और माता सीता सिंहासन पर विराजमान होंगे। उनके चरण में हनुमान जी बैठे होंगे, साथ ही लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न पास खड़े दिखाई देंगे। अन्य मूर्तियों में भगवान सूर्य, माता अन्नपूर्णा, सबरी, वाल्मीकि एवं विश्वामित्र प्रमुख हैं। मंदिर में एक सप्तऋषि मंडल उसी क्रम में विराजमान होगा, जैसा ब्रह्मांड में नजर आता है। हम इन दिनों मुख्य गर्भगृह के लिए राम दरबार को तैयार कर रहे हैं। मूर्तियां राजस्थान के ही मकराना के प्रख्यात सफेद संगमरमर से तैयार की जा रही है। मूर्तियों की विशेष बात यह होगी कि यह प्राचीन भारतीय शिल्प कला पर आधारित होगी।

परिवार के मुखिया सत्य नारायण पांडे ने बताया कि अगले माह के प्रारंभ तक मूर्तियां अयोध्या भेज दी जाएंगी। करीब डेढ़ सप्ताह में मूर्तियों को अंतिम रूप दे दिया जाएगा।

पुनर्विवाह के कारण विधवा को मुआवजे से नहीं किया जा सकता वंचित : हाई कोर्ट

दयानंद शर्मा ● जागरण, चंडीगढ़ : पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया कि सड़क हादसे में पति की मौत के बाद विधवा को मुआवजे से सिर्फ इसलिए वंचित नहीं किया जा सकता क्योंकि उसने पुनर्विवाह कर लिया है। 14 नवंबर, 2006 को बलविंदर कौर के पति हरजिंदर सिंह मोटरसाइकिल से जा रहे थे। गांव अमरगढ़ के बस स्टैंड के पास एक मारुति कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हरजिंदर सिंह को गंभीर चोटें आईं और 17 नवंबर 2006 को उनकी मौत हो गई। बलविंदर कौर ने 20 लाख रुपये का मुआवजा मांगा, लेकिन ट्रिब्यूनल ने सिर्फ 2.68 लाख रुपये का मुआवजा तय किया। उसे भी हरजिंदर के माता-पिता को देने का आदेश दिया गया। बलविंदर कौर को उनके पुनर्विवाह के कारण कुछ नहीं दिया गया। फरीदकोट की बलविंदर ने ट्रिब्यूनल के फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें उनके पति की मौत के मुआवजे से पर वंचित कर दिया गया था।

बिजनौर पुलिस का कमाल, बिना हेलमेट वाहन चालन में कार का चालान

जागरण संवाददाता, बिजनौर

- डाक्टर की कार खड़ी थी धामपुर में, चांदपुर में किया चालान

यातायात पुलिस के कारनामे भी अजीब हैं। उत्तर प्रदेश के बिजनौर की पुलिस ने एक चिकित्सक की कार का बिना हेलमेट वाहन चालन के आरोप में एक हजार रुपये का चालान कर दिया। हद तो यह है कि कार धामपुर में खड़ी थी और चालान चांदपुर में काट दिया गया। मोबाइल पर कार का बिना हेलमेट के चालान का मैसेज देखकर चिकित्सक भी अचंभित रह गए। चालान के बाद विरोध स्वरूप उनके मैनेजर ने हेलमेट पहनकर कार चलाई।

बाल रोग विशेषज्ञ डा. लोकेंद्र सिंह का धामपुर में नगीना मार्ग पर सरल अस्पताल है। उनके पास 18 मार्च की दोपहर लगभग एक बजे मोबाइल पर मैसेज आया, जिसमें उनका बिना हेलमेट का एक हजार रुपये का चालान काटे जाने की जानकारी थी। यह मैसेज देखकर चिकित्सक अचंभित रह गए, क्योंकि वह बाइक नहीं, कार चलाते हैं।

बिजनौर के धामपुर में विरोध स्वरूप चिकित्सक की कार को हेलमेट पहनकर चलाते उनके मैनेजर। सौ. चिकित्सक

डा. लोकेंद्र सिंह ने मोबाइल पर मिले मैसेज से चालान स्लिप की जांच की तो उसमें बाइक का फोटो दिखाई दिया, लेकिन नंबर उनकी कार का था। चालान चांदपुर के हल्दौर मार्ग पर काटा गया था, जबकि डा. लोकेंद्र सिंह का कहना है कि 18 मार्च की दोपहर उनकी कार घर पर ही खड़ी थी। उन्होंने बताया कि उनकी कार उनके अस्पताल के मैनेजर भूपेंद्र सिंह चलाते हैं।

पुरी मंदिर के रत्न भंडार चाबी मामले में हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर : पुरी के श्रीजगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार की चाबी गायब होने के मामले की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी या नहीं इस पर अभी भी संशय बरकरार है। जांच आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के मामले में राज्य सरकार द्वारा दो अलग-अलग विरोधाभासी हलफनामे दाखिल करने को लेकर उड़ीसा हाई कोर्ट ने सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। रत्न भंडार में जिसमें सदियों से राजा-महाराजाओं द्वारा मंदिर को दान की गई निधियां हैं। हाई कोर्ट में 29 जनवरी 2024 को तत्कालीन बीजद सरकार की ओर से दाखिल किए गए हलफनामे में सरकार ने जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का विरोध किया है। हालांकि, 5 अप्रैल 2024 को दाखिल एक अन्य हलफनामे में सरकार ने कहा है कि सरकार विधानसभा में रिपोर्ट पेश करने का इरादा रखती है। इस बीच पांच मार्च 2025 को राज्य सरकार ने कहा है कि जांच पूरी हो चुकी है, लेकिन रिपोर्ट सार्वजनिक करने की जरूरत नहीं है।

****

राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शुक्रवार 21 मार्च, 2025
आजकल
14
www.jagran.com

अंतरिक्ष यान ने ब्रह्मांड के 13.8 अरब वर्ष पुराने होने के साक्ष्य दिए

2013 में आज ही के दिन प्लैंक अंतरिक्ष यान ने इस बात के प्रमाण दिए कि ब्रह्मांड 13.8 अरब वर्ष पुराना है। नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने इस यान को ब्रह्मांड में सबसे पुराने प्रकाश, कास्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड को मापने के लिए डिजाइन किया था। प्रकाश बिग बैंग के बाद उत्पन्न हुआ था।

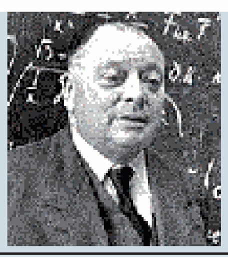

वोल्फगैंग पाली ने अपना अपवर्जन सिद्धांत प्रकाशित किया

1925 में आज ही के दिन आस्ट्रियाई भौतिक विज्ञानी वोल्फगैंग पाली ने अपना अपवर्जन सिद्धांत प्रकाशित किया था। पाली ने बताया था कि आस-पास मौजूद दो इलेक्ट्रान एक ही समय में समान अवस्था में नहीं हो सकते। यह सिद्धांत क्वांटम यांत्रिकी का आधार है। इस खोज के लिए उन्हें नोबेल मिला।

पेरिनी शिवतांडवम को पुनर्जीवित करने वाले रामकृष्ण

नृत्य गुरु नटराज रामकृष्ण का जन्म 1923 में आज ही इंडोनेशिया में हुआ था। आठ वर्ष की उम्र में मंदिर में नृत्य देख इसके प्रति उनका प्रेम जागा। नृत्य में रुचि की वजह से परिवार से बेदखल कर दिए गए। विभिन्न नृत्य रूपों पर शोध के माध्यम से सुप्त अवस्था में पड़े शास्त्रीय नृत्यों को पुनर्जीवित करने का बीड़ा उठाया। 700 साल पुराने नृत्य रूप पेरिनी शिवतांडवम को पुनर्जीवित करने का श्रेय रामकृष्ण को ही दिया जाता है। कुचिपुड़ी को शास्त्रीय का दर्जा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विदेश में भारतीय नृत्य कला का प्रचार- प्रसार भी किया।

इधर-उधर की

अनोखे कुत्ते के लिए खर्च किए 50 करोड़ रुपये

बेंगलुरु, एजेंसी : कुत्ते पालने का शौक काफी लोगों को होता है लेकिन बेंगलुरु के एस सतीश ने जितना रुपया खर्च कर एक कुत्ता खरीदा है उतना खर्च करने में एक आम आदमी को शायद पूरा जीवन भी कम पड़ जाए। सतीश ने 57 लाख डालर (लगभग 50 करोड़ रुपये) खर्च कर कैडाबांब ओकामी नामक दुर्लभ वुल्फडाग खरीदा। यह अनोखा कुत्ता भेड़िया और कोकेशियान शेफर्ड के बीच का क्रास है और माना जाता है कि यह अपनी तरह का पहला है। इसे दुनिया के सबसे महंगे कुत्तों में से एक माना जाता है। सतीश महंगी नस्ल के कुत्तों के मालिक के रूप में प्रसिद्ध हैं। उनके पास 150 से अधिक कुत्ते हैं। सतीश ने कहा कि अनोखे कुत्तों को पालना उनका शौक है। ये उससे आय भी अर्जित करते हैं।

इस कुत्ते की उम्र आठ महीने है ● इंटरनेट मीडिया

अब स्टेम सेल विधि से जल्द ठीक होंगे पशुओं के फ्रैक्चर

शोध ▸ डीवीवीएएसयू मथुरा की असिस्टेंट प्रो. ज्योत्सना भट्ट ने पंत विवि में किया शोध, निकले सार्थक परिणाम

अरविंद कुमार सिंह ● जागरण

पंतनगर (ऊधम सिंह नगर): अब पशुओं की हड्डी टूटने या दरार पड़ने (फ्रैक्चर) पर स्टेम सेल विधि से उपचार कर जल्द उन्हें ठीक किया जा सकेगा। पं. दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विवि एवं गो अनुसंधान संस्थान (डीवीवीएएसयू) मथुरा (उप्र) में असिस्टेंट प्रोफेसर डा. ज्योत्सना भट्ट ने गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विवि पंतनगर से किए शोध में यह निष्कर्ष निकाला। उन्होंने न्यूजीलैंड के सफेद खरगोश के पैर में फ्रैक्चर का स्टेम सेल थेरेपी से उपचार कर सफलता हासिल की। इस शोध को अखिल भारतीय वेटेनरी संघ ने बेस्ट वुमेन अवार्ड के लिए चयनित किया है।

▸ **न्यूजीलैंड के सफेद खरगोश की स्टेम सेल थेरेपी में जल्द ठीक हुई हड्डी, शोध बेस्ट वुमेन अवार्ड के लिए चयनित**

गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विवि के पशु चिकित्सा महाविद्यालय की लैब में खरगोश की हड्डी में स्टेम सेल का प्रयोग करतीं डा. ज्योत्सना भट्ट। फोटो- साभार- स्वयं

स्टेम सेल विधि से पशुओं के उन फ्रैक्चरों का इलाज करने में सहायता मिलेगी, जिनका इलाज केवल प्लास्टर या इंट्रामेड्युलरी पिनिंग (प्लेटिंग) से संभव नहीं हो पाता है। इस प्रयोग से फ्रैक्चर न ही केवल कम समय में भरेगा बल्कि अधिक कारगर तरीके से भरेगा। यह तकनीक भविष्य के लिए बेहद कारगर साबित होगी। **- डा. ज्योत्सना भट्ट**

मानव के शल्य चिकित्सा (सर्जरी) में स्टेम सेल थेरेपी का प्रयोग होता है। अब तक पशुओं की सर्जरी में इस पर काफी कम काम हुआ है। कुत्ता, बिल्ली, खरगोश आदि पशुओं का स्टेम सेल थेरेपी से उपचार के लिए पंत विवि के वेटेनरी कालेज के सर्जरी एवं रेडियोलाजी विभाग में लंबे समय से शोध हो रहे हैं। अभी तक घोड़ों के लिगामेंट फ्रैक्चर के अलावा अन्य पशुओं के घाव, आंख के अल्सर, लीवर की बीमारी का स्टेम सेल से उपचार संभव भी हुआ है। पशुओं के पैर या अन्य जगह पर फ्रैक्चर हो जाता है तो सामान्य विधि से ही सर्जरी की जाती है। इस तरह चोटिल पशु को ठीक होने में दो से ढाई माह का समय लग जाता है। दुधारु पशु में फ्रैक्चर का असर दूध उत्पादन पर भी पड़ता है।

डा.ज्योत्सना ने पंत विवि के वेटेनरी कालेज के पूर्व डीन डा. नरेंद्र सिंह जादौन के निर्देशन में 2017 से 2022 तक अस्थि मज्जा से व्युत्पन्न स्टेम कोशिकाओं से पशुओं के फ्रैक्चर ठीक करने के विषय पर शोध किया। उन्होंने न्यूजीलैंड के सफेद खरगोशों की हड्डी के फ्रैक्चर पर शोध किया तो पाया कि इस शल्य चिकित्सा से फ्रैक्चर एक से डेढ़ माह में ठीक हो गया। सामान्य विधि (प्लास्टर या प्लेटिंग) से इलाज करने में दो से ढाई माह का समय लग गया। स्टेम सेल थेरेपी से फ्रैक्चर का घाव भी जल्द भर गया।

कार्बन डाइआक्साइड का स्तर आठ लाख वर्षों में सबसे ज्यादा

नई दिल्ली, प्रेट्र : विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यूएमओ) की जलवायु रिपोर्ट में कहा गया है कि 2023 में वायुमंडलीय कार्बन डाइआक्साइड का स्तर 420 पार्ट प्रति मिलियन तक पहुंच गया, जो पिछले आठ लाख वर्षों में सबसे अधिक है। यह पूर्व-औद्योगिक स्तर (1750) का 151 प्रतिशत था। वर्तमान में दीर्घकालिक वैश्विक तापमान 1850-1900 बेसलाइन की तुलना में 1.34 और 1.41 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि 2024 में उष्णकटिबंधीय (ट्रापिकल) चक्रवात, बाढ़, सूखा और अन्य आपदाओं के कारण पिछले 16 वर्षों में सबसे अधिक नए विस्थापन दर्ज किए गए। इन घटनाओं ने खाद्य संकट को भी बदतर बना दिया और बड़े पैमाने पर आर्थिक नुकसान हुआ।

आज दिन और रात का समय होगा बराबर

जागरण संवाददाता, नैनीताल: वसंत विषुवत यानी आज शुक्रवार को दिन व रात की अवधि बराबर होगी। 21 मार्च के बाद दिन की अवधि रात से लंबी होने लगेगी। सूर्य का केंद्र पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर सीधा होने के कारण दिन व रात का समय बराबर होता है।

आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान (एरीज) नैनीताल के वरिष्ठ विज्ञानी डा. शशिभूषण पांडेय के अनुसार दिन व रात की अवधि का घटना-बढ़ना सामान्य घटना है। यह पृथ्वी के अक्ष में 23.5 डिग्री झुके होने व कक्षा में परिभ्रमण के कारण होती है। वर्ष में दो दिन ऐसे आते हैं जब दिन व रात का समय 12-12 घंटे का होता है। अब रोजाना दिन का समय लंबा होता जाएगा, जो 21 जून तक जारी रहेगा। 21 मार्च के बाद 23 सितंबर को दिन व रात बराबर होंगे। 23 सितंबर को शरद विषुवत कहा जाता है। 23 सितंबर से रातें लंबी होने लगती हैं।

लगातार दूसरी बार भारत में होगी मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता

दीपेश पांडेय

हैदराबाद : लगातार दूसरी बार भारत में हो रही मिस वर्ल्ड (विश्व सुंदरी) प्रतियोगिता के शंखनाद के दौरान गुरुवार को जब वर्तमान मिस वर्ल्ड क्रिस्टीना पिस्जकोवा साड़ी पहनकर मंच पर पहुंचीं तो सभी मंत्रमुग्ध हो गए। पिछले साल मुंबई में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इस साल 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता तेलंगाना में आयोजित की जा रही है। यह प्रतियोगिता सात से 31 मई तक चलेगी, जिसमें 140 देशों की सुंदरियां अपने-अपने कौशल, व्यक्तित्व के आधार पर मिस वर्ल्ड के ताज पर अपना दावा पेश करेंगी।

तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में मिस वर्ल्ड क्रिस्टीना पिस्जकोवा के साथ मिस वर्ल्ड आर्गेनाइजेशन की चेयर वूमेन जूलिया मोर्ले, तेलंगाना के पर्यटन मंत्री जुपल्ली कृष्ण राव और तेलंगाना सरकार में पर्यटन विभाग की सचिव स्मिता सभरवाल की उपस्थिति में इस प्रतिस्पर्धा का शंखनाद किया गया।

इस मौके पर क्रिस्टीना ने कहा, साड़ी पहनने के लिए मैं बहुत उत्साहित थी। मेरी बहन ने मुझे साड़ी दी थी, जो वह मेरे लिए भारत से चेक रिपब्लिक लेकर गई थी। मैं उसे पहनना चाहती थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि साड़ी कैसे पहनते हैं। जब मैं तेलंगाना आई तो मैंने कहा कि मैं साड़ी पहनना पसंद करूंगी। मैं भारतीय पारंपरिक कपड़े पहनना चाहती हूं, क्योंकि मैं यहां की संस्कृति का अनुभव करना चाहती हूं। इसलिए मैंने आज साड़ी पहनी है।

तेलंगाना सरकार में पर्यटन विभाग की सचिव स्मिता सभरवाल ने कार्यक्रम से इतर दैनिक जागरण से बातचीत में कहा, जो मिस वर्ल्ड सौंदर्य प्रतिस्पर्धा में उतरना चाहती हैं, उन्हें जरूर उतरना चाहिए। इस साल मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में 140 देशों की प्रतिभागी आ रही हैं। उनमें से 20 पेशेवर डाक्टर हैं। प्रतिभागियों में कई इंजीनियर और वकील भी हैं। सपने बड़े देखें, जिंदगी में कोई बड़ा उद्देश्य रखें और कठिन परिश्रम करें।

« मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2025 को लेकर गुरुवार को हैदराबाद में प्रेस कान्फ्रेंस के दौरान हाथ जोड़कर अभिवादन करतीं मिस वर्ल्ड 2024 क्रिस्टीना पिस्जकोवा। इस अवसर पर वह साड़ी पहने हुए दिखीं। प्रेट्र

▸ **सात से 31 मई तक तेलंगाना करेगा 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की मेजबानी**

▸ **साड़ी पहन विश्व सुंदरी क्रिस्टीना पिस्जकोवा ने लोगों को किया मंत्रमुग्ध**

मंत्री का दावा 200 नहीं, 27 करोड़ आएगा सरकारी खर्च

पिछले दिनों मिस इंडिया प्रतिस्पर्धा के आयोजन पर करीब 200 करोड़ रुपये खर्च करने के लेकर विपक्ष ने तेलंगाना सरकार को घेरा था। समारोह में इससे जुड़े सवाल पर तेलंगाना के पर्यटन मंत्री ने कहा कि मिस वर्ल्ड संस्था के साथ हुए करार के तहत इस आयोजन पर कुल 54 करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं। जिसमें से आधा खर्च यानी 27 करोड़ रुपये सरकार और आधा मिस वर्ल्ड लिमिटेड वहन कर रही है। सरकार की कोशिश इस 27 करोड़ में से भी अधिकांश हिस्सा स्पांसरशिप से जुटाने की है।

विज्ञानियों ने पेट के कैंसर के संभावित नए कारण का पता लगाया

अनुसंधान

विज्ञानियों की एक टीम ने पेट के कैंसर के नए संभावित कारण का पता लगाया है। यह दुनिया भर में पांचवां सबसे आम कैंसर है। इसे गैस्ट्रिक कैंसर के नाम से भी जाना जाता है। एक अध्ययन में सेंगर इंस्टीट्यूट के अनुसंधानकर्ता ने हांगकांग, अमेरिका और ब्रिटेन के 30 लोगों के पेट से सामान्य, गैर-कैंसर वाले गैस्ट्रिक ग्रंथि ऊतक के 238 नमूनों के पूरे जीनोम को अनुक्रमित किया। इनमें से 18 को गैस्ट्रिक कैंसर था और 12 को नहीं।

लेजर कैप्चर माइक्रोडिसेक्शन के साथ जीनोम अनुक्रमण के लिए पेट की परत के नमूनों से अलग-अलग कोशिकाओं की ठीक से जांच की। उन्होंने पाया कि पेट की अम्लीय सामग्री के नियमित संपर्क के बावजूद, सामान्य गैस्ट्रिक ग्रंथियों में उत्परिवर्तन शरीर की अधिकांश कोशिकाओं के समान दर पर उत्पन्न हुए। इससे पता चलता है कि गैस्ट्रिक एपिथेलियम में कोशिकाएं अम्लीय पेट की सामग्री के किसी भी विषाक्त प्रभाव से सुरक्षित हैं। हालांकि, गैस्ट्रिक कैंसर से पीड़ित लोगों में, सामान्य, गैर-कैंसरग्रस्त पेट की परत की कुछ ग्रंथियों में सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ऐसे परिवर्तन दिखाई दिए। इन सामान्य ग्रंथियों में उत्परिवर्तन की संख्या में वृद्धि थी, जिसने गैस्ट्रिक कैंसर की शुरुआत में योगदान दिया हो सकता है। कैंसरग्रस्त ऊतकों में म्यूटेशन की संख्या अधिक थी, जो दर्शाता है कि गैस्ट्रिक कैंसर विकास के दौरान बाद में उत्परिवर्तन को बड़े पैमाने पर बढ़ाता है। प्रोफेसर सुएट यी लेउंग ने बताया कि हमने एक असामान्य घटना की खोज की, जहां कुछ व्यक्तियों में कुछ निश्चित गुणसूत्रों की तीन प्रतियां थीं, जिन्हें ट्राइसोमी के रूप में जाना जाता है, वहीं अन्य में यह नहीं थी। (एएनआइ)

स्क्रीन शाट

...शर्मीले सिद्धांत चतुर्वेदी कुछ ऐसे बन गए कवि

विश्व कविता दिवस विशेष

मैं कहीं कवि ना बन जाऊं, तेरे प्यार में ऐ कविता... मोहम्मद रफी का गाया यह गीत वास्तविक साबित हुआ, जब अभिनेता सिद्धांत चतुर्वेदी ने लड़की से बात करने के लिए अपने शब्दों को कविताओं की शक्ल दी। विश्व कविता दिवस के मौके पर अभिनय के साथ कविताएं लिखने का शौक रखने वाले सिद्धांत कहते हैं कि स्कूल के दिनों में मैं काफी शर्मीला बच्चा हुआ करता था और अभी भी हूं। जब किसी लड़की से कोई बात नहीं कह पाता था, तो वह मैं लिख लेता था। उसको कुछ ऐसे तरीके से लिखता कि वह थोड़ा फिल्मी या कविता के रूप में हो। कविताएं लिखने की शुरुआत तो वहां से हुई थी। उसके बाद भी मैं कविताएं लिखते रहा लेकिन कभी उसके अपने इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट नहीं किया। हां, कभी-कभार अपने तस्वीरों के फोटो कैप्शन में कुछ पंक्तियां लिख देता था। फिर मेरी फिल्म गल्ली ब्वाय आई। उसमें मुझे कुछ लिखने का मौका मिला, क्योंकि रैप और कविताएं लगभग एक जैसी होती हैं। कविताएं तो मैं पहले से लिखता था, तो मैंने गली ब्वाय में अपनी भूमिका में जाने के लिए काफी रैप गाने लिखे। उसके बाद मुझे लिखने का भूत थोड़ा और चढ़ा, तो मैंने तय किया कि अपनी कविताओं का एक अलग ही पेज बना लेता हूं। तो मैंने अपनी कविताओं का सिडीचैट्स नाम से एक अलग ही पेज बना दिया। जिस पर मैं तीन-चार पंक्तियों की कविताएं लिखता हूं। यह मेरा एक और शौक है, जो मैं करता हूं। मुझे जो कुछ भी महसूस होता है, जिंदगी के बारे में मैं जो कुछ भी सोचता या देखता हूं, उन्हें काव्यात्मक तरीके से कहने की कोशिश करता हूं।

सिद्धांत चतुर्वेदी। फाइल

बचपन में साइकिल खो जाने का दुख व्यक्त किया था कविता लिखकर : पारितोष त्रिपाठी

चाय-सी मुहब्बत और मन पतंग दिल डोर किताबें लिख चुके अभिनेता और कवि पारितोष त्रिपाठी भी कविताओं के लिए खासा प्रसिद्ध हैं। आज विश्व कविता दिवस पर कविताओं से लगाव को लेकर वह कहते है कि लिखने की इस कला की वजह से मैं काफी कुछ कर पाता हूं। पहली बार कविता बचपन में तब लिखी थी, जब मेरी साइकिल खो गई थी। उस दुख को व्यक्त करने के लिए कविता का सहारा लिया था। वह कविता बहुत ही बच्चों जैसी थी, लेकिन अहसास असली थे। माता-पिता साहित्यकार रहे हैं, पूरा परिवार शिक्षा के क्षेत्र में रहा है। उस परवरिश की वजह से साहित्य की तरफ रुझान था। जब दिल्ली गया, तो सबसे ज्यादा कविताओं का लिखना हुआ। आप जब वहां स्कूल से निकलकर कालेज जाते हैं, कोई लड़की भी पसंद आ रही होती है, प्रेम प्रसंग भी शुरू रहता है, थिएटर चल रहा था, तो नाटक में भी कुछ लिख रहा था, वहां से कविताओं का सफर तेज हुआ। सुपर डांसर शो में मेरे पात्र मामाजी शायर थे। उसमें काफी सारा लिखना हुआ। मेरी कविताओं को किताब की शक्ल देने का श्रेय गीता (कपूर) दीदी को जाता है। मैंने कई अलग-अलग पन्नों पर लिखकर कविताएं बिखेर रखी थी। किताब छपनी चाहिए। मेरी मजदूर और पिता पर लिखी कविताएं खासा प्रसिद्ध रही हैं, इसलिए मेरा लिखना भी कभी छूटा नहीं। कवि के रूप में मुझे इंडस्ट्री में जल्द अपना लिया था। मैं तो कविताओं के शोज भी करता हूं। कविताएं लिखने का यह गुण मुझे अभिनय में भी काम आता है। मैं लिखता हूं, तो समझ आता है कि लेखक ने क्या सोचकर लिखा होगा। कविताओं की समझ अगर अच्छी है, तो जीवन की समझ बेहतर हो जाती है।

अपनी कविताओं को लेकर शोज भी करते हैं पारितोष।

साल 2008 में फिल्म 1920 से हिंदी सिनेमा में कदम रखने वाली अभिनेत्री अदा शर्मा को साल 2023 में प्रदर्शित फिल्म द केरल स्टोरी से देशव्यापी लोकप्रियता मिली। वह आज (21 मार्च) से सिनेमाघरों में प्रदर्शित हो रही फिल्म तुमको मेरी कसम में इंदिरा आइवीएफ के संस्थापक डाक्टर अजय मुर्डिया की दिवंगत पत्नी इंदिरा की भूमिका में नजर आएंगी। अदा से उनके फिल्म करियर और अभिनय सफर पर बातचीत :

● द केरल स्टोरी के बाद लोगों को आपसे हर प्रोजेक्ट में एक अलग उम्मीद होती होगी, उस पर खरी उतरने के क्या प्रयास हैं?

-एक फिल्म को हिट बनाने में बहुत से लोगों का हाथ होता है। मैं बस यही कोशिश कर सकती हूं कि मेरी भूमिका लोगों के दिल को छुए। उसके बाद फिल्म का बजट क्या हो, किस प्लेटफार्म पर या कितने स्क्रीन पर रिलीज होगी, वह सब मेरे हाथों में नहीं है। द केरल स्टोरी के बाद मैंने सुनील ग्रोवर के साथ वेब सीरीज सनफ्लावर की। उसमें मेरी कोशिश रही कि मेरी कामेडी भी उनके टक्कर की हो। उसके बाद रीटा सान्याल किया, उसमें 10 अलग-अलग लुक को अलग-अलग भूमिकाओं की तरह निभाने की कोशिश की। मैं सिर्फ अपनी भूमिका पर ध्यान देती हूं।

● वास्तविक व्यक्ति (इंदिरा) की भूमिका निभाने की क्या चुनौतियां रहीं?

-इंदिरा जी अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन यह भूमिका निभाने से पहले मैं उनके परिवार से मिली, उनकी ढेर सारी तस्वीरें देखी। मैंने शारीरिक हाव-भाव, बातचीत की शैली से लेकर कई चीजें उनके जैसे ही करने की कोशिश की।

● इंटरनेट पर आप कभी बिना मेकअप, तो कभी पसीने में भीगी तस्वीरें साझा करती रहती हैं..

-मैं जो हूं, जैसी हूं वो लोगों को बता देती हूं। लोग कुछ कलाकारों को ऐसे नहीं पसंद करते हैं, वो चाहते हैं कि वह कलाकार सिर्फ फैशन या डिजाइनर कपड़ों में ही तस्वीरें साझा करें। मैं तो अगर पसीने में या कभी बिखरे बालों के साथ भी फोटो या वीडियो डालती हूं तो लोग उसे भी पसंद करते हैं। शायद मैंने कोई पुण्य किए होंगे जो मुझे ऐसा प्यार मिल रहा है।

● पेड़, पहाड़, जंगल, चिड़िया अक्सर आप प्राकृतिक चीजों के करीब दिखती हैं?

-इससे मुझे खुश रहने में मदद मिलती है। अगर मैं खुश हूं तो हर किरदार को पूरी शिद्दत के साथ निभा सकती हूं। अगर मैं खुश नहीं हूं तो डायलाग भूलती हूं, मन कहीं और भी होता है। मैं प्रकृति से जुड़ी नहीं रहती हूं, बल्कि मैं वही हूं। वही मेरा वास्तविक व्यक्तित्व है।

● फिल्मों में डांस के मौके कम मिले

-मुझे तो फिल्मों में डांस करने के मौके मिले ही नहीं हैं। मैं स्टारकिड नहीं हूं, मुझे ऐसे मेरी मनपसंद के प्रोजेक्ट सजाकर नहीं मिलेंगे। हालांकि, मुझे जो मिला है, उससे खुश हूं। ऐसी कौन सी हीरोइन है कि वो हारर से शुरुआत करे, फिर एक्शन और कामेडी करे तथा द केरल स्टोरी जैसी फिल्म भी करे। मैं खुद को खुशकिस्मत मानती हूं कि इंडस्ट्री में बिना किसी रिश्ते-नाते के मुझे इतने सारे मौके मिले हैं। बाकी डांस करने का मौका तो सभी को मिलता है, मुझे भी कभी न कभी मिल ही जाएगा।

● पहली बार स्टारडम कब महसूस हुआ था?

-पहली बार स्टारडम पहली फिल्म 1920 के बाद महसूस हुआ, तब लोग मुझे पहचानने लगे थे। हालांकि, तब लीजा-लीजा (1920 के पात्र के नाम) कहकर बुलाते थे। सबसे बड़ा स्टारडम तो द केरल स्टोरी के बाद महसूस हुआ। हर कोई मेरे नाम से जानने लगा।

● आगे टिब्बा और गेम आफ गिरगिट के अलावा और कौन से प्रोजेक्ट हैं?

-अभी मैं छह फिल्में कर रही हूं। इनमें एक और हारर फिल्म भी है। 1920 के बाद दोबारा हारर फिल्म करने के लिए काफी इंतजार करना पड़ा। फिर दो रोमांटिक फिल्में हैं। एक अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट है। दक्षिण भारतीय सिनेमा में भी मैं दो प्रोजेक्ट कर रही हूं।

(दीपेश पांडेय)

ट्रोलर्स को करण का करारा जवाब

निर्माता करण जौहर अक्सर नेपोटिज्म को बढ़ावा देने को लेकर ट्रोलर्स के निशाने पर रहते हैं। अब अपनी फिल्म केसरी चैप्टर 2 : द अनटोल्ड चैप्टर आफ जलियांवाला बाग से पहले इंस्टाग्राम पर एक नोट लिखकर ट्रोलर्स को जवाब दिया है। उन्होंने लिखा, 'जब मैंने 2003 में कल हो ना हो के साथ फिल्में बनाना शुरू किया था, तो विचार यही था कि निर्माताओं और कहानीकारों को सशक्त बनाया जाए। हमने सही किया या गलत किया, लेकिन इरादा हमेशा ऐसी कहानियां और फिल्में पेश करने का था, जिन पर हमें विश्वास हो। मकसद केवल मनोरंजन करना, प्रशंसा पाना या फिर फिल्मों का मजा लेना था। मुझे यह कहते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि हिंदी सिनेमा में हम 24वां नवोदित निर्देशक लेकर आ रहे हैं (ट्रोल करने वालों के लिए सामान्य ज्ञान : उनमें से 90 प्रतिशत 'आउटसाइडर' हैं)। मैं किसी फिल्म की रिलीज से पहले शायद ही कभी नोट्स लिखता हूं, लेकिन कुछ फिल्में मुझे उत्साहित करती हैं, ऊर्जा देती हैं, जिस तरह से इस फिल्म की प्रक्रिया ने किया है।

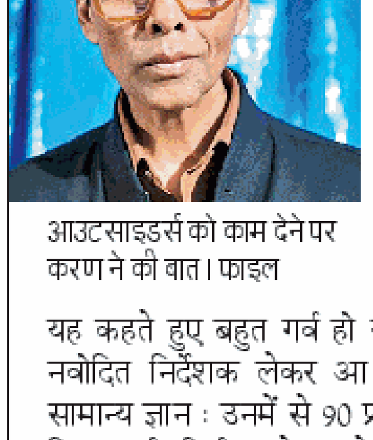

आउटसाइडर्स को काम देने पर करण ने की बात। फाइल

कल्कि के सीक्वल में प्रभास का बड़ा रोल

पिछले साल रिलीज साइंस फिक्शन माइथोलाजिकल फिल्म कल्कि 2898 एडी में प्रभास का स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन सीक्वल में उनकी भूमिका काफी बड़ी और गहरी होगी। यह बात फिल्म के निर्देशक नाग अश्विन ने कही है। साथ ही बताया कि फिल्म के सीक्वल की शूटिंग इस साल के अंत में दिसंबर से आरंभ होगी। फिल्म में अमिताभ बच्चन, प्रभास, दीपिका पादुकोण और कमल हासन प्रमुख भूमिका में थे। फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 1180 करोड़ रुपये की कमाई की थी। प्रभास के कम स्क्रीन टाइम को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में अश्विन ने कहा कि मूल फिल्म में उस दुनिया और सुमति (दीपिका पादुकोण का पात्र) की बैकस्टोरी पर फोकस किया गया था ताकि सीक्वल की नींव मजबूत हो और प्रभास के पात्र कर्ण को एक्सप्लोर किया जा सके। उन्होंने कहा कि सीक्वल में प्रभास का हिस्सा बड़ा होगा। कहानी मुख्य रूप से कर्ण और अश्वत्थामा (अमिताभ बच्चन) के पात्र पर ज्यादा केंद्रित होगी। कल्कि 2898 एडी में प्रभास ने भैरव की भूमिका अभिनीत की थी। इसमें उसका साथ देती है एक विशेष प्रकार की गाड़ी जिसे वह बुज्जी बुलाता है। उनके पात्र कर्ण को कहानी में पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं किया गया है। प्रभास आगामी दिनों में फिल्म द राजासाब में नजर आएंगे।

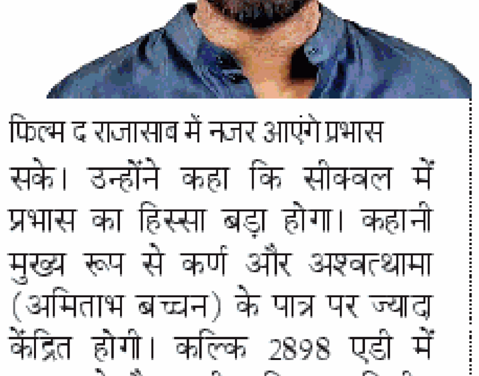

फिल्म द राजासाब में नजर आएंगे प्रभास

सुबह छह बजे एल 2: एम्पुरान का पहला शो देखेंगे मोहनलाल

दर्शकों के साथ फिल्म देखने का अनुभव कलाकारों के लिए बेहद खास होता है। दर्शकों के प्यार के कारण ही वह स्टार बनते हैं। ऐसे में उन्हें सम्मान देना कलाकारों के लिए जरूरी है। यह मानना है मलयालम फिल्म अभिनेता मोहनलाल का। गुरुवार को मुंबई में ट्रायोलाजी फिल्म लूसिफर के दूसरे पार्ट एल 2 : एम्पुरान के ट्रेलर लांच के मौके पर मोहनलाल के साथ फिल्म के निर्देशक पृथ्वीराज सुकुमारन और फिल्म की अभिनेत्री मंजू वारियर मौजूद रहीं। इस मौके पर मोहनलाल ने कहा, 'यह फिल्म मुझे दर्शकों के साथ देखनी है। 27 मार्च को सुबह छह बजे हम सभी यह शो उनके साथ देखेंगे।' इस फिल्म को पैन इंडिया रिलीज करने को लेकर आगे मोहनलाल कहते हैं, 'मैं 47 साल से अभिनय कर रहा हूं। मलयालम में इस स्तर की फिल्म बनाना आसान नहीं है। हम इसे पैन इंडियन फिल्म कह रहे हैं। हालांकि हमने बहुत साल पहले सजा-ए-कालापानी (मलयालम में फिल्म का नाम कालापानी था) नाम की पैन इंडियन फिल्म बनाने का प्रयास किया था। सपना वैसी ही फिल्म दोबारा बनाने का था। यह सपना पूरा होने जैसा है।'

फिल्म लूसिफर के दूसरे पार्ट में लौटे मोहनलाल ● फिल्म टीम

****